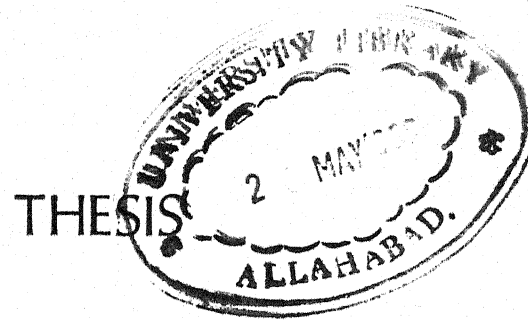


SALES TAX STRUCTURE : PROBLEMS AND SOLUTIONS

WITH SPECIAL REFERENCE TO U. P.



**SUBMITTED TO THE UNIVERSITY OF ALLAHABAD FOR THE
DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY.**

IN

COMMERCE

Under The Supervision Of :

Dr. K. M. SHARMA

M. Com., D.Phil.

Reader,

Department of Commerce &

Business Administration

University of Allahabad

ALLAHABAD.

Submitted By :

NARESH K. KESHARWANI

M. Com.

Research Scholar,

Department of Commerce &

Business Administration

University of Allahabad

ALLAHABAD.

विषय परिचय

विषय परिचय एवं स्वरंज

वर्तमान समय में राज्य सरकारों के कर आगम में बिजुलीकर अप्रत्याशित रूप से स्वयं में अत्यधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। वर्तमान समय में यह कर 1938 में मध्य प्रान्त एवं बरार में प्रारम्भ हुआ था, लेकिन अत्यन्त अल्प अवधि में ही सभी राज्य सरकारों ने इसे आगम के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्वीकार किया। इस सन्दर्भ में यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पता चलता है कि सत्र 1951-52 में बिजुली कर से सभी राज्य सरकारों को कुल आगम 58.93 करोड़ रुपये था जो कि सत्र 1985-86 में 7884.94 करोड़ रुपये हो गया अतः इस अवधि में राज्य सरकारों के कर आगम में बिजुलीकर का अंशदान 25.88 प्रतिशत से बढ़कर 54.74 प्रतिशत हो गया। स्पष्ट है कि राज्य सरकारों के वित्तीय तालाबों में सर्वोच्च अंशदान के रूप में बिजुली कर की अपनी विशिष्ट भूमिका बन गयी है।

बिजुलीकर की निरन्तर बढ़ती हुई भूमिका में जहाँ एक ओर राज्य सरकारें इसे अपनी वित्तव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयोग करके इस व्यवस्था की उत्पादकता और लोचकता का पूर्ण लाभ उठा रही हैं। वहीं दूसरी ओर व्यापारी वर्ग इसके प्रभाव तथा इसके क्रियान्वयन के प्रति तबल आनोचक हैं तथा इसके सरलीकरण तथा प्रतिस्थापन की माँग बढ़ती जा रही है। बिजुलीकर के विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण करने तथा इसके प्रतिस्थापन के विविध पक्षों पर विचार करने के लिये केन्द्रीय एवं राज्यकीय स्तर पर कई समितियों का गठन किया गया, परन्तु उन सभी समितियों की सिफारिशों के बावजूद भी ऐसा कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर बिजुलीकर प्रावधानों एवं प्रवृत्तियों की विस्तृत एवं समग्र स्थिति स्पष्ट हो सके। इन्हीं सभी पक्षों से प्रभावित होकर मैं अपने शोध-कार्य के लिये "बिजुलीकर के दायि, समस्याएँ एवं समाधान उत्तर प्रदेश के विशिष्ट सन्दर्भ में" सम्बन्धित विषय का चयन किया। विषय की महत्ता और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत शोध-कार्य में विभिन्न राज्यों की बिजुलीकर व्यवस्था का अध्ययन करते हुए उत्तर प्रदेश में बिजुलीकर व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत शोध-कार्य के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। बिजुलीकर तथा

केन्द्रीय बिजलीकर तथा बिजलीकर प्रशासन और क्रियान्वयन में प्रशासकों, व्यापारियों और सामान्य दृष्टिकोण से विभिन्न समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन । यद्यपि इन सभी उद्देश्यों के तन्द्भ में बिजलीकर व्यवस्था का देश में विभिन्न राज्यों की दृष्टि से अध्ययन किया गया है । और आगम प्रवृत्तियों के विश्लेषण में देश के सभी राज्यों की प्रवृत्तियों को शामिल किया गया है, लेकिन पूर्व उल्लेखित क्षेत्र के तन्द्भ में उत्तर प्रदेश के बिजलीकर प्रावधानों, बिजलीकर प्रशासन, आगम प्रवृत्तियों और समस्याओं के विश्लेषण पर प्रथम और विशिष्ट ध्यान दिया गया है ।

प्रस्तुत शोध-कार्य को कुल दस अध्यायों में विभाजित किया गया है । प्रथम अध्याय में बिजलीकर के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि प्रारम्भ में विश्व के विभिन्न देशों में किस प्रकार बिजलीकर चलाया जाता था । इसी अध्याय में देश के विभिन्न राज्यों में बिजलीकर के प्रारम्भ और विकास की संक्षिप्त ऐतिहासिक विवेचना की गयी है । द्वितीय अध्याय में बिजलीकर के पृष्ठावलोकन, स्वभाव, प्रवृत्ति तथा बिजलीकर के विभिन्न स्वरूपों की विवेचना की गयी है । तृतीय अध्याय में भारत में बिजलीकर के सामान्य अध्ययन तथा तथैधानिक स्थिति का उल्लेख किया गया है । चतुर्थ अध्याय में केन्द्रीय बिजलीकर का परिचय देते हुए उसके उद्देश्यों एवं विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है साथ ही इस पर प्राप्त आगम की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए समीक्षात्मक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है । पाँचवें एवं छठवें अध्याय में उत्तर प्रदेश में बिजलीकर व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है साथ ही प्रदेश के तन्द्भ में बिजलीकर प्रशासनिक एवं संगठनात्मक ढाँचे की विस्तृत विवेचना करते हुए विभिन्न स्तर पर कार्यरत बिजलीकर पदाधिकारियों के कार्य, क्षेत्र, अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है । सातवाँ अध्याय देश के विभिन्न राज्यों में विविध वर्गों में बिजलीकर आगम की संख्यात्मक प्रवृत्तियों को दर्शाता है । इस अध्याय में राज्य सरकारों के आगम में बिजलीकर की भूमिका को भूम्यांकित करने का प्रयास किया गया है । इसी अध्याय में देश के अनेक राज्यों में बिजलीकर से सम्बन्धित प्रमुख व्यवस्थाओं और प्रावधानों की तुलनात्मक समीक्षा की गयी है । आठवाँ अध्याय बिजलीकर की प्रमुख

समस्याओं से सम्बन्धित है। इन समस्याओं का उत्तर प्रदेश के विशिष्ट तन्त्र में उल्लेख किया गया है। नवम अध्याय में बिजली के प्रतिस्थापन के पल्लू का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। अन्तिम अध्याय में शोध-कार्य के निष्कर्षों को प्रस्तुत करने हुए बिजली की व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये हैं।

प्रस्तुत शोध-कार्य का मुख्य आधार व्यापारियों, उद्योगपतियों, अधिक्ताओं, राजवित्त विभागों, अधिष्ठात्रियों, जनप्रतिनिधियों तथा उद्योग एवं पत्रिकाओं के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये विचारों, तैयारियों तथा विभिन्न न्यायिक वादों में दिये गये निर्णय हैं। संक्षेपतः तथ्यों की दृष्टि से यह शोध-कार्य मुख्यतः प्रकाशित समकों के विश्लेषण एवं निर्वहन पर आधारित है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के कबलों तथा विभिन्न राज्य सरकारों के प्रकाशनों का प्रयोग उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश के तन्त्र में सभी समक उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा मध्यमपूर्ण आदेशों एवं परिपत्रों की दृष्टिकोण पर आधारित है जबकि अन्य राज्यों के समक विभिन्न राज्य सरकारों के बिजली विभागों द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनों और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया क्वोटिन पर आधारित है। इसके साथ ही कर बोध समिति, अप्रत्यक्ष कर बोध समिति तथा त्रिपाठी समिति के प्रतिवेदनों का भी व्यापक प्रयोग किया गया है। आवश्यकतानुसार बिजली से सम्बन्धित व्यक्तियों, व्यवसायियों, फार्मों, अधिक्ताओं तथा अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क भी स्थापित करके बिजली की समस्याओं, नियमों की कठिनायियों तथा प्रावधानों की भिन्नताओं को समझने एवं उनके द्वारा दिये गये विचारों के आधार पर भी आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि बिजली के विभिन्न पल्लुओं से सम्बन्धित तथ्यों एवं समकों में, विभिन्न राज्य सरकारों के बिजली विभाग के प्रकाशनों में विवरण तथा संगोष्ठी और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया क्वोटिन से इन प्रकाशनों के अन्तर के कारण उनको तभी एवं क्रमशः रूप में प्रस्तुत करने में अनेक सीमाएँ रही हैं तथा देश में सभी राज्य सरकारों के बिजली प्रावधानों को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका है। तथापि मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत शोध-कार्य भारत में बिजली की व्यवस्था को

एक स्व तथा विवेकपूर्ण बनाने तथा विशेष स्व से उत्तर प्रदेश में बिड़ौकर प्राधान्यों को तरल, तर्कमय तथा प्रगतिशील को प्रभावशाली बनाने में पर्याप्त उपयोगी सिद्ध होगा । मैं उन सभी शुभाकांक्षियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, अधिवक्ताओं, राजपति विशेषकों, अध्यक्षत्वियों एवं संस्थाओं के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता प्रकट करना अपना पावन कर्तव्य समझता हूँ, जिन्होंने प्रस्तुत शोध-कार्य को पूर्ण करने और प्रस्तुतीकरण में मुझे विविध प्रकार से बहुमूल्य योगदान प्राप्त हुआ है ।

मैं प्रो० बी०सी० अग्रवाल । विभागाध्यक्ष वाणिज्य एवं प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समय-समय पर अपने विचारों के द्वारा मुझे शोध कार्य के लिये प्रेरित किया तथा मुझे आगे बढ़ने में सहयोग दिया । मैं प्रो० एत०के० मिश्र । डीन वाणिज्य एवं प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति भी आभार व्यक्त करना अपना धर्म समझता हूँ, जिन्होंने इस शोध में मुझे सहयोग प्रदान किया । मैं प्रो० पी०सी० शर्मा, प्रोफेसर, वाणिज्य एवं प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने अपने विचार विमर्श के द्वारा मुझे मार्गनिर्दिष्ट किया तथा काफी अल्प समय में ही शोध-कार्य प्रस्तुत करने के लिये प्रेरित किया ।

इस महत्वपूर्ण विषय पर शोधकार्य हेतु प्रेरणा तब और अपने परममूल्य गुरु डा० के०एम० शर्मा, रीडर, वाणिज्य एवं प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मेरा परमकर्तव्य है, जिन्होंने कुशल निर्देशन में प्रस्तुत शोध कार्य पूर्ण किया था तब । वास्तव में उनकी तत्त्व प्रेरणा, उत्कृष्ट निर्देशन, सक्रिय व्यक्तित्व रुचि एवं उच्च स्तरीय शैक्षणिक विचार-विमर्श से ही प्रस्तुत शोध-कार्य की कल्पना को साकार रूप में प्रस्तुत करने में सफलता सम्भव हुई है।

प्रस्तुत शोध-कार्य के सन्दर्भ में विषय सामग्री का अध्ययन करने तथा विभिन्न तथ्यों के संकलन में मुझे जिन पुस्तकालयों की सुविधा मिली है, उनके पुस्तकालयाध्यक्षों एवं सहयोगी कर्मचारियों का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । मैं विभिन्न व्यापारियों, उद्योग-पतियों एवं अधिवक्ताओं का आभारी हूँ जिन्होंने बिड़ौकर की विभिन्न समस्याओं

एवं उनके सन्दर्भ से अपने सुझाव दिये । मैं श्री राम बरन यादव, टंकणकता, तैला विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आभारी हूँ जिन्होंने समय के अन्दर मेरे शोध-कार्य की उत्कृष्ट पाण्डुलिपि तैयार करके दी । मैं श्री डी०के० लहरी, वाणिज्य एवं प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे शोध-कार्य में सहयोग प्रदान किया । मैं अपने मित्र श्री रामजी टण्डन एवं श्री तुनील कुमार का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे शोध कार्य में सहयोग प्रदान किया । मैं अपने पूज्य चाचाजी ।श्री मेवालाल केसरवानी, सड़सोकेट। का भी आभारी हूँ, जिन्होंने विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श करके मुझे सहयोग प्रदान किया । मैं अपने परम पूजनीय पिताजी, माताजी एवं बड़े भाई साहब का ऋणी हूँ जिन्होंने मेरे पठन-पाठन के कार्य में हमेशा उत्तुङ्गता दिखायी तथा मुझे शोध-कार्य के लिये प्रेरित किया ।

इलाहाबाद

११ अक्टूबर, १९८८

नरेश कुमार केसरवानी

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठांक
	विषय परिचय	1 - v
	तालिका सूची	vi - viii
<u>प्रथम</u>	: <u>भारत में बिड़ोकर का ऐतिहासिक विकास</u>	1 - 12
	विषय में बिड़ोकर : सामान्य परिचय ; भारत में बिड़ोकर का ऐतिहासिक विकास एवं विभिन्न राज्यों में बिड़ोकर की विवेचना ।	
<u>द्वितीय</u>	: <u>बिड़ोकर : पृष्ठावलोकन</u>	13 - 40
	बिड़ोकर का आशय ; बिड़ोकर का स्वभाव एवं प्रकृति; बिड़ोकर के रूप ; विद्रुय कर एवं क्रय कर में अन्तर ; बिड़ोकर अधिनियम ; बिड़ोकर के पक्ष एवं विपक्ष के तर्कों का मूल्यांकन तथा निष्कर्ष ।	
<u>तृतीय</u>	: <u>भारत में बिड़ोकर का सामान्य अध्ययन एवं तथैधानिक स्थिति</u>	41 - 52
<u>चतुर्थ</u>	: <u>केन्द्रीय बिड़ोकर : परिचय, उद्देश्य एवं विरोधतार्</u>	53 - 75
	केन्द्रीय बिड़ोकर अधिनियम का परिचय; उद्देश्य, प्रमुख विरोधतार् एवं केन्द्रीय बिड़ोकर से आगम की प्रभुत्तियाँ तथा उनका विवेचना ।	
<u>पंचम</u>	: <u>उत्तर प्रदेश में बिड़ोकर</u>	76 - 118
	परिचय : ऐतिहासिक विवेचना : प्रमुख विरोधतार् एवं अधिनियम के प्रावधानों का विवेचनात्मक अध्ययन ; आगम-प्रभुत्तियाँ एवं विवेचना ।	

अध्याय	विषय	पृष्ठानि
--------	------	----------

प्रथम	: <u>बिहारीकर : पुशातनात्मक पहलु एवं दार्शनिक उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में।</u>	119 - 152
-------	--	-----------

पुशातनिक स्वरूपा ; विभागीय संगठन एवं पुशातनिक व्यवस्था ; बिहारीकर पदाधिकारी ; कार्यक्षेत्र, अधिकार एवं कर्तव्य ।

तृतीय	: <u>बिहारीकर आगम : तुलनात्मक विश्लेषण</u>	153 - 191
-------	--	-----------

बिहारीकर से आगम : सामान्य प्रवृत्ति ; बिहारीकर आगम : राज्यवार एवं वर्धवार विश्लेषण ; बिहारीकर आगम की राज्यवार और वर्धवार स्थिति ; बिहारीकर आगम : राज्यों की तुलनात्मक स्थिति ; राज्यों की आगम में बिहारीकर की स्थिति ; राज्य सरकारों की कर आगम में बिहारीकर का भाग ।

अष्टम	: <u>विभिन्न राज्यों में बिहारीकर व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन एवं उनकी समस्याएँ</u>	192 - 239
-------	--	-----------

विभिन्न राज्यों का तुलनात्मक आधार राष्ट्रीय नीति के रूप में बिहारीकर की सामान्य समस्याएँ ; उत्तर प्रदेश के विशिष्ट सन्दर्भ में ; पुशातनिक समस्याएँ ; व्यवसायिक समस्याएँ तथा अन्य समस्याएँ ।

नवम	: <u>बिहारीकर का पुनर्स्थापन</u>	240 - 263
-----	----------------------------------	-----------

बिहारीकर के पुनर्स्थापन की आवश्यकता, औचित्य एवं स्वल्प ।

अध्याय	विषय	पृष्ठांक
--------	------	----------

दशम : समाय एवं निष्कर्ष 264 - 273

परिशिष्ट

274
-275 - 285

।अ। उत्तर प्रदेश में बिजुकर विभाग का प्रशासनिक ढांचा

।ब। बिजुकर विभाग परिशेन, क्षेत्र, मण्डल, उपमण्डल

।त। कर मुक्त वस्तुओं की सूची

।द। जांच चौकियाँ एवं तय्य दल इकाइयाँ

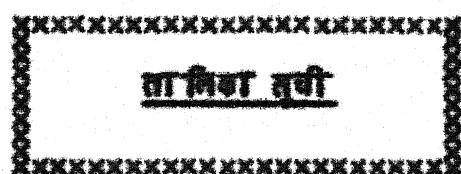
।य। विक्रय कर से मुक्त संस्थाएँ

ग्रन्थ सूची

286 - 289

सरकारी मजदूर एवं रिपोर्ट

जनक पत्रिकाएँ तथा समाचार पत्र



ता लिका सूची

ता लिका संख्या	विषय	पृष्ठांक
1	2	3
4. 1	राज्यों में केन्द्रीय बिजुलीकर अधिनियम के अन्तर्गत वर्षवार बिजुलीकर संग्रह	65
4. 2	केन्द्रीय बिजुलीकर से राज्यवार एवं वर्षवार आगम	68
4. 3	केन्द्रीय बिजुलीकर आगम में राज्यों की तुलनात्मक स्थिति	71
4. 4	केन्द्रीय बिजुलीकर अधिनियम के अन्तर्गत वर्षवार बिजुलीकर संग्रह	72
4x5 5. 1	उत्तर प्रदेश में बिजुलीकर की सामान्य दर	81
5. 2	उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त बिजुलीकर	82
5. 3	कर योग्य तथा पंजीकृत व्यापारियों की संख्या	84
5. 4	विक्रय धन की मौद्रिक सीमानुसार कर योग्य व्यापारियों की संख्या तथा वास्तविक बिजुलीकर संग्रह	86
5. 5	उत्तर प्रदेश में बिजुलीकर संग्रह	100
5. 6	बिजुलीकर का कुल कर राजस्व में प्रतिशत अंशदान	103
5. 7	बिजुलीकर संग्रह तथा संग्रहण व्यय एवं प्रतिशत	104
5. 8	परिदेष्टावार बिजुलीकर राजस्व प्राप्तियों का विवरण	106
5. 9	बिजुलीकर राजस्व प्राप्ति के जिलेवार आंकड़े	109
5. 10	उत्तर प्रदेश में वस्तुवार एवं वर्षवार बिजुलीकर संग्रह	114
6. 1	उपायुक्त (अपील) बिजुलीकर के अधिक्षेत्र की अपीलों की स्थिति	126
6. 2	निस्तारित अपीलों का वर्षवार प्रति अधिकारी प्रति कार्यदिवस और निस्तारण	127

1	2	3
6.3	निस्तारित बिड्डीकर अपीलों के वर्षवार परिणाम तथा घटाई गई/बढ़ाई गई विवादित कर की धनराशि के अंकड़े	128
6.4	करापचयन	130
6.5	उत्तर प्रदेश में सहायक आयुक्त (न्याय) बिड्डीकर से सम्बन्धित अपीलों की विभिन्न वर्षों की स्थिति	134
6.6	निस्तारित बिड्डीकर की अपीलों के वर्षवार परिणाम तथा विवादित कर राशि	136
6.7	बिड्डीकर जांच चौकियों की कार्य प्रगति	139
6.8	बिड्डीकर सयन दलों की प्रगति	141
6.9	सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) बिड्डीकर, उत्तर प्रदेश द्वारा बिड्डीकर से सम्बन्धित कर निर्धारण वादों की स्थिति	142
6.10	उत्तर प्रदेश में बिड्डीकर से सम्बन्धित समस्त कर निर्धारण के वादों की प्रगति	146
6.11	बिड्डीकर न्यायाधिकरण द्वारा द्वितीय अपीलों की प्रगति	149
7.1	विभिन्न वर्षों में बिड्डीकर से आगम	153
7.2	राज्यों की बिड्डीकर-आगम	158
7.3	नियोजन काल में राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व बिड्डीकर से आगम	161
7.4	राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिड्डीकर से आगम	164
7.5	तृतीय पंचवर्षीय योजना में बिड्डीकर से आगम	166
7.6	तीन पंचवर्षीय योजनाओं में बिड्डीकर से आगम	167
7.7	चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में बिड्डीकर से आगम	169
7.8	पाँचवी पंचवर्षीय योजना एवं छठी पंचवर्षीय योजना के पूर्व बिड्डीकर से आगम	172

1	2	3
7.9	छठवीं पंचवर्षीय योजना में बिजलीकर से आगम	175
7.10	कुल बिजलीकर आगम की राज्यवार और वर्षवार स्थिति	178
7.11	बिजलीकर आगम : विविध राज्यों की तुलनात्मक स्थिति	182
7.12	राज्य की आगम, कुल कर आगम, कुल आगम एवं कुल प्राप्त में बिजलीकर का भाग	185
7.13	राज्य सरकारों की कर आगम में बिजलीकर का भाग	188
9.1	कुछ देशों द्वारा प्रतिस्थापित मूल्य वृद्धि कर	256

अध्याय प्रथम

भारत में बिजुली का ऐतिहासिक विकास

अध्याय-।

भारत में बिड़ी कर का ऐतिहासिक विकास

भारत में बिड़ी कर का इतिहास पारंपारिक देशों की तुलना में और भी प्राचीन है। यहाँ के प्राचीनतम ग्रन्थों में इस बात का पर्याप्त उल्लेख है। बिड़ी कर के प्रादुर्भाव का उल्लेख यहाँ पर दो पद्यों में किया गया है। पहले हम इसका अध्ययन पारंपारिक देशों के उदाहरण उद्धृत करते हुए करेंगे तत्पश्चात् भारतीय परिवेश में इसका विस्तृत अन्वेषण करेंगे।

एथेन्स और मिस्र में "पोलेमिक्स" द्वारा बिड़ी कर वसूल किया जाता था। रोम में भी इस प्रकार की व्यवस्था थी। टैस्टिट के कथनानुसार रोम में कुछ वस्तुओं पर एक प्रतिशत बिड़ी कर लगाया जाता था। रोम में अगस्तु ने इसे ऋष्य युग में सम्मिलित किया था। ऋष्य कालीन योरोप में भी आवश्यक वस्तुओं पर बिड़ी कर लगाये जाने का उल्लेख पाया जाता है। फ्रांस में वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर वर्ष 1292 में कर लगाया गया लेकिन छोटे-छोटे विक्रय वस्तुओं को इस कर की परिधि से पूर्णतया मुक्त रखा गया। स्पेन में वर्ष 1342 से वर्ष 1845 तक बिड़ी कर "अलकावाला" नाम से वसूल किया जाता था। इसी प्रकार का कर मैक्सिको में वर्ष 1893 में 6 प्रतिशत की दर से बिड़ी कर लगाया गया। प्रथम विश्वयुद्ध की अवधि में विश्व के अधिकांश देशों ने अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने एवं राज्य के तत्तत आय के स्त्रोत को बृद्धि की दिशा में काफी प्रयत्न किया। बिड़ी कर को इन देशों ने अप्रत्यक्ष कर के रूप में राजस्व प्राप्त का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार किया।

फिलीपीन्स में बिड़ी कर को 1915 में अपनाया गया। जर्मनी में बिड़ीकर 'डाइकमस्टबस्टर' को वर्ष 1916 में प्रारम्भ किया गया था और वर्ष 1919 में इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया गया। फ्रांस, इटली, चेकोस्लोवाकिया में बिड़ी कर वर्ष 1919 में लागू किया गया जिसको "विम्पटतेतरनी वीष्टड अपेजर" के नाम से जाना जाता था। कनाडा में यह कर वर्ष 1920 में और बेल्जियम, यूगोस्लाविया, रूमानिया, हंगरी तथा स्लो आदि देशों में वर्ष 1921 में अपनाया गया। स्लो में इस

कर को "टर्न ओवर टैक्स" के नाम से जाना जाता था । वर्तमान समय में इस की कुल आय का लगभग 80 प्रतिशत भाग इसी कर के द्वारा प्राप्त होता है । तन् 1922 में लक्जवर्ग तथा ब्यूडा में तन् 1923 में पोलैण्ड तथा आस्ट्रिया में तन् 1924 में ब्राजील में तन् 1925 में इक्वेडोर में तन् 1928 में उरुग्वे में और तन् 1930 में नावे, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड तथा तन् 1931 में अर्जेन्टाइना में बिजुी कर को विभिन्न नामों से प्रारम्भ किया गया ।

संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य सरकारों तथा नीदरलैण्ड ने तन् 1933 में मन्दी काल में इसे अपनाया था जो कि उनकी आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। तन् 1937 तक बिजुी कर को योरोप के 12 देशों में दक्षिणी अमेरिका के 6 गणराज्यों में ब्रिटिश कॉमन वेल्थ के तीन उपनिवेशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के 29 राज्यों में अपनाया जा चुका था । यद्यपि प्रारम्भ में ब्रिटेन में बिजुी कर के पक्ष में वातावरण नहीं था लेकिन बाद में तन् 1940 में वहाँ पर भी यह कर अपना लिया गया था । इसके पश्चात् तन् 1941 में स्वीट्जरलैण्ड और फिनलैण्ड में तथा तन् 1943 में चीनी में यह कर अपनाया गया । द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति तक लगभग 30 देशों ने सामान्य बिजुी कर को अपना लिया था । पाकिस्तान ने भी स्वतंत्र होने के बाद 1948 में बिजुी^{कर} को "बहु बिन्दु कर प्रणाली" के रूप में अपनाया । इन्डोनेशिया ने तन् 1950 में बिजुी कर को अपनाया ।

बिजुी कर का इतिहास भारत में भी काफी प्राचीन है । यहाँ बिजुी कर के इतिहास के विकास के बारे में बताना काफी कठिन है । प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में भी इस कर का उल्लेख मिलता है । उदाहरणार्थ मनुस्मृति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारत में माल के लागत पर लगभग 5 प्रतिशत कर लगाया जाता था जो कि उस समय राज्य की आय का मुख्य साधन था । कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वस्तुओं की बिजुी पर व्यापारिक कर लगाने का उल्लेख किया है । शुक्र-नीति में विक्रय कर की चर्चा करते हुए उल्लेख किया गया है कि वस्तुओं पर एक ही बार कर लगाना चाहिए जब विक्रेता वस्तु की लागत के बराबर या लागत से कम धनराशि प्राप्त करता है तो वह कर देने के लिये उत्तरदायी नहीं है और फिर भी

यदि वह क्रेता से कर प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में वह कर देने के लिये उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार राजा को क्रेता और विक्रेता से 32वाँ भाग प्राप्त करना चाहिए। अतः यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में भी अप्रत्यक्ष करारोपण का सिद्धांत प्रमुख था। इसके अन्तर्गत यदि व्यक्ति व्यापार से अपना जीवन निर्वाह करता था उसे कुछ न कुछ राजकोष में अंशदान करना चाहिए। मेगस्थनीज ने भी एक स्थान पर लिखा है कि वस्तुओं के बिक्री मूल्य का 1/10 भाग बिक्री कर के रूप में वसूल किया जाता था और भुगतान न करने के दोषी को मृत्यु दण्ड दिया जाता था।

मुगल काल में भी सीमा शुल्क तथा बिक्री कर महत्वपूर्ण करों के रूप में प्रचलित थे। औरंगजेब के समय में 55 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं पर बिक्री कर वसूल किया जाता था। मुगल शासन में नमक तथा नील की बिक्री पर कर के द्वारा राज्य को अच्छी आय प्राप्त होती थी परन्तु जिन खानों पर साम्राज्य का प्रत्यक्ष अधिकार था उनकी बिक्री पर आय का 1/5 भाग कर के रूप में स्वतः उनसे वसूल लिया जाता था।

स्वतन्त्रता के पूर्व ब्रिटिश काल में करारोपण जांच समिति 1924 ने सर्वप्रथम चुंजी तथा सीमा शुल्क के स्थान पर एक स्थायी फुटकर बिक्री कर लगाने की सिफारिश की थी। परन्तु भारत में यह कर अधिनियम 1935 में लागू हुआ।

भारत सरकार अधिनियम 1935

भारत के वर्तमान रूप में बिक्री कर का प्रारम्भ प्रान्तीय स्वशासन व्यवस्था से प्रारम्भ होता है, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 की सातवीं अनुसूची के मद संख्या 48 के अन्तर्गत सर्वप्रथम प्रान्तीय स्वायत्तता के साथ-साथ सामान्य बिक्री कर तम्बाकू, मोटर, स्प्रिट, मोटरवाहन आदि पर बिक्री कर की व्यवस्था कर उसे प्रान्तीय सरकारों को तौल देने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक प्रान्तीय सरकार अपने प्रान्त में होने वाले माल के विक्रय पर कर लगा सकती थी। धीरे-धीरे सभी प्रान्तीय सरकारों ने अपने-अपने प्रान्तों में होने वाले विक्रयों पर कर लगाना प्रारम्भ कर दिया।

इस व्यवस्था का लाभ उठाते हुए सर्वप्रथम 1938 में मध्य प्रान्त, मध्य प्रदेश एवं बरार में मोटर ईंधन तथा उससे सम्बन्धित चिकने पदार्थों जैसे मोटर स्पिड, पेट्रोल आदि पर 5 प्रतिशत बिड़्डी कर लगाया गया। विस्तृत रूप में बिड़्डी का प्रारम्भ 1939 में मद्रास में किया गया। इसके पश्चात् 1941 में बंगाल सरकार तथा पंजाब सरकार ने एक बिन्दु सामान्य बिड़्डी कर के रूप में बिड़्डी कर लगाया। उत्तर प्रदेश में बिड़्डी कर को तन् 1942 में कुछ वस्तुओं पर लगाया गया था लेकिन तन् 1948 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य बिड़्डी कर को अपनाया जो बहु बिन्दु आधार पर लगाया गया। तन् 1944 में बिहार में एकल बिन्दु बिड़्डी कर लगाया गया। तन् 1946 से 1948 के मध्य में बम्बई, असम, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में भी बिड़्डी कर लागू किया गया। तन् 1948 तक अधिकांश राज्य सरकारें बिड़्डी कर लगा चुकी थी इनमें से कुछ ने इसे बहु बिन्दु कर प्रणाली तथा कुछ ने एकल बिन्दु कर प्रणाली के रूप में अपनाया। अन्तराज्यीय व्यापार में क्रय विक्रय पर कर लगाने की दृष्टि से तन् 1956 में केन्द्रीय बिड़्डी कर अधिनियम पारित किया गया।

विभिन्न राज्यों में बिड़्डी कर के ऐतिहासिक स्थिति को इस प्रकार व्यक्त किया गया है:-

1. आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्र प्रदेश में बिड़्डी कर तन् 1939 में लगाया गया था जबकि आन्ध्र प्रदेश-मद्रास राज्य का एक भाग था। जब आन्ध्र प्रदेश पृथक राज्य बना तो आन्ध्र प्रदेश में अलग से "आन्ध्र प्रदेश सामान्य बिड़्डी-कर अधिनियम, 1957" पारित किया गया। यद्यपि कुछ वस्तुओं की प्रथम बिड़्डी पर एक बिन्दु बिड़्डी कर भी लगाया जाता है। इसी प्रकार वस्तुओं की बहुत सीमित संख्या पर एक बिन्दु क्रय-कर भी लगाया जाता है। तन् 1983-84 में आन्ध्र प्रदेश सरकार को बिड़्डीकर से 503.38 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है।

2. असम

असम राज्य में तन् 1947-48 के बजट में बिजुी कर लगाया गया । "असम, बिजुी कर अधिनियम, 1947" के नाम से जाना जाता है । असम में एक बिन्दु बिजुी कर को अपनाया गया जो बिजुी की अन्तिम स्थिति पर लगाया गया । तन् 1956 में "आसाम वित्त । बिजुीकर । अधिनियम, 1956 बनाया गया । इस प्रकार वर्तमान में असम में दो अधिनियमों के अन्तर्गत बिजुी-कर लगता है । प्रथम अधिनियम के अधीन समस्त वस्तुओं पर, उन वस्तुओं को छोड़कर जिनकी घोषणा राज्य सरकार ने द्वितीय अधिनियम में की है, बिजुी कर लगाया जाता है । वित्त अधिनियम के अन्तर्गत बिजुी कर बहु बिन्दु पद्धति से लगाया जाता है । असम का बिजुी कर अधिनियम पश्चिमी बंगाल के बिजुी कर के समान है । तन् 1983-84 में असम सरकार को बिजुी कर से 93.89 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति हुई ।

3. बिहार

बिहार राज्य में की जाने वाली बिजुी पर कर लगाने के लिए "बिहार बिजुी कर अधिनियम, 1944" बनाया गया । इस अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं की प्रथम बिजुी पर एक बिन्दु बिजुी कर लगाया जाता था । बिहार बिजुी कर अधिनियम बंगाल के बिजुी कर अधिनियम पर आधारित है । बिहार राज्य में कुछ वस्तुओं को बिजुी कर से मुक्त रखा गया तथा विलासिता की वस्तुओं और आवश्यकता की वस्तुओं की दर की दरें अलग-अलग रखीं गयीं । समय-समय पर आवश्यकतानुसार बिहार बिजुी कर अधिनियम में परिवर्तन होते रहे हैं । तन् 1983-84 में बिहार सरकार की बिजुी कर से 298.41 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

4. दिल्ली

बंगाल के वित्त । बिजुीकर । अधिनियम, 1941 को ही दिल्ली ने तन् 1951 में अपना लिया था, जो कि तन् 1975 तक लागू रहा । 21 अक्टूबर तन् 1975 से "दिल्ली बिजुी कर अधिनियम, 1975" प्रचलन में आ गया जो कि पूरे केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली पर लागू होता है । यह अधिनियम दिल्ली में एक स्तर बिजुी कर की व्यवस्था करता है जो कि बिजुी के प्रथम या अन्तिम स्तर पर लगाया जा सकता है ।

इस अधिनियम में कुल 10 अध्याय तथा 75 धाराएँ हैं। इस अधिनियम के कुशल संघालन के लिये आवश्यक नियम "दिल्ली बिज्जी कर नियम, 1975" के अधीन बनाये गये जो कि 21 अक्टूबर तन् 1975 से ही प्रभाव में आये। तन् 1983-84 में दिल्ली प्रशासन की बिज्जी कर से 230.85 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है।

5. हरियाणा²

तन् 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके। नवम्बर, 1966 से हरियाणा राज्य अलग बनाया गया। हरियाणा राज्य ने पंजाब सामान्य बिज्जी कर अधिनियम, 1948 131.10.1966 तक संशोधित। को ही अपनाया। बाद में हरियाणा ने "हरियाणा सामान्य बिज्जी कर अधिनियम, 1973 बनाया तथा 5 मई 1973 से इसे पूरे हरियाणा राज्य में लागू किया गया। इस अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिये इसमें काफी नयी व्यवस्थाएँ की गयीं। इस अधिनियम में एक स्तर आधार पर सामान्य बिज्जी कर की व्यवस्था है। इस अधिनियम में कुल 68 धाराएँ हैं तथा चार अनुसूचियाँ संलग्न हैं। अधिनियम के कुशल संघालन के लिये राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के तहत "हरियाणा सामान्य बिज्जी कर नियम, 1975" बनाये गये हैं। इसमें कुल 72 नियम तथा 51 फार्म हैं। इन नियमों का प्रकाशन 25 नवम्बर, 1975 को किया गया। अधिनियम में माल को कर मुक्त माल, विलासिता पूर्ण माल तथा साधारण माल की श्रेणी में बाँटा गया है। तन् 1983-84 में हरियाणा सरकार को बिज्जी कर से 167.46 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है।

6. कर्नाटक मैसूर

मैसूर में बिज्जी कर को तन् 1948 में लगाया गया जो कि बहू बिन्दु बिज्जी कर पर आधारित है। तन् 1952 में मैसूर बिज्जी कर अधिनियम में संशोधन किया गया जिसके आधार पर कर मुक्त वस्तुओं की सूची में कुछ परिवर्तन किये गये, साथ ही

मैसूर में बिछी कर बहु बिन्दु पद्धति एवं एक बिन्दु पद्धति दोनों से लगाया जाने लगा । लगभग 15 वस्तुओं पर प्रथम बिन्दु पर क्रय-कर लगाया गया । वर्तमान समय में मैसूर कर्नाटक में बहु बिन्दु बिछी कर, कुछ वस्तुओं पर एक बिन्दु बिछी कर तथा कुछ घुनी हुई वस्तुओं पर एक बिन्दु क्रय कर लगाया जाता है । तन् 1983-84 में कर्नाटक सरकार को बिछी कर से 399.30 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

7. केरल

केरल राज्य में वस्तुओं की बिछी पर सबसे पहले तन् 1950 में बिछी कर लगाया गया और केरल बिछी कर अधिनियम, 1950 बनाया गया जिसके अन्तर्गत सामान्य बिछी कर लगाया गया, जो कि बहु बिन्दु बिछी कर पर आधारित था । वर्तमान समय में कुछ विशेष वस्तुओं पर एक बिन्दु बिछी कर भी लगाया जाता है । तन् 1983-84 में केरल सरकार को बिछी कर से 306.61 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

8. मध्य प्रदेश³

तन् 1938 में मध्य प्रदेश राज्य में पेट्रोल कर के नाम से सबसे पहले बिछी कर लगाया गया था । पेट्रोल कर के अधीन मोटर ईंधन तथा उससे सम्बन्धित पिकनाई के पदार्थों पर बिछी कर लगाया गया था । वास्तविक रूप में मध्य प्रदेश राज्य में वस्तुओं की बिछी पर तन् 1947 में बिछी कर लगाया गया । यह बिछी कर एक बिन्दु बिछी कर के आधार पर था । मध्य प्रदेश सरकार ने तन् 1952 में बिछी कर के सम्बन्ध में बिछी कर जाय तमिति भी नियुक्त की थी । राज्यों का पुनर्गठन होने से तन् 1958 में मध्य प्रदेश राज्य में माल के विक्रय या क्रय पर सामान्य कर लगाने से सम्बन्धित विधियों का स्वीकरण एवं संशोधन करने हेतु मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय-कर अधिनियम, 1958 11959 का क्रमांक 21 पारित किया गया, जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, तन् 1959 की प्राप्त हुई । यह अनुमति

3. डब्ल्यूओसी० टींगरा : मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958.

प्रथम बार दिनांक 13 मार्च, 1959 के "मध्य प्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित हुई। वर्तमान में मध्य प्रदेश में एक बिन्दु बिड़ी कर लगाया जाता है जो कि बिड़ी की प्रथम स्थिति पर लगाया जाता है। तन् 1983-84 में मध्य प्रदेश सरकार को बिड़ी कर से 352.78 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्त हुई है।

9. महाराष्ट्र एवं गुजरात। बम्बई।

बम्बई में सामान्य बिड़ी कर तन् 1946 में लागू किया गया जिसे एक बिन्दु के आधार पर अपनाया गया और जिसके अन्तर्गत केवल उपभोक्ताओं और अनरजिस्टर्ड विक्रेताओं की बिड़ी पर ही कर लगाया जाता था। बम्बई राज्य में बिड़ी-कर बंगाल और बिहार के बिड़ी कर के ही समान था। बम्बई राज्य में बिड़ी कर का इतिहास 1939 से शुरू होता है जबकि तन् 1939 में मोटर स्पिड की बिड़ी पर बिड़ी कर लगाया गया। इसके बाद तन् 1943 में एक अधिकारी को अन्य राज्यों की बिड़ी-कर प्रणाली का अध्ययन करने के लिए भेजा गया, जिसके आधार पर 1 अक्टूबर तन् 1946 से बम्बई सरकार ने एक बिन्दु बिड़ी कर लगाया। यह एक बिन्दु बिड़ी कर वस्तु की अन्तिम बिड़ी पर लगाया जाता था। इस प्रकार तन् 1946 में "बम्बई बिड़ी कर अधिनियम, 1946" पारित किया गया। तन् 1952 में बम्बई सरकार ने एक बिन्दु बिड़ी कर के स्थान पर बहु-बिन्दु बिड़ी कर लगाने का निश्चय किया जो कि 1 नवम्बर तन् 1952 से लागू किया गया। 1 अप्रैल तन् 1954 से दो बिन्दु बिड़ी कर लगाया गया। बम्बई राज्य में दो भाग महाराष्ट्र एवं गुजरात होने पर दोनों में ही बम्बई बिड़ी कर अधिनियम लागू है। तन् 1983-84 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य सरकारों की बिड़ी कर से क्रमाः 1196.71 एवं 554.87 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्त हुई है।

10. पंजाब

पंजाब राज्य में की जाने वाली बिड़ी पर कर लगाने के लिए "पंजाब सामान्य

बिछोड़ कर अधिनियम 1941" बनाया गया था, जो कि मद्रास, अब तमिलनाडु। सामान्य बिछोड़ कर अधिनियम पर आधारित था। तन् 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय सिन्ध, खैरोपिस्तान तथा पंजाब का कुछ हिस्सा कटकर पाकिस्तान में जा गया और 15 अगस्त, 1947 को पूर्वी पंजाब राज्य का निर्माण हुआ। इसलिए 1941 के बिछोड़ कर अधिनियम को रद्द कर दिया गया तथा "पंजाब सामान्य बिछोड़ कर अधिनियम, 1948" बनाया गया जो 1 मई, 1949 से पूरे पंजाब प्रान्त पर लागू हुआ। इस अधिनियम को पंजाब के गवर्नर ने 15 नवम्बर, 1948 को स्वीकृत किया था। इस अधिनियम में बहु-बिन्दु कर को प्राथमिकता नहीं दी गई और बहु-बिन्दु बिछोड़ कर के स्थान पर एक बिन्दु बिछोड़ कर को अपनाया गया। तन् 1948 का अधिनियम पश्चिमी बंगाल के समान था। बाद में समय-समय पर इसमें परिवर्तन किये गये। तन् 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया और हरियाणा नया राज्य बना। हरियाणा ने 1973 तक इसी को अपनाया। 6 जुलाई, 1968 को केन्द्रीय सरकार ने एक विधायित्व निकाली जिसमें पंजाब सामान्य बिछोड़ कर अधिनियम, 1948 को उस तारीख तक पूर्ण तंशोधित कर दिया और केन्द्रशासित प्रदेश जडिगढ़ पर भी इसे लागू कर दिया। तन् 1983-84 में पंजाब राज्य सरकार को बिछोड़ कर से 255.33 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है।

11. राजस्थान⁵

राजस्थान सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1955 से "राजस्थान बिछोड़ कर अधिनियम 1954" को लागू किया गया था। इस समय यह अधिनियम सम्पूर्ण राजस्थान में लागू है। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य में हुए मात के क्रय-विक्रय पर कर लगाना था। राज्य सरकार ने इस अधिनियम को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने के लिए कुछ नियम बनाये हैं जिन्हें "राजस्थान बिछोड़-कर नियम, 1955" कहा जाता है। राजस्थान बिछोड़-कर अधिनियम के अन्तर्गत मुख्यतया मात के क्रय-विक्रय पर एकल बिन्दु कर लगाने व्यवस्था है जो कि मध्य प्रदेश के बिछोड़ कर अधिनियम पर आधारित है। यद्यपि यह

कर दो प्रकार से लगाया जाता है । अधिकांश मालों पर प्रथम बिन्दु पर तथा कुछ मालों पर अन्तिम बिन्दु पर कर लगाया गया है । अपवाद स्वल्प कुछ मालों पर बहुत बिन्दु कर लगाने की भी व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त राजस्थान में निर्माण-कत्ताओं द्वारा निर्मित माल पर बिज्जी कर लगाने के सम्बन्ध में कुछ अलग व्यवस्थायें हैं । तन् 1983-84 में राजस्थान सरकार को बिज्जी कर से 249.98 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

12. तमिलनाडु मद्रास⁶

मद्रास भारत का पहला राज्य था जिसने 1939 में बिज्जी कर को अपनाया । मद्रास में सामान्य बिज्जी कर लागू किया गया जो बहु-बिन्दु बिज्जी कर के आधार पर लगाया जाता था । इसका नाम "मद्रास सामान्य बिज्जी कर अधिनियम, 1939" था, यह अधिनियम कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री श्री सी० राजगोपालाचारी के समय बनाया गया । तन् 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो अधिकांश राज्यों ने अपने बिज्जी कर कानूनों में संशोधन किया और नये अधिभूत क्षेत्रों तक उनका विस्तार कर दिया । जब तमिलनाडु एक राज्य बना तो तमिलनाडु में अलग से "तमिलनाडु सामान्य बिज्जी कर अधिनियम 1959" पारित किया गया । इस पर राज्यपाल की स्वीकृति 11 मार्च 1959 को प्राप्त हुई जिसे पछी बार 18 मार्च, 1959 को राज्य सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया । यह 1 अप्रैल, 1959 से सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य में लागू है । इस अधिनियम के द्वारा तमिलनाडु राज्य में माल के क्रय-विक्रय पर सामान्य कर लगाया जाता है । परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर इस अधिनियम में परिवर्तन होते रहे हैं । तन् 1983-84 में तमिलनाडु सरकार को बिज्जी कर से 701.52 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

13. उड़ीसा

उड़ीसा राज्य में वस्तुओं की बिज्जी पर बिज्जी कर लगाने के लिए तन् 4947-48

के कजट में सामान्य बिज्जी कर लगाने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार उड़ीसा में "उड़ीसा सामान्य बिज्जी कर अधिनियम, 1947" बना। यह अधिनियम 1950-51 में संशोधित किया गया। उड़ीसा में एक बिन्दु बिज्जी कर लगाये जाने की व्यवस्था की गई जो कि विक्रय के अन्तिम बिन्दु पर लगाया जाता है। यद्यपि उड़ीसा सरकार को यह अधिकार है कि वह बिज्जी कर को विक्रय के किसी भी बिन्दु पर लगा सकती है। तन् 1983-84 में उड़ीसा सरकार को बिज्जी कर से 114 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है।

14. उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में बिज्जी कर का प्रारम्भ तन् 1948 में हुआ था। इस हेतु 27 फरवरी तन् 1948 को एक विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और जिसके आधार पर 1 अप्रैल 1948 से "उत्तर प्रदेश बिज्जीकर अधिनियम, 1948" लागू हुआ। प्रारम्भ में प्रान्त के कुछ भाग इस कर की परिधि से मुक्त थे, लेकिन बाद में अधिनियम की धारा 26 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 1 जनवरी, 1950 से यह अधिनियम राज्य में सम्मिलित बनारस, रामपुर तथा टेटरी मद्रवाल रियासतों पर भी लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा उत्तर प्रदेश में बहु स्तर आधार पर बिज्जी कर लगाया गया। अधिनियम में कुल 36 धारार्यें एवं दो अनुसूचियाँ हैं। इस अधिनियम के कुशल क्रियान्वयन के लिए "उत्तर प्रदेश बिज्जी कर अधिनियम, 1948" भी बनाये गये हैं। इनमें 88 नियम तथा 41 प्रात्य शामिल हैं। तन् 1983-84 में उत्तर प्रदेश सरकार को बिज्जीकर से 551.14 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है।

15. पश्चिमी बंगाल

बंगाल में बंगाल वित्त बिज्जी कर अधिनियम, 1941 के नाम से जाना जाता है, जो कि 1 जुलाई, 1941 से लागू किया गया। इसके अन्तर्गत बंगाल राज्य में माल की बिज्जी पर सामान्य कर लगाया जाता था। देश का विभाजन हो जाने के बाद, इस अधिनियम का नाम बदल दिया गया तथा जो "पश्चिमी बंगाल बिज्जी कर अधिनियम" में बंगाल के अन्तर्गत एक बिन्दु बिज्जी कर के आधार पर कर लगाया जाता है।

तन् 1983-84 में पश्चिमी बंगाल सरकार को बिक्री कर से 450.06 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

उपर्युक्त राज्यों के अतिरिक्त यह कर नागालैण्ड और मेघालय के क्षेत्रों में तन् 1947 में, हिमाचल प्रदेश में तन् 1949 में, मणिपुर में तन् 1952 में, जम्मू और कश्मीर में तन् 1958 में, त्रिपुरा में तन् 1962 में और तिविक्रम में तन् 1974 में लागू किया गया । तन् 1983-84 में हिमाचल प्रदेश को 22.25 करोड़ रुपये, जम्मू व कश्मीर प्रदेश को 26.50 करोड़ रुपये तथा मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, तिविक्रम एवं त्रिपुरा को बिक्री-कर से क्रमाः 1.69, 4.89, 5.27, 0.92 एवं 4.10 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है ।

-----:0:-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
अध्याय द्वितीय

विहीकर : पृष्ठाकोन
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

बिक्री कर : पुष्ठावलोकन

सरकार को अपने उत्तरदायित्वों का पूर्णतया पालन करने हेतु विविध कार्यों एवं परियोजनाओं पर सामाजिक लाभ के सिद्धान्तों के अनुस्यू व्यय करना होता है। इसके लिये सरकार को धन की आवश्यकता होती है। यद्यपि राज्यों को आगम के अनेक साधन हैं, लेकिन उनमें कर का प्रमुख एवं विशिष्ट स्थान है। करों को भी कर आधार तथा कर भार इत्यादि की दृष्टि से विविध स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है उदाहरणार्थ - प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सम्पत्ति, आय व व्यय के आधार पर कर एकल कर, बहुकर इत्यादि। कर नामावली की दृष्टि से इन्हें आयकर, सम्पदा कर, आयात-निर्यात कर, उत्पादक शुल्क, बिक्री कर, भू-मगान इत्यादि रूप में रखा जा सकता है। भारत में स्वतन्त्रता से पूर्व राज्य सरकारों को राजस्व व्यवस्था में भू-राजस्व का महत्वपूर्ण स्थान था। राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व अनेक देशी रियासतों ने अपने क्षेत्र में आने वाले माल पर सीमा शुल्क भी लगाया था, लेकिन भारतीय संविधान लागू होने पर अन्तराज्यीय सीमा शुल्क हटाना अनिवार्य हो गया। अतः राज्य सरकारों के आगम की दृष्टि से वैकल्पिक साधन की आवश्यकता अनुभव की गई और इस सन्दर्भ में विभिन्न राज्यों में वस्तुओं की बिक्री पर बिक्री कर लागू किया गया।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में ही नहीं, वरन् सभी विकासशील देशों की कर व्यवस्था में बिक्री कर का विशिष्ट महत्व स्वीकार किया जाता है। इस सन्दर्भ में जान. एफ. ड्यू का यह कथन महत्वपूर्ण है कि "प्रायः सभी विकासशील ^{अर्थो-}व्यवस्थाओं में सामान्य बिक्री कर का सम्भावित महत्व व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि इन देशों में आयकर से सीमित आय होती है और अधिक विकास होता है सीमा शुल्क भी उत्तरोत्तर अतन्तोषजनक होते जाते हैं।"¹

1. John. F. Due : The Retail Sales Tax in Honduras, Readings on Taxation in Developing Countries, Ed. Bird and Oldman, Johns Hopkins Press 1967, Page 326.

13A। बिक्री कर का आशय

बिक्री कर से आशय उस कर से है जो सम्बन्धित अधिनियम में वर्णित अपवादों को छोड़कर दृष्टिगत सम्पत्ति अथवा वस्तुओं को व्यावसायिक बिक्रियों पर लगाया जाता है। यह विक्रय फुटकर या थोक व्यापार अथवा निर्माण की स्थिति में हो सकता है। यह उल्लेखनीय है कि सामान्यतः बिक्री कर वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है किन्तु कभी-कभी यह सेवाओं की बिक्री पर भी लगा दिया जाता है। बिक्री कर को "हस्तान्तरण कर" तथा "आवर्तन कर" भी कहा जाता है। बिक्री कर की कुछ प्रमुख परिभाषायें इस प्रकार हैं :

"बिक्री कर एक ऐसा कर है जो सभी अथवा अधिकांश वस्तुओं की बिक्री पर अथवा बिक्री से सम्बन्धित तत्त्व जैसे कि उनसे होने वाली प्राप्तियों पर लगाया जाता है।"²

- जॉन. एफ. ड्यू

उपरोक्त परिभाषा के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बिक्री कर सभी वस्तुओं की बिक्री या अधिकांश वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है। कुछ वस्तुओं को बिक्री कर से मुक्त भी किया जा सकता है। साथ ही बिक्री कर केवल उन्हीं वस्तुओं की बिक्री पर लगता है जिनकी बिक्री से प्राप्त हो, यदि प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर बिक्री कर नहीं लगाया जायेगा।

"बिक्री कर वह कर है, जिसके क्षेत्र के अन्तर्गत कर सम्बन्धी वैधानिक अपवादों को छोड़कर फुटकर, थोक या उत्पादन स्तर पर दूर्य व्यक्तिगत सम्पत्ति के समस्त व्यापारिक विक्रय को सम्मिलित किया जाता है।"³

- हैग और शोप

2. "A Sales Tax is a levy imposed upon the sales, or element incidental to the Sales, such as receipts from them, of all or a wide range of commodities". John F. Due: Sales Taxation, Page 3.

3. "Sales Tax is any tax which includes within its scope all business sales of tangible personal property at either the retailing, whole selling or manufacturing stage, with exceptions noted in the taxing Law. "Haig and Shoup : The Sales Tax in American States.

प्रो. हैग ने यहाँ बिड्डी कर के क्षेत्र को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार बिड्डी कर के क्षेत्र के अन्तर्गत उन समस्त व्यापारिक बिड्डियों को सम्मिलित किया गया है जो व्यापारिक बिड्डय, फुटकर व्यापार के बिड्डय, धोक व्यापार के बिड्डय या उत्पादन स्तर के बिड्डय से सम्बन्धित हों लेकिन ऐसे बिड्डय कानून में दिये गये नियमों को उत्पन्न न करते हों।

इस प्रकार तर्क में यह कहा जा सकता है कि "बिड्डी कर से आशय उस कर से है जो वस्तुओं की बिड्डी के आधार पर लगाया जाता है। बिड्डी कर का मुख्य आधार बिड्डी है अर्थात् जब कोई वस्तु बिड्डय-प्रक्रिया में आये, उस समय कर लगेगा तथा कर का आधार बिड्डय की राशि या मात्रा होगी। यह महत्वपूर्ण है कि परम्परागत अर्थ में तो वस्तुओं की बिड्डी पर लगने वाले कर को ही बिड्डय कर कहा गया है जबकि सेवाओं के प्रदान करने पर बिड्डय कर लगाया जा सकता है। बिड्डी कर वस्तुओं या सेवाओं के बिड्डय सम्बन्धी उन सभी व्यवहारों पर लगाया जा सकता है जिनके मध्य वस्तुएं गुजरती हैं। यह भी हो सकता है कि यह कर सभी व्यवहारों पर न लगाया जाकर बिड्डी के केवल एक अथवा थोड़े ही स्तरों पर लगाया जाये। सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि बिड्डी कर उपभोक्ताओं की ओर अन्तरित कर दिया जायेगा और विक्रेता फर्ष तो केवल कर की एकत्रित करने वाली एजेंट मात्र है।

बिड्डी कर का स्वभाव एवं प्रकृति

बिड्डी कर के स्वभाव एवं प्रकृति के सन्दर्भ में अनेक पक्षों का विवेचना किया जा सकता है। सामान्यतः कर की दरों की दृष्टि से यह कर आनुपातिक कर होता है लेकिन प्रभाव की दृष्टि से यह कर प्रगतिशील या प्रतिगामी भी हो सकता है। यदि इस कर को मुख्य रूप से पिनायिता की वस्तुओं या धनी वर्ग द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है या सामान्य वस्तुओं की तुलना में इन वस्तुओं पर कर की दरें ऊँची रखी जाती है तो कर का प्रभाव प्रगतिशील होता है। इसके विपरीत यह कर सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता है तो कर की दर आनुपातिक होते हुए भी कर का प्रभाव प्रतिगामी होता है क्योंकि धनी और निर्धन

दोनों वर्गों द्वारा समान दर से कर दिया जाता है जबकि दोनों वर्गों के लिए मुद्रा की तीमान्त उपयोगिता में अन्तर होता है। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि कर से पर्याप्त जीवम प्राप्त करने की दृष्टि से सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर बिजुी कर लगाया जाता है लेकिन इनके प्रतिभासी प्रभाव को दूर करने की दृष्टि से सरकारें अनेक छूट एवं सुविधार्थ प्रदान करती हैं।

कर भार को वहन करने के सन्दर्भ में बिजुी कर एक अप्रत्यक्ष कर है। बिजुी कर का आरोपण सरकार के द्वारा व्यापारियों पर किया जाता है किन्तु व्यापारी माल का विक्रय करते समय वस्तुओं के क्रेताओं या उपभोक्ताओं पर बिजुी कर का विवर्तन कर सकता है। प्रायः सभी बिजुी-कर अधिनियमों में यह अधिकार दिया गया है कि व्यापारी माल का विक्रय करते समय अपने ग्राहकों से कर को वसूल कर सकता है। यद्यपि ऐसा व्यवहार में हो सकता है कि विक्रेता अपनी किसी विक्रय नीति, बाजार की प्रतियोगी स्थिति अथवा वस्तु की माँग व पूर्ति की लोच सम्बन्धी विशेषताओं के कारण बिजुी कर की सम्पूर्ण अथवा आंशिक राशि को विवर्तित न कर सकें।

कर लगाने के आधार के दृष्टि से बिजुी कर एक मूलानुसार कर है क्योंकि इसका आरोपण बिजुी के भार के आधार पर न होकर बिजुी की राशि के आधार पर होता है।

1. बिजुी कर के विविध स्वरूप

बिजुी कर का मूल आधार विक्रय राशि तथा विक्रय प्रक्रिया है लेकिन कर लगाने की प्रकृति के आधार पर विक्रय कर अनेक रूपों में वर्गीकृत किये जा सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख वर्गीकरण निम्न प्रकार हैं :

सामान्य बिजुी कर एवं वयनात्मक बिजुी कर

सामान्य बिजुी कर अधिकतम वस्तुओं पर लगाया जाता है बिन वस्तुओं पर बिजुी कर नहीं लगाया जाता उनका उल्लेख अधिनियम में स्पष्ट रूप से कर दिया जाता

है। इस प्रकार तंतद या विधान सभा द्वारा घोषित कर मुक्त वस्तुओं को छोड़ दिया जाता है अर्थात् सामान्य बिक्री कर उन सभी सामान्य वस्तुओं पर लगाया जाता है जो कि किसी व्यापारी अथवा विक्रेता के हाथों से गुजरती है अथवा जिसे उसकी कुल बिक्री कहा जाता है।

वास्तविक अर्थ में भारत में कहीं भी सामान्य बिक्री कर नहीं है क्योंकि अधिकांश परिस्थितियों में सेवारत बिक्री कर के क्षेत्र से बाहर रखी जाती है और लगभग सभी राज्यों में कुछ वस्तुएं कर मुक्त रखी जाती हैं। अतः भारत में जिसे सामान्य बिक्री कर कहा जाता है, वह जम्मू व कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू है। सामान्य बिक्री कर सर्वप्रथम मद्रास तमिलनाडु राज्य में सन् 1939 में लगाया गया था। यह कर अब सभी राज्यों में, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अतिरिक्त, जहाँ पर चयनात्मक बिक्री कर लगाया जाता है, प्रभावशील है। जिन वस्तुओं पर अन्य कर अधिनियमों के अन्तर्गत कर लगाया जाता है उन्हें बिक्री-कर से मुक्त रखा जाता है। इस सन्दर्भ में अनेक राज्यों में नशीली वस्तुओं एवं शराब की बिक्री पर बिक्री-कर नहीं लगाया जाता, क्योंकि इन पर राज्यीय उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। मोटर स्प्रिट एवं विद्युत शक्ति पर राज्यों में अलग से कर लगाया जाता है। समस्त राज्यों में स्टॉक, अंश तथा गृह-सम्पत्ति को इस कर से छूट प्रदान की गई है। यद्यपि कर वसूली की सुविधा तथा राजस्व की दृष्टि से यह कर काफी उपयोगी है, लेकिन कर भार के न्यायपूर्ण वितरण के दृष्टिकोण से यह कर उचित नहीं है। इसका प्रभाव अधोगामी होता है। साथ ही सामान्य बिक्री कर में न्यूनतम कर रहित सीमा के अन्तर्गत भी व्यापारी होते हैं सभी से कर-अधिकारियों को सम्पर्क रखना होता है और उनके जाते एवं लेखों का निरीक्षण करना पड़ता है, चूँकि ऐसे व्यापारियों की संख्या बहुत अधिक होती है अतः कर-निर्धारण एवं कर-वसूली, प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयाँ भी स्वभावतः अधिक होती हैं। सामान्य बिक्री कर सामान्यतः जनताधारण द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं पर लगाया जाता है। अतः इससे जन साधारण को काफी कठिनाई भी होती है।

चयनात्मक बिक्री कर केवल कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर ही लगाया जाता है और अन्य वस्तुओं को कर-मुक्त कर दिया जाता है। इसके अन्तर्गत व्यापारी को विभिन्न

प्रकार के मालों की बिक्री पर भिन्न-भिन्न दरों से बिक्री कर चुकाना पड़ता है क्योंकि इस पद्धति में विभिन्न प्रकार के मालों के लिए बिक्री कर की दरें अलग-अलग निर्धारित की जाती हैं। अतः व्यापारी के लिए विभिन्न मालों के सम्बन्ध में बिक्री के लेख अलग-अलग रखना आवश्यक हो जाता है। इसके अन्तर्गत अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुएँ ही कर मुक्त होती हैं और उन पर कर इस आधार पर नहीं लगाया जाता जिससे कि कर का भार गरीबों पर न पड़ सके। कर के लिये पुनी हुई वस्तुएँ अधिकांश रूप में विलासिता की वस्तुएँ तथा अधिक मूल्यवान वस्तुएँ ही होती हैं, जैसे रेडियो, कार, रेफ्रिजरेटर आदि।

समस्त राज्यों में भी, जहाँ पर सामान्य बिक्री कर लगाया जाता है वहाँ उसके अतिरिक्त चयनात्मक करों को भी लगाया जाता है जिसमें मोटर-स्प्रिट, कच्चे जूट तथा गन्ने पर लगाये जाने वाले कर प्रमुख हैं। कुछ राज्य जैसे आन्ध्र-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पंजाब तम्बाकू पर एक चयनात्मक बिक्री कर लगाते थे। इस कर से प्राप्त आय अल्प थी क्योंकि निर्मित तम्बाकू पर सामान्य बिक्री कर लगाया जाता था। जब से तम्बाकू पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगने लगा है तब से समस्त राज्यों में तम्बाकू साथ में निर्मित तम्बाकू भी पर चयनात्मक तथा सामान्य बिक्री कर समाप्त कर दिया गया है। जम्मू एवं कश्मीर में तो केवल चयनात्मक बिक्री कर लगाया जाता है। समस्त राज्यों में मोटर-स्प्रिट की फुटकर बिक्री पर एक चयनात्मक बिक्री कर लगाया जाता है। विभिन्न राज्यों में इस कर की दर तमान नहीं है। कुछ राज्य कच्चे तेल तथा डीजल तेल पर भी चयनात्मक कर लगाते हैं। अधिकतर राज्यों में इस कर की दर को अनेक बार बढ़ाया गया है। परियमी कंगाल में कच्चे तेल पर, उत्तर-प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र-प्रदेश राज्यों में चयनात्मक बिक्री कर लगाया जाता है।

एक बिन्दु और बहु-बिन्दु बिक्री कर

जब किसी वस्तु के विक्रय की किसी एक स्थिति पर ही बिक्री कर लगाया जाता है तो यह एक बिन्दु बिक्री कर कहलाता है। यह कर उत्पादक, थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी किसी एक पर लगाया जा सकता है। एक बिन्दु बिक्री कर प्रणाली के

अन्तर्गत वस्तु के उत्पादन से उपभोग तक की स्थिति में केवल किसी एक बिन्दु पर बिड़्डी कर लगाया जाता है । एक बिन्दु पर कर निम्न दो बिन्दुओं में से एक बिन्दु पर लगाया जा सकता है : प्रथम बिन्दु पर या अन्तिम बिन्दु पर ।

प्रथम बिन्दु बिड़्डी कर के अन्तर्गत बिड़्डी कर उस समय लिया जाता है जब किसी वस्तु की बिड़्डी राज्य में प्रथम बार की जाती है, यदि किसी राज्य में वस्तु का निर्माण या उत्पादन किया गया है तो उस वस्तु का निर्माण या उत्पादक जब वस्तु को बेचता है तो उससे बिड़्डी कर वसूल किया जाता है । यदि व्यापारी किसी दूसरे राज्य से वस्तु लाकर बेचता है तो बिड़्डी कर उस व्यापारी से वसूल किया जाता है जो प्रथम बार उस वस्तु को उस राज्य में बेच रहा है । अन्तिम बिन्दु बिड़्डी कर के अन्तर्गत बिड़्डी कर उस समय लिया जाता है जब पंजीकृत व्यापारी द्वारा वस्तु उपभोक्ता को या अपंजीकृत व्यापारी को बेची जाती है । जब वस्तु एक पंजीकृत व्यापारी से दूसरे पंजीकृत व्यापारी को बेची जाती है तो अन्तिम बिन्दु बिड़्डी कर के अन्तर्गत कोई कर नहीं लिया जाता, परन्तु जब पंजीकृत व्यापारी माल को राज्य में या अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान उती स्थ में जिसमें उसने खरीदा है पुनः बेचने के लिए नहीं खरीदता तो उससे भी कर लिया जायेगा । जब उत्पादन संगठित रूप से किया जाता है तब प्रथम बिन्दु तरीके द्वारा कर संग्रह करने में सुविधा रहती है किन्तु यदि वस्तुओं का उत्पादन छोटे-छोटे उत्पादकों द्वारा बिखरे हुए रूप में किया जाता है तो अन्तिम बिन्दु वाले तरीके में कर संग्रह करना सुविधाजनक होता है । जब इस कर को उत्पादन की स्थिति के समय में प्रथम बार लगाया जाता है तो छोटे-छोटे दुकानदारों के पास उन वस्तुओं के वर्तमान स्टॉक पर कर लगने नहीं पाता किन्तु जब वह दुकानदार बाद में उन वस्तुओं को बिक्री करेंगे तो उन्हें कर का भुगतान करना पड़ेगा । अतः ऐसी स्थिति में वे दुकानदार अपने वर्तमान स्टॉक में स्थित वस्तुओं के मूल्य को कर की मात्रा के बराबर देंगे । वस्तु के उद्गम स्थान पर उसका मूल्य नीचा होता है और इस कारण कर में संग्रह की गई राशि की मात्रा अल्प होती है । यद्यपि ऐसा हो सकता है और पाया भी जाता है कि उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देना पड़े क्योंकि दुकानदार इस स्थिति का लाभ उठाकर वस्तु का मूल्य ऊँचा निर्धारित करते हैं । जब यह कर अन्तिम

स्थिति पर उपभोक्ता को बेचे जाने पर लगाया जाता है तब रजिस्टर्ड क्रेताओं को, जो वस्तु को पुनः बिछी के लिए क्रय करते हैं, कर से मुक्त रखा जाता है। इसी प्रकार से वस्तु उत्पादन करने वाले उद्योगों को क्रय किये जाने वाले कच्चे माल पर कर से छूट प्रदान की जा सकती है।

बहु बिन्दु कर प्रणाली के अन्तर्गत जब भी वस्तु को बेचा जाता है तभी कर लगाया जाता है। ऐसी दशा में, अन्तिम उपभोक्ता के पास पहुँचने से पूर्व वस्तु पर अनेक बार कर लग जाता है। सामान्यतः एक बिन्दु बिछी कर की अपेक्षा बहु बिन्दु बिछी कर की दर नीची होती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में जब एक बिन्दु बिछी कर के स्थान पर बहु बिन्दु बिछी कर को अपनाया गया तो कर की दर को 6 पैसे प्रति स्यया के स्थान पर घटाकर 3 पैसे प्रति स्यया कर दिया गया। इस प्रणाली के अन्तर्गत कर-वर्षन अथवा कर की चोरी की कम गुंजाइश रहती है, क्योंकि प्रथम व्यापारी से लेकर अन्तिम व्यापारी तक को अपने लेखे जोखों में परिवर्तन कर बिछी को कम दिखाना कठिन ता जान पड़ता है। किसी भी स्थिति पर कर-वर्षन अथवा कर-चोरी का पता लग जाने के भय से राजकीय हित सुरक्षित रखा जा सकता है। यद्यपि व्यावहारिक जीवन में क्रय-विक्रय के समस्त तौरों को ज्ञात करना बहुत कठिन है। जबकि एक बिन्दु बिछी-कर प्रणाली के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी कर की चोरी करता है तो सरकार को आय का अधिक नुकसान होता है तथा ईमानदार व्यापारियों को भी अधिक हानि पहुँचती है, क्योंकि उनकी स्पर्धा शक्ति केईमान व्यापारियों की अपेक्षा कम हो जाती है। बहु बिन्दु कर प्रणाली की अपेक्षा एक बिन्दु बिछी कर प्रणाली के अन्तर्गत कर वर्षन से व्यापारियों को अधिकतम लाभ होता है क्योंकि एक बिन्दु कर प्रणाली में कर की दरें उंची होती हैं।

बहु बिन्दु बिछी कर प्रणाली के अन्तर्गत मध्यस्थों की संख्या सीमित होने की प्रवृत्ति पायी जाती है। थोक विक्रेताओं द्वारा वस्तु के आयात तथा उनके द्वारा वस्तुओं के छोटे-छोटे व्यापारियों को बिछी के लिए वस्तु के वितरण के स्थान पर इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है कि छोटे-छोटे व्यापारी स्वयं ही तीथे वस्तु को मंगा लेते हैं। इस तरीके के द्वारा उत्पादन में सक्रियकरण की प्रवृत्ति को भी जन्म मिलता है।

इस एकत्रीकरण से मध्यस्थों की समाप्ति के कारण उत्पादन लागत को कम करने तथा नीचे मूल्य निर्धारण करने में भी सहायता मिलती है ।

बहु बिन्दु बिड़ी-कर पुणाली का एक अन्य लाभ यह है कि हिसाब-किताब रखना अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक होता है । एक बिन्दु बिड़ी-कर पुणाली के अन्तर्गत व्यापारियों को उस बिड़ी के सम्बन्ध में अलग हिसाब-किताब रखना पड़ता है जिसका सम्बन्ध रजिस्टर्ड व्यापारियों अथवा उत्पादकों से है तथा जिन्हें बिड़ी कर से छूट प्रदान की जाती है । अन्तिम उपभोक्ताओं अथवा गैर रजिस्टर्ड कम्पनियों को बेची गई वस्तुओं की बिड़ी का अलग हिसाब रखना पड़ता है, क्योंकि इनसे बिड़ी कर वसूल किया जाता है । ऐसी अवस्था के कारण कर-निर्धारण करने में कठिनाइयाँ सामने आती हैं । क्योंकि रजिस्टर्ड व्यापारी तथा उत्पादकों को की गई बिड़ी की सत्यता कर-छूट प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित करनी पड़ती है ।

बहु बिन्दु कर पुणाली के अन्तर्गत वस्तु का मूल्य अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचते-पहुँचते कर की मात्रा से अधिक बढ़ जाता है तथा उपभोक्ता से जो कर की मात्रा वसूल की जाती है वह राज्य को प्रदान की गई कर मात्रा से अधिक होती है । सामान्य उपभोग की वस्तुएँ जिनकी माँग अधिकतर कम लोचदार होती है । उनके सम्बन्ध में ऐसा ही पाया जाता है । जब माँग लोचदार होती है तो व्यापारी कर का भुगतान, अधिकारिता: अपने लाभ को कम करके उदा करते हैं तथा स्वयं ही कर का भार सहन करते हैं । सामान्य तौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि जिला-तहसील की वस्तुएँ एवं मुख्यतः वस्तुएँ जिनकी माँग लोचदार होती है, वे कम लोचदार वस्तुओं की अपेक्षा अल्प-कम व्यापारियों के हाथों से गुजरती हैं । उदाहरण के लिए जब मोटर-कार अथवा रेफ्रिजरेटर किसी राज्य में आयात करने वाले व्यापारी द्वारा सीधे उपभोक्ता के पास पहुँचता है । दूसरी ओर अनाज, कपड़ा, चीनी आदि वस्तुएँ अनेक व्यापारियों के हाथों से गुजरती हैं । इस कारण बहु बिन्दु बिड़ी करों की प्रवृत्ति भी अवरोही होने की होती है ।

बिड़ी कर बनाम आयतन कर

बिड़ी कर केवल वस्तुओं की बिड़ी पर लगाया जाता है लेकिन जब वस्तुओं और

तेवाजों दोनों की बिछी पर कर लगाया जाता है तो इसे "आवर्तन कर" कहते हैं । यदि व्यापारी की सभी प्रकार के मालों की कुल वार्षिक बिछी पर एक ही दर से बिछी कर लिया जाये तो इसे "कुल विक्रय राशि पर कर" कहा जायेगा । इस पद्धति में सभी प्रकार के मालों की बिछी पर कर की दर समान होती है । अतः व्यापारी को विभिन्न मालों के सम्बन्ध में बिछी के लैडे अलग-अलग रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है । जब कोई कर केवल वस्तुओं की बिछी पर ही नहीं अपितु तेवाजों की बिछी पर भी लगाया जाता है तो उस कर को "सकल प्राप्ति कर" कहा जाता है । कभी-कभी इस कर के निर्धारण के आधार के रूप में वस्तुओं तथा तेवाजों की बिछी से मिलने वाली प्राप्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्राप्तियाँ भी इसमें शामिल कर ली जाती है जैसे मकान का किराया, अंशों पर लाभांश आदि । तब ऐसे करों को "तौदा कर" भी कहा जाता है ।

धोक बिछी कर या फुटकर बिछी कर

जब धोक व्यापारियों द्वारा वस्तुओं की धोक बिछी पर बिछी कर लगाया जाता है और धोक-व्यापारियों से ही वस्तु लीया जाता है तो उसे "धोक बिछी कर" के नाम से पुकारा जाता है । इसके विपरीत फुटकर व्यापारियों द्वारा वस्तुओं की फुटकर बिछी पर बिछी-कर लगाया जाता है और फुटकर व्यापारियों से ही वस्तु लीया जाता है तो उसे "फुटकर-बिछी कर" के नाम से सम्बोधित किया जाता है ।

जोड़े गये मूल्य पर बिछी कर

यदि किसी माल पर बिछी कर केवल उस राशि पर लगाया जाये जो विक्रेता व्यापारी ने उस माल के क्रय मूल्य में जोड़ी है तो उसे "जोड़े गये मूल्य पर बिछी कर" कहा जायेगा । इस पद्धति में किसी भी माल के क्रय-विक्रय के उत्तरात्तर व्यवहारों की शृंखला में, जिसके द्वारा वह माल उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुँचता है, प्रत्येक बिन्दु पर बिछी कर लिया जाता है किन्तु यह बिछी कर माल के विक्रेता से उस माल के सम्पूर्ण विक्रय पर नहीं लिया जाता, वरन् इस पद्धति में बिछी कर प्रत्येक विक्रेता से केवल उसी राशि पर लिया जाता है जो उसके द्वारा उक्त माल के क्रय मूल्य में जोड़ी गई है ।

विक्रय कर एवं क्रय कर में अन्तर

व्यापारिक व्यवहार के सामान्यतः दो पक्ष होते हैं : विक्रय और क्रय । इसी आधार पर यदि वस्तु के विक्रय पक्ष पर कर लगाया जाए तो उसे विक्रय कर कहा जाता है और यदि क्रय पक्ष पर कर लगाया जाए तो इसे क्रय कर कहा जाता है । इन दोनों करों में वस्तु-विनिमय के पक्ष का अन्तर पाया जाता है लेकिन अधिकांश परिस्थितियों में इनका प्रभाव समान होता है । यह ठीक है कि विक्रय कर विक्रेताओं पर लगाया जाता है लेकिन व्यवहार में वह क्रेताओं पर ही विवर्तित हो जाता है जबकि क्रय कर सीधे ही क्रेताओं पर लगाया जाता है । विक्रय कर पंजीकृत व्यापारी या विक्रेता की कुल बिक्री पर लगाया जाता है जबकि क्रय कर उसके द्वारा क्रय किये गये माल की राशि पर लगाया जाता है । भले ही उसमें से कोई माल बिका हो या न बिका हो । सैद्धान्तिक रूप से क्रय कर किसी भी क्रेता द्वारा किये जाने वाले क्रय राशि पर लगाया जाता है लेकिन व्यवहार में क्रय कर उन क्रेता व्यापारियों या उत्पादकों पर लगाया जाता है जो वस्तु को पुनः बेचे जाने या वस्तु का प्रयोग कर तैयार माल बेचने के उद्देश्य से क्रय करते हैं । सामान्यतः निजी उपभोग के लिए किये जाने वाले क्रयों को कर की परिधि में शामिल नहीं किया जाता । कर के अन्तरण में के सन्दर्भ में यह उल्लेख है कि वस्तु की माल और पूर्ति की परिस्थितियाँ, प्रतियोगी दशाएँ, कर राशि तथा प्रतिस्थाप्य वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए दोनों की दशाओं में कर को विवर्तित करने की संभावना रहती है । हाँ इतना अवश्य है कि विक्रय कर सामान्यतः इसी नाम से विवर्तित हो जाता है जब कि क्रय कर अनेक परिस्थितियों में लागत का एक अंग बन कर विवर्तित होता है ।

बिक्री कर औचित्य

बिक्री कर के औचित्य को लेकर विशेषज्ञों में काफी मतभेद है । फिर भी ऐसा देखने में मिलता है कि यह कर प्रायः सभी देशों में प्रचलित है । आमतौर पर यह विक्रय की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है । बिक्री कर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और उनका क्षेत्र तथा उनके लगाने के विशिष्ट उद्देश्य भी अलग-अलग हो सकते हैं । बिक्री पर कर लगने से प्रायः वस्तुओं का मूल्य अधिक हो जाता है । इससे उपभोग

की मांग घट जाती है और उपभोक्ताओं की रहन-सहन की लागत अधिक हो जाती है। मूल्य बढ़ने से मांग कम हो जाने से वस्तु का उत्पादन निरुत्साहित हो सकता है। जिसके कारण कभी-कभी नियोजताओं को और क्रमिकों के मध्य विवादों की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बिक्री कर के विभिन्न प्रकारों के बारे में यदि कोई तथ्य समान है तो यह कि बिक्री कर उपभोक्ताओं पर भार डालने की इच्छा से लगाये जाते हैं। सामान्यतः बिक्री कर सभी उपभोक्ताओं के साथ समान अथवा अनुपातिक व्यवहार करते हैं और उनमें छूट की कोई व्यवस्था नहीं होती इसके साथ ही बिक्री कर वस्तुओं अथवा क्रियाओं की लागत में प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से जोड़ दिया जाता है। बिक्री करों से सम्बन्धित कानूनों में इनको सम्पूर्ण रूप से अन्तरित करने की स्पष्ट व्यवस्थायें होती हैं और उपभोक्ताओं को भी इस बात का पूरा ज्ञान होता है कि बिक्री कर उनकी ओर को अन्तरित किया जा रहा है। इस प्रकार सामान्यतः बिक्री कर का भार उपभोक्ता ही सहन करते हैं और इन करों को लगाते समय सरकार का भी यही उद्देश्य होता है कि इसका भार सभी उपभोक्ता सहन करें।

बिक्री करों की प्रवृत्ति ऐसी है कि इनका आमतौर पर अग्रान्तरण हुआ करता है यद्यपि इनका परवान्तर्ण अथवा पीछे की ओर अन्तरण भी सम्भव है। इसके अन्तरण का सामान्य तरीका यह है कि इस कर का द्रव्य भार, उत्पादकों की ओर से, जिन पर यह मूल रूप से लगाया जाता है, मध्यवर्ती स्नेन्तियों जैसे थोक व्यापारियों एवं फुटकर व्यापारियों के माध्यम से अन्तिम उपभोक्ता की ओर को स्थानान्तरित कर दिया जाता है। यह आगे की ओर अन्तरण का सामान्य रूप है और इसमें कर के कारण वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। यदि उपभोक्ता द्वारा कर के सेते कुले अन्तरण का कुछ प्रतिरोध किया जाता है तो उत्पादक करान्तरण के अन्य तरीके अपनाते हैं जिनमें एक यह भी है कि वे कर लगी वस्तु की किंमत या मात्रा में अथवा दोनों में ही कुछ कमी कर देते हैं। कभी-कभी उत्पादक उपभोक्ताओं के प्रतिरोध के कारण जब यह देखते हैं कि कर का आगे की ओर अन्तरण करना संभव नहीं है और साथ ही वे उत्पादित वस्तु की किंमत अथवा मात्रा में भी कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते तो कर को पीछे की ओर अन्तरित करने का प्रयास करते हैं और इस तरह वे या तो क्रमिकों को कम मजदूरी देने की वाध्य करते हैं अथवा कच्चे माल की पूर्तिकर्ताओं पर दबाव डालते हैं कि वे अपनी

वस्तुओं की अपेक्षाकृत कम कीमतेँ लेना स्वीकार करें। यदि इन दोनों को करना सम्भव नहीं होता तो उपभोक्ताओं की ओर कर का अन्तरण करने का केवल एक ही अन्तिम शेष रहता है। इस उपाय के द्वारा सीमान्त फायों को गैर: गैर: उद्योग से बाहर कर दिया जाता है और इस प्रकार उत्पादित वस्तु की पूर्ति में कमी करके उनके मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है।

व्यवहारतः वस्तु पर लगे कर का विवर्तन होना या न होना वस्तु की माँग या पूर्ति की लोच पर निर्भर रहता है। यदि करासोपित वस्तु की माँग लोचदार होती है तब मूल्य वृद्धि द्वारा कर भार उपभोक्ताओं पर सरलता से विवर्तित किया जा सकता है, लेकिन यदि वस्तु की माँग लोचदार होती है तो कर का भार अंगतः उपभोक्ता की ओर अंगतः उत्पादक या विक्रेता को वहन करना पड़ता है। वस्तु की आपूर्ति जितनी अधिक लचीली होगी, उतनी ही अधिक सम्भावना इस बात की है कि कर क्रेता को वहन करना होगा। यदि वस्तु की पूर्ति लोचदार और माँग लोचदार होती है तो कर लगने पर कर का भार विवर्तन नहीं होने पाता और सम्पूर्ण कर का भार उत्पादकों को ही वहन करना पड़ता है।

वस्तु कराधान का अन्तरण तथा उसकी वाह्यता बिछी करों की प्रकृति तथा उसके क्षेत्र पर निर्भर करती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि बिछी-कर दो तरह के होते हैं - 111 सामान्य बिछी कर खम् 121 विशिष्ट बिछी कर।

111 उत्पादक, सामान्य बिछी कर के भार को पूर्णतः एवं सरलता से उपभोक्ताओं पर विवर्तित कर देते हैं और सरकार का भी यही उद्देश्य होता है। इसका कारण एक तो उनका क्षेत्र व्यापक है और दूसरे सभी प्रतियोगी वस्तुओं पर वे एक समान दर से लगते हैं। इसमें उपभोक्ताओं को प्रतिरोध की बहुत थोड़ी छूट प्राप्त होती है और इस कारण उसे बड़ी कीमत का भुगतान करना होता है क्योंकि वे अपने उपभोग को अन्य करों में लगी वस्तुओं के लिए स्थानान्तरित नहीं कर सकते। इसमें एक बात यह भी है कि क्योंकि जनता बिछी कर लगने की अभ्यस्त हो जाती है अतः अन्तरण को सामान्य स्थिति के रूप में स्वीकार करने लगते हैं। साथ ही व्यवसायी लोगों को भी

सामान्य बिक्री करों के अन्तर्गत से सम्बन्धित विभिन्न तरीकों के सम्बन्ध में अधिक अनुभव मिल जाता है। इसके अलावा बिक्री कर से वस्तु की उत्पादन लागत तथा बाजार में लाने की लागत बढ़ जाती है और इसमें कर लगी फर्मों को कर के भार का अन्तर्गत करने की एक प्रेरणा मिलती है। उत्पादन की दशा में तथा उसके साथ ही माँग की मुख्य तापेक्षता अथवा लोचशीलता की स्थितियाँ भी सामान्य बिक्री कर के अन्तर्गत की सम्भावनाओं पर प्रभाव डालती हैं।

121 विशिष्ट बिक्री कर के भार का विवर्तन इतना सरल नहीं होता क्योंकि ऐसे कर के लागू होने का क्षेत्र बड़ा सीमित होता है। यह अन्तर्गत कर लगी फर्म पर दो स्थितियों में बुरा प्रभाव डाल सकता है, एक तो तब जब कि उस वस्तु की स्थानापन्न वस्तुओं पर करारोपण नहीं होता है तो इन करों का भार प्रायः उत्पादकों को ही वहन करना पड़ता है। दूसरे, उस समय जब कर लगी वस्तुओं की माँग मुख्य तापेक्ष अथवा लोचदार होती है तो भी उसके भार को उत्पादक ही वहन करते हैं। ऐसी स्थिति में कर लगी फर्म यदि कर लगने के कारण कीमत में वृद्धि करती है तो वह दो प्रकार से घाटे में रहती है - प्रथम, इस स्थिति में वस्तु का बाजार इनके हाथ से निकल जायेगा और वे प्रतिपोगी फर्मों जिनकी उत्पादित वस्तुओं पर कर नहीं लगा है, बाजार पर प्रभुत्व जमा लेंगी। दूसरे, यदि फर्म कीमत में वृद्धि करती है तो उस फर्म के वे उपभोक्ता जिनके लिए उस वस्तु की माँग मुख्य तापेक्ष अथवा लोचदार है उस फर्म से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेंगे। अतः कर लगी फर्म इस के लिए बाध्य हो जायेगी कि वह कर-भार को पूर्णतया स्वयं ही वहन करें। इसके विपरीत करारोपित वस्तु की स्थानापन्न वस्तु के बाजार में न होने पर और उसकी माँग लोचदार होने पर कर भार को उपभोक्ताओं पर विवर्तित किया जा सकता है जैसे-पेट्रोल, तम्बाकू आदि। ऐसी वस्तुओं पर कर अन्तर्गत किये जा सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि उन्हें उपभोक्ता के कर सम्बन्धी कोई विशेष प्रतिरोध का सामना न करना पड़े।

भारत में बिक्री कर की स्थिति कुछ भिन्न है। यहाँ बिक्री कर राज्य स्तर पर लगाए जाते हैं। जब एक राज्य में बिक्री कर की दरें दूसरे राज्य से अधिक हैं तथा कर लगने वाली वस्तुएँ एक राज्य से दूसरे राज्य में बिकती हैं तो उपभोक्ता उस वस्तु को

जिस पर एक राज्य में कर लगा हुआ है परन्तु दूसरे में नहीं, उसे अन्य राज्यों से मंगा लेते हैं और इस प्रकार कर-भार उपभोक्ताओं पर डाला जाना सम्भव नहीं हो पाता तथा उत्पादक स्वयं ही अधिकांशतः कर भार सहन करते हैं। यह स्पष्ट है कि बिज्जी कर सामान्यतः अन्तिम उपभोक्ताओं पर आने की ओर अन्तरित कर दिये जाते हैं। यह अन्तरण अनिवार्य अथवा आदेश प्राप्त हो सकता है और बिज्जी कर के विधान में इसका स्पष्ट उल्लेख कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जिनके अन्तर्गत इन करों का अन्तरण न हो सके और उत्पादक कर के भार को पूर्णतया या अंशतया स्वयं ही सहन करने को बाध्य हो जाय। वास्तव में कर का भार किस अंश तक क्रेता और विक्रेता तथा उत्पादकों पर पड़ेगा, यह अनेक तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे करारो-पित वस्तु की माँग और पूर्ति की लोच, उत्पादित वस्तु पर उत्पात्ति के नियमों का प्रभाव, उत्पादन तथा विपणन दशा, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, कर की प्रकृति, बाजार में प्रचलित उपयोगिता इत्यादि। इन सब कारणों के सामूहिक प्रभाव के आधार पर ही बिज्जी कर के अन्तिम भार का निर्धारण किया जाता है।

बिज्जी कर तुलनात्मक रूप से एक नवीन कर है एवम् भारत में राज्य सरकारों की आय का महत्वपूर्ण आधार बन गया है। पिछले कुछ समय में इस कर को प्रतिस्थापित करने की प्रयत्न मँगि बनी रही है। लेकिन अनेक प्रयत्न तर्कों एवं औचित्यों के आधार पर इस कर को लगाने और बनाये रखने का समर्थन किया जाता रहा है। बिज्जी कर के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले तर्क इस प्रकार हैं :-

राजकीय आगम स्रोत

सरकारी पक्ष की दृष्टि से बिज्जी कर के समर्थन में प्रमुख तर्क इस कर से होने वाली पर्याप्त आय है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह कर वस्तुओं तथा व्यापारियों के विस्तृत क्षेत्र पर लगाया जा सकता है और कर की छोटी सी दर से ही एक बड़ी धनराशि एकत्रित की जा सकती है। यही कारण है कि बिज्जी कर राज्य-सरकारों की आगम का मुख्य स्रोत बन गया है। कुछ राज्यों में तो यह आय का सबसे बड़ा स्रोत है। राज्यों की लगभग 55 प्रतिशत से अधिक आय इसी कर से प्राप्त होती है।

बिड़ी कर की आगम उत्पादकता की पुष्टि करते हुये कराधान जांच आयोग ने भी लिखा है कि "बिड़ी कर का शुभ आय के मुख्य साधन के रूप में इस तथ्य पर आधारित है कि यदि इसे कम दर से अधिक व्यापारियों एवं वस्तुओं पर लगाया जाय तो इससे एक अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है।"⁴

बिड़ी कर द्वारा आगम में शीघ्रता

बिड़ी कर का एक लाभ यह भी है कि इस कर से सरकार को शीघ्र आगम प्राप्त होने लगती है। करदाता बिड़ी-कर का भुगतान पूरे वर्ष करता ही रहता है क्योंकि इसका भुगतान अनेक वस्तुओं की खरीद पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में करना पड़ता है, इसलिये यह कर अत्यन्त सुगम भी होता है। टेलर के शब्दों में "बिड़ी कर के समर्थन में एक लोकप्रिय तर्क यह है कि कानून बनने के उपरान्त बहुत कम समय में यह कर आय उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। सामान्यतः यह किसी कर का वांछनीय चिह्न है।"⁵

सरकार के आगम में स्थायित्व

बिड़ी कर से होने वाले आगम में अन्य करों की अपेक्षा अधिक स्थिर रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि सामान्यतः यह कर उन वस्तुओं की बिड़ी पर लगाया जाता है जिनका उपभोग प्रायः स्थिर और नियमित होता है। टेलर ने लिखा है कि "अन्य करों सामान्यतः आयकर आगम की आगम की तुलना में बिड़ी कर से आय अधिक स्थिर होती है। यह कर उपभोग की वस्तुओं पर होता है जो एक काल में लगभग स्थिर रहता है।"⁶

4. Report of Taxation Enquiry Commission. Vol. III. Page 44.

5. Philips E. Taylor : "The Economics of Public Finance",
Page 414.

6. Philips E. Taylor : The Economics of Public Finance, P. 411.

लौच

बिक्री कर में लौच का अंश भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है। बिक्री कर की दरों में घोड़ी सी वृद्धि करके, बिक्री के अन्तर्गत सम्मिलित की जाने वाली वस्तुओं की संख्या में वृद्धि करके तथा कर मुक्ति की सीमाओं में परिवर्तन करके, कर से प्राप्त होने वाली राशि में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। चूंकि यह कर बहुसंयुक्त वस्तुओं और व्यापारियों पर लगाया जा सकता है, अतः सरकार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसमें परिवर्तन किये जा सकते हैं और आय प्राप्त की जा सकती है।

व्ययों पर नियन्त्रण एवं बचतों को प्रोत्साहन

बिक्री कर लगाने से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है जिससे उपभोक्ताओं को अपने उपभोग व्यय में कुछ कमी करनी पड़ती है और व्यय पर रोक लग जाती है। अनेक परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से वस्तु का राशनिंग न करके उनकी बिक्री पर अधिक बिक्री कर लगा देने से ही उपभोग कम हो जाता है और वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है। डा० आर. एन. भार्गव के शब्दों में "एक सामान्य बिक्री कर छायों पर अनुपातिक कर की भाँति होता है। यह बचतों को प्रोत्साहित करता है तथा कल्याणकारी आधार पर पतन्द किया जाता है।"

आबंटनात्मक कुशलता

इस कर से आबंटनात्मक कुशलता भी प्राप्त की जा सकती है। यह अब सामान्यतः मान लिया गया है कि "आबंटनात्मक कुशलता के लिए जिन वस्तुओं का उपभोग निरोत्साहित करना है, उन पर कर लगाना अधिक अच्छा है, चाहे वे किसी भी देश में उत्पादित की गई हों, बजाय इसके कि केवल आयातित वस्तुओं पर विभेदात्मक कर लगाये जाये।"⁷

बिड्डी कर तथा प्रेरणात्मक प्रभाव

यह बात सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि आयकर, और विशेष रूप से अत्यधिक आरोही आयकर, आर्थिक प्रेरणाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि निवेश से होने वाली समस्त आयों का कुछ भाग लेकर आयकर नये व्यवसायों के विकास तथा पुराने व्यवसायों के विस्तार को रोकता है। ऐसा कुछ तो इस कारण होता है क्योंकि व्यवसाय के विस्तार व व्यवसाय के लिए उपलब्ध द्रव्य पूंजी की प्राप्ति में कमी हो जाती है और कुछ इसलिये क्योंकि विस्तार की प्रेरणाओं में कमी हो जाती है।

दूसरी ओर, बिड्डी कर नये पूंजी विनियोग से होने वाली आय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता क्योंकि पूंजी-निवेश से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की कुल मांग बिड्डी कर द्वारा प्रभावित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, उन व्यक्तियों के मामले में, जो कि अपनी आय मजदूरियों और वेतनों के रूप में प्राप्त करते हैं, आयकर उनकी कार्य करके प्राप्त की हुई आय का एक हिस्सा लेकर, कार्य करने की विशेष रूप से ओवर टाइम वर्क (समयोपरिकाम) करने की उनकी प्रेरणाओं में परिवर्तन कर देता है किन्तु यह भी सम्भव है कि उपर्युक्त स्थिति में व्यक्ति अपने कार्य की मात्रा में वृद्धि कर दें, वगैरह कि वह अपने पुराने जीवन-स्तर को बनाये रखने में रुचि रखता है।

दूसरी ओर, बिड्डी कर प्रेरणाओं पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा इसलिये होता है क्योंकि अधिकांश मामलों में व्यक्ति अपने छर्च आदि का हिसाब लगाने में बिड्डी कर की कोई गणना नहीं करता। प्रो. एफ. डब्ल्यू. पैश ने कहा है कि "व्यक्ति उस समय अतिरिक्त कार्य करने को तैयार नहीं होगा जब कि उसे यह बात होता कि उसके कमाये हुए धन का आधा भाग उससे आयकर के रूप में ले लिया जायेगा, परन्तु तम्बाकू खरीदने के लिए धन कमाने हेतु वह अवश्य ही काम करेगा, यद्यपि होता यह है कि उस तम्बाकू के लिए जो धनराशि वह अदा करता है उसका तीन चौथाई भाग सरकार के पास जाता है।"

बिड्डी कर और सरकार को सामान्य अंशदान

बिड्डी कर का और विशेषतः सभी उपभोग करों का इस आधार पर भी समर्थन

किया जाता है कि इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सरकार को अपना अंशदान देता है। जब सरकार सभी की है और सरकार की सेवाओं के लाभ सभी व्यक्ति प्राप्त करते हैं तो यह, किन्तुल उचित तथा स्वाभाविक ही है कि सरकार के व्ययों का भार भी सभी उठाये और इस कार्य के लिए गरीबों तक पहुँचने का केवल एक ही रास्ता है, और वह है - वस्तुओं का कराधान। वस्तु करों की ही एक किस्म के रूप में, बिजुली कर सरकार को इस योग्य बनाते हैं कि वह निर्धन से निर्धन कितान से भी प्राप्त कर लें।

बिजुली कर और पूंजी निर्माण

बिजुली कर के समर्थकों का दावा है कि बिजुली कर बचत करने की प्रेरणा को कम नहीं करता जबकि आयकर ऐसा करता है। बिजुली कर का भार जिन व्यक्तियों पर अधिक मात्रा में केन्द्रित होगा। वे बचतों की बजाय उपभोग को ही कम करने को मजबूर होंगे। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा जाता है कि कर-राजस्व की एक निश्चित रकम प्राप्त करने के लिए जो बिजुली कर लगाया जाता है। उसका एक बड़ा भाग उन धनराशियों में से लिया जाता है जो कि अन्य स्थिति में उपभोग कार्यों में खर्च कर दी जाती है, जबकि आयकर में ऐसा नहीं होता। इसका परिणाम यह होगा कि आय के कराधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय के बचतों का कुल अनुपात अपेक्षाकृत अधिक रहेगा और पूंजी निर्माण की दर मुद्रास्फीति की सम्भावना के बिना अधिक हो जायेगी।⁸

अल्पविकसित देशों के लिए यह तर्क बड़े महत्व का है। जैसा कि तर्कविदित है, इन देशों में पूंजी निर्माण की कमी पाई जाती है अतः बिजुली के कराधान द्वारा पूंजी निर्माण में जो वृद्धि सम्भव होती है, उसके कारण बढ़ते हुए जीवन स्तर में तेजी से गिरा-वट आती है। इस प्रकार, स्पष्टतः पूंजी निर्माण तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से बिजुली का कराधान अधिक लाभप्रद है।

बिजुली कर और प्रशासन में सरलता

अन्य वस्तु करों के समान ही, बिजुली कर का समर्थन इस आधार पर भी किया

जाता है कि सामान्यतः इसकी वस्तु करना बड़ा सरल होता है, चूँकि बिड़ी कर खरीदी गई वस्तुओं की कीमतों में घिमा रहता है, अतः लोगों को शायद ही कभी इसका आभास होता हो कि वे कर दे रहे हैं फिर जब भी खरीद की जाती है, यह आप से आप ही अदा कर दिया जाता है ।

इसके अतिरिक्त, आयकर और व्ययकर की तुलना में बिड़ी कर का प्रबन्ध एवं प्रशासन बड़ा सरल होता है । एक तो इस कारण, क्योंकि यह बड़ी संख्या में पृथक - पृथक व्यक्तियों से वसूल न किया जाकर थोड़ी व्यावसायिक फर्मों से वसूल कर लिया जाता है । दूसरे, इसका संग्रह दर्ज हुई कुल बिड़ी के आधार पर किया जाता है और इसमें शुद्ध आमदनियों की अनेक व्याख्याओं तथा उनके विभिन्न द्रोतों की जान-बीन नहीं करनी पड़ती ।

बिड़ी-कर-मुद्रा स्फीति विरोधी उपाय के रूप में

युद्ध काल में तथा अन्य मुद्रा स्फीति की अवधियों में, एक सामान्य बिड़ी कर का सम्बन्ध इस आधार पर भी किया जाता है कि इसके द्वारा मुद्रा स्फीति के दबाव को कम किया जा सकता है । ऐसा दो प्रकार से किया जा सकेगा : प्रथम तो इस प्रकार यह व्यक्तियों के हाथों में उपलब्ध फलतु इयक्ति को कम करेगा और दूसरे, यह उपभोग व्यय को सीमित करेगा और इस प्रकार अपर्याप्त पूर्ति पर मणि के पड़ने वाले दबाव को कम करेगा ।

।परन्तु यह भी सम्भव है कि इस सम्बन्ध में एक विरोधी तर्क यह दिया जाए कि ऊँची दरों से लगाया जाने वाला बिड़ी कर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वे अधिक मजदूरी और वेतन की माँग करें तथा उसे प्राप्त करें, और यदि ऐसा हुआ तो कीमतों पर मुद्रा-स्फीति सम्बन्धी दबाव घटने की क्जार और बढ़ जायेगा ।।

बिड़ी कर और भ्रष्टाचार जनसंख्या

बिड़ी करों के पक्ष में एक अत्यन्त ठोस तर्क, जो कि महत्त्वपूर्ण नगरों एवं पर्यटक केन्द्रों पर विशेष रूप से लागू होता है, यह है कि बिड़ी कर ही एकमात्र यह उपाय है

जिसे द्वारा भ्रमणीय जनसंख्या से भी यह आशा की जा सकती है कि वह सरकार की सामान्य सेवाओं की प्राप्ति के उपलक्ष में कुछ अदा करें। भ्रमणीय जनसंख्या में ऐसे सभी लोग सम्मिलित किये जाते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में अध्यापिकाओं के, करने के लिए नहीं, बल्कि भ्रमण के लिए अध्यापिका अस्थायी रूप से ठहरने के लिए आते हैं। स्पष्ट है कि इन भ्रमणीय व्यक्तियों अध्यापिका पर्यटकों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे आयकर अध्यापिका अन्य कोई प्रत्यक्ष कर अदा करें। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति का एक मात्र रास्ता, जिसे द्वारा उन तक पहुंच की जा सकती है, वस्तुओं का करधान ही है और बिजली कर उसका एक महत्वपूर्ण अंग है।

संघीय प्रशासन-व्यवस्था में बिजली कर

बिजली कर के पक्ष में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण तर्क का सम्बन्ध विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यापिका भारत जैसे संघीय ढांचे वाले देशों से है। ऐसे देशों में संघ सरकार आयकर के कारण बड़ी अच्छी स्थिति में रहती है और राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपनी आय का एक बड़ा भाग प्राप्त करने के लिए वे बिजली करों पर निर्भर रहें, परन्तु जैसा कि जॉन ड्यू ने कहा है कि "कुछ देशों में, इससे उल्टी ही बात है, अर्थात् आयकर पर राज्य का स्वामित्व होने के कारण केन्द्र सरकारों को बिजली के करधान पर निर्भर होना पड़ा है।"

उपयुक्त विभिन्न तर्क, बिजलीकर के औचित्य को स्पष्ट करने में पर्याप्त सीमा तक सक्षम है लेकिन जनसामान्य की दृष्टि से यह कर अनेकों आलोचनाओं और विपक्षी तर्कों के द्वावों से घिरा रहा है। सन् 1920 में ही राजस्व के प्रसिद्ध विद्वान् सैलिगमैन ने यह लिखा था कि "सामान्य बिजली-कर एक कष्टदायी व्यवस्था का एक बदनाम अवशेष है, निश्चय ही इसकी प्रकृति अलोकतन्त्रीय है, और यदि इसको लागू किया गया तो इससे धन तथा अवसरों की वर्तमान असमानताएँ घटने की बजाये बढ़ेगी ही।"¹⁰

9. John, F. Due : Sales Taxation, Page 35.

10. Seligman : Studies in Public Finance, Page 138.

इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए हैरोल्ड एम. ग्रेव्स ने लिखा है कि "बिड़ी का कराधान और वस्तुतः सम्पूर्ण परोक्ष कराधान ही स्वरेखा में आयुक्तिपूर्ण तथा भार की दृष्टि से अन्यायपूर्ण एवं अनुचित है ।"¹¹

बिड़ी कर के विषय में प्रस्तुत किये जाने वाले तर्कों को संक्षेप में निम्न प्रकार रखा जा सकता है :

अयोगामी या प्रतिगामी प्रभाव

बिड़ी-कर का एक बड़ा दोष यह है कि यह प्रगतिशील नहीं है । यह एक अप्रत्यक्ष कर है और वस्तु पर लगाया गया कर है, इसलिये इसमें प्रगतिशीलता लाने की पर्याप्त सम्भावना नहीं होती है । सामान्यतः सभी उपभोक्ताओं पर बिना उनकी आय की ओर ध्यान दिये हुए या उनकी कर दान योग्यता को ध्यान में रखे हुए एक ही दर से कर लगाया जाता है । इसलिये यह कर दरों की दृष्टि से अनुपातिक होते हुए भी प्रभाव की दृष्टि से प्रतिगामी होता है, क्योंकि इसका भार निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि व्यवहार में बिड़ी कर की प्रतिगामिता को कम करने के लिए बहुधा दो उपाय किये जाते हैं । प्रथम, बिड़ी कर केवल धनासम्पन्न वस्तुओं पर ही लगाये जाते हैं, परन्तु ये इतने उत्पादक नहीं होते जितने कि सामान्य बिड़ी कर होते हैं । द्वितीय, उपभोग की कुछ वस्तुओं पर, जिनका उपभोग मुख्यतः निर्धन व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है, या तो कर लगाया ही नहीं जाता या बहुत नीची दर से कर लगाया जाता है ।

औद्योगिक गुटबन्दी को प्रोत्साहन

औद्योगिक गुटबन्दी को इस कर से अधिकतम प्रोत्साहन मिलता है । व्यापारीका परस्पर मिलकर ऐसी संस्थाएँ स्थापित कर लेते हैं जिनमें कच्चे माल के उत्पादन से लेकर निर्मित माल के उत्पादन तक सभी क्रियाएँ एक ही संगठन के भिन्न-भिन्न

विभागों द्वारा सम्पन्न की जाती है। एक विभाग दूसरे विभाग को वस्तुएँ बिना बिक्री कर का भुगतान किए ही देता है और इस तरह कर के भुगतान से बच जाता है। साथ ही प्रत्येक व्यापारी के उत्पादन कार्य से सम्बद्ध विभिन्न वस्तुएँ एक दूसरे को बिना बिक्री कर के ही प्रदान कर दी जाती है। इस प्रकार पारस्परिक सम्बन्धों के द्वारा व्यापारी लोग बिक्री कर से बच जाते हैं। साथ ही वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण के प्रत्येक स्तर पर बिक्री कर से बचने के लिए उद्योग स्वीकरण की नीति को अपनाते हैं ऐसा करने से उत्पादन से लेकर फुटकर बिक्री की समस्त क्रियाएँ एक ही तंगठन इकाई के अन्तर्गत लाई जाती है। ऐसी दशा में कर एक ही बार दिया जाता है।

अन्तर्राज्यीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव

बिक्री कर से अन्तरस्थानीय अन्तर्राज्यीय व्यापार को, विशेषकर उन देशों में जहाँ संघ सरकार स्थापित होती है, बहुत हानि पहुँचती है। एक वस्तु के स्थानान्तरण पर जब प्रत्येक राज्य बिक्री कर लगाता है तो जितने राज्यों में होकर वह वस्तु बिकती है उतना ही उसका मूल्य बढ़ता जाता है और इस प्रकार अन्तरस्थानीय व्यापार को क्षति पहुँचती है। साथ ही विभिन्न राज्यों में बिक्री कर की दरें अलग-अलग निर्धारित की जाएं तो अन्तर्राज्यीय व्यापार का विकास प्रतिकूल रूप में प्रभावित होता है। इसी प्रकार यदि एक राज्य बिक्री कर लगाता है और दूसरा राज्य नहीं लगाता तब सीमा पर स्थित लोग दूसरे राज्य से माल खरीदने लगते हैं, जो बिक्री कर नहीं लगाता है। इस प्रकार वे अपने राज्य के बिक्री कर को प्रभावहीन कर देते हैं और दूसरे राज्य के व्यापारियों को हानि उठाने के लिए विवश करते हैं।

कर प्रशासन में जटिलताएँ

बिक्री-कर प्रणाली अन्य कर-प्रणालियों की अपेक्षा काफी जटिल है। इसमें प्रशासन को भी बड़ी ओजबजीन करनी होती है। उसे हर प्रकार की बातों का पता लगाना कठिन होता है और यह देखना होता है कि किन-किन व्यापारियों के द्वारा किन-किन वस्तुओं को बेचा व खरीदा जा रहा है। उसी प्रकार बिक्री-कर की अदायगी के लिए धिक्केताओं को लम्बे चौड़े हिसाब-किताब रखने होते हैं। व्यापारियों

को बिछोकर अधिकारियों के सामने समय-समय पर अपनी वस्तुओं का हिसाब प्रस्तुत करना होता है और बिछोकर अधिकारियों द्वारा भी अनेक प्रकार की जाँच की जाती है, जो व्यापारियों को परेशानी में डाल सकती है।

बिचौलियों का प्रादुर्भाव

बिछोकर का एक दोष यह भी है कि इसके लगने से व्यापार करने के ढंग को भी बदल दिया जाता है। कर का भुगतान न करने के लिए थोक व्यापारियों के स्थान पर दलालों को नियुक्त कर दिया जाता है और वस्तुओं को ऐसे बेचा जाता है जैसे कि स्वयं उत्पादक बेच रहा हो यह दोष मुख्यतया बहु-बिन्दु प्रणाली में होता है जिसमें बिछोकर वस्तु की प्रत्येक बिछोकर वस्तु की प्रत्येक बिछो पर लगता है यह दोष मुख्यतया बहु बिन्दु प्रणाली में होता है। व्यापार करने के ढंग में ऐसे परिवर्तन हो जाने से वस्तु की बिछो पर कर केवल एक ही बिन्दु पर लग पाता है।

कर संग्रह की ऊँची लागत

बिछोकर के विषय में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इस कर की आय को संग्रह करने की लागत अधिक होने के कारण यह मितव्ययी नहीं है, क्योंकि इस कर को व्यापारियों से एकत्रित किया जाता है जो दूर-दूर तक फैले रहते हैं। साथ ही अनेक छोटे-छोटे व्यापारियों के खातों के निरीक्षण के लिए सरकार को बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। इसलिये बिछोकर की लागत काफी अधिक होती है। बिछो कर की चोरी का भय भी रहता है। इसलिये सरकार की आय कम हो जाती है, जबकि सरकारी व्यय उतना ही बना रहता है। सरकार का यह व्यय प्रशासन सम्बन्धी होता है। यह कहा जाता है कि बिछोकर एकत्रीकरण में उन्ने प्राप्त होने वाली आय का $\frac{2}{3}$ भाग तक व्यय हो जाता है। टैलर का मत है कि "यह सामान्यतया सत्य प्रतीत होता है कि 3 प्रतिशत बिछोकर लगाने पर 2 प्रतिशत से कम आय प्राप्त होती है, 2 प्रतिशत कर लगाने से 3 प्रतिशत से भी कम आय प्राप्त होती तथा 1 प्रतिशत कर से औसत रूप में 3 प्रतिशत से भी अधिक आय संग्रह की जा सकती है।"¹²

दोहरा करारोपण एवं वस्तु लागत में वृद्धि

बिड़ी कर में दोहरे कर की समस्या भी रहती है। एक ही वस्तु पर कई बार कर लग जाता है। सर्वप्रथम कच्चे माल की बिड़ी पर कर लगता है, फिर जब दुकानदार कच्चे माल को खरीदता है तब कर लगता है और अन्त में उपभोक्ता खरीदता है तो भी कर लग जाता है। बिड़ी कर से वस्तुओं की लागत में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जब कच्चे माल पर बिड़ी कर लगाया जाता है तो उत्पादकों की सीमान्त लागत में वृद्धि हो जाती है।

कर-वैतन्यता का अभाव

बिड़ी कर में सामान्यतः कर वैतन्यता का अभाव होता है। अधिकांशतः यह कर वस्तु के मूल्य में छिपा रहता है अर्थात् उपभोक्ता को यह ज्ञात नहीं होता कि वह कर के रूप में राज्य को कुछ अंशदान दे रहा है। फलस्वरूप नागरिकों में कर-वैतन्यता कम हो जाती है। इस प्रकार बिड़ी कर का वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो जाता है। यह हो सकता है कि निर्धन व्यक्ति एवं सामान्य व्यक्ति बिड़ी कर के भार से पूर्णतया परिचित न हो और ऐसी दशा में वे सरकार की वित्तीय क्रियाओं के प्रति कभी भी आलोचनात्मक रुख नहीं अपना सकते।

असमान भार वितरण

बिड़ी कर से प्राप्त होने वाली आय और आयकर से प्राप्त होने वाली आय समान होती है, परन्तु बिड़ी कर का भार असमान रूप से पड़ता है। मध्यम और उच्च वर्ग पर इस कर का भार बहुत अधिक पड़ता है जबकि धनी वर्ग पर इस कर का भार कम पड़ता है।

आर्थिक तटस्थता

यदि कुछ आवश्यक शर्तें पूरी हो जाएँ तो तटस्थता रूप में बिड़ी कर को प्रभाव डालने की दृष्टि से तटस्थ माना जा सकता है किन्तु व्यवहार में, यह स्पष्टतः तटस्थ एवं अतर्कपूर्ण है। उदाहरण के लिए यदि कुछ वस्तुओं को इस कर से मुक्त किया गया तो

उत्त वस्तु के उपभोग में अपेक्षित वृद्धि हो जायेगी । इसी प्रकार, यदि कर का अन्तरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है अर्थात् यदि वस्तुओं की कीमतों में कर की राशि से अधिक वृद्धि होती है, तो उत्त वस्तुओं का उत्पादन तथा उपभोग प्रभावित होगा । फिर, यदि बिजुली कर उत्पादक पदार्थों पर भी लगाया गया तो यह सम्भव हो सकता है कि उत्पादन की कुछ रीतियाँ अन्य के मुकाबले अधिक खर्चीली अर्थात् इष्टतम कार्यक्षमता की प्राप्ति की आशा क्षीण हो सकती है ।

स्फीतिकारक प्रभाव

मुद्रा प्रसार की अवस्था में कर इसलिए लगाया जाता है कि लोगों से क्रय-शक्ति छीनकर वस्तुओं के मूल्य को कम किया जावे, परन्तु बिजुली कर से मूल्य स्तर नीचा होने की अपेक्षा ऊँचा हो जाता है क्योंकि जितना ही अधिक कर सरकार लगाती है, विक्रेता उतना ही ऊँचा मूल्य-स्तर निर्धारित करके वस्तुओं की बिजुली करते हैं । इस प्रकार सामान्य मूल्य-स्तर में वृद्धि होने से नागरिकों में भोजन भोगी एवं मजदूर, महेगाई-भत्ते की माँग बढ़ने लगती है और यदि सरकार इन माँगों को पूरा कर दे तो और अधिक मुद्रा-स्फीति की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बिजुली कर का सामान्य प्रभाव यह होता है कि कीमतें बढ़ जाती हैं और उत्त उपभोक्ताओं को अपने उपभोग में कटौती करने की प्रेरणा मिलती है । बिजुली कर के गुणों में बताया जा चुका है कि बिजुली कर का उपयोग मुद्रास्फीति विरोधी उपाय के रूप में किया जा सकता है, परन्तु इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि अवस्फीति अर्थात् मन्दीकाल में, जबकि वस्तुओं की कीमतें स्वयं ही गिर रही होती हैं और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर होती है, यदि बिजुली कर लगाया जाए तो उत्त अवस्फीति अर्थात् मन्दी की स्थिति और भी बदतर हो जाती है । बिजुली कर के द्वारा उपभोग की मात्रा कम होने लगती है और उत्त के फलस्वरूप माँग में कमी होने के कारण विनियोग की मात्रा भी घटने लगती है । अर्थव्यवस्था के लिए यह प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक होती है । इस स्थिति में तो यह आयकर से निश्चय ही घटिया है, क्योंकि मन्दीकाल में आयकर से होने वाली सरकारी आय में कमी हो जाती है और कर-दाताओं के पास अधिक मात्रा में आय रह जाती है जिससे उनकी उपभोग्य वस्तुओं की माँग बढ़ने

की आशा की जा सकती है । बिजुली कर जहाँ तक उपभोग्य पदार्थों की बिजुली में कमी करता है उस सीमा तक इसे अवस्फीति सम्बन्धी प्रभाव डालने वाला ही कहा जायेगा ।

बिजुली-कर के पक्ष तथा विपक्ष में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उनमें एक बात तो स्पष्ट ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और वह यह कि बिजुली कर अत्यधिक अप-रोही है । यह एक कठोर तथा अन्यायपूर्ण कर है । इन मानों में क्योंकि यह उन व्यक्तियों पर अधिक तीव्र प्रहार करता है जिनकी कर उदा करने की सामर्थ्य न्यूनतम है। देश की औद्योगिक और व्यापारिक उन्नति में भी यह बाधक बनता है । यद्यपि यह सत्य है कि छाद्य पदार्थों तथा अनिवार्य आवश्यकता की कुछ अन्य वस्तुओं को कर मुक्त करके इसका अवरोहीपन कम किया जा सकता है, परन्तु केवल इतना करके ही बिजुली कर को समता एवं न्याय की दृष्टि से न्यायोचित सिद्ध करना सम्भव नहीं है । तथापि इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि आधुनिक अर्थ-व्यवस्थाओं में बिजुली कर को एक स्थायी स्थान प्राप्त है । ऐसा अनेक कारणों से है :

तत्पश्चात् यह है कि आधुनिक युग में राज्य के खर्चे इतने अधिक बढ़ गये हैं कि आय-कर तथा प्रत्यक्ष व परोक्ष किस्म के अन्य उपयुक्त कर प्रेरणाओं पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले पर्याप्त मात्रा में राजस्व प्रदान नहीं कर सकते । यदि आयकर आरोहण के निश्चित स्तरों को भी लांघ जाएं, तो स्पष्ट रूप से वे काम करने व बचत करने की प्रेरणाओं पर प्रभाव डालते हैं और इस प्रकार वे राष्ट्रीय आय के स्तर को कम करते हैं । यही वही कमी है जिसकी पूर्ति के लिए बिजुली कर को अपना योगदान करना होता है । दूसरे, भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को यदि गरीबी और पिछड़ेपन की दलदल से बाहर निकालना है तो यह बड़ा जरूरी है कि उनमें पूँजी निर्माण व विनियोग की दर को ऊँचा किया जाए । बिजुली कर उपभोग में कमी करके बचत तथा पूँजी निर्माण की ऊँची दरों के विषय में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है । तीसरे, जहाँ आयकर को लागू करना कठिन होता है, विशेषतः वहाँ जहाँ अधिकांश व्यक्तियों की आमदनियाँ बहुत थोड़ी होती हैं और जहाँ सरकारी प्रशासन अकुशल होता है, वहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि बिजुली कर पर निर्भर रहा जाए । चौथे, संघीय ढाँचे वाले देशों में, आयकरों

तथा बिजुली करों को बढ़ी आसानी के साथ संघ या राज्य सरकारों के बीच बाँटा जा सकता है जिससे कि प्रत्येक सरकार के राजस्व को एक निश्चित तथा उपयुक्त स्त्रोत मिल जाए ।

निष्कर्ष

बिजुली कर के विपक्षी तर्कों के सन्दर्भ में इसके स्थान पर उत्पादन कर को प्रति-स्थापित करने का समर्थन किया जाता है । ऐसा करने से एक ओर बिजुली कर से होने वाली हानियों से बचा जा सकेगा तथा दूसरे, राज्य सरकारों की आय भी यथावत बनी रहेगी । परन्तु आधुनिक राज्यों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण बिजुली कर का लगाना अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि बिजुली कर न केवल सतत रूप से जमा ही आ रहा है अपितु यह सरकारी आय का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्त्रोत बन गया है । इसका उपयोग सभी अथवा कुछ थोड़ी सी विशिष्ट वस्तुओं के उपभोग को सीमित करने में किया जा सकता है । इसको उत्पादन शुल्कों से भ्रष्ट माना जाता है, किन्तु सामान्यतया आयकर से घटिया समझा जाता है । इस सम्बन्ध में जॉन ह्यू का यह कथन उल्लेखनीय है कि "सम्पूर्ण रूप में, बिजुली कर को दूसरा सर्वोत्तम कर माना जाना चाहिए - एक ऐसा कर जो कि केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब कि अन्य ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएँ जिनके कारण आयकर तथा अन्य उपयुक्त करों पर पूर्णतया निर्भर रहना अवांछनीय हो जाए ।"

डॉ० जे.सी. पन्त ने लिखा है कि "बिजुली कर ऐसा कर है जिसमें क्रेताओं व विक्रेताओं को हानि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिल पाता है । यह कर देश के आर्थिक विकास में बाधक हो सकता है । इस कर की जितनी आलोचनाएँ की जाएँ, कम हैं, परन्तु इतने पर भी इन करों को हटलाया नहीं जा सकता है । वर्तमान में राज्य सरकारों के व्यय बढ़ते ही जा रहे हैं । यह कर राज्यों की आय का प्रधान साधन बन गया है । आज इस कर की चाहे जितनी आलोचना की जाए, तो भी इस करारोपण को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में राजस्व आय के बाद बिजुली कर राज्य सरकारों की आय का मुख्य साधन बन चुका है ।" 13

अध्याय तृतीय

भारत में किरीटर का सामान्य अध्ययन एवं तैयारी
विज्ञान

भारत में बिक्रीकर का सामान्य अध्ययन एवंसंवैधानिक स्थिति

बिक्रीकर से सम्बन्धित संविधान लागू होने से पूर्व, परिचामी बंगाल के अतिरिक्त सभी राज्य दूसरे समस्त राज्यों को जाने वाली वस्तुओं पर बिक्री कर लगाते थे। मद्रास में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि अन्तिम विक्रेता को यह कर आधा देना पड़ता था, यदि वह विक्रेता उन वस्तुओं को मद्रास राज्य के बाहर बेचता था। पंजाब राज्य से दूसरे राज्यों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को इस कर से छूट प्रदान की गई थी, परन्तु बम्बई में 1 अप्रैल, 1949 ई० से बिक्री कर में छूट प्रदान नहीं की गई और वस्तुओं को दूसरे राज्यों को निर्यात करते समय 3 पैसे प्रति रुपये की दर से कर लगाया गया। बम्बई में बन्दरगाह होने के कारण ऐसी वस्तुओं पर, जो दूसरे राज्यों के उपभोग के लिए वहाँ पर आयात की जाती थी, कर लगाना वास्तव में उन राज्यों से एक प्रकार का पथकर वसूल करना था। उन राज्यों ने इस प्रवृत्ति पर अपना असंतोष प्रकट किया। तन् 1950 में भारतीय संविधान 1950 के अनुच्छेद 286 के द्वारा इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने का यथेष्ट प्रबन्ध किया गया है। इस अनुच्छेद 286 में की गई मुख्य व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं :-

किसी राज्य का कोई कानून निम्न परिस्थितियों में माल की बिक्री या खरीद पर कोई कर नहीं लगायेगा - जब माल की बिक्री या खरीद राज्य के बाहर हो, या जब माल भारत की सीमा में आयात के दौरान या भारत की सीमा से निर्यात के दौरान खरीदा या बेचा गया हो।

इसी प्रकार किसी राज्य का कोई भी कानून अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली माल की बिक्री या खरीद पर न तो कर लगायेगा और न कर लगाना अधिकृत करेगा, सिवाय उन परिस्थितियों व सीमाओं के जो संसद कानून बनाकर निर्धारित कर दें। किसी राज्य की विधान सभा द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून जो ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाता है या कर लगाने को अधिकृत करता है जिसे संसद ने कानून बनाकर समाज के लिए अनिवार्य घोषित कर दिया है उस समय तक लागू नहीं होगा जब तक कि उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ

प्रस्तुत न किया गया हो तथा उस पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति न दे दी हो ।

इस प्रकार से उपर्युक्त संविधान के अनुच्छेद 286 के अन्तर्गत कोई भी राज्य सरकार न तो अपने राज्य की सीमा से बाहर होने वाले माल के क्रय-विक्रय पर कर लगा सकती है और न आयात अथवा निर्यात के दौरान माल के क्रय-विक्रय पर ही कर लगा सकती है । इस प्रकार के प्रतिबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर नियन्त्रण एवं इसके द्वारा सीमा शुल्क लगाने के दृष्टिकोण तथा देश में वाणिज्य और व्यापार की स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक है, जो संविधान के अनुच्छेद 301 के अन्तर्गत प्रदत्त किये गये हैं । संविधान के अनुच्छेद 304(अ) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि यदि कोई राज्य अपने राज्य में उत्पादित अथवा निर्मित वस्तुओं के समान, दूसरे राज्य से वस्तुओं का आयात करता है तो उस पर कर लग सकता है किन्तु कर की मात्रा राज्य में उत्पादित, निर्मित वस्तुओं तथा आयात की वस्तुओं पर भिन्न-भिन्न नहीं हो सकती । अतः राज्य सरकारों ने दूसरे राज्य में उत्पादित वस्तुओं पर भेदभावी कर की दरें नहीं लगा सकती ।

बिक्री कर लगाने का अधिकार एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय :

बम्बई राज्य बनाम दी यूनाइटेड मोटर्स इण्डिया लिमिटेड¹ के मामले में सन् 1953 में यह निर्णय दिया गया कि :-

1अ। संविधान के अनुच्छेद 286 1।। 1अ। तथा उसके दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार किसी माल की बिक्री या खरीद पर केवल वही एक राज्य कर लगा सकता है जिसमें माल के उपभोग के लिए माल की सुपुर्दगी दी गई हो ;

1ब। इस स्पष्टीकरण के अनुसार वह राज्य ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर भी कर लगा सकता है जो अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचा गया हो ;

1. इन्क्व्यूजरी ट्रीगलर : मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958, पृष्ठ 6.

12। अनुच्छेद 286 12। ऐसे राज्य पर कर लगाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता है जो उक्त स्पष्टीकरण के अनुसार कर लगाने का अधिकारी है ।

सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय से राज्य सरकारों को ऐसे व्यापारियों से भी बिक्रीकर वसूल करने की कुली छूट मिल गई जो उस राज्य के निवासी नहीं थे किन्तु जिन्होंने माल की सुपुर्दगी उस राज्य में दी थी । इसका परिणाम यह हुआ है कि कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य के बाहर के व्यापारियों को बुलाना, उनसे लेखा पुस्तकें पेश करवाना, बिक्री के नक्के भरवाना और बिक्री कर माँगना प्रारम्भ कर दिया । इससे व्यापारिक क्षेत्रों में अनिश्चितता व अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई और यह माँग की जाने लगी कि बिक्री कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों से लेकर केन्द्र सरकार को सौंपा जाए ।

इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक दूसरे निर्णय में "बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड बनाम बिहार सरकार" के मामले में 6 तितम्बर तन् 1955 को संविधान के अनुच्छेद 286 के सम्बन्ध में एक नया निर्णय दिया । यह निर्णय इसी न्यायालय द्वारा तन् 1953 में बम्बई राज्य बनाम दी पूनाइटेड मोर्टर्स इण्डिया लिमिटेड के मामले में दिये गये निर्णय से भिन्न था । निर्णय के आधार पर यह कहा गया कि,

13। जहाँ तक आयात एवं निर्यात के दौरान माल के क्रय या विक्रय का सम्बन्ध है, ऐसे क्रय-विक्रय पर कोई भी राज्य सरकार बिक्रीकर नहीं लगा सकती है ।

14। संविधान के अनुच्छेद 286 1 13। में जो स्पष्टीकरण दिया गया है, वही उही अनुच्छेद के लिए है और उसका अनुच्छेद 286 12। पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः कोई भी राज्य सरकार अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के क्रय या विक्रय पर उस समय तक कोई कर नहीं लगा सकती है जब तक अनुच्छेद 286 12। के अनुसार उसे तंतद से ऐसा कर लगाने की अनुमति नहीं मिल जाती है ।

15। यदि संविधान के अनुच्छेद 286 12। के अनुसार तंतद किसी राज्य सरकार को अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के क्रय-विक्रय पर कर लगाने की अनुमति दे देती है तो अनुच्छेद 286 1 13। के

स्पष्टीकरण के अनुसार यह निर्धारित किया जायेगा कि ऐसे क्रय या विक्रय पर कितनी राज्य की सरकार कर लगा सकती है ।

इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय से व्यापारिक क्षेत्रों में व्याप्त अनिश्चितता व अराजकता की स्थिति तो समाप्त हो गई, किन्तु साथ ही अन्य कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई । प्रथम, इस निर्णय से पूर्व राज्य सरकारों के द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के क्रय या विक्रय पर जो कर लगाये जा चुके थे या वसूल किये जा चुके थे, वे सभी अवैध हो गये क्योंकि संसद द्वारा कितनी भी राज्य सरकार को ऐसे क्रय या विक्रय पर कर लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी । अतः राज्य सरकारों के द्वारा लगाये गये ऐसे करों को निरस्त करने की तथा जो राशि वसूल की जा चुकी थी उसे वापिस करने की समस्या उत्पन्न हुई । द्वितीय, सभी राज्य सरकारों के बजट अनुमानों में संशोधन करने की समस्या उत्पन्न हुई । इस समस्या का समाधान करना तो सरल कार्य था किन्तु वसूल हुई राशि को वापिस लौटाना राज्य सरकारों के लिए अशुभ था ।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए 30 जनवरी तन् 1956 को राष्ट्रपति द्वारा "बिस्फी कर कानून मान्यता अध्यादेश, 1956" जारी किया । इसके अनुसार 1 अप्रैल, 1951 से 6 सितम्बर, 1955 तक की अवधि में राज्य सरकारों ने अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के क्रय-विक्रय पर जो कर वसूल कर लिया था उसे वैध बना दिया गया । 1 अप्रैल, 1951 को संविधान की धारा 286(2) लागू हुई थी और 6 सितम्बर 1955 को सर्वोच्च न्यायालय ने कंगाल इम्युनिटी कम्पनी लिमिटेड बनाम बिहार सरकार के मामले में अपना उपर्युक्त निर्णय दिया था । इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध ठहराये गये करों को इस अवधि में वैध बना दिया गया । बाद में इस अध्यादेश को "बिस्फीकर कानून मान्यता अधिनियम, 1955" द्वारा पुनर्स्थापित कर दिया गया ।

तन् 1953 में प्रबन्धों राज्य बनाम दी यूनाइटेड मोटर्स इण्डिया लिमिटेड के मामले में उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए 1 अप्रैल, 1953 को भारत सरकार ने देश में कर प्रणाली के अध्ययन तथा सुधार के लिए सुझाव देने हेतु एक 'कराधान बोर्ड'

आयोग का गठन किया। राज्य सरकारों के करों की जाँच करने का भी कार्य इसे सौंपा गया था। आयोग ने सन् 1954 के अन्त में अपना प्रतिवेदन सरकार को दिया। अन्य करों के साथ-साथ आयोग ने बिक्री कर का भी अध्ययन किया और बिक्री कर तथा विशेषकर अन्तराज्यीय क्रय एवं विक्रय के सम्बन्ध में निम्न सुझाव प्रस्तुत किये :-

- 111 बिक्री कर राज्य की आय का ही साधन बना रहना चाहिए, क्योंकि बिक्री कर राज्यों की वित्तीय व्यवस्था में प्रमुख स्थान रखता है और विभिन्न राज्यों में व्यापारिक दशाओं में बहुत अधिक भिन्नताएँ होती हैं। इसलिए राज्य के अन्दर वस्तुओं की बिक्री पर केवल राज्य सरकारें कर लगायें और इतको लगाने तथा वसूल करने का कार्य एवं इतसे सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रशासन राज्य सरकारों के अधीन ही रहने दिया जाये। साथ ही अन्तर-राज्य व्यापार में आने वाली वस्तुओं पर तय सरकार कर लगाये। इसी प्रकार समस्त व्यापार को दो भागों में विभाजित किया जाये। अ। ऐसी वस्तुएँ जो अन्तर-राज्य व्यापार में नहीं आती अर्थात् राजकीय व्यापार और वाणिज्य, और दूसरी। ब। वे वस्तुएँ जो अन्तर-राज्य व्यापार में आती हैं अर्थात् अन्तराज्यीय व्यापार और वाणिज्य। इस प्रकार राजकीय व्यापार और वाणिज्य पर इते राज्यों द्वारा लगाना चाहिए और अन्तराज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर यह कर तय सरकार द्वारा लगाया जाना चाहिए।
- 121 अन्तराज्यीय व्यापार की कर की दरों का निर्धारण तो संतद के द्वारा ही होना चाहिए, परन्तु इनका प्रशासन राज्यों द्वारा होना चाहिए और इन करों से जो आय प्राप्त हो वह राज्य-सरकारों को दी जाये।
- 131 अन्तराज्यीय व्यापार पर बिक्री-कर अन्तराज्यीय बिक्री के अन्तिम निर्यात पर लगाना चाहिए।
- 141 अन्तराज्यीय व्यापार पर कर की दर बहुत कम होनी चाहिए ताकि उप-भोक्ताओं पर कर-भार बहुत अधिक न पड़े और अन्तराज्यीय व्यापार को बहुत हानि न हो। आयोग ने सुझाव दिया कि कुछ विशेष वस्तुओं को

छोड़कर अन्तराज्यीय व्यापार की अन्य वस्तुओं पर । प्रतिशत की दर से बिक्री कर लगाया जाना चाहिए । । प्रतिशत की न्यूनतम दर तभी लगानी चाहिए जब कि वस्तु अन्य राज्यों में स्थित पंजीकृत व्यापारियों को बेची जा रही हो, परन्तु यदि वस्तु ऐसे व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं को बेची जा रही है जो पंजीकृत नहीं हैं तो उन पर उसी दर से कर लगाया जाये जो राज्य में प्रचलित है । इस तरह बिक्री कर के अपवर्जन से रोक लग जायेगी।

- 151 कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना देनी चाहिए जो अन्तराज्यीय व्यापार के लिए आवश्यक है और उन पर कर बहुत नीची दर से लगाया जाये जैसे 3 पाई प्रति स्क्वा का एक बिन्दु कर और वह भी वस्तु की अन्तिम बिक्री पर । इन वस्तुओं में आयोग ने कोफा, लोहा और इस्पात, कपास, कच्ची और पक्की आलें, तिलहन, तेल और जूट को विशेष महत्व की वस्तुएँ घोषित करके इन पर $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से एक बिन्दु बिक्री कर लगाने का सुझाव दिया । इन वस्तुओं पर इतनी नीची दर से कर लगाने का प्रस्ताव आयोग ने कदाचित् इती विचार से दिया कि ये कच्ची सामग्री की वस्तुएँ हैं और इनसे बनी हुई वस्तुओं का निर्यात अन्य राज्यों को होगा । यदि इन पर बहुत ऊँची दर से कर लगा दिया जाए तो अन्य राज्यों में रहने वाले उपभोक्ताओं पर बहुत अधिक कर का भार पड़ेगा ।

- 161 आयोग ने सुझाव दिया कि सन् 1952 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विस्तृत संख्या में वस्तुएँ कर मुक्त सूची में सम्मिलित कर ली गई हैं । अतएव इस सूची में उत्तम उपरोक्त वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी को निकाल देना चाहिए ।

- 171 आयोग ने सुझाव दिया कि विभिन्न राज्यों के बिक्री कर विभाग के अध्यक्षों की वर्ष में एक बार मीटिंग की जानी चाहिए, जिसमें वे विचार-विनिमय करें, अपने सामूहिक हितों पर वाद-विवाद करें और पारस्परिक हित की समस्याओं की विवेचना करें ताकि कर की व्यवस्था सरल हो जाये । ऐसी मीटिंग "अन्तराज्यीय करारोपण परिषद्" के नेतृत्व में होनी चाहिए ।

अन्तर्राज्यीय करारोपण परिषद् को विभिन्न राज्यों की कर व्यवस्था को सरल बनाने तथा उसमें एकत्वता लाने का प्रयास करना चाहिए ।

- 181 कर वंश की प्रवृत्ति को रोकने हेतु व्यवस्था एवं निरीक्षण को पहले की तुलना में कठोर किया जाए तथा उच्च अधिकारियों को आकस्मिक निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाए ।
- 191 आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में एक बिज्जी कर ट्रिब्यूनल की स्थापना की जानी चाहिए जो बिज्जी कर विभाग तथा व्यापारियों की अपीलों के बारे में अन्तिम निर्णय कर सकें ।
- 2101 केवल कुछ सुपरिभाषित वस्तुओं के वर्ग को ही बिज्जी कर से छूट प्रदान की जाए ।
- 1111 उद्योग एवं व्यापार से व्यवस्थित सम्पर्क के लिए बिज्जी कर विभाग द्वारा व्यापार एवं उद्योग के तथ्यों आदि से सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में एक बिज्जी कर तलाहकार समिति की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे व्यापार, उद्योग एवं व्यवसायों के हितों का प्रतिनिधित्व हो तथा जो बिज्जी कर समस्याओं का अध्ययन करें ।
- 1121 आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि बिज्जी कर प्रशासन की अलोकप्रियता को दूर करने के लिए उच्च अधिकारियों को विस्तृत अधिकार दिये जाने चाहिए। निरीक्षण कर्मचारी और अधिकारी पृथक-पृथक होने चाहिए, प्रत्येक बिज्जीकर विभाग में इन्स्टीमिनेन्ट तैय्य होना चाहिए, कर्मचारियों का व्यवहार व्यापारियों के साथ मधुर होना चाहिए तथा उन्हें व्यापारियों की समस्याओं पर उचित तलाह देनी चाहिए ।
- 1131 आयोग ने यह सुझाव दिया कि बिज्जी कर की केवल वस्तुओं तक ही सीमित रहना चाहिए तथा सेवाओं पर कर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे प्रशासन में कठिनाइयाँ आयेंगी तथा कर बचाने की सम्भावना बढ़ेगी ।

संविधान 1956 संशोधन अधिनियम, 1956

कराधान जांच आयोग की संस्तुतियों को व्यावहारिक रूप देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सन् 1956 में संविधान 1956 संशोधन अधिनियम पारित किया, जिससे बिजुली-कर के सम्बन्ध में व्याप्त भ्रान्तियों, कठिनाइयों तथा जटिलताओं का निवारण किया जा सके। इस संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किये गये²:

1. अन्तराज्यीय बिजुली पर कर लगाने का अधिकार केन्द्र को

संशोधन अधिनियम द्वारा संघीय सूची में एक नवीन प्रविष्टि 92-अ सम्मिलित की गई जो केन्द्रीय सरकार को, समाचार पत्रों के अतिरिक्त, अन्य समस्त माल के अन्तराज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य के दौरान हुए क्रय-विक्रय पर कर लगाने का अधिकार देती है।

2. राज्य सूची में परिवर्तन

संघीय सूची में प्रविष्टि 92-अ के सम्मिलित किये जाने पर राज्य सूची की प्रविष्टि 54 को पुनर्स्थापित किया गया ताकि राज्य सरकारों के बिजुली कर सम्बन्धी अधिकारों को उपर्युक्त 92-अ के अधीन रखा जा सके।

3. कर वसूली तथा कर को राज्यों को वापसी

संविधान के अनुच्छेद के 269 के प्रथम वाक्य में एक उपवाक्य-जी सम्मिलित किया गया। इस उपवाक्य के द्वारा भारत सरकार के अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल समाचार पत्रों के अतिरिक्त के क्रय या विक्रय पर कर लगाने के अधिकार को विस्तृत किया गया। द्वितीय वाक्य के अन्तर्गत इस कर को राज्यों को वापित देने की व्यवस्था है।

4. संसद को सिद्धान्त बनाने का अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 269 में नवीन वाक्य 131 जोड़ा गया जिसके द्वारा संसद

को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह उन सिद्धान्तों की रक्षा करे जिनके द्वारा इस बात का निर्धारण हो सके कि अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य के अन्तर्गत बिक्री कब मानी जावे ।

5. अनुच्छेद 286 में संशोधन

अनुच्छेद 286 में इस प्रकार संशोधन किया गया कि उसका संशोधित रूप निम्न प्रकार हो गया :

अनुच्छेद 286 : माल के क्रय-विक्रय पर कर लगाने सम्बन्धी प्रतिबन्ध

।अ। किसी राज्य का कोई भी कानून माल की निम्न प्रकार हुई बिक्री या खरीद पर न तो कोई कर लगायेगा और न ही कर लगाने के लिए अधिकृत करेगा : राज्य के बाहर बिक्री तथा भारतीय सीमा के अन्दर माल का आयात एवं सीमा से बाहर माल का निर्यात ।

।ब। तंतद कोई कानून पारित करके उन सिद्धान्तों का निर्माण कर सकती है जिनसे उपर्युक्त वाक्यांश में वर्णित माल की बिक्री या खरीद को निषिद्ध किया जा सके ।

।त। ऐसी वस्तुएँ जो तंतद द्वारा कानून पारित कर अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में विशेष महत्व की घोषित की जायें, के सम्बन्ध में राज्य द्वारा निर्मित कोई भी कानून जो या तो कर लगाता है या कर लगाने के लिए अधिकृत करता है, जहाँ तक कर लगाने, कर की दरें एवं कर के अन्य मुद्दों का सम्बन्ध है तंतद द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन होगा ।

इस प्रकार उपर्युक्त संशोधनों के फलस्वरूप तंतद को निम्न कार्यों के लिए अधिकृत किया गया :

।।। यह निश्चित करने के लिए सिद्धान्तों का निर्माण करना कि, माल का क्रय-विक्रय कब : ।अ। अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान, या ।ब। राज्य के बाहर, या ।त। भारत के अन्दर आयात या भारत से बाहर निर्यात के दौरान होता है ।

12। अन्तराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान हुई माल की बिक्री पर कर लगाने, संग्रह करने एवं उसका वितरण करने का प्रावधान करना ।

13। कतिपय वस्तुओं को अन्तराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अन्तर्गत विशेष महत्व की घोषित करना तथा उन शर्तों एवं प्रतिबन्धों का उल्लेख करना जिनका पालन राज्य सरकारें ऐसी विशेष महत्व की वस्तुओं पर कर लगाने के सम्बन्ध में कानून बनाते समय करेंगी ।

उपयुक्त संशोधनों के तन्दर्भ में ही तन् 1956 में "केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम" पारित किया गया ।

संविधान । छियालीसवाँ संशोधन । अधिनियम 1982

बिक्रीकर व्यवस्था में कुछ कमियों का समाधान करने तथा अन्तराज्यीय बिक्री कर में अपव्यय को रोकने की दृष्टि से तन् 1982 में संविधान में कुछ संशोधन किये गये । संविधान । छियालीसवाँ संशोधन । अधिनियम 1982 के द्वारा बिक्री कर के तन्दर्भ में संविधान में निम्न प्रकार से परिवर्तन किये गये :

13। अनुच्छेद 269 में परिवर्तन

इसके अनुसार यदि किसी माल का अन्तराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रेषण कर दिया गया हो, तो उस प्रेषण पर केन्द्रीय सरकार को कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है । माल का यह प्रेषण चाहे प्रेषण कर्ता को स्वयं को किया गया हो चाहे किसी अन्य व्यक्ति को हुआ हो ।

14। अनुच्छेद 286 में परिवर्तन

अब इस अनुच्छेद का रूप निम्न प्रकार हो गया है : वाक्यांश 13। राज्य सरकार का कोई भी कानून जो निम्न के सम्बन्ध में या तो कर लगाता है अथवा कर लगाने को अधिकृत करता है, जहाँ तक कर लगाने, कर की दरें स्वयं कर के अन्य मुद्दों का सम्बन्ध है, संसद के द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन होगा :

1।। ऐसे माल के क्रय या विक्रय पर जिन्हें संसद के द्वारा कानून पारित करके अन्तराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में विशेष महत्व का मान घोषित कर दिया गया है ।

121 मालों के क्रय या विक्रय पर ऐसा क्रय जो अनुच्छेद 366 के वाक्यांश 29 ए के उपवाक्य बी ती या डी में वर्णित कर की प्रकृति का हो ।

1त। अनुच्छेद 366 में परिवर्तन

संविधान के अनुच्छेद 366 में वाक्यांश 29 के आगे एक नया वाक्यांश 29 ए जोड़ा गया । यह नया वाक्यांश 29 ए निम्न प्रकार है :-

29 ए "मालों के क्रय या विक्रय पर कर" में शामिल है :

- 111 किसी नकद राशि, स्थगित भुगतान या अन्य किसी मुख्यवान प्रतिफल के बदले में मालों के स्वामित्व के हस्तान्तरण पर कर, यदि ऐसा हस्तान्तरण किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत हस्तान्तरण न हो ।
- 121 किसी कार्य अनुबन्ध के निष्पादन में प्रयुक्त सामग्री के स्वामित्व के हस्तान्तरण पर कर, चाहे वह सामग्री मालों के स्व में हो या अन्य किसी स्व में हो ।
- 131 किराया क्रय पर या स्थित भुगतान पद्धति के अन्तर्गत माल की सुपुर्दगी पर कर ।
- 141 किसी नकद राशि, स्थगित भुगतान या अन्य किसी मुख्यवान प्रतिफल के बदले में किसी भी उद्देश्य के लिए माल को प्रयोग में लेने के अधिकार के हस्तान्तरण पर कर ।
- 151 व्यक्तियों के किसी समुदाय या संघ जो समामेलित न हो । द्वारा अपने सदस्य को नकद राशि, स्थगित भुगतान या अन्य किसी मुख्यवान प्रतिफल के बदले माल की पूर्ति पर कर ।
- 161 सेवा के स्व में या अन्य किसी स्व में ऐसे मालों की पूर्ति पर कर, जो मानव उपभोग का तत्मान हो या कोई पेय पदार्थ हो । माल की यह पूर्ति नकद राशि, स्थगित भुगतान या अन्य किसी मुख्यवान प्रतिफल के बदले में हो सकती है ।

उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में ऐसे माल के हस्तान्तरण, सुपुर्दगी या पूर्ति को उस माल के हस्तान्तरण, सुपुर्दगी या पूर्ति करने वाले व्यक्ति के द्वारा उस माल की

बिक्री माना जायेगा तथा जिस व्यक्ति को उस माल का हस्तान्तरण, सुपुर्दगी या पूर्ति हुई है, उसे माल का क्रेता समझा जायेगा ।

1द। सातवीं अनुसूची में संशोधन

संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रथम सूची में वर्णित मदों में 92 ए के बाद एक नई मद 92 बी को जोड़ा गया है । यह मद निम्न प्रकार है :

92 बी - माल के प्रेषण कर, यदि वह प्रेषण अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुआ हो । माल का प्रेषण जाहे प्रेषक द्वारा स्वयं को किया गया हो या किसी अन्य व्यक्ति को किया गया हो ।

उपयुक्त संशोधनों के कारण सरकार को अब "कार्य अनुबन्ध के अन्तर्गत माल की बिक्री पर, प्रेषण बिक्री कर" आदि पर भी बिक्री कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया है ।

संक्षेप में वर्तमान समय में भारत में बिक्री कर को संवैधानिक व्यवस्था को निम्न प्रकार रखा जा सकता है :-

1अ। भारत में आयात होने वाले या यहाँ से निर्यात होने वाले माल के क्रय-विक्रय पर बिक्री कर नहीं लगाता है ।

1ब। विभिन्न राज्य सरकारें केवल उन्नी क्रय-विक्रय पर बिक्री कर लगा सकती हैं जो उनके राज्य में हुआ है । इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगभग सभी राज्यों में बिक्री कर अधिनियम पारित किये गये हैं । कुछ वस्तुओं को विशेष महत्व का माल घोषित किया गया है । इस माल पर राज्य सरकार बिक्री कर कुछ विशेष दशाओं में कुछ शर्तों तथा नियन्त्रणों के अधीन ही लगा सकती है । अपने राज्य के बाहर की बिक्री पर कोई राज्य सरकार बिक्री कर नहीं लगा सकती है ।

1त। अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के क्रय-विक्रय पर केवल केन्द्रीय सरकार ही बिक्री कर लगा सकती है । इस कर की व्यवस्था "केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम" के अन्तर्गत की गई है किन्तु फिर भी कर संग्रहण का कार्य विभिन्न राज्यों में सम्बन्धित राज्य सरकार ही करती है ।

अध्याय चतुर्थ

केन्द्रीय विज्ञान : परीक्षा, उद्देश्य एवं विशेषताएँ

अध्याय 4

केन्द्रीय बिड्डी कर : परिचय, उद्देश्य एवं विशेषतायें । भारतीय परिपेक्ष में।

संक्षिप्त परिचय

केन्द्रीय बिड्डीकर अधिनियम 1955 के अन्तर्गत भारत सरकार ने वस्तुओं के विक्रय पर बिड्डीकर लगाने का अधिकार कुछ अपवादों को छोड़कर प्रान्तीय सरकार को दिया गया तथा अन्तर्राज्यीय व्यापार में वस्तुओं की बिड्डी पर कर लगाने के प्रान्तीय सरकारों के अधिकारों पर इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रतिबन्ध नहीं था । स्वतन्त्रता के पश्चात् केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय सम्बन्धों का उल्लेख देश के संविधान में किया गया । इसके अन्तर्गत समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर लगाने एवं इसका संग्रह करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया । निम्न दशाओं में कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं दिया गया :

- 11। भारत की सीमाओं के बाहर व्यापार के सम्बन्ध में किया गया क्रय-विक्रय;
- 12। अन्य राज्यों में उपयोग के लिये की गई वस्तुओं की बिड्डी ;
- 13। अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य से सम्बन्धित विक्रय ।

कराधान जाँच आयोग, 1955 की संस्तुतियों के तन्दर्भ में मई 1956 में संविधान में एक संशोधन पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप अन्तर्राज्यीय क्रय-विक्रय के करारोपण को केन्द्र की तृप्ति में रक दिया गया और यह व्यवस्था की गई कि राज्य के अन्दर ऐसी वस्तुओं, जो अन्तर्राज्यीय व्यापार की दृष्टि से विशेष महत्व रखती हैं, के क्रय-विक्रय पर कर लगाने के राज्यों के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं । इस संशोधन के आधार पर केन्द्रीय बिड्डीकर अधिनियम तन् 1956 में पारित किया, जिसे 21 दिसम्बर, 1956 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई और यह अधिनियम 5 जनवरी, 1957 से लागू किया गया । इस अधिनियम में 18 धाराएँ हैं जो पाँच अध्यायों में विभाजित की गई हैं । प्रथम अध्याय, जिसमें पहली तथा दूसरी धाराएँ हैं, एक प्रारम्भिक अध्याय है । इसमें अधिनियम के लागू होने का समय, क्षेत्रीय सीमा तथा परिभाषाएँ दी गई हैं । अगले चार अध्यायों में इस अधिनियम को पारित करने के तीन प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए

समुचित व्यवस्था की गई हैं। अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य से सम्बन्धित धाराएँ 3, 4 तथा 5 की। जुलाई, 1957 से तथा दूरे और तीतरे उद्देश्यों से सम्बन्धित धाराओं की। अक्टूबर, 1958 से लागू किया गया।

केन्द्रीय बिजुली-कर अधिनियम के उद्देश्य

केन्द्रीय बिजुलीकर अधिनियम¹ के निर्माणधीन काल में इस अधिनियम द्वारा निम्न उद्देश्यों को पूरा करने पर सरकार की ओर से अत्यधिक जोर दिया गया:-

- 111 इस सम्बन्ध में सिद्धान्त निर्धारित करना कि जिस समय किसी वस्तु का क्रय-विक्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की प्रक्रिया में अथवा राज्य के बाहर अथवा आयात या निर्यात की प्रक्रिया में माना जायेगा ;
- 121 अन्तर्राज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में बेचे गये माल पर बिजुली कर लगाने, उसका संग्रह करने और राज्यों के मध्य वितरण करने के सम्बन्ध में सिद्धान्त निर्धारित करना ;
- 131 इन वस्तुओं को अन्तर्राज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण घोषित करना तथा उन वस्तुओं पर राज्यों द्वारा बिजुली कर वसूल करने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध एवं शर्तें निर्धारित करना।

केन्द्रीय बिजुली कर अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

केन्द्रीय बिजुली कर के क्षेत्र, प्रकृति एवं विशेषताओं को संक्षेप में निम्न प्रकार रखा जा सकता है :

अधिनियम की क्षेत्रीय सीमाएँ : प्रारम्भ में यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर शेष समस्त भारत में लागू किया गया था। तन् 1958 में इसको जम्मू और कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। तन् 1963 में इसको गोआ, दमन, दीव और पाण्डीचेरी में लागू किया गया। तन् 1972 में इसको नागालैण्ड के कोहिमा और मीकोकपुंग जिलों में भी लागू कर दिया गया। वर्तमान में यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू होता है।

कर की प्रकृति : केन्द्रीय बिड़्डीकर "सामान्य बिड़्डी कर" एवं "एक स्तरीय बिड़्डी कर" है ।

अन्तराज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में माल का क्रय-विक्रय : केन्द्रीय बिड़्डीकर अधिनियम के दूसरे अध्याय में धारा 3, 4 और 5 में उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है जिनके आधार पर यह निर्णित किया जा सके कि किसी माल का क्रय या विक्रय अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुआ है अथवा राज्य के बाहर या भीतर हुआ है अथवा आयात या निर्यात व्यापार के दौरान हुआ है । इन सिद्धान्तों को संक्षेप में निम्न प्रकार रखा जा सकता है :

1. अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल का क्रय-विक्रय : अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जब किसी माल का क्रय या विक्रय निम्नलिखित दो परिस्थितियों में से किसी भी प्रकार से किया जाए तो उसे अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल का क्रय-विक्रय माना जाता है :

1क। जब किसी माल का क्रय या विक्रय हो तथा उस क्रय-विक्रय के फलस्वरूप उस माल का एक राज्य से दूसरे राज्य में गमन हो : यह उल्लेखनीय है यदि किसी माल के गमन का प्रारम्भ तथा अन्त दोनों एक ही राज्य में हो, किन्तु गमन के दौरान उस माल को किसी दूसरे राज्य की सीमा में होकर गुजरना पड़े तो इस माल का अन्तराज्यीय गमन नहीं माना जायेगा । कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें उस माल का अन्तराज्यीय गमन तो होता है, किन्तु यह गमन उस माल के क्रय व विक्रय के परिणामस्वरूप नहीं होता है । अतः इन परिस्थितियों में उस माल का अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान क्रय या विक्रय नहीं माना जा सकता है ;

1ख। जब किसी व्यापारी के व्यवसाय के मुख्य कार्यालय से किसी दूसरे राज्य में स्थित शाखा को माल भेजा जाए या उस शाखा से मुख्य कार्यालय को माल भेजा जाए ;

1ब। जब किसी व्यापारी के व्यवसाय की एक शाखा से दूसरे राज्य में स्थित दूसरी शाखा को माल भेजा जाये ;

18। जब किसी व्यापारी के द्वारा कोई माल किसी दूसरे राज्य में स्थित प्रतिनिधि के पास भेजा जाये या उस प्रतिनिधि के द्वारा माल को व्यापारी के पास भेजा जाए ।

19। जब माल का विक्रय माल के अधिकार प्रलेख को उस समय हस्तान्तरित करके किया जाए तब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते समय मार्ग में हो ।

2. राज्य के अन्दर माल का क्रय अथवा विक्रय : अधिनियम की धारा 4121 के अन्तर्गत किसी माल का क्रय अथवा विक्रय उस राज्य के अन्दर हुआ माना जाता है जब माल निम्न समय इस राज्य के अन्दर रहता है :

1क। जब विशिष्ट अथवा निश्चित माल के क्रय अथवा विक्रय का अनुबन्ध किया जाता है तो माल के अनुबन्ध के समय ;

1ख। अनिश्चित या भावी वस्तुओं की दशा में क्रेता अथवा विक्रेता द्वारा विक्रय के अनुबन्ध के आधार पर माल के नियोजन या पृथक् करने के समय, चाहे दूसरे पक्ष की सहमति से नियोजन से पहले ली गयी है अथवा बाद में ।

यह ध्यान रहे कि यदि एक से अधिक स्थानों पर स्थित वस्तुओं के क्रय अथवा विक्रय के सम्बन्ध में एक ही अनुबन्ध किया जाता है, तो यह माना जायेगा जैसे प्रत्येक स्थान पर स्थित वस्तुओं के सम्बन्ध में अलग-अलग अनुबन्ध किये गये हैं ।

3. आयात या निर्यात व्यापार के दौरान माल का क्रय या विक्रय : ये निम्न दो हैं :

1क। निर्यात व्यापार के दौरान माल का क्रय-विक्रय धारा 5111 131 के अनुसार माल का क्रय-विक्रय भारत की सीमाओं के बाहर उस समय निर्यात हुआ माना जाता है जब ऐसा क्रय अथवा विक्रय या तो निर्यात का कारण होता है या माल का क्रय अथवा विक्रय भारत की सीमाओं के बाहर माल निकल जाने के बाद माल के स्वामित्व प्रलेखों के हस्तान्तरण द्वारा होता है । निर्यात व्यापार के तीन आवश्यक तत्त्व हैं -

1अ। विदेशी क्रेता से सम्बन्धित ;

- ।ब। माल के आयात-आयात के लिये सार्वजनिक वाहन का प्रयोग तथा
।त। विदेशी ठिकाना ।

।क। आयात की प्रक्रिया में माल का क्रय-विक्रय : धारा 5।2। के अनुसार माल का क्रय-विक्रय भारत की सीमाओं के अन्दर आयात की प्रक्रिया में हुआ माना जाता है। यदि क्रय-विक्रय या तो माल के आयात का कारण होता है या माल का क्रय-विक्रय भारत की सीमाओं के अन्दर माल आ जाने से पहले माल के स्वामित्व प्रलेखों के हस्तान्तरण द्वारा होता है ।

कर योग्य सीमा न होना : राज्य बिज्जी कर अधिनियमों की भाँति केन्द्रीय बिज्जी कर अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर योग्य सीमा नहीं है । केन्द्रीय बिज्जी कर अधिनियम की धारा 6।।। के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यापारी, जो अन्तराज्यीय व्यापार में वस्तुओं को बेचता है । विपुल शक्ति को छोड़कर। ऐसी सभी बिक्रियों पर कर चुकाने के लिए दायी होगा चाहे उसकी बिज्जी कितनी ही क्यों न हो । यह भी उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के अधीन व्यापारी द्वारा अन्तराज्यीय व्यापार में बेची गई प्रत्येक वस्तु की बिज्जी पर कर देय होगा चाहे सम्बन्धित राज्य के अन्दर ऐसी वस्तु की बिज्जी कर-मुक्त ही क्यों न हो ।

अनिवार्य पंजीकरण : प्रत्येक ऐसा व्यापारी जो अन्तराज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में माल का क्रय-विक्रय करता है । इस अधिनियम के अन्तर्गत कर देने के लिए उत्तरदायी है । ऐसे व्यापारी को अपना पंजीकरण कराना भी अनिवार्य है । यह उल्लेखनीय है कि कोई व्यापारी केन्द्रीय बिज्जी कर अधिनियम के अधीन कर चुकाने के लिए दायी न होने पर भी ऐच्छिक रूप से अपना पंजीकरण करा सकता है यदि :

।।। वह राज्य बिज्जी कर अधिनियम के अधीन कर चुकाने के लिए दायी है;
अथवा

।2। उसका व्यापारिक स्थान ऐसे राज्य में या राज्य के किसी ऐसे भाग में है जहाँ राज्य बिज्जी कर अधिनियम लागू नहीं होता है ; अथवा

13। राज्य बिड़ी कर अधिनियम के अधीन व्यापारी को कोर्ड खरीद अथवा बिड़ी कर से मुक्त है अथवा उसे इस सम्बन्ध में कोर्ड घुट या वापसी मिलती है ।

यह आवश्यक है कि पंजीकृत व्यापारी को पंजीकरण प्रमाण-पत्र अपने समस्त व्यापारिक संस्थानों, स्थानों पर प्रदर्शित करना चाहिए ।

व्यापारी की प्रतिभूति की व्यवस्था : यदि बिड़ीकर अधिकारी इस अधिनियम की धारा 7 (2ए) एवं (3ए) के अधीन कर की समुचित वसूली तथा निर्दिष्ट फार्मों के उचित प्रयोग एवं संरक्षण के लिए आवश्यक समझता है तो वह कारणों का लिखित रूप में उल्लेख करके पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रत्यक्ष में रहने के दौरान यदि पंजीकरण प्रमाण-पत्र पहले जारी किया जा चुका है। लिखित आदेश द्वारा व्यापारी से निर्धारित राशि की प्रतिभूति अथवा अतिरिक्त प्रतिभूति निर्धारित ढंग से देने को कह सकता है ।

अन्तर्राज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में विक्रय पर कर की दरें : भागों की अन्तर्राज्यीय विक्रयों पर केन्द्रीय बिड़ी कर सामान्यतः निम्न प्रकार वसूल किया जाता है :

1अ। यदि माल सरकार को बेचा गया है : यदि व्यापारी अन्तर्राज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में माल सरकार को बेचता है तथा विक्रेता व्यापारी "फार्म डी" में सरकार के अधिकृत क्रय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र बिड़ी कर अधिकारी के यहाँ दाखिल कर देता है तो बेती पण्यवस्तु पर कर की दर 4 प्रतिशत होगी ।

1ब। यदि माल पंजीकृत व्यापारी को बेचा गया है : यदि अन्तर्राज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में माल पंजीकृत व्यापारी को बेचा जाता है और विक्रेता व्यापारी क्रेता पंजीकृत व्यापारी से "फार्म डी" में निश्चित सूचना देते हुए ^{रकम} हस्ताक्षर करके एक घोषणा पत्र बिड़ी कर अधिकारी को दे देता है तो कर की दर 4 प्रतिशत होगी । यह उल्लेखनीय है कि प्रारम्भ में केन्द्रीय बिड़ीकर की सामान्य दर 1 प्रतिशत थी, धीरे-धीरे बढ़कर 4 प्रतिशत किया गया है । दर वृद्धि की व्यवस्था को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है ।

पंजीकृत व्यापारियों के लिए केन्द्रीय बिजली कर की दरें

घोषित वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर।

अवधि	1.7.57 से 31.3.63	1.4.63 से 30.6.66	1.7.66 से 30.6.75	1.7.75 से आगे
कर की दर प्रतिशत में।	1	2	3	4

केन्द्रीय बिजली कर के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं को अन्तराज्यीय व्यापार की दृष्टि से विशेष महत्व की वस्तुएँ घोषित किया गया है। इन वस्तुओं पर वर्तमान समय में कर की अधिकतम सीमा 4 प्रतिशत है, लेकिन व्यवहार में अनेक वस्तुओं पर इसे कम दर से भी लगाया गया है। उदाहरण के लिए साईकिल, ट्रैक्टर, निवाड़ इत्यादि पर केन्द्रीय बिजलीकर की दर 2 प्रतिशत है।²

1। यदि माल किसी अन्य व्यक्ति को बेचा गया है : यदि व्यापारी द्वारा अन्तराज्यीय व्यापार में माल का विक्रय गैर पंजीकृत व्यापारी को किया जाता है तो:

11। बेचा गया माल "घोषित माल" होने पर कर की दर उत कर की दो गुनी होगी जो दर "उपयुक्त राज्य" में ऐसे माल के क्रय-विक्रय पर लागू होती है ;

12। यदि बेचा गया माल "घोषित माल" के अलावा है तो कर की दर 10 प्रतिशत अथवा उपयुक्त राज्य में ऐसे माल के क्रय-विक्रय पर लागू दर, जो भी दोनों में अधिक हो, होगी।

अन्तराज्यीय विक्रयों पर केन्द्रीय बिजली कर के सम्बन्ध में निम्नलिखित छूटें स्वीकार्य भी उपलब्ध है :

सामान्य कर-मुक्तियाँ : यदि किसी माल का क्रय या विक्रय उपयुक्त राज्य के सामान्य बिजली-कर कानून के अनुसार "सामान्य रूप से कर मुक्त" हो तो उत माल की

2. Radhey Shyam Goyal : Rates & Interpretations of Sales Tax commodities under Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948 & Central Sales Tax Act, 1956, Page 292.

अन्तराज्यीय बिड्डी भी केन्द्रीय बिड्डी कर से मुक्त होगी। इसी प्रकार यदि किसी माल के क्रय या विक्रय पर उपयुक्त राज्य के सामान्य बिड्डीकर कानून के अनुसार सामान्य दर 4 प्रतिशत से कम है, तो उस माल की अन्तराज्यीय बिड्डी कर केन्द्रीय बिड्डीकर की दर भी वही होगी जो राज्य के बिड्डी कर के अनुसार निर्धारित है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कर-मुक्तिपत्र : यदि राज्य सरकार सार्वजनिक हित में ऐसा करना उचित समझती है तो वह सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन यह निर्देश कर सकती है कि निर्दिष्ट वस्तुओं पर या निर्दिष्ट व्यापारिक स्थान से अथवा निर्दिष्ट ज़ेरी के व्यवस्थितियों को अन्तराज्यीय व्यापार में माल बेचने पर केन्द्रीय बिड्डी कर नहीं लगेगा अथवा ^{धारा} 8111 तथा 8121 में वर्णित दरों की अपेक्षा कम दर से लगेगा।

पर्यावर्त या विक्रय राशि का निर्धारण : केन्द्रीय बिड्डीकर अधिनियम की धारा 8ए के अनुसार ^{पहले} किसी भी वर्ष में अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचे गये माल के विक्रय मूल्यों का योग ज्ञात किया जाता है फिर इस योग में से निम्नलिखित राशिओं को घटाकर कर योग्य बिड्डी ज्ञात की जाती है :

13। केन्द्रीय बिड्डी-कर की राशि : यदि व्यापारी द्वारा देता है बिड्डी कर की राशि विक्रय मूल्य में शामिल करके वसूल की जाती है तो निम्न सूत्र के आधार पर निकाली गयी कर की राशि को विक्रय मूल्य के योग में से घटा दिया जायेगा।³ यदि व्यापारी की विक्रय राशि अलग-अलग दरों से कर योग्य है तो उपयुक्त सूत्र अलग-अलग विक्रय पर अलग-अलग दर से प्रयोग किया जायेगा तथा इस प्रकार कर की कुछ राशि ज्ञात करके उसे कुल विक्रय मूल्य में से घटा दिया जायेगा। यदि पंजीकृत व्यापारी द्वारा कर

$$3. \text{ केन्द्रीय बिड्डी कर की राशि } = \frac{\text{कर की दर} \times \text{विक्रय मूल्यों का योग}}{100 + \text{बिड्डी कर की दर}}$$

के रूप में सक्रम की गई राशि को इस अधिनियम के अनुसार अन्य किसी प्रकार से घटा दिया गया है तो उपरोक्त सूत्र के आधार पर कोई कटौती नहीं दी जायेगी ।

।ब। वापस लौटाये गये माल का मूल्य : यदि क्रेता सुपुर्दगी की तिथि से 6 माह में विक्रेता को सम्पूर्ण या कुछ ऐसा माल वापस कर देता है जो अन्तर्राज्यीय बिक्री के अन्तर्गत बेचा गया है तो उसका मूल्य ।

।स। अन्य कटौतियाँ : ऐसी अन्य कटौतियाँ जो बाजार की शर्तों व्यापार की सुविधा तथा उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जाये ।

करारोपण एवं संग्रहण का अधिकार : केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम केन्द्रीय सरकार का अधिनियम है, लेकिन इसके अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर कर-निर्धारण करने तथा बिक्री कर वसूल करने का अधिकार राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है । यदि व्यापारी के व्यापार का स्थान एक हो तो केन्द्रीय बिक्रीकर का निर्धारण एवं वसूली उसी राज्य में होगा, जहाँ व्यापारी पंजीकृत है । लेकिन यदि एक व्यापारी के अनेक व्यापारिक स्थान है लेकिन सभी स्थान एक राज्य में हैं तो भी कर का निर्धारण एवं वसूली एक ही राज्य में होगा जहाँ व्यापारी पंजीकृत है किन्तु यदि किसी व्यापारी के अनेक व्यापारिक स्थान हो और अलग-अलग राज्यों में स्थित हो तो कर निर्धारण एवं वसूली किस राज्य सरकार द्वारा किया जाए । इसकी व्यवस्था अधिनियम की धारा 9111 में उल्लिखित की गई है ।

कर का संचालन एवं प्रशासन : धारा 9121 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए "सम्बन्धित राज्य" के बिक्री कर कानून के अधीन कर - निर्धारण एवं कर का संग्रह आदि करने के लिये अधिकृत अधिकारी केन्द्र सरकार की ओर से इस अधिनियम के अधीन भी कर-निर्धारण, पुनः कर निर्धारण, कर एवं अर्थदण्ड का संग्रह आदि कार्य उसी प्रकार करेंगे जैसे वे राज्य बिक्री कर कानून के अन्तर्गत करते हैं । इस आशय के लिये वे अधिकारी उन सब अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जो अधिकार उन्हें राज्य बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हैं ।

राज्य के सामान्य बिज्जी कर अधिनियम के प्रावधानों का लागू होना : केन्द्रीय बिज्जी-कर अधिनियम में बिज्जी-व्ययण दाखिल करने, अस्थायी कर-निर्धारण, कर का अग्रिम भुगतान, अपील, व्यापार के क्रेता का पंजीकरण, ताँदेलदारी संस्था में विघटन अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन पर कर-दायित्व, पुनर्विचार, प्रतिरोध, कर की वापसी इत्यादि के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में राज्य बिज्जी कर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।

कर से एकत्रित राशि का वितरण : धारा 9(3) के अनुसार बिज्जी-~~राज्य~~ ~~राज्य~~ में किसी वित्तीय वर्ष में किसी राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार की ओर से एकत्र की गयी कर तथा अर्थदण्ड की राशि उनी राज्य को दे दी जाती है तथा केन्द्र शासित क्षेत्र में इस प्रकार से एकत्र की गई राशि को भारत सरकार की "संचित निधि" में जमा कर दिया जाता है।

अधिनियम का उल्लंघन होने पर अर्थ दण्ड एवं तजार्ज : धारा 10 के अनुसार यदि कर दाता इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा नियम की अवहेलना करता है तो उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर उस पर अर्थदण्ड लगाया जा सकता है अथवा तजार्ज दी जा सकती है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों के नियमों में संगतता : धारा 13 के अनुसार केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें इस अधिनियम के संचालन के लिये नियम बना सकती हैं। राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये नियम इस अधिनियम के प्रावधानों में तथा केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अंतर्गत नहीं होने चाहिये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने के लिए एवं प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से तत्तद ने 1957 में कुछ नियम पारित किये। ये नियम-केन्द्रीय बिज्जीकर (पंजीयन एवं विद्युय राशि) नियम, 1957 कहलाते हैं। इन नियमों के द्वारा केन्द्रीय बिज्जी-कर अधिनियम के दूसरे उद्देश्य से सम्बन्धित धाराओं और तही दंग से प्रभावशाली बनाने की व्यवस्था की गई है।

वस्तुओं का वर्गीकरण : अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत वस्तुओं को घोषित वस्तु अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार में महत्वपूर्ण वस्तु तथा अन्य वस्तुओं में वर्गीकृत किया गया है। अधिनियम में उन वस्तुओं को अन्तर्राज्यीय व्यापार में महत्वपूर्ण घोषित किया गया है जो राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राज्यीय व्यापार में विशेष महत्व रखती हैं।

कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो अन्तर्राज्यीय व्यापार में विशेष महत्व रखती हैं। यह राष्ट्र एवं व्यापार दोनों के हित में है कि ऐसी वस्तुएँ उचित मूल्य पर उपलब्ध हों और उन पर बिज्जी कर का अधिक भार न डाला जाये। अतः केन्द्रीय बिज्जी कर अधिनियम में कुछ वस्तुओं को अन्तर्राज्यीय व्यापार में महत्वपूर्ण मान घोषित किया गया है और उस माल पर राज्यों द्वारा बिज्जी-कर वसूल करने के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध एवं शर्तें लगा दी गयी हैं। धारा 14 में उन मालों का वर्णन किया गया है जो केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान विशेष महत्व के घोषित किये हैं। अतः इनको घोषित माल कहा जाता है।⁴

घोषित वस्तुओं पर बिज्जी कर : घोषित वस्तुओं पर बिज्जीकर की दर अन्य वस्तुओं पर बिज्जी कर की दर की तुलना में कम रखी गयी है। यदि कोई राज्य अपने बिज्जी कर अधिनियम द्वारा घोषित माल के कृय-विक्रय पर बिज्जी कर लगाने का अधिकार प्रदान करता है तो वह अधिकार निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही हो सकता है:

13। कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य के सामान्य बिज्जी कर कानून के द्वारा

4. काष्ठान्न, कोफा, ज्वात, तृती वस्त्र, जूनी वस्त्र एवं कृत्रिम रेशम के वस्त्र, केसर तृती धागे को छोड़कर तृती धागा, असोषित तेल। कच्चा तेल, कच्चा पेट्रोलियम तेल, रात मिश्रित छन्नि से प्राप्त कच्चा तेल, चमड़ा और छतें। ये कच्ची अथवा अपनी परिष्कृत। ताक की हुई। अवस्था में हो सकती है।, लोहा एवं त्पात, जूट। पट्टन।-गाँठ में बंधी हुई या अन्य प्रकार से, तिलहन, दालें, चीनी, तम्बाकू, रेयन या कृत्रिम रेशम के कपड़े।

राज्य के भीतर इन मालों के क्रय या विक्रय पर 4 प्रतिशत से अधिक दर पर कर नहीं लगा सकती है तथा यह एक बिन्दु कर ही हो सकता है ।

।ब। यदि राज्य बिड़्डी कर अधिनियम के अधीन राज्य के अन्दर घोषित वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर लगा दिया जाता है और बाट में इन वस्तुओं को अन्तराज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में दुबारा बेच दिया जाता है तथा इस अन्तराज्यीय बिड़्डी पर केन्द्रीय बिड़्डी कर चुका दिया जाता है तो राज्य बिड़्डी कर अधिनियम के अधीन लगाया गया कर अन्तराज्यीय व्यापार में ऐसी बिड़्डी करने वाले व्यक्ति को निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर वापस लौटा दिया जायेगा ।

।त। यदि किसी राज्य में धान की करीद या बिड़्डी पर कर लगा दिया जाता है तथा बाट में उत धान से निकाले गये चावल पर कर लगाया जाता है तो चावल पर लगाये जाने वाले कर में ते पहले धान पर लगाया कर घटा दिया जायेगा तथा शेष राशि ही वसूल की जायेगी ।

केन्द्रीय बिड़्डी कर अधिनियम की धारा 15 के द्वारा राज्य सरकारों पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । घोषित मालों में ते कुछ माल तो ऐसे हैं जिनका उत्पादन कुछ विशेष राज्यों में ही होता है, किन्तु इसका उपभोग अन्य राज्यों में अधिक होता है या वे अन्य राज्यों में स्थित उद्योगों के लिये कच्चे माल के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं । जैसे - चीनी, तूती कपड़ा का उत्पादन कुछ विशेष राज्यों में ही होता है, किन्तु इनका उपभोग सभी राज्यों में किया जाता है । यदि इन मालों पर प्रतिबन्ध न हों, तो जिन राज्यों में इनका उत्पादन होता है, वहाँ की सरकारें अपनी आगम में वृद्धि करने के प्रलोभन में आकर इन मालों पर बिड़्डी कर की दरें बढ़ा सकती हैं या एक से अधिक बिन्दुओं पर बिड़्डी कर लगा सकती हैं, इससे इन राज्यों की आय तो बढ़ जायेगी, परन्तु इससे अन्य सभी राज्यों के उपभोक्ताओं को माल महंगा मिलेगा । इससे अन्य राज्यों में स्थित वे उद्योग भी प्रभावित होंगे, जिनमें उपरोक्त घोषित माल कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है । अतः बिड़्डी कर बढ़ाने की इस प्रवृत्ति का प्रभाव उद्योग धन्यों पर, निर्यात एवं जनताधारण पर भी पड़ेगा व समूचे देश की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो जायेगी । देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । इसी उद्देश्य से राज्य सरकार के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ।

केन्द्रीय बिजली-कर से आगम की प्रवृत्तियाँ

देश में केन्द्रीय बिजली कर अधिनियम सन् 1957 में लागू हुआ और इसके प्राप्त आगम में निरन्तर वृद्धि होती रही है। यह उल्लेखनीय है कि राजकीय प्रकाशनों में इसके पूर्ण, विस्तृत और व्यवस्थित तमकों का अभाव है, लेकिन फिर भी जो तमक उपलब्ध हैं, उनसे कर आगम की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जा सकता है। इन तमकों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 4।

राज्यों में केन्द्रीय बिजलीकर अधिनियम के अन्तर्गत वर्षवार बिजलीकर संग्रह

। करोड़ रुपये में।

वर्ष	कर-राशि	वर्ष	कर-राशि
1960-61	22.49	1976-77	4651.19
1967-68	101.36	1977-78	474.20
1968-69	100.07	1978-79	547.50
1969-70	126.92	1979-80	613.06
1970-71	158.38	1980-81	720.04
1971-72	159.25	1981-82	970.41
1972-73	202.98	1982-83	1014.02
1973-74	212.21	1983-84	1047.08
1974-75	300.78	1984-85	1287.07
1975-76	374.70	1985-86	1423.99

स्रोत : रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया क्वैटिन अक्टूबर 1962, जून 1969, अगस्त 1970, अगस्त 1971, सितम्बर 1972, जून 1973, सितम्बर 1974, सितम्बर 1975, दिसम्बर 1976, सितम्बर 1978, अक्टूबर 1979, अक्टूबर 1980, अगस्त 1981, सितम्बर 1982, अक्टूबर 1983, अक्टूबर 1984, नवम्बर 1985 एवं अप्रत्यक्ष करा-रोपण जयि समिति प्रतिवेदन भाग-21, जनवरी 1978, पृष्ठ 440 पर आधारित।

राज्य सरकारों की केन्द्रीय बिछी कर से आगम की वास्तविक राशियाँ तालिका नं० ५-१ में दी गई राशियों से अधिक हो सकती हैं क्योंकि विभिन्न वर्षों में भिन्न-भिन्न राज्यों के समक उपलब्ध नहीं हो सके हैं और कुछ राज्यों की दशा में केन्द्रीय बिछी कर की राशि के समक अलग से उपलब्ध नहीं हैं और कुल बिछी कर में शामिल है ।

तालिका नं० ५-१ में केन्द्र शासित क्षेत्रों को प्राप्त केन्द्रीय बिछी कर से आगम शामिल नहीं है ।

यद्यपि विभिन्न राजकीय प्रकाशनों में केन्द्रीय बिछी कर से सम्बन्धित समकों में व्यापक भिन्नता रही है लेकिन समक स्रोतों में एकत्वता बनाये रखने के लिए लगभग सभी समक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया क्लेडिन से लिये गये हैं, लेकिन तन् 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के समक अप्रुत्फुल कर जाँच समिति 1 जनवरी 1978 के प्रतिवेदन से लिये गये हैं । इसका कारण यह है कि प्रतिवेदन में यह समक योग के रूप में दिये गये हैं, जबकि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया क्लेडिन में राज्यवार दिये गये हैं और उनमें कई राज्यों के समक अनुपलब्ध दिखाये गये हैं ।

तालिका नं० ५-१ के विश्लेषण से स्पष्ट है कि तन् 1960-61 में इस कर से आगम 22.49 करोड़ रुपये थी जो तन् 1967-68 में बढ़कर 101.36 करोड़ रुपये हो गई । तन् 1968-69 में इस आगम में लगभग स्थिरता रही, लेकिन इसके पश्चात् धीमी गति से बढ़ता हुआ यह कर तन् 1973-74 में 212.21 करोड़ रुपये हो गया । इसके पश्चात् तीन वर्षों में ही इस कर से आगम इतनी तेजी से बढ़ी कि यह 1973-74 की तुलना में 1976-77 में दो गुने से अधिक [465.19] करोड़ रुपये हो गया । तन् 1980-81 से इस कर के आगम में वृद्धि की दर पर्याप्त ऊँची रही है और तन् 1983-84 में यह राशि 1047.08 करोड़ रुपये हो गयी । तन् 1984-85 और 1985-86 के तथोचित एवं कपट अनुमानों में इस कर से लगातार बढ़ते हुए आगम के समक प्रस्तुत किये गये हैं जो क्रमशः 1287.07 और 1423.99 करोड़ रुपये हैं । यहाँ इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि आगम में वृद्धि का कारण केवल बिछी की राशि में वृद्धि या कर-क्षमता की प्रभावशीलता में वृद्धि ही नहीं है बल्कि समय-समय पर इस कर की दर में वृद्धि की गई है । प्रारम्भ में इस कर की दर मात्र

1. प्रतिपात थी जो तन् 1963 में 2 प्रतिपात, तन् 1966 में 3 प्रतिपात और तन् 1975 में 4 प्रतिपात कर दी गई है।¹

केन्द्रीय बिजुली कर अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय बिजुलीकर का राज्यवार आगम संग्रह तालिका नं० 5-2 में दर्शाया गया है।

तन् 1970-71, 1971-72 एवं 1972-73 के समकों की योग राशि जो कोष्ठक में दिये हुए हैं। व्यक्तिगत राज्यों के समकों के योग जो कोष्ठक में नहीं हैं। ते भिन्न है, क्योंकि इनमें कई राज्यों के समक अनुपलब्ध है। जबकि योग की राशि कोष्ठक वाली। अप्रत्यक्ष कराधान जांच आयोग के प्रतिवेदन जनवरी 1978। से उपलब्ध हुई गई है।

तन् 1973-74 के व्यक्तिगत राज्यों के समकों का योग 21471 लाख रुपये होता है लेकिन रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन तथा अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति के प्रतिवेदन, दोनों में ही, 21221 लाख रुपये दिया गया है। अतः किसी राज्य की राशि में ही त्रुटि की मान्यता करके योग को यथावत मान लिया गया है।

प्रस्तुत तालिका में उत्तर प्रदेश के समक और उत्तर प्रदेश में बिजुली कर अध्याय (5) में उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय बिजुली कर के समकों में कहीं-कहीं भिन्नताएँ हैं और पूर्ण प्रयास करने पर भी इन भिन्नताओं को समाप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि प्रस्तुत अध्याय में समक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन से लिये गये हैं जिनमें सभी राज्यों के समक उपलब्ध थे। जबकि "उत्तर-प्रदेश में बिजुलीकर" अध्याय 5। में बिजुली कर के समक उत्तर प्रदेश बिजुली कर विभाग द्वारा प्रकाशित "सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1983-84" से लिये गये हैं और उत्तर प्रदेश की दशा में जिन्हें अधिक विश्वसनीय माना जाना स्वाभाविक है।

प्रस्तुत तालिका में जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, त्रिफुकम और त्रिपुरा राज्यों के केन्द्रीय बिजुली कर आगम को पृथक से नहीं दिखाया जा सका है क्योंकि रिजर्व बैंक आफ

केन्द्रीय विद्युत् से राज्यवार एवं वर्षार आगम

लाख किलो वॉट

राज्य का नाम	1960-61	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76
1. आन्ध्र प्रदेश	44	436	216	317	362	अनु०	491	957	1936	2439
2. असम	3	51	50	50	60	60	128	170	437	699
3. बिहार	268	740	अनु०	अनु०	998	786	अनु०	674	1049	1420
4. गुजरात	88	764	934	1150	1290	1497	अनु०	1865	2787	3353
5. हरियाणा	-	अनु०	अनु०	875	अनु०	अनु०	अनु०	1245	1463	1822
6. हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	2	12	8	14	16	20
7. कर्नाटक	63	244	409	661	591	727	1110	1285	1712	2305
8. केरल	80	262	246	288	357	394	465	501	632	818
9. मध्य प्रदेश	107	766	809	1002	1064	1110	1398	1614	2114	2743
10. महाराष्ट्र	488	2418	2545	3041	3743	3957	4476	5591	7101	8598
11. मेघालय	-	-	-	-	अनु०	अनु०	5	3	4	7
12. नागालैण्ड	-	-	3	अनु०	अनु०	अनु०	अनु०	अनु०	1	1
13. उत्तीरा	48	422	430	497	635	अनु०	714	832	686	791
14. पंजाब	135	437	680	697	882	774	871	1017	1751	1700
15. राजस्थान	28	256	247	261	333	380	471	587	810	1088
16. तमिलनाडु	228	1016	1036	1239	1379	1694	अनु०	2082	2887	3327
17. उत्तर प्रदेश	88	356	347	399	501	509	628	527	1055	1658
18. पश्चिमी बंगाल	581	1968	2055	2207	2525	2230	2675	2507	3637	4681
योग	2249	10136	10007	12692	14722	14130	13440	21471	30078	37470
					15838	15925	20298	21221		

साल खर्चों में।

राज्य का नाम	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
1. आन्ध्र प्रदेश	1990	1671	1870	2131	3313	7618	6639	7287	8500	10000
2. आसम	637	655	अनु०	251	अनु०	अनु०	1776	2919	2920	3029
3. बिहार	1556	2340	1756	273	2192	अनु०	5101	अनु०	8760	9636
4. गुजरात	4567	4997	5571	6851	9240	10519	11112	11301	12891	13500
5. हरियाणा	2721	2723	3103	3682	अनु०	5546	6122	6628	7500	8295
6. हिमाचल प्रदेश	27	32	37	72	79	117	144	146	127	169
7. कर्नाटक	2766	3010	3975	3753	4661	7866	7362	7404	8300	9300
8. केरल	1042	1105	1404	1502	2143	2135	1911	2334	3530	4039
9. मध्य प्रदेश	3125	2810	3533	3870	4425	6469	5784	7391	8900	9612
10. महाराष्ट्र	11215	11137	13845	15836	18937	22486	23313	24316	26494	28688
11. मेघालय	8	14	112	14	35	22	38	91	60	77
12. नागालैण्ड	1	1	अनु०	3	अनु०	अनु०	अनु०	अनु०	अनु०	अनु०
13. उड़ीसा	1549	1690	1618	1953	2026	2614	2335	2453	3104	3957
14. पंजाब	1898	2680	2458	2939	3414	4296	अनु०	अनु०	अनु०	अनु०
15. राजस्थान	1426	1463	1706	1768	1622	2107	2344	2275	2758	3075
16. तमिळनाडू	4242	4290	4984	6245	8559	9547	10159	11835	12700	14022
17. उत्तर प्रदेश	2347	1985	2301	2197	2819	4448	5227	5437	6163	6500
18. पश्चिमी बंगाल	5402	4867	6477	7966	8539	11251	12035	12970	16000	18500
योग	46519	47420	54750	61306	72004	97041	101402	104708	128707	142399

स्रोत : विभिन्न वर्षों के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया क्वैटियों के आधार पर । पूर्णकृत माह एवं वर्ष ।
अनु० = अनुमान

इण्डिया बुलेटिन में इन राज्यों के केन्द्रीय बिजुली कर के समक या तो अनुपलब्ध दिखाये गये हैं या सामान्य बिजुलीकर एवं कुल बिजुली कर में जोड़कर दिखाये गये हैं।

तालिका नं० 4.2 के अप्लोकेन से स्पष्ट है कि कुछ अपवादों को छोड़कर इस कर से प्राप्त आगम में प्रायः सभी राज्यों में निरन्तर वृद्धि होती रही है। राज्यवार विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि तन् 1967-68 से महाराष्ट्र राज्य कर आगम की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा है। देश में केन्द्रीय बिजुली कर के कुल आगम का लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक भाग अकेला महाराष्ट्र राज्य ही अर्जित करता रहा है।

यद्यपि तन् 1960-61 में केन्द्रीय बिजुली कर से आगम में प्रथम स्थान परिचमी कंगाल का था लेकिन तन् 1967-68 से इसका स्थान महाराष्ट्र के पश्चात् लगातार दूसरा बना रहा है और इसका भाग देश में केन्द्रीय बिजुली कर के कुल आगम में 10 से 15 प्रतिशत तक उच्चावधित होता रहा है और कुछ वर्षों में यह 20 प्रतिशत तक पहुँच गया था। महाराष्ट्र में तन् 1977-78 को छोड़कर लगातार कर आगम में वृद्धि का क्रम रहा है, लेकिन परिचमी कंगाल में दीर्घकालीन प्रवृत्ति बढ़ने की होते हुए भी तन् 1971-72, 1973-74 तथा 1977-78 में कर आगम में गत वर्षों की तुलना में कमी आयी थी।

महाराष्ट्र और परिचमी कंगाल के पश्चात् गुजरात और तमिलनाडू ऐसे राज्य हैं जिनका इस कर-आगम की दृष्टि से तीसरे और चौथे स्थान पर अधिकार बना रहा है, परन्तु यह स्थान विभिन्न वर्षों में दोनों राज्यों में परिवर्तित होता रहा है। केन्द्रीय बिजुलीकर के आगम की राशि की दृष्टि से अन्य उल्लेखनीय राज्य बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ में इस कर से सीमित आय प्राप्त होती थी लेकिन तन् 1973-74 के पश्चात् तेजी से वृद्धि हुई है।

केन्द्रीय बिजुली कर के राज्यवार विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि इस कर से देश के विकसित राज्यों को विकाशशील और पिछड़े राज्यों की लागत पर लाभ हुआ है। इस स्थिति को संक्षिप्त रूप में तालिका नं० 4.3 में दर्शाया गया है।

इस तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि देश में केन्द्रीय बिजुली कर आगम का लगभग 2/3 भाग देश के 8 विकसित एवं विकाशशील राज्यों को प्राप्त हो रहा है और

तालिका नं० 4.3

केन्द्रीय कृषीकरण आगम में राज्यों की तुलनात्मक स्थिति
उपलब्ध तमकों के योग में प्रतिशत के रूप में भाग।

राज्य का नाम	1960-61	1970-71	1980-81	1983-84	1984-85 तमकों में प्रतिशत	1985-86 तमकों में प्रतिशत
अ। औद्योगिक						
विकसित राज्य						
1. महाराष्ट्र	21.70	25.42	26.30	23.23	20.59	20.15
2. प० बंगाल	25.83	17.15	11.86	12.39	12.43	12.99
3. तमिलनाडु	10.14	9.37	11.89	11.30	9.87	9.85
4. गुजरात	3.91	8.76	12.83	10.79	10.02	9.48
5. हरियाणा	-	-	-	6.33	5.83	5.83
6. पंजाब	6.00	5.99	4.74	-	-	-
योग	67.58	66.69	66.62	64.04	58.74	58.30
ब। विकासशील राज्य						
1. कर्नाटक	2.80	4.01	6.48	7.08	6.46	6.53
2. केरल	3.58	2.43	2.98	2.30	2.75	2.84
योग	6.38	6.44	9.46	9.38	9.21	9.37
ग। औद्योगिक						
पिछड़े राज्य						
1. आन्ध्र प्रदेश	1.95	2.46	4.60	6.88	6.60	7.02
2. मध्य प्रदेश	4.76	7.23	6.16	7.06	6.92	6.75
3. बिहार	11.92	6.78	4.04	-	6.82	6.77
4. उत्तर प्रदेश	3.91	3.40	3.93	5.19	4.79	4.57
5. उड़ीसा	2.13	4.32	2.82	2.35	2.41	2.79
6. राजस्थान	1.24	2.26	2.26	2.17	2.14	2.20
7. असम	0.13	0.41	-	2.79	2.27	2.13
8. हिमाचल प्रदेश	-	0.01	0.11	0.14	0.10	0.10
योग	26.04	26.87	23.92	26.58	32.05	32.33
कुल योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत : तालिका नं० 4.2 में दिये गये तमकों के आधार पर परिकल्पित ।

मात्र 1/3 भाग शेष अन्य सभी राज्यों को प्राप्त होता है।

जहाँ तक केन्द्रशासित क्षेत्रों का प्रश्न है, इनमें नई दिल्ली के सम्बन्ध में ही विस्तृत एवं क्रमबद्ध समक उपलब्ध हैं जिन्हें तालिका नं० 4.4 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका नं० 4.4

केन्द्रीय बिजलीकरण अधिनियम के अन्तर्गत वर्षवार बिजली कर संग्रह

वर्ष	करोड़ रुपये में	वर्ष	करोड़ रुपये में	वर्ष	करोड़ रुपये में
1957-58	0.56	1966-67	04.67	1975-76	26.97
1958-59	1.15	1967-68	05.66	1976-77	33.88
1959-60	1.18	1968-69	06.61	1977-78	36.70
1960-61	1.36	1969-70	06.91	1978-79	43.78
1961-62	1.50	1970-71	07.98	1979-80	52.73
1962-63	1.68	1971-72	08.51	1980-81	62.62
1963-64	2.72	1972-73	10.40	1981-82	73.07
1964-65	3.31	1973-74	13.28	1982-83	77.00
1965-66	3.66	1974-75	18.70	1983-84	83.99

स्रोत : आयुक्त बिजलीकरण नई दिल्ली। त्रिमासिक अनुभाग : बिजली कर विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन 1983-84, पृष्ठ 28-29.

इस तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि नई दिल्ली को इस कर से निरन्तर बढ़ती हुई और महत्वपूर्ण कर आगम प्राप्त हुई है। तन् 1957-58 में दिल्ली को इस कर से मात्र 56 लाख रुपये की आगम प्राप्त हुई थी जो तन् 1958-59 में बढ़कर 1.15 करोड़ रुपये हो गयी और तन् 1983-84 में इस कर से दिल्ली को 83.99 करोड़ रुपये की आगम हुई है। इस दृष्टि से यदि राज्यों को भी ध्यान में रखा जाए तो तन् 1983-84 में केन्द्रीय बिजली कर आगम की दृष्टि से महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात के पश्चात् इसका पाँचवा स्थान था। स्पष्ट है कि नई दिल्ली देश की एक बड़ी और महत्वपूर्ण व्यापारिक मण्डी है, जिससे देश के सभी भागों का व्यापार होता है और इस कारण नई दिल्ली को इस कर से पर्याप्त आय प्राप्त होती है।

केन्द्रीय बिजलीकर आगम के विश्लेषण से स्पष्ट है कि देश में कर आगम के अन्य उत्पादक वस्तुओं की भाँति इस कर से प्राप्त आगम में भी निरन्तर और उल्लेखनीय वृद्धि होती रही है और इस वृद्धि के तीन मुख्य आधार रहे हैं : बिजली कर की राशि में निरन्तर वृद्धि, अन्तराज्यीय व्यवहारों पर कर आरोपण की प्रभावशीलता में वृद्धि तथा केन्द्रीय बिजलीकर की दर को मात्र 1 प्रतिशत से धीरे-धीरे बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर देना । यद्यपि बिजलीकर की धारणा के पीछे इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि यह कर उपभोक्ता राज्य में बिजली होने पर लगना चाहिए लेकिन उत्पादक राज्य को भी अपने द्वारा उत्पादित या निर्मित वस्तुओं के अन्तराज्यीय व्यवहार में कुछ हिस्सा मिलने के आधार पर केन्द्रीय बिजलीकर का औचित्य सिद्ध किया गया । केन्द्रीय बिजलीकर की राज्यवार प्रवृत्तियों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यह कर क्षेत्रीय दृष्टि से आर्थिक विषमताएँ उत्पन्न करता है क्योंकि इस कर से उन्हीं राज्यों को अधिक लाभ होता है जिनमें विस्तृत औद्योगिक आधार हो या पर्याप्त कृषि आधिक्य हो और जिन्हें अन्य राज्यों को भेजा जा सके । तमकों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय बिजलीकर आगम का लगभग 2/3 भाग देश के आठ विकसित और विकसितशील राज्यों को प्राप्त होता है और इस कर आगम में पहले चार स्थान औद्योगिक विकसित राज्यों - महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात के ही रहे हैं । यह संयोग की बात है कि विशाल लोह एवं इस्पात कारखानों के कारण बिहार और मध्य प्रदेश को भी इस कर से पर्याप्त आगम मिल जाता है ।

केन्द्रीय बिजली कर की दरों में समय-समय पर जो वृद्धि की जाती रही है, उसके कारण बिजलीकर की उत्पादन शक्ति से वह भिन्नता समाप्त हो जाती है जिसके आधार पर बिजलीकर मुख्यतः राज्य विशेष में किये जाने वाले उपभोग पर लगाया जाना चाहिए । प्रारम्भ में केन्द्रीय बिजलीकर की दर को 1 प्रतिशत के निम्नतम स्तर पर निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि वहाँ एक ओर उत्पादक राज्य को कुछ आगम की प्राप्ति हो जाए, वहाँ दूसरी ओर आयातक राज्य के निवासियों पर इसका अनावश्यक भार न पड़े, लेकिन राज्यों के निरन्तर बढ़ते हुए दबावों के कारण यह दर 1 प्रतिशत से क्रमिक रूप से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी गई । इस प्रकार इससे एक ओर तो कम विकसित राज्यों से

अधिक विकसित राज्यों को वित्तीय संसाधनों का प्रवाह हो रहा है, वहाँ दूसरी ओर अनेक उत्पादक इतने कर को बचाने की दृष्टि से अन्य राज्यों में अपने विपणन केन्द्रों या भंडारण केन्द्रों के नाम से मान भेजते हैं। इतने लघु उत्पादकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके साधन इतने पर्याप्त नहीं होते कि वे अपनी शाखा या विपणन केन्द्र अन्य राज्यों में स्थापित कर सकें।

यह भी उल्लेखनीय है कि उत्पादक कार्यों में प्रयुक्त आगतों पर केन्द्रीय बिजुलीकर और स्थानीय बिजुलीकर की दरों में अन्तर होने के कारण व्यापार का अनावश्यक विपथन (Diversification) होता है। जिन राज्यों में आगतों पर बिजुली कर की दर अधिक होती है, वे ऐसे अन्य राज्यों से अपना कच्चा माल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जहाँ कर की दर कम हो। उदाहरण के लिए तमिळनाडु में ट्रांसफोर्मर तेल पर 8 प्रतिशत का बिजुलीकर है, अतः वहाँ के उत्पादक उसे अन्य राज्यों से 4 प्रतिशत केन्द्रीय बिजुलीकर का भुगतान करके प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी रसायन उत्पादन करने वाली फैक्टरियाँ अपना अधिकांश उत्पादन बिहार के ऐसे कारखानों को बेचती हैं जो इन रसायनों का प्रयोग अपने उत्पादनों में आगतों के रूप में करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में इन रसायन आगतों का प्रयोग करने वाली फैक्टरियाँ मुबरात से रसायन मँगाना पतन्द करती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में रसायन पर कर की दर अन्तराज्यीय बिजुलीकर की 4 प्रतिशत की दर से अधिक है।⁶ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि अन्तराज्यीय व्यापार के लिए कर के अतिरिक्त उत्पादक के मूल्य और क्तिम भी उत्तरदायी होती है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि यदि क्तिम और मूल्य लगभग समान हो और केन्द्रीय बिजुलीकर तथा राज्य बिजुलीकर की दरों में पर्याप्त अन्तर हो तो व्यापार का अनावश्यक विपथन स्वाभाविक है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अग्रुप्प कर बाँच समिति।डा समिति। ने यह सुझाव दिया था कि केन्द्रीय बिजुलीकर की दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया जाए लेकिन राज्य सरकारों ने इस सुझाव पर पूर्णतया असहमति प्रकट की, क्योंकि वे इस कर

आगम को आय के एक उपयोगी स्रोत के रूप में मानने लगे हैं । जहाँ तक केन्द्रीय बिक्री कर की व्यवस्था में सुधार का प्रश्न है । यह इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि बिक्री कर व्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन या प्रतिस्थापन किया जाता है, क्योंकि यदि बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाये तो उत्पादित और निर्मित वस्तुओं पर केन्द्रीय बिक्री कर की अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी और यदि ऐसा नहीं होता तो आर्थिक निष्पक्षता के आधार पर केन्द्रीय बिक्री कर की दरों को विवेकपूर्ण और राज्य बिक्री कर की दरों को उसके अनुस्यू एवं संगत करना होगा ।

-----: 0 :-----

अध्याय पंचम

उत्तर प्रदेश में कृषि

अध्याय-5

उत्तर प्रदेश में बिड़ी कर

राजकीय आय के स्रोत के रूप में बिड़ी कर को महत्वपूर्ण स्थान देते हुये उत्तर प्रदेश में इसका शुभारम्भ 1948 में किया गया । इस तन्दर्भ में 27 फरवरी तन् 1948 को यहाँ विधान सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया । जो तन् 1948-49 में पारित होकर एक अधिनियम बन गया । यह अधिनियम "उत्तर प्रदेश बिड़ी कर अधिनियम 1948" के नाम से जाना जाता है और 1 अप्रैल, 1948 से कुछ दरियाततों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में लागू हुआ है । सरकार ने राज्य में बिड़ी कर लगाने के लिए निम्न ढलीनें प्रस्तुत की । राज्य सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए विशाल योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं । इनके कारण राज्य सरकार का व्यय काफी बढ़ गया है, जिसकी पूर्ति के लिए एक साधन के रूप में बिड़ी कर आवश्यक था । नशाबन्दी योजना के कारण उत्पादन शुरू से प्राप्त राज्य सरकार के राजस्व में कमी हुई है, जिसकी क्षतिपूर्ति के रूप में एक नया कर लगाना आवश्यक है । राज्य के काय्दम और उत्तरदायित्वों में वृद्धि की पूर्ति के लिए भी राजस्व में वृद्धि करना आवश्यक है ।¹

उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों के अनुभव से लाभ उठाते हुये समय-समय पर इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये । प्रारम्भ में कर की दर 2 पैसे प्रति त्पया थी, जो कुछ वस्तुओं पर एक बिन्दु प्रणाली से और कुछ वस्तुओं पर बह बिन्दु प्रणाली से निर्धारित की गई थी । इसके अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं पर 3 पैसे से लेकर 6 पैसे प्रति त्पया तक बिड़ी कर लगाया गया था । 25,000 त्पये से कम कुय विक्रय करने वाले व्यवसायियों को कर से मुक्त रखा गया था । न्यूनतम कर रहित सीमा 15,000 त्पये थी । अनाज, आटा, तूजी, मैदा, घी, तेल आदि वस्तुओं की बिड़ी पर कर नहीं लगाया गया था । तन् 1956 में उत्तर प्रदेश विधान सभा ने एक "बिड़ी कर संशोधन" विधेयक पारित किया था, जिसके अनुसार कर की सामान्य दर

1. मेहरोत्रा एवं गोयल : उत्तर प्रदेश बिड़ी कर अधिनियम, पृ० 1.

2 पैसे प्रति स्वया से बढ़ाकर 3 पैसे प्रति स्वया कर दी गई थी। बहु बिन्दु कर पुणाली के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं पर यही कर की अधिकतम दर थी। इस संशोधन के अनुसार आटा, दाल, अनाज, मैदा, तूजी आदि वस्तुओं की बिड़ी पर बहु बिन्दु कर पुणाली के अन्तर्गत 3 पैसे प्रति स्वया बिड़ी कर लगा दिया गया। औद्योगिक तैलों तथा खादों पर बिड़ी कर की दर 5 पैसे प्रति स्वया थी। दूसरे राज्यों से आने वाली वस्तुओं में से कुछ पर एक बिन्दु कर पुणाली से और कुछ पर बहु बिन्दु कर पुणाली से कर लगाया गया था। अफीम, भांग, देशी शराब आदि पर बिड़ी कर को बढ़ाकर 6 पैसे प्रति स्वया कर दिया गया था। सोना और चांदी के विक्रय पर भी बहु बिन्दु कर पुणाली के अनुसार प्रति 500 रुपये पर 24 पैसे कर लगा दिया गया। न्यूनतम कर रहित सीमा को घटाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। सरकार द्वारा मोटे अनाजों पर भी बिड़ी कर लगाने की बड़ी आलोचना हुई थी। तन् 1958 से सरकार द्वारा अनाज पर बिड़ी कर की एक बिन्दु पुणाली लागू करने का निश्चय किया गया। साथ ही यह व्यवस्था भी की गई कि बिड़ी कर केवल उन्हीं व्यवसायियों पर लगेगा, जिनकी वार्षिक बिड़ी 30,000 रुपये से अधिक है। इसके पश्चात् भी समय-समय पर बिड़ी कर अधिनियम में विविध संशोधन किये गये।

बिड़ी कर अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ एवं अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषणात्मक व आलोचनात्मक अध्ययन

उत्तर प्रदेश बिड़ी कर के स्वभाव, क्षेत्र, विशेषताओं एवं अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या अधोलिखित है :-

1. अधिनियम का क्षेत्र

यह अधिनियम सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होता है। इसे "उत्तर प्रदेश बिड़ी कर अधिनियम 1948" के नाम से सम्बोधित किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि यह अधिनियम राज्य में 1 अप्रैल 1948 से लागू हो गया था लेकिन बनावल, रामपुर और देहरी मद्रास की रियासतों पर 1 जनवरी, 1950 से लागू हुआ। यह भी महत्वपूर्ण है कि मूल रूप से इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश शब्द नहीं था परन्तु

"संयुक्त राज्य" शब्द था क्योंकि उस समय विद्यमान उत्तर-प्रदेश को "आगरा और अवध का संयुक्त राज्य" कहा जाता था। अधिनियम में संयुक्त राज्य के स्थान पर उत्तर प्रदेश शब्द को। अगस्त 1958 से प्रतिस्थापित किया गया। अधिनियम की कार्यविधि को निर्धारित करने के लिए "उत्तर-प्रदेश बिजुली कर नियम 1948" बनाये गये हैं और समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज्य सरकार इन नियमों में संशोधन करती रही है। बिजुली कर अधिनियम में भी हाल के वर्षों में सन् 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 और 1984 में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं। प्रारम्भ में 105 धारार्यें थीं परन्तु 1981 के संशोधन में 35 धारार्यें निकाल दी गयी थी। इनका अध्ययन 15 अध्यायों में किया गया है।

2. कर बिन्दु

प्रारम्भ में बिजुली कर अधिनियम में कुछ वस्तुओं पर बहु-बिन्दु बिजुली कर लगाया गया था, परन्तु वर्तमान में यह मुख्यतया एक बिन्दु कर ही रह गया है। एक बिन्दु आधार पर भी कुछ वस्तुओं की दशा में बिजुली के प्रथम बिन्दु पर और कुछ वस्तुओं की दशा में बिजुली के अन्तिम बिन्दु पर अर्थात् उपभोक्ता को बिजुली होने पर यह कर लगाया जाता है।

3. प्रशासनिक व्यवस्था

बिजुली कर अधिनियम के क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए अनेक प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, परन्तु इस विभाग का उच्चतम अधिकारी बिजुली कर आयुक्त होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। आयुक्त की सहायतार्थ राज्य सरकार अनेक अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करती है। अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को अनेक परिक्षेत्रों में विभाजित किया है। परिक्षेत्रों को क्षेत्रों में बाँटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र मण्डल एवं उपमण्डल में बाँटा होता है। ये बिजुली कर अधिकारी के नियन्त्रण में होते हैं।

4. करारोपित वस्तुएँ

अधिनियम के अन्तर्गत करारोपित वस्तुओं का तन्दर्भ अधिनियम की धारा 31ए के अन्तर्गत उल्लिखित किया गया है। इसमें विभिन्न वस्तुओं का उल्लेख 5 उपवर्गों में किया गया है :

1अ। घोषित वस्तुएँ ;

1ब। किसी होटल या रेस्टोरेंट में केबरे या अन्य मनोरंजन प्रोग्राम के साथ दिये जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थ ;

1त। स्प्रिट तथा सभी प्रकार की शुद्ध शराब ;

1द। प्रथम अनुसूची में वर्णित मात तथा

1य। अन्य वस्तुएँ ।

प्रथम अनुसूची में जिन विभिन्न वस्तुओं को बिज्जी कर की दृष्टि से शामिल किया गया है। उनको कर के स्तर एवं कर की दर की दृष्टि से 76 वर्गों में विभाजित किया गया है जबकि अन्य वस्तुओं को 56 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सरकार ने विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता और बिज्जी-कर का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए कुछ वस्तुओं को बिज्जी कर से मुक्त रखा है। इस तन्दर्भ में अधिनियम की धारा 4 में यह उल्लेख है कि पानी, दूध, नमक, समाचार पत्र, मोटर स्प्रिट, डीजल तेल तथा अल्कोहल पर क्रय या विक्रय कर नहीं लगाया जायेगा। अधिनियम में राज्य सरकारों को यह अधिकार भी दिया जाता है कि यदि सरकार उचित समझे तो अन्य किन्हीं वस्तुओं को बिज्जी कर से मुक्त घोषित कर सकती है और इस अधिकार के अन्तर्गत सरकार ने लगभग 63 प्रकार की वस्तुओं को क्रय-विक्रय कर से मुक्त घोषित किया है।

5. क्रय-विक्रय कर से मुक्त संस्थाएँ

कुछ समाज उपयोगी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने ऐसी संस्थाओं द्वारा मात के क्रय-विक्रय को कर से मुक्त घोषित किया है। इस तन्दर्भ में मूल रूप से अधिनियम में दो संस्थाओं : अखिल भारतीय कताई संघ तथा गांधी आश्रम मेरठ एवं उनकी शाखाओं का उल्लेख था लेकिन बाद में ऐसी अनेक संस्थाओं को

क्रय-विक्रय कर से मुक्त घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त निम्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों को किया गया विक्रय भी राज्य सरकार ने कर मुक्त घोषित कर रखा है, भौे ही माल किसी व्यापारी द्वारा बेचा गया हो :

111. भूटान सरकार, भूटान नरेश अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को;
121. भारतीय सैनिक प्रशिक्षण टीम, भूटान को ;
131. भूटान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अथवा व्यापारी को;
141. भारत में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों तथा राजदूतों को ;
151. अमेरिकन सहकारिता कल्याण समिति को ;
161. उत्तर प्रदेश में यू०एन०ओ० की संस्थाओं को ;
171. मुस्लिम अनायालय, कानपुर को;
181. छोटे तथा मध्यम समाचार-पत्रों को अख्त्यारी कामज की विक्री इत्यादि।

6. विक्री कर से मुक्त सीमायें

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक ऐसे व्यापारी पर विक्री कर लगाया जाता है, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय करते हैं तथा जिनकी विक्री की राशि कर निर्धारण वर्ष के लिए कर योग्य सीमा से अधिक होती है। वर्तमान में उत्पादक विक्रेता की दशा में 50,000 रुपये की सीमा तक तथा अन्य व्यापारी की दशा में 1,00,000 रुपये तक का विक्रय कर से मुक्त है। इस सीमा से अधिक विक्रय होने पर ही कर-निर्धारण वर्ष में कर लगाया जायेगा।

7. विक्री कर की दरें

उत्तर प्रदेश में सभी वस्तुओं पर एक दर से विक्रय कर नहीं लगाया जाता है बल्कि विभिन्न वस्तुओं पर, वस्तुओं की उपयोगिता और विक्री कर का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग दरों से विक्रय कर लगाया जाता है। वर्तमान में विक्री कर की न्यूनतम दर 2 प्रतिशत एवं अधिकतम 14 प्रतिशत है। यह उल्लेखनीय है कि प्रथम अनुसूची में घोषित माल पर विक्रय कर की अधिकतम दर 15 प्रतिशत तक हो सकती है। होटल या रेस्टोरेंट में कैबरे या अन्य मनोरंजन प्रोग्राम के साथ दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों की विक्री पर 40 प्रतिशत की दर

तक बिछी कर लगाया जा सकता है। इसी प्रकार लिप्ट तथा तभी प्रकार की शुद्ध शराब। देशी शराब व अल्कोहल को छोड़कर। की बिछी पर बिछी कर की सीमायें 20 से 25 प्रतिशत तक हैं।

उत्तर प्रदेश में बिछी कर की सामान्य दर की व्यवस्था भी रही है। यह दर उन सभी वस्तुओं पर लागू होती है जो निम्न परिधि में नहीं आती : 13। केन्द्रीय बिछी कर अधिनियम 1956 की धारा 15 के अन्तर्गत घोषित वस्तुएँ। 14। होटल या रेस्टोरेन्ट में केबरे कार्यक्रमों के साथ परोसे जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थ। 15। तभी प्रकार की लिप्ट एवं शुद्ध शराब। 16। प्रथम अनुसूची में शामिल की गई वस्तुएँ। बिछी कर की सामान्य दर 30 नवम्बर, 1973 तक बहु बिन्दु कर के त्थ में थी लेकिन उसके पश्चात्। दिसम्बर, 1973 से एक बिन्दु कर के त्थ में कर दी है। बिछी कर की सामान्य दर की प्रवृत्ति को तालिका नं० 5.। में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 5.।

उत्तर प्रदेश में बिछी कर की सामान्य दर²

अवधि	दर	कर का बिन्दु
1.4.1948 से 31.3.1954 तक	2 पैता प्रति त्थया	बहु-बिन्दु
1.4.1954 से 31.3.1959 तक	3 पैता प्रति त्थया	"
1.4.1959 से 30.9.1969 तक	2 पैता प्रति त्थया	7
1.10.1969 से 21.8.1971 तक	3 पैता प्रति त्थया	"
22.8.1971 से 14.11.1971 तक	3 प्रतिशत	"
15.11.1971 से 30.11.1973 तक	3½ प्रतिशत	"
1.12.1973 से 6.9.1981 तक	7 प्रतिशत	उत्पादन स्तर पर
7.9.1981 से	8 प्रतिशत	अथवा आयातकर्ता द्वारा बिछी होने पर

2. Goyal, Radhey Shyam : Rates & Interpretations of Sales Tax Commodities under Uttar Pradesh Sales Tax Act 1948 & Central Sales Tax Act 1956, P. 1.

उत्तर प्रदेश में बिजुलीकर व्यवस्थाओं में अतिरिक्त कर का प्रावधान भी है। इस कर का प्रावधान अधिनियम की धारा 3 1एफ। के अन्तर्गत। अक्टूबर 1970 से किया गया। इस दर में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं और। अक्टूबर 1983 से इस धारा को समाप्त कर धारा 3 1ई। के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था की गई। राज्य में अतिरिक्त कर की व्यवस्था को निम्नलिखित तालिका नं० 5.2 में स्पष्ट किया गया है :

तालिका नं० 5.2

उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त बिजुलीकर

अवधि	दर	विवरण
1. 10.70 से 14. 11.71 तक	1/2 प्रतिशत	कुल 2,00,000 रुपये से ऊपर होने पर कर योग्य बिजुलीकर
15. 11.71 से 3. 11.74 तक	1/2 प्रतिशत	" "
4. 11.74 से 3. 12.79 तक	1 प्रतिशत	" "
4. 12.79 से 6.09.81 तक	1 प्रतिशत	कुल करयोग्य कुल और विक्रय पर
7. 10.83 से	देयकर का 5 प्रतिशत	उन विक्रेताओं पर जिनकी वांछित बिजुली 10,00,000 रुपये से अधिक हो।

8. व्यापारियों के पंजीयन की व्यवस्था

इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे व्यापारी को पंजीयन कराना अनिवार्य है जो 11। उत्तर प्रदेश के बाहर से ऐसे माल को आयात करके बेचता है जिनकी बिजुली पर इस अधिनियम की धारा 3 1ए। के अन्तर्गत कर लगता है 12। उत्पादक की दशा में 50,000 रुपये से अधिक बिजुली होने तथा अन्य व्यापारी की दशा में, 1,00,000 रुपये से अधिक बिजुली होने पर 13। प्रत्येक व्यापारी जिस पर इस अधिनियम की अन्य क़िस्ती धारा के अन्तर्गत कर दायित्व है।

इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यापारियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा

रही है। प्रदेश में दो प्रकार के पंजीकृत व्यापारी हैं, एक उत्तर प्रदेश बिज्जी कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी, दूसरे केन्द्रीय बिज्जी कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी। इन पंजीकृत व्यापारियों की संख्या को तालिका नं० 5.3 में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 5.3 के अन्वयेन से स्पष्ट है कि तन् 1971-72 में उत्तर प्रदेश बिज्जी कर अधिनियम के अन्तर्गत 1 लाख 19 हजार व्यापारी पंजीकृत थे, जो लगातार बढ़ते हुए तन् 1978-79 को छोड़कर तन् 1980-81 में सर्वाधिक 2 लाख 68 हजार हो गये। तन् 1984-85 में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या घटकर 2 लाख 31 हजार रह गयी। केन्द्रीय बिज्जी कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 1971-72 में 64 हजार थी जो 1976-77 में बढ़कर 87 हजार हो गई। तन् 1980-81 में सर्वाधिक पंजीकृत व्यापारी। जाख 8 हजार थे। परन्तु तन् 1981-82 में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या तन् 1971-72 की संख्या से काफी कम हो गई। तन् 1984-85 में यह संख्या 71 हजार थी। यह उल्लेखनीय है कि कर योग्य व्यापारियों की संख्या में कर मुक्ति सीमा में परिवर्तन के तन्द्भ में उतार चढ़ाव होते रहे हैं।

9. व्यापारियों की बिज्जी एवं बिज्जी कर का निर्धारण

उत्तर प्रदेश बिज्जी कर अधिनियम के अन्तर्गत जिन-जिन वस्तुओं पर बिज्जी कर लगता है। उन सभी वस्तुओं की कुल बिज्जी का योग किया जाता है। सामान्यतः व्यापारियों को अपनी बिज्जी का प्रेमातिक विवरण दाखिल करना पड़ता है, लेकिन यदि किसी व्यापारी की किसी कर-निर्धारण वर्ष में बिज्जी दो लाख रुपये से अधिक होने का अनुमान है तो उसे अपनी बिज्जी का मासिक विवरण अगले माह की समाप्ति से पूर्व बिज्जी कर अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत करना होता है जब बिज्जी का विवरण दाखिल कर दिया जाता है। तो इस बिज्जी के विवरण के आधार पर बिज्जी कर का निर्धारण किया जाता है। इसे नियमित कर-निर्धारण कहा जाता है। यदि 111 व्यापारी नियत समय में विवरण दाखिल नहीं करता है, अथवा 121 कर निर्धारण अधिकारी की राय में दाखिल किया गया विवरण अपूर्ण अथवा असत्य है अथवा इसमें

तालिका नं० 5.3

कर योग्य तथा पंजीकृत व्यापारियों की संख्या³

1971-72 से 1984-85।

वर्ष	कर योग्य व्यापारियों की संख्या	पंजीकृत व्यापारियों की संख्या लाख में।	
		उत्तर प्रदेश बिज्जी- कर अधिनियम के अन्तर्गत	केन्द्रीय बिज्जीकर अधिनियम के अन्तर्गत
1971-72	1,51,919	1.19	0.64
1972-73	1,56,923	1.28	0.65
1973-74	1,68,051	1.36	0.71
1974-75	1,83,813	1.53	0.78
1975-76	2,04,600	1.61	0.86
1976-77	2,17,746	1.81	0.87
1977-78	2,42,400	2.24	0.87
1978-79	2,33,250	2.08	0.79
1979-80	2,12,842	2.37	0.93
1980-81	2,15,399	2.68	1.08
1981-82	2,14,957	2.18	0.54
1982-83	2,10,601	2.36	0.65
1983-84	2,11,195	2.37	0.71
1984-85	1,99,426	2.31	0.71

3. आयुक्त बिज्जीकर उत्तर प्रदेश। तांछियकी अनुभाग। : बिज्जी कर विभाग का
सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85, लखनऊ, पृ० 48.

गत तथ्य शामिल है अथवा 13। निर्धारित दंग से कर चुकाये बिना अथवा देयकर से कम कर चुकाने के बाद विवरण दाखिल किया गया है तो बिजुी कर अधिकारी आवश्यक पुछताछ के बाद अस्थायी कर निर्धारण कर सकता है। गत कुछ वर्षों में कर योग्य व्यापारियों एवं उनसे कर संग्रह की विनोदनात्मक स्थिति को तालिका नं० 5.4 में दर्शाया गया है। इस तालिका के विनोदनात्मक स्पष्ट है :

- 13। यद्यपि कुल कर योग्य व्यापारियों की संख्या में सर्वाधिक भाग ऐसे व्यापारियों का है जिनकी वार्षिक बिजुी 50,000 ₹ तक है लेकिन इनसे मिलने वाली बिजुी कर की राशि सबसे कम है। ऐसा स्वाभाविक भी है क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्यतः 50,000 ₹ तक बिजुी कर से मुक्त है।
- 14। कर मुक्ति की सीमा के कारण 50,000 ₹ तक और 50,000 ₹ से 80,000 ₹ तक के वर्गों में कर योग्य व्यापारियों की संख्या में निरन्तर कमी हुई है लेकिन इससे ऊपर के वर्गों में कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्यतः कर योग्य व्यापारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। 50 लाख रुपये से अधिक कर योग्य व्यापारियों की संख्या में तन् 1980-81 से तन् 1984-85 के मध्य 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
- 15। यद्यपि 50 लाख रुपये से अधिक बिजुी वाले व्यापारियों की संख्या कुल कर योग्य व्यापारियों की संख्या का मात्र 1 प्रतिशत है लेकिन इनसे प्राप्त कर राशि तन् 1980-81 में 54.5 प्रतिशत थी जो तन् 1984-85 में 66 प्रतिशत से ऊपर हो गयी।

10. स्वतः कर निर्धारण योजना

सामान्य व्यापारियों के 500 ₹ वार्षिक तथा सरकारी कार्यालयों के 1000 ₹ वार्षिक तक निहित कर से सम्बन्धित वादों का निस्तारण करने के लिये जून 1976 में "समरी योजना" प्रारम्भ की गई, किन्तु व्यावहारिक रूप में किसी भी निर्माता एवं अथवा सामान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त व्यापारी के वादों को उक्त योजना में सम्मिलित नहीं किया गया। इसके पश्चात् 1 जनवरी तन् 1978 से स्वतः कर निर्धारण योजना प्रारम्भ की गई। यह योजना उन व्यापारियों के लिये थी। जिनका सम्पूर्ण वार्षिक

तालिका नं० 5.4

विद्युत धन की मौद्रिक सीमानुसार कर योग्य व्यापारियों की संख्या तथा वास्तविक बिजुली कर संग्रह

संख्या हजारों में धनराशि करोड़ रु० में।

विद्युत धन की नं० मौद्रिक सीमा	1980-81				1981-82				1982-83			
	कर योग्य व्यापारियों की संख्या	बिजुली कर संग्रह	कर योग्य व्यापारियों की संख्या	बिजुली कर संग्रह	कर योग्य व्यापारियों की संख्या	बिजुली कर संग्रह	कर योग्य व्यापारियों की संख्या	बिजुली कर संग्रह	कर योग्य व्यापारियों की संख्या	बिजुली कर संग्रह	कर योग्य व्यापारियों की संख्या	बिजुली कर संग्रह
संख्या प्रतिशत धनराशि प्रतिशत संख्या प्रतिशत धनराशि प्रतिशत												
1. 50,000 तक	75.1	34.8	7.21	2.4	67.4	31.4	8.31	2.2	54.7	26.0	6.08	1.5
2. 50,000 से 80,000 तक	46.2	21.4	9.05	3.0	42.8	19.9	9.07	2.4	40.6	19.3	9.58	2.3
3. 80,000 से 1,25,000 तक	32.1	14.9	11.76	3.9	34.0	15.8	12.85	3.4	36.7	17.4	13.31	3.2
4. 1,25,000 से 2,00,000 तक	22.7	10.6	14.99	5.0	25.3	11.8	16.63	4.4	29.1	13.8	17.07	4.2
5. 2,00,000 से 5,00,000 तक	18.3	8.5	18.91	6.3	21.1	9.8	22.67	6.0	24.2	11.5	24.73	6.0
6. 5,00,000 से 10,00,000 तक	10.2	4.8	20.90	6.9	11.7	5.4	25.70	6.8	12.6	6.0	29.75	7.2
7. 10,00,000 से 25,00,000 तक	6.3	2.9	26.11	8.7	7.4	3.5	33.63	8.9	7.4	3.5	36.44	8.9
8. 25,00,000 से 50,00,000 तक	2.8	1.3	28.04	9.3	3.3	1.5	38.16	10.1	3.3	1.5	43.60	10.6
9. 50,00,000 से अधिक	1.7	0.8	164.59	54.5	2.0	0.9	210.86	55.8	2.0	1.0	231.02	56.1
योग	215.4	100	301.56	100	215.0	100	377.88	100	210.6	100	411.58	100

1983-84

1984-85

शुद्ध विद्युत धन की मौद्रिक सीमा

क्र.सं.		1983-84		1984-85	
		कर योग्य व्यापारियों की संख्या	बिछोटी कर संग्रह	कर योग्य व्यापारियों की संख्या	बिछोटी कर संग्रह
		संख्या	प्रतिशत संख्या	संख्या	प्रतिशत संख्या
1.	50,000 तक	50.7	24.0	6.93	1.5
2.	50,000 से 80,000 तक	39.3	18.6	6.71	2.1
3.	80,000 से 1,25,000 तक	38.2	18.1	13.41	2.9
4.	1,25,000 से 2,00,000 तक	31.0	14.7	19.42	4.2
5.	2,00,000 से 5,00,000 तक	23.1	10.9	24.50	5.3
6.	5,00,000 से 10,00,000 तक	14.1	6.7	30.06	6.5
7.	10,00,000 से 25,00,000 तक	8.9	4.2	37.92	8.2
8.	25,00,000 से 50,00,000 तक	3.5	1.7	41.15	8.9
9.	50,00,000 से अधिक	2.4	1.1	279.28	60.4
योग		211.2	100	462.39	100

4. आयुक्त बिछोटीकर उत्तर प्रदेश। सांख्यिकी अनुभाग। बिछोटीकर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85, लखनऊ, पृ० 49.

देयकर 2500 रुपये से अधिक न हो, नियमानुसार नवी व स्वीकृति कर जमा हो, पुनर्निर्माण विधुय धन तथा देयकर प्रदर्शित किया हो तथा सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में कोई प्रतिफल सर्वेक्षण सूचना अध्या तथ्य न हो । प्रारम्भ में उन व्यापारियों को स्वतः कर निर्धारण योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था जो अन्तर्देशीय बिजली, निर्यात बिजली अध्या प्रान्त के बाहर के आदतियों को कन्साइनमेन्ट बिजली करते हों, भी ही उनकी कुल कर देयता 2500 रुपये से अधिक न हो, किन्तु बाद में इस प्रतिबन्ध को शिथिल कर दिया गया । जनवरी तन् 1981 से स्वतः निर्धारण योजना का आधार और व्यापक करते हुए यह सुविधा उन व्यापारियों को भी प्रदान की गई जिनका कुल वार्षिक विधुय धन 2 लाख रुपये तथा वार्षिक कर देयता दस हजार रुपये से अधिक न हो । इस योजना में छोटे कर दाताओं को बिजलीकर कार्यालय नहीं बुलाया जाता है तथा उनके द्वारा दाखिल किये गये अभिलेखों को मानते हुये उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है । केवल करायवर्ष के मामलों तथा संदिग्ध मामलों में ही छोटे करदाताओं को बिजली कर कार्यालय बुलाया जाता है । इस योजना का लाभ उन व्यापारियों को भी अनुमन्य हैं जिनके विस्तृत प्रातंगिक सर्वेक्षण अध्या अन्य त्रुटि से क्रय/विधुय धन ठीक-ठीक न प्रदर्शित करने की सूचना प्राप्त न हुई हो तथा जिनका प्रातंगिक कर निर्धारण वर्ष में तस्यपूर्ण क्रय-विधुय धन पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में प्रदर्शित बिजली से 20 प्रतिशत से अधिक उन्नतिशील हो ।

11. कर का भुगतान, फली तथा वापसी

बिजली कर का भुगतान व्यापारी को विधुय विवरण दाखिल करने से पूर्व ही करने का प्रावधान है । कर, फीत, अर्थदण्ड आदि की राशि का भुगतान प्रथम, सरकारी कोष, उपकोष या भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखा में बालान की चार प्रतिशों द्वारा जमा करके, अध्या द्वितीय पैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा बालान की चार प्रतिशों भर कर बिजली कर अधिकारी को निर्धारित तिथि से पूर्व देकर अध्या तृतीय सरकारी विभाग द्वारा पुस्तकों में हस्तान्तरण की प्रविष्टि करके, किया जा सकता है लेकिन 500 रुपये से अधिक का भुगतान केवल पैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही किया जायेगा ।

यदि किसी व्यापारी ने इस अधिनियम के अधीन देयकर, फीत अथवा अन्य कोई राशि से अधिक राशि जमा कर दी है तो निर्धारित विधि से व्यापारी इस राशि को प्राप्त कर सकता है। यदि वह राशि वापित आदेश की तिथि से या न्यायालय के आदेश की प्राप्ति से 3 माह में वापित नहीं की जाती है तो व्यापारी ऐसे आदेश की तिथि से वापसी की तिथि तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज पाने का अधिकारी होता है।⁵

12. मार्गस्थ माल का निरीक्षण

राज्य सरकार यदि यह उचित समझती है कि राज्य के बाहर से आयातित माल की छिड़ी पर देय कर अथवा अन्य राशि की चोरी को रोकने के लिए चैक पोस्ट या बैरियर स्थापित करना आवश्यक है तो वह अधिसूचना जारी करके राज्य में निर्धारित स्थानों पर चैक पोस्ट या बैरियर की स्थापना का निर्देश दे सकती है।⁶

प्रत्येक गाड़ी या नाके या किसी अन्य स्थान पर जब जांच के प्रभारी अधिकारी द्वारा गाड़ी या यान का स्वामी, ड्राइवर या कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति गाड़ी यान को रोकेंगे और उसे तब तक रोके रहेगा, जब तक ऐसे अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो। वह ऐसे अधिकारी को गाड़ी या यान की अन्तर्गस्तुओं का परीक्षण करने देगा और ले जाये जाने वाले माल से सम्बन्धित समस्त लेखों तथा अभिलेखों का, जो उसके कब्जे में हों, या गाड़ी अथवा यान में किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हों, निरीक्षण करने देगा। गाड़ी यान का स्वामी, ड्राइवर या अन्य कोई प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी दशा हो, अधिकारी द्वारा रस्ता अपेक्षित हो, अपना नाम और पूरा पता, गाड़ी यान के स्वामी का नाम और पूरा पता तथा माल के स्वामी का नाम तथा पूरा पता, यदि वह गाड़ी या यान में उपस्थित न हो, उसे देगा।

यदि ऐसे परीक्षण पर अधिकारी को यह पता चले या उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि —

1क। कोई एक या एकाधिक पारोक्ष्य अभिदिष्ट एक या एकाधिक लेखों के अन्तर्गत नहीं आते, या

14। किसी पारोक्ष के सम्बन्ध में कोई ऐसा लेख्य मिया, झूठा, अशुद्ध या अपूर्ण या अवैध है, तो अधिकारी गाड़ी या यान के ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति को यह कारण बताने के लिये कि माल क्यों न अभिलेखित कर लिया जाय, तुरन्त नोटिस जारी करेगा ।

यदि अधिकारी का, यथास्थिति, भ्रम या दोष के कारण या कारणों के संबंध में समाधान हो जाय तो वह अपनी उपपत्तियों को अभिलेखित करने के पश्चात् नोटिस रद्द कर सकता है और अधिकारी का गाड़ी के स्वामी, ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण से समाधान न हो तो वह माल को अभिलेखित करने का आदेश देगा और अभिलेखित माल के सम्बन्ध में उपर्युक्त व्यक्ति को एक रसीद देगा ।

घोषणा-पत्र का जारी तथा प्रस्तुत किया जाना और तत्सम्बन्धी आनुषंगिक

विषय - कोई रजिस्टर्ड व्यापारी जो राज्य के बाहर किसी स्थान से इस राज्य में माल, जो तदधीन निर्दिष्ट परिमाण, माप या मूल्य से अधिक हो, आयात या प्राप्त करना चाहता है तो वह दूसरे राज्य के विक्रेता, व्यापारी या पारोक्ष को उपनियम 14। के अधीन प्राप्त स्व-पत्र 3। में घोषणा-पत्र की दो प्रतियाँ भेजेगा ।

रजिस्टर्ड व्यापारी तादे घोषणा-पत्रों को जारी करने के लिए उस किसी-कर अधिकारी को, जिसके क्षेत्राधिकार में उसके व्यापार का मुख्य स्थान हो प्रार्थना-पत्र देगा । यदि किसी-कर अधिकारी का समाधान हो जाय कि व्यापारी की तादे घोषणा-पत्रों की मांग वास्तविक और उचित है, तो वह उतने पत्र जारी कर सकता है जो वह उचित समझे । कोई घोषणा-पत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यापारी पहले प्राप्त किये गये ऐसे समस्त पत्रों का हिसाब न दे दे । यदि अदा किया गया शुल्क जारी किए गये स्व-पत्रों के लिए देय शुल्क से अधिक हो तो रीस धराराशि व्यापारी के खाते में जमा रहेगी जिसे भविष्य में जारी किये जाने वाले स्वपत्रों के प्रति समायोजित किया जायेगा । रजिस्टर्ड व्यापारी स्व-पत्र के मूल तथा द्वितीय प्रति के भागों को, समस्त अपेक्षित व्योरे भरने तथा उस पर हस्ताक्षर करने के बाद, दूसरे राज्य के विक्रय व्यापारी या पारोक्ष को भेजेगा । वह ^{प्रमाण} प्रतिपूरा अपने पास रख लेगा ।

रजिस्टर्ड व्यापारी प्रत्येक घोषणा-पत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रहेगा । वह किसी ऐसे पत्र

के को जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिए जाने और इस प्रकार को जाने, नष्ट जाने या चुरा लिये जाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की हानि के लिये, यदि कोई हो, स्वयं उत्तरदायी होगा। कोई रजिस्टर्ड व्यापारी, जिसे घोषणा-पत्र जारी किया गया हो, विधिक प्रयोजनों के सिवाय अन्य प्रयोजनों के लिए उसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करेगा। प्रत्येक रजिस्टर्ड व्यापारी, जिसे घोषणा-पत्र जारी किया जाय, एक रजिस्टर में, प्रत्येक ऐसे स्व-पत्र का तारीख और पूर्ण विवरण रखेगा, यदि कोई स्व-पत्र को जाफ़ नष्ट हो जाय या चुरा लिया जाय तो व्यापारी इस तथ्य की सूचना तुरन्त बिड़ी-कर अधिकारी को देगा, उपरोक्त रजिस्टर में समुचित प्रविष्टियाँ करेगा और इस प्रकार को जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिये जाने की समुचित तार्किक सूचना जारी करने के लिए कार्यवाही करेगा। रजिस्टर्ड व्यापारी, यथास्थिति, अपना व्यापार बन्द कर देने पर या उसका रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र रद्द कर दिये जाने या वैधता की अवधि समाप्त हो जाने पर समस्त अप्रयुक्त घोषणा-पत्र, जो उसके स्टॉफ में बच रहे हों, तुरन्त अभ्यर्पित कर देगा। यदि क्रेता व्यापारी या पारेक्षिती द्वारा विक्रेता व्यापारी या पारेक्षक को जारी किया गया यथाविधि भरा गया घोषणा-पत्र मार्ग में विक्रेता व्यापारी या पारेक्षक द्वारा को जाय, तो क्रेता व्यापारी या पारेक्षिती ऐसे विक्रेता व्यापारी या पारेक्षक की मर्ग पर उसे एक दूसरा घोषणा-पत्र उस रीति से जारी करेगा जिस प्रकार मूल घोषणा-पत्र जारी किया गया हो।

बिड़ी-कर कमिशनर, समय-समय पर, गबट में ऐसे घोषणा-पत्र के व्यौरे प्रकाशित करेगा, जिसके सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई हो। बिड़ी-कर कमिशनर, विज्ञप्ति द्वारा, यह घोषणा कर सकता है कि किसी विशिष्ट क्रेती, डिजाइन या रंग के घोषणा-पत्र उस दिनांक से जिसे विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, अप्रयुक्त और अवैध समझे जायेंगे और उनके स्थान पर नई क्रेती, डिजाइन या रंग के नये स्व-पत्र प्रतिलिप्यापित कर सकता है। कोई विज्ञप्ति जब उपनियम 113A के अधीन जारी की जाय तो सभी रजिस्टर्ड व्यापारी उस दिनांक को या उसके पूर्व, जब से उन्हें इस प्रकार अप्रयुक्त तथा अवैध घोषित ऐसे सभी अप्रयुक्त स्व-पत्र, जो उनके पास हों, बिड़ी-कर अधिकारी को अभ्यर्पित कर देंगे और उनके कब्जे में ऐसे नये स्व-पत्र प्राप्त करेंगे जो उनके स्थान पर प्रतिलिप्यापित

किये जायें : प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी को नये स्व-पत्र तब तक जारी नहीं किये जायेंगे जब तक कि उसने पहले जारी किये गये समस्त स्व-पत्रों का लेखा न दे दिया हो और जब तक कि उसने शेष स्व-पत्र, यदि कोई हो बिक्री-कर अधिकारी को लौटा न दिये हों । कोई रजिस्टर्ड व्यापारी, कोई घोषणा, तिवाय ऐसे घोषणा-पत्र में जो उस बिक्री-कर अधिकारी से, जिसका उसके व्यापार के मुख्य स्थान पर क्षेत्राधिकार हो, प्राप्त किया गया हो और जो अप्रवर्तित या अवैध न घोषित किया गया हो, जारी नहीं करेगा । बिक्री-कर अधिकारी ऐसे घोषणा-पत्रों के सम्बन्ध में जो उसे प्राप्त हुये हों अथवा जो उसके द्वारा जारी किए गए हों, और अभ्यर्पित स्व-पत्रों के सम्बन्ध में स्व-पत्र 37, 38 तथा 39 में लेखा रहेगा ।

प्रमाण-पत्र का जारी तथा प्रस्तुत किया जाना और तत्सम्बन्धी आनुवंशिक विषय - रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न कोई व्यक्ति जो राज्य के बाहर किसी स्थान से इस राज्य में धारा 28-क की उप-धारा 111 के अधीन विज्ञापित या उसमें निर्दिष्ट माल, जो तदधीन निर्दिष्ट परिमाण, माप या मूल्य से अधिक हों, आयात या प्राप्त करना चाहे, इस नियम के उपबन्धों के अनुसार बिक्री-कर अधिकारी से स्व-पत्र 32 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है और उसकी मूल तथा दूसरी प्रतियाँ दूसरे राज्य के विक्रेता व्यापारी या पारोक्ष को भेज सकता है । किसी प्रमाण-पत्र के लिए, प्रार्थना-पत्र, स्व-पत्र 33 में होगा और ऐसे बिक्री-कर अधिकारी को, जिसके क्षेत्राधिकार में प्राचीन व्यापार करता हो या, यदि वह व्यापार नहीं करता, निवास करता हो, प्रस्तुत किया जायेगा । प्रत्येक पारोक्ष के लिए अलग-अलग प्रार्थना-पत्र दिया जायेगा । कोई प्रमाण-पत्र तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि प्रति प्रमाण-पत्र के लिए बीस पैसे के शुल्क का भुगतान न कर दिया जाय । यदि बिक्री-कर अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि प्रमाण-पत्र के लिये माँग वास्तविक और उचित है तो वह उसे जारी कर सकता है, अन्यथा प्राचीन को तुनवाई का अवसर देने के पश्चात् वह प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर सकता है । जारी किया गया प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के दिनांक से एक माह की अवधि तक के लिये वैध होगा ।

बिक्री-कर अधिकारी जारी किए गए प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में स्व-पत्र 40 में

लेखा रहेगा । उप-नियम ॥५॥ के अधीन प्राप्त कोई प्रमाण-पत्र, उप-नियम ॥१॥ में उल्लिखित विधि-संग्रह प्रयोजनों के सिवाय हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा । प्राचीन प्रमाण-पत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रहेगा । वह व्यक्तिगत रूप से इसके छो जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिए जाने तथा इस प्रकार छो जाने, नष्ट हो जाने अथवा चुरा लिए जाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की हानि के लिए भी, यदि कोई हो, उत्तरदायी होगा । यदि कोई प्रमाण-पत्र छो जाय, नष्ट हो जाय या चुरा लिया जाय, तो वह व्यक्ति जिसने इसे प्राप्त किया हो इस तथ्य की सूचना तुरन्त बिक्री-कर अधिकारी को देगा और इस प्रकार छो जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिये जाने की सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करेगा । सभी अप्रयुक्त प्रमाण-पत्र बिक्री-कर अधिकारी को तौटा दिये जायेंगे जो स्व-पत्र ५१ में इसका लेखा रहेगा । बिक्री कर कमिशनर, विज्ञप्ति द्वारा, यह घोषणा कर सकता है कि किसी विशिष्ट ज़ेमी, डिजाइन या रंग के प्रमाण-पत्र उस दिनांक से, जितने विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, अप्रचलित तथा अवैध समझे जायेंगे और उनके स्थान पर नई ज़ेमी, डिजाइन या रंग के नये स्व-पत्र प्रतिलिखित कर सकता है ।

राज्य से होकर तड़क से मान का पारगमन और पारगमन-पत्र का जारी किया जाना - किसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति द्वारा 28-अ के अधीन पारगमन-पत्र पाने के उद्देश्य से, राज्य में प्रवेश स्थल के निकट स्थापित, जाँच चौकी या नाके, यदि कोई हो, जितने आगे प्रवेश जाँच चौकी कहा गया है, के प्रभारी अधिकारी को स्व-पत्र 34 में प्रार्थना-पत्र तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेगा । प्रवेश जाँच चौकी का प्रभारी अधिकारी, लेख्यों का परीक्षण करने के पश्चात् और ऐसी जाँच, जितने वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् प्रार्थना-पत्र की द्वितीय और तृतीय प्रतियों पर पारगमन-पत्र जारी करेगा और मूल प्रति अपने पास रख लेगा । पारगमन पत्र में गाड़ी या यान द्वारा पार किये जाने वाली राज्य की जाँच चौकी या नाके का । जितने आगे निर्गम जाँच चौकी कहा गया है। और उस समय तथा दिनांक का जब तक उसे पार कर लेना चाहिये, निर्देश होगा । गाड़ी या यान का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति अपनी गाड़ी को ऐसी निर्गम जाँच चौकी पर रोकेगा, पारगमन-पत्र की द्वितीय प्रति अभ्यर्पित करेगा तथा जाँच चौकी के प्रभारी अधिकारी को, यह सुनिश्चित करने के लिये कि राज्य

के बाहर ले जाये जाने वाले पारेज्ज वही है जिनके लिये पारगमन-पत्र प्राप्त किया गया, लैडरों, पारेज्जों तथा माल का निरीक्षण करने देगा । निर्गम जाँच चौकी का प्रभारी अधिकारी गाड़ी के ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति द्वारा अभ्यर्पित द्वितीय प्रति के लिये पारगमन-पत्र की तृतीय प्रति पर एक रसीद जारी करेगा । निर्गम जाँच चौकी के प्रभारी अधिकारी को, गाड़ी की अन्तर्वस्तुओं को रोकने, उतारने तथा तलाशी लेने का अधिकार होगा ।

रेल, नदी या वायु मार्ग द्वारा माल का आयात या उसकी प्राप्ति तथा तत्सम्बन्धी आनुवंशिक विषय - बोर्ड रजिस्टर्ड व्यापारी या रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न कोई व्यक्ति जो राज्य के बाहर किसी स्थान से उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर रेल, नदी या वायु मार्ग द्वारा, माल उस परिमाण, माप या मूल्य से अधिक का आयात करना या प्राप्त करना चाहता है, जो तदधीन विनिर्दिष्ट हो, अपने द्वारा यथाविधि भरे गए तथा हस्ताक्षरित, यथास्थिति, त्व-पत्र 31 या 32 में घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र की मूलप्रति तथा द्वितीय प्रति को पूष्ठांकन के लिये उस बिज्जी-कर अधिकारी या सहायक बिज्जी-कर अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में वह व्यापार करता हो, अथवा यदि व्यापार न करता हो तो साधारण निवास करता हो ।

यह बिज्जी-कर अधिकारी या सहायक बिज्जी-कर अधिकारी जिसे कोई घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र पूष्ठांकन के लिए प्रस्तुत किये जायें उनकी शुद्धता तथा पूर्णता के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात् उन पर हस्ताक्षर करके अपनी शासकीय मुहर लगायेगा । घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को अपने पास रखेगा तथा उसकी द्वितीय प्रति पर रौकी गई मूल प्रति की प्राप्ति की रसीद पूष्ठांकित करके उसे यथास्थिति, रजिस्टर्ड व्यापारी को या रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न अन्य व्यक्ति को, सौटा देगा । बिज्जी-कर अधिकारी या सहायक बिज्जी-कर अधिकारी, स्वविवेकानुसार, व्यापारी अथवा सम्बद्ध व्यक्ति को निर्देश दे सकता है कि वह अन्य राज्य के विद्येता व्यापारी अथवा पारथेक से अपने को प्राप्त हुये कि या नकदी पचाँ या चालान या बीजक की प्रतियों का घोषणा-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र की अन्तर्वस्तु के सत्यापन के लिये प्रस्तुत करें ।

नियम 83 तथा 84 नियम 85 उनके उप-नियम 111, 161, 181 तथा 1111 को छोड़कर। तथा नियम 86 इसके उप-नियम 111 तथा 161 को छोड़कर। के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उप-नियम 111 में अभिविष्ट, यथास्थिति, घोषणा-पत्रों अथवा प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

प्रतिभूति ले कर आदि का समायोजन - व्यापारी या किसी व्यक्ति द्वारा, किसी भी दशा हो, देय कर या अन्य धनराशि को उसके द्वारा प्रदत्त नकद प्रतिभूति से, यदि कोई हो, समायोजित किया जा सकता है ।

धनराशि की वापसी⁷

अधिनियम की धारा 29 के अधीन धनराशि की वापसी, के वाउचर के माध्यम से, वापस की जाने वाली धनराशि पाँच हजार रुपये से अधिक न हो; और अन्य मामलों में, फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, कण्ड पांच, भाग एक में दिये गये नियम 194 से 197 के अनुसार की जायगी ; या व्यापारी पर उसी कर निर्धारण वर्ष या किसी अन्य कर-निर्धारण वर्ष के लिए बकाया किसी धनराशि के प्रति समायोजित करके की जायगी ।

जब धनराशि की वापसी के लिए कोई दावा किया जाय, तब बिड़्रीकर अधिकारी समस्त सुलगत अभिलेखों की तबीक्षा और आवश्यक तत्पापन करने के पश्चात् अपना यह समाधान करेगा कि धनराशि वापस करने योग्य है । यदि किसी वर्ष के लिए व्यापारी द्वारा कोई देय बकाया न हो तो वापसी का वाउचर तैयार किया जायगा । यदि किसी वर्ष के लिए व्यापारी द्वारा कोई देय बकाया हो या यदि व्यापारी वापस करने योग्य धनराशि का भावी देयों के प्रति समायोजन करने का अनुरोध करे तो वापस करने योग्य अधिक धनराशि का ऐसे देयों के प्रति समायोजन करने के लिये एक समायोजन वाउचर तैयार किया जायगा । वापसी या समायोजन के वाउचर पर हस्ताक्षर किये जाने के पूर्व समस्त सुलगत अभिलेखों में, जिनके अन्तर्गत

7. नये नियम 89 से 105 तक उ0प्र0 बिड़्रीकर ।द्वितीय संशोधन। नियमावली, 1985 द्वारा अन्तःस्थापित ।प्रभावी 1.4.1985। ।

दैनिक चसूली रजिस्टर, व्यापारी की छाता-बही, माग, चसूली और बकाया रजिस्टर, धनराशि की वापसी का रजिस्टर, सुतंगत कर - निर्धारण पत्रावली का आदेश-पत्र । आर्डर शीट, धनराशि की वापसी का निर्देश करने वाला आदेश और समस्त सम्बद्ध छाना चालान की प्रतियाँ भी हैं, धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में प्रविष्टियाँ की जाएँगी । ऐसी सभी प्रविष्टियाँ बिछीकर अधिकारी के हस्ताक्षर से । दिनांक, मास और वर्ष सहित । अधिमुमानित की जाएँगी । बिछी-कर अधिकारी द्वारा पारित वापसी के वाउचर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायगा । समायोजन द्वारा भुगतान के लिये प्राप्त समायोजन के वाउचर पर भी बिछी-कर अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा । व्यापारी द्वारा जमा की गई धनराशि के लिए स्व-पत्र में यथाविधि भरी गयी छाना चालान की चार प्रतियाँ भी समायोजन के लिए छाने में भेजे जाने के पूर्व वाउचर के साथ संलग्न की जाएँगी । बिछी-कर अधिकारी द्वारा पारित समायोजन के वाउचर पर भी आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायगा ।

छाने का अधिकारी अपने अभिलेखों से समायोजन के वाउचर की प्रविष्टियों का सत्यापन करने के पश्चात् अतिरिक्त धनराशि वापस कर देगा और तत्पश्चात् उती धनराशि को वाउचर के संलग्न चालान में उल्लिखित वर्ष के लिए समायोजन द्वारा जमा की गई धनराशि मान लेगा । तत्पश्चात् ऐसे चालान की दो प्रतियाँ बिछी-कर अधिकारी को अग्रसारित की जायगी जो एक प्रति सम्बद्ध व्यापारी को उसके अभिलेख के लिए देगा । वापसी के वाउचर का भुगतान छाने का कार्य करने वाली भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में या जहाँ स्टेट बैंक की कोई ऐसी शाखा न हो, वहाँ छाने या उपछाने से लिया जा सकेगा । वापसी का वाउचर अनन्तरणीय होगा । वापसी का वाउचर जारी करने के साथ ही साथ एक सूचना-पत्र । सहसंज्ञित नोट, यथास्थिति, भारतीय स्टेट बैंक, छाना या उपछाना को भेजा जायगा । सूचना-पत्र पर वही क्रम-संख्या डाली जायगी जो जारी किये गये वापसी के वाउचर पर उल्लिखित हो । भारतीय स्टेट बैंक, छाने के अधिकारी या उपछाने के अधिकारी द्वारा कोई धनराशि तब तक वापस नहीं की जायगी जब तक कि उसे सूचना-पत्र प्राप्त न हो जाय ।

वापसी के वाउचर और सूचना-पत्र में तमस्त प्रविष्टियाँ स्याही से की जायेंगी, और शुद्धियाँ, यदि कोई हों, बिज्जीकर अधिकारी के दिनांक तहति पूरे हस्ताक्षर से अनुप्रमाणित की जायेंगी । भारतीय स्टेट बैंक के नाम जारी किये गये 500 रुपये या उतते अधिक के प्रत्येक वापसी के वाउचर को रेंजितःकृतः किया जायगा और केवल पाने वाले के लेखा में ही देय होगा । परन्तु छाने या उप-छाने के नाम जारी किये गये वाउचर को इस प्रकार रेंजितःकृतः नहीं किया जायेगा।

उपनियमः।। में किसी बात के होते हुये भी, यदि व्यापारी का कोई बैंक-लेखा न हो और वह बिज्जीकर अधिकारी से लिखित रूप में यह अनुरोध करता है कि वापसी का वाउचर रेंजितःकृतः न किया जाय तो उसे रेंजितःकृतः नहीं किया जायगा किन्तु इस तथ्य को तमस्त सुतंगत अभिलेखों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया जायगा । 500 रुपये या उतते अधिक का प्रत्येक वापसी का वाउचर और अरेंजित प्रत्येक वापसी का वाउचर व्यापारी, ताह्सेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को तदैव व्यक्तिगत रूप से दिया जायगा जो दिनांक और अपने पूर्ण नैवातिक पता तहति अपने पूरे हस्ताक्षर करके उसकी प्राप्त स्वीकार करेगा । वापसी का वाउचर जारी होने के दिनांक से साठ दिन की अवधि तक के लिए विधिमान्य होगा । यदि उसे इस अवधि के भीतर न भुनाया जाय तो व्यापारी वाउचर को रद्द करने के लिए उसे बिज्जीकर अधिकारी को वापस कर सकता है और नया वाउचर जारी करने के लिए लिखित रूप से आवेदन कर सकता है । बिज्जीकर अधिकारी द्वारा मूल वाउचर रद्द कर दिया जायगा और उसे प्रतिपण के साथ संलग्न कर दिया जायगा, और तब इस नियमावली के अनुसार रद्द किये गये और नये वाउचर के सम्बन्ध में सुतंगत अभिलेखों में प्रविष्टियाँ करने के पश्चात् वापस किये गये वाउचर के बदले में एक नया वापसी का वाउचर जारी किया जायगा ।

यदि वापसी का वाउचर जो जाय तो व्यापारी दूसरी प्रति जारी करने के लिए बिज्जीकर अधिकारी का लिखित रूप में आवेदन कर सकता है । यदि बिज्जीकर अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि मूल वाउचर को उसकी विधिमान्यता की अवधि में भुनाया नहीं गया है, तो वह इस नियमावली के अनुसार तमस्त सुतंगत

अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने और यथास्थिति, भारतीय स्टेट बैंक, छजाने के अधिकारी और उपछजाने के अधिकारी को मूल वाउचर को रद्द किये जाने की सूचना देने के पश्चात् छो गये वाउचर के बदले में उनकी दूसरी प्रति जारी कर सकता है ।

वापसी के वाउचर की धराशि का भुगतान किये जाने के पश्चात् सूचना-पत्र का "मूल" अंकित भाग, यथास्थिति, भारतीय स्टेट बैंक, छजाने के अधिकारी या उप-छजाने के अधिकारी द्वारा बिड्डी-कर अधिकारी को वापस कर दिया जायगा । उसकी प्राप्ति पर समस्त सुसंगत अभिलेखों में अधिप्रमाणित प्रविष्टियाँ की जायेंगी जिन पर बिड्डी कर अधिकारी दिनांक सहित हस्ताक्षर करेगा । वापसी के वाउचर, समायोजन के वाउचर और सूचना-पत्र की पुस्तक बिड्डी-कर अधिकारी की वैयक्तिक अभिरक्षा में रखी जायगी, जो भारतीय स्टेट बैंक, छजाने के अधिकारी और उपछजाने के अधिकारी को उनके द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले वापसी के वाउचर, समायोजन के वाउचर और सूचना-पत्र की पुस्तक संख्या और क्रम-संख्या सूचित करेगा ।

वित्तीय मास में अनुमत वापसी का सत्यापन छजाने के अभिलेखों से उसी मास के आगामी मास में किया जायगा जिसके लिए जारी किये गये वापसी के वाउचर का व्योरा देते हुए विवरण-पत्र बिड्डी-कर अधिकारी द्वारा तैयार किया जायगा और हस्ताक्षर किया जायगा और उसे छजाने के अधिकारी को भेजा जायगा । छजाने का अधिकारी वापसी का सत्यापन करेगा और विवरण-पत्र बिड्डी-कर अधिकारी को लौटा देगा । वापसी का वाउचर स्व-पत्र संख्या 42 में, समायोजन का वाउचर स्व-पत्र संख्या 43 में, और सूचना-पत्र स्व-पत्र संख्या 44 में जारी किया जायगा और वापसी के वाउचर की दूसरी प्रति जारी किये जाने के लिये आवेदन-पत्र स्व-पत्र संख्या 45 प्रस्तुत किया जायगा ।

इस अध्याय में वापसी से सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध अधिनियम की धारा 29-अ के अधीन पूर्तिपूर्ति पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

13. अपराध एवं अर्थ दण्ड

पुस्तक व्यापारी एवं अन्य व्यक्ति को उत्तर प्रदेश बिड्डीकर अधिनियम, 1948

के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यापारी या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के वैधानिक कर्तव्यों एवं विभिन्न व्यवस्थाओं का पालन नहीं करता है तो वह अपराध कहलाता है। ऐसी दशा में उस व्यापारी एवं व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दण्डित किया जा सकता है।

कोई अदालत इस अधिनियम के अधीन या इसके साथ संलग्न नियमों के अधीन किये गये किसी अपराध की सुनवाई तब तक नहीं करेगी जब तक कि बिछी कर आयुक्त की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली जाती तथा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे की अदालत ऐसे किसी अपराध पर विचार नहीं करेगी।

यदि कर निर्धारण अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि कोई व्यापारी अथवा अन्य व्यक्ति अपराध करता है तो वह आवश्यक जांच पड़ताल करने के आदेश दे सकता है कि व्यापारी या अन्य व्यक्ति बकाया धराशि के साथ-साथ अर्थदण्ड भी चुकायेगा।

बिछी कर से आगम - प्रवृत्तियाँ एवं विश्लेषण

उत्तर प्रदेश में बिछी कर से आगम का शुभारम्भ सन् 1948-49 से हुआ। उस समय से इस कर की प्रवृत्तियों का विश्लेषण निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :

1. बिछी कर संग्रह की वर्षानुसार प्रवृत्ति

उत्तर प्रदेश में सन् 1948-49 से सन् 1984-85 तक के बिछी कर आगम का विवरण तालिका नं० 5.5 में दर्शाया गया है। इसमें सन् 1957-58 से केन्द्रीय बिछी कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त राशि को भी दर्शाया गया है। तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सन् 1948-49 में प्रारम्भिक बिछी कर अधिनियम के अन्तर्गत बिछी कर से मात्र 4.25 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी। जो सन् 1955-56 तक लगभग 6 करोड़ रुपये हो पायी थी। सन् 1960-61 में 10.78, सन् 1970-71 में 46.12, सन् 1980-81 में 268.20 और सन् 1984-85 में 444.69 करोड़ रुपये हो गई। इस तरह बिछी कर आगम में केवल वृद्धि ही नहीं बल्कि तीव्र वृद्धि की

तालिका नं० 5.5

उत्तर प्रदेश में बिजली-कर संग्रह^B 1948-49 से 1984-85 तक।

। करोड़ रु० में।

वर्ष	प्रान्तीय बिजलीकर अधिनियम के अन्तर्गत संग्रह	केन्द्रीय बिजलीकर अधिनियम के अन्तर्गत संग्रह	योग	प्रगत्यात्मक संग्रह	प्रतिशतगत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी।
1	2	3	4	5	6
1948-49	4.23	-	4.23	4.23	-
1949-50	6.11	-	6.11	10.34	+ 44.4
1950-51	4.92	-	4.92	15.26	- 19.5
1951-52	4.81	-	4.81	20.07	- 2.2
1952-53	4.46	-	4.46	24.53	- 7.3
1953-54	5.12	-	5.12	29.65	+ 14.8
1954-55	5.70	-	5.70	35.35	+ 11.3
1955-56	5.95	-	5.95	41.30	+ 4.4
1956-57	9.20	-	9.20	50.50	+ 54.6
1957-58	9.51	0.48	9.99	60.49	+ 8.6
1958-59	7.74	0.54	8.28	68.77	- 17.1
1959-60	9.19	0.72	9.91	78.68	+ 19.7
1960-61	10.78	0.91	11.89	90.57	+ 20.0
1961-62	12.05	0.96	13.01	103.58	+ 9.4
1962-63	13.92	1.04	14.96	118.54	+ 15.0
1963-64	16.66	1.67	18.33	136.87	+ 22.5
1964-65	19.05	2.07	21.12	157.99	+ 15.2
1965-66	22.67	2.26	24.93	182.92	+ 18.0
1966-67	27.26	2.82	30.08	213.00	+ 20.6
1967-68	34.48	3.56	38.04	251.04	+ 26.5

1	2	3	4	5	6
1968-69	38.47	3.50	41.97	293.01	+ 10.3
1969-70	43.05	4.14	47.19	340.20	+ 12.4
1970-71	46.12	5.96	52.08	392.28	+ 10.4
1971-72	52.69	5.96	58.65	450.93	+ 12.6
1972-73	64.06	6.91	70.97	521.90	+ 21.0
1973-74	76.97	6.52	83.49	605.39	+ 17.6
1974-75	108.92	11.26	120.18	725.57	+ 43.9
1975-76	157.00	18.80	175.80	901.37	+ 46.3
1976-77	184.93	23.83	208.76	1110.13	+ 18.7
1977-78	190.89	19.47	210.36	1320.49	+ 1.0
1978-79	206.98	22.15	229.13	1549.62	+ 8.9
1979-80	226.68	28.94	255.62	1805.24	+ 11.6
1980-81	268.20	33.36	301.56	2106.80	+ 18.0
1981-82	329.54	48.34	377.88	2484.68	+ 25.3
1982-83	344.17	67.41	411.58	2896.26	+ 8.9
1983-84	400.73	61.50	462.23	3358.49	+ 12.3
1984-85	444.69	83.50	528.19	3886.68	+ 14.3

8. पूर्वोद्धत, पृष्ठ 11.

प्रवृत्ति रही है और मात्र पिछले 10 वर्षों में ही इससे प्राप्त आगम चार गुने से अधिक हो गई। यह महत्वपूर्ण है कि बिजुली कर की राशि में वृद्धि केवल बिजुली में वृद्धि के कारण ही नहीं हुई है बल्कि समय-समय पर बिजुली कर की दरों में जो तीव्र वृद्धि की गई है उसका भी योगदान रहा है। कुछ वर्षों में प्रशासन द्वारा कर वसूली के कठोर प्रयासों ने भी कर आगम को बढ़ाया है। उदाहरण के लिए सर्वप्रथम आपातकालीन अवधि में तन् 1975-76 के एक वर्ष में बिजुली कर आगम में 55.62 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी जो उस समय तक के इतिहास में एक रिकार्ड थी। छठी योजना के प्रारम्भ होने पर वित्तीय साधनों को जुटाने की तीव्र आवश्यकता के तन्दर्भ में पुनः कर वसूली पर ध्यान दिया गया। इसके फलस्वरूप योजना ^{के} पाँच वर्षों में बिजुली कर के कुल आगम में क्रमांक: 45.94, 76.32, 33.70, 50.81 और 65.96 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। केन्द्रीय बिजुली कर अधिनियम के अन्तर्गत सर्वप्रथम तन् 1957-58 में मात्र 48 लाख रुपये का संग्रह किया गया था, जो तन् 1960-61 में 0.91 करोड़, 1970-71 में 5.96 तथा 1980-81 में 33.36 और तन् 1984-85 में 83.50 करोड़ रुपये हो गया। उत्तर-प्रदेश में बिजुली कर लगने के प्रारम्भ से लेकर तन् 1984-85 तक 3886.68 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की गई है। यह उल्लेखनीय है कि तन् 1948-49 से लेकर 1976-77 तक के 28 वर्षों में इस राशि का मात्र $1/3$ से कम 11110.13 करोड़ रुपये एकत्र किया गया जबकि 1977-78 से 1984-85 के 8 वर्षों में $2/3$ राशि से अधिक एकत्रित की गई। स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में इस कर से प्राप्त राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और राज्य सरकार को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुआ है।

2. बिजुली कर का कुल राजस्व में अंशदान

तन् 1948-49 में उत्तर प्रदेश में बिजुली कर से प्राप्त राशि का भाग राज्य के कुल कर आगम का मात्र 11.98 प्रतिशत था जो तन् 1960-61 तक विभिन्न वर्षों में 10 से 16 प्रतिशत तक के मध्य घटता बढ़ता रहा। तन् 1970-71 से तन् 1984-85 तक के विभिन्न वर्षों में राज्य के कर राजस्व में बिजुली कर के योगदान को तालिका नं० 5.6 में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 5.6

बिजुलीकर का कुल कर राजस्व में प्रतिशत अंशदान^१

वर्ष	बिजुली कर संग्रह [करोड़ रु० में]	बिजुली कर का कुल कर राजस्व में प्रतिशत अंशदान
1970-71	52.08	34.1
1971-72	58.65	37.7
1972-73	70.97	39.9
1973-74	83.49	37.0
1974-75	120.18	43.5
1975-76	175.80	43.9
1976-77	208.76	46.9
1977-78	210.36	45.9
1978-79	229.13	45.1
1979-80	255.62	45.5
1980-81	301.56	46.7
1981-82	377.88	45.9
1982-83	411.58	44.3
1983-84	462.23	46.6
1984-85	528.19	47.7

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि तन् 1970-71 में राज्य न के कुल कर राजस्व में बिजुली कर का भाग 34.1 प्रतिशत था जो तन् 1975-76 में 43.9 प्रतिशत, तन् 1980-81 में 46.7 प्रतिशत तथा तन् 1984-85 में बढ़कर 47.7 प्रतिशत हो गया ।

3. बिजुली कर संग्रह लागत की प्रवृत्ति

उत्तर प्रदेश में बिजुली कर संग्रह लागत प्रवृत्ति को तालिका नं० 5.7 में प्रदर्शित किया गया है ।

तालिका नं० 5.7

बिजुली कर संग्रह तथा संग्रहण व्यय एवं प्रतिशत¹⁰

वर्ष	बिजुली कर संग्रह । करोड़ रुपये में।	बिजुली कर संग्रह में वास्तविक व्यय । करोड़ रु० में।	प्रतिशत
1970-71	52.08	1.08	2.1
1971-72	58.65	1.23	2.1
1972-73	70.97	1.53	2.2
1973-74	83.49	1.98	2.4
1974-75	120.18	2.90	2.4
1975-76	175.80	3.66	2.1
1976-77	208.76	4.38	2.1
1977-78	210.36	5.09	2.4
1978-79	229.13	5.97	2.6
1979-80	255.62	6.99	2.7
1980-81	301.56	8.11	2.7
1981-82	377.88	9.50	2.5
1982-83	411.58	12.36	3.0
1983-84	462.23	13.66	2.9
1984-85	528.19	15.81	3.0

10. पूर्वोद्धृत, पृष्ठ 10.

तालिका नं० 5.7 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बिड़ीकर संग्रहों के व्ययों में निरन्तर वृद्धि हुई है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि निरन्तर बिड़ी कर विभाग के कर्मचारियों एवं उनके वेतनमानों में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही पैक-पोस्ट, तख्त दस्ते इत्यादि पर भी पहले वर्षों में विशेष व्यय बढ़े हैं, लेकिन विचारणीय पहलू यह है कि बिड़ी कर संग्रह की लागत का प्रतिशत भी बढ़ता गया है। तन् 1970-71 में संग्रह की लागत एकत्रित किये गये बिड़ी कर का 2.1 प्रतिशत थी जो तन् 1980-81 में 2.7 प्रतिशत और तन् 1984-85 में बढ़कर लगभग 3 प्रतिशत हो गयी।

4. परिक्षेत्रानुसार बिड़ी कर आगम का विश्लेषण

वर्तमान समय में राज्य का बिड़ी कर प्रशासन 12 परिक्षेत्रों में विभक्त है, जिनके सम्बन्ध में तन् 1973-74 से राजस्व प्राप्ति का विवरण तालिका नं० 5.8 में सम्पादित किया गया है।

प्रस्तुत तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से तन् 1973-74 में कानपुर, मेरठ, लखनऊ और आगरा परिक्षेत्रों का महत्वपूर्ण स्थान था। उसी वर्ष एकत्रित बिड़ी कर में इनका भाग क्रमशः 17.9, 17.8, 16.2 और 12.3 प्रतिशत था। तन् 1984-85 में सर्वोच्च स्थान लखनऊ परिक्षेत्र का था जितने राज्य के कुल बिड़ी कर राजस्व के 107.20 करोड़ रुपये प्राप्त किये। इसके पश्चात् क्रमशः कानपुर 172.85 करोड़ रुपये, आगरा 169.57 करोड़ रु०, तथा गाजियाबाद 164.48 करोड़ रुपये, परिक्षेत्रों का स्थान था। यह भी स्पष्ट है कि कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी परिक्षेत्रों में बिड़ीकर राजस्व में निरन्तर वृद्धि हुई है। ज़मीन, जलाबाद, कानपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, तहारनपुर तथा वाराणसी परिक्षेत्रों में बिड़ीकर राजस्व में वृद्धि क्रमिक और लगभग नियमित रूप से हुई है। आगरा परिक्षेत्र में तन् 1982-83 में बिड़ी कर राजस्व में एक साथ वृद्धि हुई जबकि यह राशि 33.75 करोड़ रुपये से बढ़कर 50.41 करोड़ रुपये हो गई अर्थात् एक ही वर्ष में 50 प्रतिशत के लगभग वृद्धि हुई। लखनऊ परिक्षेत्र में तन् 1977-78 में बिड़ी कर राजस्व में महत्वपूर्ण मिरावट आयी थी तो तन् 1981-82 में तन् 1980-81 की तुलना में 33.5 प्रतिशत की

तालिका नं० 5.8

परिचय वार विही कर राजस्व प्राप्ति का विवरण।।

11973-74 से 1984-85 तक।

रुपये करोड़ में।

परिचय का नाम	1973- 1974	1974- 1975	1975- 1976	1976- 1977	1977- 1978	1978- 1979	1979- 1980	1980- 1981	1981- 1982	1982- 1983	1983- 1984	1984- 1985	1985- 1986
1. डीपरा	10.31	14.98	20.22	18.10	20.30	21.49	24.56	27.74	33.75	50.41	59.41	69.57	
2	112.31	112.51	111.51	18.71	19.65	19.38	19.61	19.20	18.93	12.25	12.85	13.17	
2. जलपिण्ड	-	-	8.02	8.04	9.52	10.23	11.20	12.97	16.32	16.44	18.77	21.05	
			14.51	13.81	14.53	14.46	14.38	14.30	14.32	13.99	14.06	13.99	
3. झारखण्ड	5.16	7.31	9.80	11.67	11.73	13.23	14.93	17.66	25.27	29.40	31.41	33.81	
	16.21	16.11	15.51	15.61	15.58	15.77	15.84	15.86	16.69	17.14	16.80	16.40	
4. बरौली	5.16	7.36	10.34	10.13	11.33	11.84	12.50	15.78	18.71	16.72	18.23	21.12	
	16.31	16.21	15.81	14.91	15.39	15.17	14.89	15.23	14.95	14.06	13.94	14.00	
5. गोरखपुर	3.04	4.95	7.49	10.12	11.04	11.66	10.42	12.49	15.48	15.32	15.15	17.48	
	13.61	14.21	14.31	14.81	15.25	15.08	14.08	14.14	14.10	13.72	13.28	13.31	
6. कानपुर	14.97	21.99	30.28	30.52	33.33	36.01	40.46	45.03	53.68	57.61	64.21	72.85	
	117.91	118.31	117.21	114.61	115.84	115.72	115.83	114.93	114.20	113.99	113.89	113.79	
7. लखनऊ	13.49	19.79	31.29	49.64	36.34	44.24	50.00	54.06	72.16	75.71	87.23	107.20	
	116.21	116.31	117.81	123.81	117.27	119.31	119.56	117.93	119.10	118.39	118.86	120.30	

परिक्षे का नाम	1973- 1974	1974- 1975	1975- 1976	1976- 1977	1977- 1978	1978- 1979	1979- 1980	1980- 1981	1981- 1982	1982- 1983	1983- 1984	1984- 1985
8. मेरठ	14.87	21.08	24.21	31.55	35.75	38.43	43.85	56.78	20.42	20.06	23.72	24.76
	117.81	117.51	113.81	115.11	116.99	116.77	117.15	118.83	15.40	14.87	15.14	14.69
9. गान्ध्याबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	50.12	52.97	57.88	64.48
									113.26	112.87	112.54	112.21
10. सुरादाबाद	3.04	4.42	6.09	6.82	7.17	7.55	8.21	10.11	11.61	11.42	12.17	14.27
	13.61	13.71	13.51	13.31	13.41	13.29	13.21	13.35	13.27	12.78	12.63	12.70
11. तबारापुर	7.29	10.04	16.85	18.54	20.03	18.71	21.34	28.80	33.21	34.76	39.48	43.91
	18.71	18.31	19.81	18.91	19.52	18.17	18.35	19.55	18.79	18.45	18.54	18.31
12. वाराणसी	6.16	8.26	11.21	13.63	13.82	15.74	18.15	20.14	27.15	30.76	34.57	37.69
	17.41	16.91	16.31	16.51	16.57	16.87	17.10	16.68	17.18	17.48	17.48	17.14
योग उत्तर प्रदेश	83.49	120.18	175.80	208.76	210.36	229.13	255.62	301.56	377.88	411.58	462.23	528.19

नोट : 111 तन् 1975-76 में अमीनद नया परिक्षे काया गया ।

121 तन् 1980-81 तक मेरठ तथा गान्ध्याबाद परिक्षों के अंक एक ही में सम्मिलित हैं ।

131 कोष्ठक में उत्तर प्रदेश के कुल बिजुली कर में प्रत्येक परिक्षे के बिजुली कर संयुक्त का प्रतिशत दर्शाया गया है ।

वृद्धि उल्लेखनीय हुई थी। मेरठ परिक्षेत्र में तन् 1981-82 में उल्लेखनीय कमी हुई लेकिन इसका कारण यह था कि इसमें से एक नया परिक्षेत्र गाजियाबाद बनाया गया। विभिन्न परिक्षेत्रों में बिजुली कर की राशि स्वाभाविक रूप से उत क्षेत्र में उद्योग एवं व्यापार के स्तर एवं मात्रा से प्रभावित होती है।

5. जिलेवार बिजुली कर आगम

तन् 1971-72 और उसके बाद 1984-85 तक कुछ वर्षों के जिलेवार बिजुली राजस्व के आकड़े तालिका नं० 5.9 में दर्शाये गये हैं। तन् 1971-72 में सबसे अधिक बिजुली कर की प्राप्ति कानपुर जिले में 19.85 करोड़ रुपये हुई थी। इसके पश्चात् क्रमशः लखनऊ 18.39 करोड़ रुपये, आगरा 15.58 करोड़ रुपये, और इलाहाबाद 12.58 करोड़ रुपये का स्थान था। तन् 1984-85 में बिजुली कर राजस्व की दृष्टि से प्रथम 6 जिलों में क्रमशः लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, महारनपुर तथा इलाहाबाद का स्थान था। विभिन्न जिलों में औद्योगिक विकास और व्यापारिक क्रियाओं का बिजुली कर राजस्व पर प्रभाव पड़ता है। इस सन्दर्भ में प्रस्तुत तालिका नं० 5.9 में जिले तन् 1984-85 के प्राप्त राजस्व के क्रम में दिये गये हैं जिसके अनुसार कुल 56 जिलों में 4 जिले 50 करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक का अंशदान करते हैं, तीन जिले 20 करोड़ रुपये प्रत्येक का। से अधिक अंशदान करते हैं, और 5 जिले 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक का बिजुलीकर जुटाते हैं। 11 जिले 1 करोड़ रुपये वार्षिक से भी कम बिजुली कर एकत्रित कर पाते हैं और 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये तक 15 जिले बिजुलीकर संग्रह करते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि मात्र 4 जिले व लखनऊ, कानपुर, आगरा और गाजियाबाद प्रान्त भर में कुल बिजुलीकर संग्रह का आधा से अधिक 155.96 प्रतिशत भाग प्रदान करते हैं।

6. बिजुली कर का वस्तुवार विश्लेषण

उत्तर प्रदेश में जिन वस्तुओं से बिजुली कर राजस्व की प्राप्ति होती है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा 103 वस्तुओं में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य वस्तुओं से बिजुली कर आगम को 104वीं मद में अन्य वस्तुओं के रूप में दिखाया जाता है। तन् 1978-79 से तन् 1984-85 तक इन वस्तुओं के सम्बन्ध में बिजुलीकर संग्रह के आकड़े उपलब्ध

विश्वी कर राजस्व प्राप्ति के विनिवार अंकित 12

विश्वी का नाम	वर्षों के लिए									
	1971-72	1975-76	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. लखनऊ	839	2770	3782	4319	4564	6170	6581	7626	9497	
2. कानपुर	985	2636	3479	3916	4358	5217	5582	6223	7069	
3. आगरा	558	1809	1994	2297	2575	3153	4305	5626	6649	
4. गाजियाबाद	-	-	-	3020	3346	4958	5184	5679	6344	
5. महाराष्ट्र	162	907	1013	1103	1392	1598	1788	2118	2248	
6. झारखण्ड	258	730	820	921	1119	1649	2010	2078	2207	
7. मेरठ	767	2421	3601	1076	1377	1615	1641	1959	2039	
8. वाराणसी	215	613	835	902	1071	1213	1425	1579	1823	
9. मिर्जापुर	220	399	502	615	699	1281	1376	1569	1625	
10. अलीगढ़	147	406	539	623	755	995	1001	1166	1365	
11. मुजफ्फरनगर	149	419	441	593	937	1015	935	1085	1270	
12. बरेली	193	493	607	630	3707	801	785	892	1038	
13. देहरादून	161	338	394	424	526	678	729	730	852	
14. मुरादाबाद	109	350	440	493	585	710	707	727	784	

प्रातिमास स्वयं शै

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. मैनीताल	81	236	317	361	523	685	557	581	727
16. गोरखपुर	85	362	491	386	468	580	550	523	639
17. झुन्डगढ	70	206	241	289	455	481	478	537	541
18. बाली	48	121	173	203	285	313	364	443	466
19. मधुरा	41	110	155	159	199	222	236	316	309
20. गौन्डा	32	73	126	124	151	202	198	190	281
21. बिजनौर	43	140	163	170	213	215	205	226	270
22. गान्धवापुर	30	101	136	140	191	228	207	255	257
23. रायबरेली	9	29	57	71	90	137	140	208	251
24. सीतापुर	43	125	159	172	181	230	219	196	246
25. रामपुर	24	59	83	99	124	146	161	184	221
26. उरई जालीन	19	77	97	111	127	174	182	182	220
27. मैथुरी	38	104	125	143	158	193	192	212	219
28. उन्नाव	35	105	121	130	145	151	178	197	218
29. धीरी	42	93	156	164	198	200	187	171	212
30. बटावा	38	109	150	149	165	194	192	202	208
31. कैजाबाद	30	90	106	104	128	154	160	177	180

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. पीलीभीत	37	102	111	116	175	171	161	148	171	
33. रटा	27	81	110	115	124	146	133	144	162	
34. राजमढ़	32	89	121	111	126	133	142	150	161	
35. हमीरपुर	15	51	74	85	70	112	107	130	159	
36. बांटा	24	42	74	74	56	119	124	136	156	
37. बहराइच	24	83	124	129	129	166	157	156	154	
38. फरखाबाद	25	68	99	89	95	125	126	153	151	
39. पीढ़ी गढ़वाल	23	54	59	54	65	85	66	70	150	
40. बस्ती	20	86	78	77	114	150	163	151	140	
41. हरदोई	21	64	72	66	94	145	130	144	133	
42. देवरिया	17	57	78	63	77	95	105	107	129	
43. जौनपुर	14	42	51	57	73	96	112	120	126	
44. बाराबंकी	15	47	62	68	88	106	108	122	125	
45. बदायूँ	25	68	88	88	108	130	100	127	114	
46. गाजीपुर	16	31	130	181	105	59	88	102	99	
47. बलिया	15	37	56	61	66	66	74	87	97	
48. ललितपुर	-	22	25	37	45	49	56	78	69	

राशि लाख रुपये में।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49. फरीदपुर	11	22	40	37	35	75	64	58	64
50. तुलसानपुर	9	28	43	48	55	68	59	61	63
51. प्रतापगढ़	5	17	21	24	29	36	33	37	40
52. अल्मोड़ा	8	27	45	37	46	56	44	47	38
53. पिथौरागढ़	2	6	17	18	19	28	24	25	25
54. उत्तर काशी	1	7	15	8	16	19	16	13	17
55. टिहरी गढ़वाल	4	13	9	6	9	12	7	2	5
56. बमौली	2	6	11	6	14	6	4	2	1
योग : उत्तर प्रदेश	58.65	175.80	229.13	255.62	301.56	377.88	411.58	462.39	528.19

नोट : गाजियाबाद 1978-79 तक मेरठ में सम्मिलित था ।

सलिलपुर 1971-72 तक हरिती में सम्मिलित था ।

12. पूर्वोक्त, पृ० 12.

है । बिड़ौकर आगम की दृष्टि से तीस शीर्षस्थ वस्तुओं का विवरण तालिका नं० 5. 10 में दर्शाया गया है ।

प्रस्तुत तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि राज्य में बिड़ौकर से सर्वाधिक प्राप्त आधान्न और दानों से होती है, जो कुल बिड़ौकर आगम के 8 से 9 प्रतिशत तक रहा है । इसी राशि में भी लगभग एक चौथाई से अधिक भाग अकेले "फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया, लखनऊ" से प्राप्त होता है । इसके पश्चात् चार महत्वपूर्ण मद्रों में उर्वरक, वनस्पति घी, लोहा एवं स्पात तथा दवाइयाँ एवं कीटनाशक उल्लेखनीय हैं । इन मद्रों से प्राप्त आगम का मुख्य आधार इन मद्रों से सम्बन्धित बड़ी-बड़ी निर्माण इकाइयाँ हैं । रासायनिक उर्वरक में इफको फूलपुर, इलाहाबाद इण्डियन फार्म फर्टीलाइजर कं० लि० लखनऊ तथा फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया, लखनऊ, वनस्पति घी के क्षेत्र में हिन्दुस्तान लीवर लि० गाजियाबाद अमृत वनस्पति कं० लि०, गाजियाबाद, गौना फ्लोर मिड कानपुर तथा प्राग आइस सण्ड आइस मिल, अलीगढ़ और औषधि तथा कीटनाशक क्षेत्र में डाबर ।डा० सत०के० बर्मन। प्रा०लि०, हाथरस, अलीगढ़ उल्लेखनीय इकाइयाँ हैं । लोहा एवं स्पात के क्षेत्र में राज्य में कुछ मनी स्पात संयंत्र अवश्य हैं, लेकिन अधिकांश आय इसकी व्यापारिक क्रियाओं से प्राप्त होती है ।

तालिका नं० 5. 10 से यह भी स्पष्ट है कि 104 वस्तु वर्गों में से मात्र 30 वस्तुओं से कुल बिड़ौकर आगम का लगभग दो-तिहाई भाग प्राप्त हो जाता है । विभिन्न वर्षों में विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त कर आगम के आनुपातिक प्रतिशतों में उच्चावचन होते रहे हैं, लेकिन कुलनात्मक स्थिति बहुत कुछ एक ही रही है ।

वस्तु का नाम	राशि करोड़ रुपये में													
	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85							
राशि प्रतिगत राशि प्रतिगत राशि प्रतिगत राशि प्रतिगत राशि प्रतिगत राशि प्रतिगत														
आयान्न अनाज एवं दालों सहित।	18.67	9.08	19.48	8.55	23.00	8.47	29.80	8.63	32.15	8.37	34.03	8.20	41.17	8.29
रासायनिक उर्वरक	10.08	4.91	9.06	3.97	11.87	4.37	19.20	5.56	21.55	5.60	21.75	5.24	24.16	4.86
वनस्पति। परिशोधित नारियल तेल सहित।	10.46	5.09	10.63	4.66	13.91	5.12	16.67	4.83	18.21	4.74	19.48	4.69	23.92	4.81
लोहा एवं इस्पात	5.06	2.46	5.83	2.56	8.30	3.06	14.65	4.25	16.07	4.19	14.82	3.57	22.93	4.61
दवाइयाँ एवं रसायन सम्बन्धी निर्मित पदार्थ। कीटाणुनाशकों एवं पैस्टीसाइड्स सहित।	7.59	3.69	8.52	3.74	10.35	3.81	12.89	3.74	12.22	3.18	13.83	3.34	21.56	4.34
मोटर गाड़ी। मोटर के टायर, पुजों एवं टायर ट्यूबों सहित।	7.60	3.70	6.27	2.75	8.44	3.11	13.89	4.03	15.69	4.09	13.58	3.27	17.71	3.56
विद्युत ताप-सज्जा का सामान एवं बिजली मोटर, उर्जा के हस्तान्तरण, वितरण और उत्पादन में काम आने वाले संयन्त्र	5.89	2.86	6.76	2.97	3.74	1.38	8.51	2.47	10.69	2.78	14.22	3.42	16.50	3.32
सीमेंट	3.96	1.93	4.67	2.05	4.31	1.59	5.10	1.48	10.74	2.79	12.76	3.10	15.90	3.20
गुड़	5.11	2.49	8.45	3.71	11.44	4.21	10.54	3.05	7.06	1.84	11.86	2.85	13.30	2.68
मीन और मीन के पुजे	4.77	2.32	5.99	2.63	13.44	4.95	9.37	2.72	11.57	3.01	11.19	2.70	13.08	2.63
किरोस्तिन। मिट्टी का। तेल	4.65	2.26	5.18	2.27	6.24	2.30	8.46	2.45	9.27	2.41	11.15	2.69	11.71	2.36
किराना	6.25	3.04	6.36	2.79	5.95	2.19	7.30	2.12	6.95	1.81	8.03	1.94	9.72	1.96
बिजली के सभी सामान, यन्त्र, उपकरण, पंखे, बल्ब आदि	3.42	1.66	2.80	1.23	3.93	1.45	5.61	1.62	5.29	1.38	6.14	1.48	7.88	1.59

55

वस्तु का नाम

1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85

राशि प्रतिवर्ष राशि प्रतिवर्ष राशि प्रतिवर्ष राशि प्रतिवर्ष राशि प्रतिवर्ष राशि प्रतिवर्ष राशि प्रतिवर्ष

14. लकड़ी एवं सभी प्रकार की इमारती लकड़ी का उत्पादन और कानों की लकड़ी के आयात

4.39 2.14 4.24 1.86 5.49 2.02 7.89 2.29 5.96 1.55 4.93 1.19 7.46 1.50

15. ईट

3.50 1.70 3.98 1.75 5.62 2.07 5.89 1.71 5.92 1.54 6.40 1.54 7.25 1.46

16. रेलमार्ग नियम तार

2.34 1.14 2.77 1.21 3.17 1.17 5.19 1.51 5.87 1.53 5.94 1.43 6.81 1.37

17. लकड़ी, रिसा एवं बटनों की लकड़ी एवं इनके सहायक और लकड़ी टायर-टयूब

2.89 1.41 3.43 1.50 3.44 1.27 4.42 1.28 4.77 1.24 5.94 1.43 6.63 1.33

18. लकड़ी

1.53 0.94 2.10 0.92 2.46 0.91 3.62 1.04 4.88 1.27 6.38 1.54 6.34 1.28

19. मोटर लकड़ी, मोटर स्क्रू, मोटर और इनके टायर-टयूब

3.27 1.59 4.60 2.02 7.07 2.60 8.19 2.37 9.56 2.49 5.48 1.32 6.33 1.27

20. सभी प्रकार के जूते, चप्पल आदि

3.07 1.49 3.76 1.65 4.08 1.50 4.50 1.30 4.69 1.20 5.02 1.20 6.23 1.25

21. चाय और कॉफी

2.14 1.04 2.64 1.16 2.86 1.05 2.88 0.84 4.08 1.06 4.90 1.18 6.09 1.23

22. कपड़े धोने का साबुन एवं धोने में प्रयुक्त अन्य वस्तुएं

3.16 1.54 2.94 1.29 1.78 0.66 2.14 0.62 2.81 0.73 3.20 0.77 5.85 1.18

23. ट्रेक्टर, ट्रैक्टर पुंज और अन्य सहायक सामान

2.85 1.39 3.63 1.59 4.67 1.72 6.72 1.95 5.56 1.45 6.38 1.54 5.78 1.16

24. सभी प्रकार के तेल

2.30 1.12 2.10 0.92 2.47 0.91 2.07 0.60 3.11 0.81 4.78 1.15 5.52 1.11

25. सभी प्रकार के चिकनाईयुक्त वस्तुएं

1.86 0.90 1.83 0.80 2.13 0.78 2.70 0.78 2.72 0.71 8.58 2.07 5.46 1.10

क्र० सं०	वस्तु का नाम	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85							
	राशि प्रतिशत राशि प्रतिशत राशि प्रतिशत राशि प्रतिशत राशि प्रतिशत राशि प्रतिशत														
26.	सूती धागा	2.16	1.05	2.16	0.95	3.48	1.28	3.67	1.06	3.77	0.98	4.46	1.07	4.74	0.95
27.	सभी प्रकार के कागज	2.43	1.18	2.65	1.16	3.45	1.27	4.11	1.19	3.89	1.01	4.05	0.98	4.16	0.84
28.	सभी प्रकार के उर्वरक।ईंधन मूल सहित।	1.95	0.95	2.10	0.92	2.50	0.92	2.53	0.73	2.59	0.68	3.35	0.81	3.77	0.76
29.	स्प्रिट और सभी प्रकार के सुरासाखुल, तंबाकू पत्त, वृत्रिम स्प्रिट, मियाऊन अल्कोहल सहित, देसी घेय के अतिरिक्त	1.04	0.51	1.86	0.62	1.61	0.59	2.79	0.81	2.70	0.70	3.66	0.88	3.59	0.72
30.	रंग रौमन	0.93	0.45	1.19	0.48	1.39	0.51	1.45	0.42	2.53	0.66	2.81	0.68	3.39	0.68
	अन्य वस्तुएँ	70.23	34.17	79.99	35.09	88.91	32.75	112.21	32.53	131.12	34.15	135.89	32.75	161.92	32.59
	104 वस्तुओं से कुल कर आगम	205.55	100	227.97	100	271.50	100	344.96	100	383.99	100	414.99	100	496.86	100
	दजीयन, लाइसेन्स, बकाया तथा विविध से प्राप्तियाँ	25.68		29.92		32.04		35.64		30.35		49.62		34.68	
	कर वापसी	231.23		257.89		303.54		380.60		414.34		464.61		531.54	
	कुल योग	2.09		2.26		1.98		2.72		2.77		2.38		3.34	
		229.14		255.63		301.56		377.88		411.57		462.23		528.20	

13. पूर्वोद्धृत, पृ० 25-30 पर आधारित ।

बिड़्डीकर आगम की प्रवृत्तियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस आगम में निरन्तर और तीव्र गति से वृद्धि होती रही है और आज राज्य सरकार से कर आगम का लगभग आधा भाग बिड़्डीकर से ही प्राप्त होता है, लेकिन यह भी स्वीकार करना होगा कि कर लागू होने के लगभग 38 वर्षों के बाद भी इस कर व्यवस्था में प्रशासनिक और व्यापारिक दोनों दृष्टिकोणों से अनेक समस्यायें विद्यमान हैं। प्रशासनिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या करापवंचन की समस्या है। यद्यपि प्रशासन इसके लिए व्यापारियों को उत्तरदायी ठहराता है, लेकिन व्यापारियों द्वारा रखे जाने वाले इस तथ्य में भी पर्याप्त सत्यता है कि बिड़्डीकर विभाग में व्याप्त भ्रष्ट नीतियाँ और पद्धतियाँ इसके लिए बड़ी सीमा तक उत्तरदायी हैं। प्रशासनिक दृष्टि से जो अन्य समस्यायें अनुभव की जाती हैं उनमें अन्तराज्यीय व्यापार में प्रयुक्त प्रपत्र 31 के कानूनी, नष्ट होने और दुरुपयोग करने की समस्या, प्रपत्र "ती" के दुरुपयोग की समस्या, बिड़्डी कर विभाग में करदाताओं की पत्रावलियों की स्कूटनी कार्य में शिथिलता, बिड़्डी कर अधिकारियों द्वारा अभिगृहीत बहीखातों को निर्धारित अवधि से अधिक अवधि तक रखना, जिला स्तरीय मासिक बैठकों में बिड़्डीकर अधिकारियों का अनुपस्थित रहना तथा बिड़्डी कर अवशेषों की धनराशि में निरन्तर वृद्धि उल्लेखनीय है। व्यापारी वर्ग भी बिड़्डी की जटिलता, क्रियान्वयन की कठिनसद्वयों और बिड़्डी कर प्रशासन की भ्रष्ट नीतियों से बहुत निरुत्साहित है। व्यापारी वर्ग का यह आरोप है कि दूरी शिकायतों के आधार पर किये गये सर्वेक्षणों से व्यापार का उत्पीड़न होता है, जाँच-वाँकी के निरुद्ध अधिकारियों की घाटों के निस्तारण की प्रक्रिया में भिन्नता रहती है, अभिगृहीत माल के विस्तृत अर्थ-दण्ड की कार्यवाही निर्धारित अवधि में पूरी नहीं हो पाती है, बिड़्डी कर नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक विभिन्न फार्मों का कृत्रिम अभाव रहता है, अनेक बार अनावश्यक कारणों से बिड़्डी कर अधिकारियों द्वारा माल को रास्ते में रोक लिया जाता है, राज्य में बिड़्डी कर की दरें तुलनात्मक रूप से काफी अधिक हैं और उस पर भी अतिरिक्त बिड़्डी कर का अनुचित और अनावश्यक भार बढ़ा दिया गया है, स्वतः कर निर्धारण योजना का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाया है और पंजीयन में भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों का यह कहना भी है कि बिड़्डी कर प्रावधानों में समय-समय पर आकस्मिक परिवर्तन घोषित किये जाते रहते हैं जिनकी पूर्ण और

उचित जानकारी व्यापारियों को नहीं मिल पाती । सामान्य परिस्थितियों में तांछिकीय आकड़ों में व्यापक भिन्नताएं, जांच चौकियों पर उचित व्यवस्था का अभाव अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय के पर कार्यालय न पहुंच पाना, ट्रान्जिट पात । 'वहती' की समस्या, ट्रान्स्पॉर्टों को कर निर्धारण के समय पर प्रस्तुत करने का अवसर न मिलना, बिजुली कर अधिकारी और व्यापारी के मध्य सम्बन्धित हो जाने से कर निर्धारण से सम्बन्धित प्रथम त्तरीय अपीलों का कम होना तथा बिजुली कर प्रशासन में विद्यमान व्यापक भ्रष्टाचार उत्तेजनीय है ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने मुक्तता इस बात की ओर ध्यान दिया है कि इस कर से अधिकाधिक आगम किस प्रकार प्राप्त किया जाए । लेकिन कर व्यवस्था को सरल, व्यवस्थित, विवेकपूर्ण, प्रभावशाली तथा आधुनिक बनाने की ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया और यदि कुछ प्रयास राज्य सरकार द्वारा किये भी गये हैं तो प्रशासन की कमियों और व्यापारियों की होशियारी के कारण उन्हें प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा सका । इन सभी परिपेक्ष्यों के सन्दर्भ में राज्य बिजुली कर व्यवस्था और प्रशासन में आवश्यक संशोधन एवं सुधार करने की महती आवश्यकता है।

-----::0::-----

अध्याय छठम

बिहारीकर : प्रशासनात्मक पद्धत एवं दायित्व उत्तर प्रदेश के तन्दर्भ में।

अध्याय-6

बिड़ी कर : पुरातनात्मक पहलु एवं ढाँचा

उत्तर प्रदेश के तन्दर्भ में।

बिड़ी कर पुरातन की व्यवस्था को लेकर विभिन्न राज्यों में बिड़ी कर आयुक्त के आधीन बिड़ी कर विभाग का संगठन किया गया। बिड़ी कर आयुक्त के आधीन उपायुक्त, सहायक आयुक्त, बिड़ी कर अधिकारी एवं बिड़ी कर निरीक्षक होते हैं। कुछ राज्यों में व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों की एक सलाहकार समिति "बिड़ी कर पुरातन" तथा करदाताओं में एक सम्पर्क स्थापन का कार्य करती है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में बिड़ी कर अधिनियम को व्यवहार में अपनाने हेतु विविध पदाधिकारियों की वित्तुत संज्ञा स्थापित की गई है। सर्वोच्च स्तर पर बिड़ी कर आयुक्त होता है। आयुक्त की सहायताार्थ राज्य सरकार अनेक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। बिड़ी कर अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य को परिक्षेत्रों तथा क्षेत्रों में विभाजित किया है। प्रत्येक क्षेत्र मण्डल एवं उपमण्डल में बँटा होता है। प्रत्येक मण्डल एवं उपमण्डल बिड़ी कर अधिकारी के नियन्त्रण में होते हैं।

उत्तर प्रदेश में बिड़ी कर पुरातन के विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से वित्तुत पुरातनिक ढाँचा परिशिष्ट 131 में दिखाया गया है।

बिड़ी कर व्यवस्था एवं पुरातन के सम्पूर्ण ढाँचे को कार्य स्थान की दृष्टि से दो मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है :-

1. मुख्यालय संगठन एवं
2. क्षेत्र संगठन।

मुख्यालय संगठन

बिड़ीकर विभाग का मुख्यालय तत्काल में है। आयुक्त बिड़ीकर विभागाध्यक्ष है और उन्हीं के सामान्य पुरातनिक नियन्त्रण में विभाग का कार्य सम्पन्न होता है। आयुक्त को भारतीय पुरातनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल के वेतनमान

पर नियुक्त किया जाता है। आयुक्त के बाद विभाग का दूसरा अधिकारी उप-आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीनियर स्केल के वेतनमान पर नियुक्त किया जाता है। दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक उपायुक्त प्रशासन होता है। विभागीय कार्यों की देख-रेख के लिये मुख्यालय पर एक उपायुक्त मुख्यालय तथा एक उपायुक्त धारा 35 का पद होता है। करापर्वत की रोकथाम के लिए कार्यरत जांच-वांकी एवं तलाश दल स्कीम की देख-रेख के लिए उपायुक्त जांच-वांकी एवं तलाश दल का पद भी है। राज्य वित्त एवं लेखा सेवा के लिए उपायुक्त संग्रह तथा उपायुक्त लेखा का एक-एक पद है।

अन्य कार्यों की देख-रेख के लिए सहायक आयुक्त विधि, सहायक आयुक्त वाद, सहायक आयुक्त परिवाद, सहायक आयुक्त विशेष अनुसन्धान शाखा तथा सहायक आयुक्त स्थापना के एक-एक पद हैं। तांछिकीय कार्यों के लिए उप निदेशक संख्या का एक पद तथा संख्याधिकारी के दो पद हैं। लेखा बजट तथा आन्तरिक तम्रेश तम्बन्धी कार्यों के लिए वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी का एक पद है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी के रूप में दो बिजु कर अधिकारी तथा संग्रह कार्यों के लिए दो, विधि के लिए एक तथा शोध एवं कम्प्यूटर कार्यों हेतु दो-दो, न्याय के दो, वाद, परिवाद एवं स्थापना के लिए दो-दो तथा धारा 35 के लिए एक बिजु कर अधिकारी का पद है। लेखा, बजट तथा आन्तरिक तम्रेश तम्बन्धी कार्यों के लिए सहायक लेखाधिकारी का भी एक पद है।

उपायुक्त प्रशासन का पद प्रान्तीय सिविल सर्विस अधिकारी का पद है। उपायुक्त के अधीन एक बिजु कर अधिकारी होता है। उपायुक्त मुख्यालय के अधीन राज्य प्रतिनिधि के रूप में उन्नीत बिजु कर अधिकारी, हाईकोर्ट के लिए दो सहायक आयुक्त तथा एक बिजु कर अधिकारी, वाद के लिए एक सहायक आयुक्त तथा दो बिजु कर अधिकारी, तांछिकीय कार्यों के लिए एक उपनिदेशक संख्या तथा दो संख्याधिकारी होते हैं। उपायुक्त संग्रह के अधीन दो बिजु कर अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार उपायुक्त लेखा के अधीन एक वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी तथा एक सहायक लेखाधिकारी होता है।

तहायक आयुक्त।विधि। के अधीन दो बिजुी कर अधिकारी।विधि। तथा बिजुी कर अधिकारी।शोध। होते हैं। तहायक आयुक्त।परिवाद। तथा तहायक आयुक्त।स्थापना। के अधीन भी दो-दो बिजुी कर अधिकारी होते हैं।

क्षेत्र तंगठन

उत्तर प्रदेश में बिजुी कर निर्धारण, एकत्रण एवं प्रशासनिक दृष्टि से क्षेत्र कार्य को करने के लिए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्रदेश को परिक्षेत्र, क्षेत्र, मण्डल, उपमण्डल और ब्लॉक में विभक्त किया गया है। प्रदेश ^{के} कुल मिलाकर 12 परिक्षेत्रों में रखा गया है और प्रत्येक परिक्षेत्र के नियन्त्रण के लिए एक उपायुक्त।शासकीय। नियुक्त किया गया है। मेरठ और माधियाबाद परिक्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी परिक्षेत्रों को दो-दो क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में 22 क्षेत्र हैं और प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक तहायक आयुक्त।शासकीय। कार्यरत है। सन् 1984-85 में उत्तर प्रदेश में कुल 99 मण्डल, 8 उपमण्डल कार्यरत रहे। 44 बहुखण्डीय मण्डल कार्यालयों को 176 ब्लॉकों में विभक्त किया गया। मण्डल/उपमण्डल/ब्लॉकों में कार्यभार के अनुसार प्रदेश में कुल मिलाकर सन् 1984-85 में बिजुी कर अधिकारी के स्वीकृत पद 759 थे जिनमें से केवल 672 पदों पर बिजुीकर अधिकारी कार्यरत रहे। इसी प्रकार कुल बिजुीकर अधिकारी ग्रेमी-2 के स्वीकृत पद 642 थे जिनमें से केवल 409 पदों पर बिजुी कर अधिकारी ग्रेमी-2 कार्यरत रहें। प्रदेश में बिजुी कर के परिक्षेत्र, क्षेत्र, मण्डल, उपमण्डल तथा ब्लॉकों का वितरित वितरण परिशिष्ट ब में दर्शाया गया है।

बिजुी कर प्रशासन व्यवस्था में न्यायिक व्यवस्था भी की गयी है। यदि व्यापारी "कर निर्धारण अधिकारी" द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय से तन्तुष्ट नहीं है तो वह ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। बिजुी कर विभाग की सम्पूर्ण न्यायिक व्यवस्था को निम्न स्तरों में विभाजित किया जा सकता है :

1. तहायक आयुक्त।न्याय।

बिजुी कर अधिकारी तथा बिजुी कर अधिकारी ग्रेमी-2 के कर निर्धारण

आदेशों के विरुद्ध दायर की गई अपीलों की सुनवाई तहायक आयुक्त (न्याय) बिछी कर करते हैं ।

।ब। उपायुक्त (अपील)।

तहायक आयुक्त (कर निर्धारण) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों की सुनवाई उपायुक्त (अपील) द्वारा की जाती है ।

।त। बिछी-कर न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल)।

यदि कोई व्यक्ति तहायक आयुक्त (न्याय) या उपायुक्त (अपील), पुनर्विचार करने वाले अधिकारी (बिछीकर आयुक्त) अथवा विवादास्पद प्रश्न पर आयुक्त के आदेश से तन्मूक्त नहीं है तो वह ऐसे आदेश के विरुद्ध बिछी कर न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) को अपील कर सकता है ।

।द। उच्च न्यायालय (कार्य)।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा लखनऊ में आवश्यकतानुसार विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिये तहायक आयुक्त (उच्च न्यायालय कार्य), बिछी कर अधिकारी तथा बिछी कर अधिकारी ग्रेजी-2 कार्यरत हैं ।

बिछी कर पदाधिकारी : कार्यक्षेत्र, अधिकार एवं कर्तव्य

बिछी कर प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्र, अधिकार एवं उनके कर्तव्यों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है :-

बिछी कर आयुक्त

बिछी कर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है । आयुक्त के कार्यक्षेत्र, तथा मुख्य अधिकारों एवं कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :

1. आयुक्त का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राज्य है और यह बिछी कर अधिनियम

के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करता है। अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में बिछीकर अधिनियम एवं नियमों के अधीन निर्देश जारी कर सकता है तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों, अपीलेट अधिकारियों को छोड़कर, को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

2. यदि किसी एक क्षेत्र में एक से अधिक तहायक आयुक्त (शासकीय) या तहायक आयुक्त (न्याय) होते हैं तो आयुक्त उस क्षेत्र में उनके अधिकार क्षेत्र का बँटवारा करता है। इसी प्रकार जब किसी मण्डल में एक से अधिक बिछीकर अधिकारी होते हैं तो आयुक्त उस मण्डल में उनके अधिकार-क्षेत्र का बँटवारा करता है। यह बँटवारा निर्धारित व्यापारियों के वर्ग के आधार पर होता है। सामान्यतः किसी तहायक आयुक्त या बिछीकर अधिकारी का स्थानान्तरण होने पर उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी का अधिकार क्षेत्र वही होता है, जो जाने वाले अधिकारी का था, लेकिन यदि आयुक्त जाँचें तो उनके अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है।
3. आयुक्त किसी भी मामले को या मामले के वर्ग को एक मण्डल में एक निर्धारण अधिकारी से दूसरे कर-निर्धारण अधिकारी को हस्तान्तरित कर सकता है।
4. अपील की सुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व आयुक्त किसी अपील को स्वेच्छा से या व्यापारी द्वारा प्रार्थना करने पर किसी मामले या मामले के वर्ग को किसी एक उपायुक्त (अपील) से दूसरे उपायुक्त (अपील) या किसी एक तहायक आयुक्त (न्याय) से दूसरे तहायक आयुक्त (न्याय) या उपायुक्त (अपील) को हस्तान्तरित कर सकता है।
5. आयुक्त किसी व्यापारी या अन्य किसी व्यक्ति को जित पर बिछीकर अर्थदण्ड या अन्य राशि को एक लाख रुपये से अधिक बढ़ाया है, अधिकतम 12 मासिक किस्तों में भुगतान की स्वीकृति दे सकता है। ऐसी व्यापारी या व्यक्ति को ऐसी स्वीकृति के 60 दिन में अध्या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बढ़ाये गये समय में उचित प्रतिभूति प्रस्तुत कर देनी चाहिए अध्या ऐसी स्वीकृति या आदेश रद्द समझा जावेगा।

अपर आयुक्त बिछीकर

अपर आयुक्त से आशय उस पदाधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा

अतिरिक्त आयुक्त के अधिकारों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया हो। यह आयुक्त के सामान्य नियन्त्रण में काम करता है। तथा आयुक्त को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करता है। इसका कार्यक्षेत्र भी पूरा राज्य होता है। अपर आयुक्त बिक्रीकर को अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है।

बिक्री कर उपायुक्त

उप-आयुक्त अपना कार्य आयुक्त के सामान्य नियन्त्रण में करते हैं। ये बिक्रीकर अधिनियम तथा इसके नियमों द्वारा एवं आयुक्त द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इनका कार्यक्षेत्र एक परिक्षेत्र होता है। कार्य संचालन के विविधीकरण की दृष्टि से उपायुक्त स्तर के पदों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है : उपायुक्त (शासकीय), उपायुक्त (अपील), उपायुक्त (विशेष अनुसंधान शाखा), उपायुक्त (प्रशासन), उपायुक्त (वार्ड चौकी) तथा उपायुक्त (संग्रह)।

(अ) उपायुक्त (शासकीय) : वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में उपायुक्त (शासकीय) के 12 पद हैं। प्रत्येक उपायुक्त (शासकीय) के नियन्त्रण में एक-एक परिक्षेत्र आता है। इनके कार्य-क्षेत्र, अधिकारों एवं कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

परिक्षेत्र में उपायुक्त (शासकीय) आयुक्त बिक्री-कर के प्रतिनिधि की तरह से कार्य करते हैं : व्यापारियों, निर्माताओं तथा अधिस्तताओं की समस्यायें सुनना तथा हल करना ; अपने अधीनस्थ तहायक आयुक्त (शासकीय) पर नियन्त्रण रखना ; तहायक आयुक्तों के कार्यालयों का वर्ष में कम से कम एक बार तथा संग्रह कार्यालयों का दो बार निरीक्षण करना ; तहायक आयुक्त (कर निर्धारण) के कार्यालय का निरीक्षण करना ; तहायक आयुक्त (वार्ड-चौकी एवं सजा ठा) के कार्यालय का निरीक्षण करना ; कम्प्यूटर इकाई का वर्ष में एक बार वित्तुत निरीक्षण करना ;

1. मैजुल-5/1984, पत्र संख्या-मैजु0 कार्य विभाजन-3/30/5/84-85-23 मुख्यालय दिनांक जुलाई 10, 1984.

कर तंगुह को बढ़ाये जाने हेतु बड़े-बड़े ककायादारों के मामलों 15 से 10 लाख रुपये तक ककाया राशि होने पर। में मानीटरिंग करना; कोषागार, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, मण्डलायुक्त तथा मुख्यालय से सम्पर्क स्थापित करना; परिशेव के सभी अधिकारियों तथा अपने कार्यालय में कार्यरत स्टाफ के व्यक्तिगत अभिलेखों को नियमानुसार रखवाना, शासन और आयुक्त के आदेशों का नियमानुसार पालन करना, बिक्रीकर अधिकारी ग्रेणी-2 को एक छण्ड से दूसरे छण्ड में तैनात करना, परिशेव के करदाताओं को पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान करना, द्वितीय अपील करने या न करने का अन्तिम निर्णय लेना, 5000 रुपये तक वसूल न होने वाली राशि को बट्टे खाते में डालना, 40,000 रुपये तक वापसी योग्य धनराशि को वापिस करना, 10,000 रुपये से अधिक देय राशि को क्वित्तों में बाँटना, आडिट आपत्तियों के निराकरण में ध्यान देना, कर निर्धारण में सहायक आयुक्त [कर निर्धारण] को परामर्श देना इत्यादि अधिकार एवं कर्तव्य हैं। कुल मिलाकर उपायुक्त [शा०] का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने परिशेव में पूरी तरह प्रभावशाली नियन्त्रण रखे।

14. उपायुक्त [अपील] : सहायक आयुक्त [कर निर्धारण] द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों की सुनवाई उपायुक्त [अपील] द्वारा की जाती है। इस प्रकार की अपीलों की सुनवाई के उद्देश्य से प्रदेश को 6 भागों में विभक्त किया गया है। ये भाग हैं : इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मेरठ तथा नाबियाबाद। प्रत्येक भाग में एक उपायुक्त [अपील] और कुल मिलाकर राज्य भर में 6 उपायुक्त [अपील] हैं।

तालिका नं० 6.1 में उपायुक्त [अपील] के कार्यालय की प्रगति को उद्घृत किया गया है। तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मामूली उच्चावचनों को छोड़कर प्रतिवर्ष उपायुक्त [अपील] के सम्मुख दायर की गई अपीलों की संख्या बढ़ती गयी है। तन् 1976-77 में मात्र 182 अपीलें दायर की गयी थीं, जिनकी संख्या 1984-85 में सर्वाधिक 1771 हो गयी। तन् 1980-81 तक दायर की गई अपीलों

तालिका नं० 6.1

उपायुक्त अपील। बिजुी कर के अधिदेव की अपीलों की स्थिति

वर्ष	1. अपील को अवरोध अपीलों की संख्या	वर्ष में दायर की गयी अपील	अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित अपीलों की संख्या	31 मार्च को अवरोध अपीलों की संख्या
1976-77	-	182	182	56	126
1977-78	126	649	775	188	587
1978-79	587	731	1318	340	978
1979-80	978	828	1806	328	1478
1980-81	1478	742	2220	384	1836
1981-82	1836	1062	2898	1320	1578
1982-83	1578	940	2518	1189	1329
1983-84	1329	1479	2808	1975	833
1984-85	833	1771 ^x 12281	2832	1079	1753

स्त्रोत : आयुक्त बिजुी कर 130501 : तारिखिकीय अनुभाग, बिजुीकर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85, तख्त, पृ० 39.

की संख्या की तुलना में निस्तारित अपीलों की संख्या कम रही। जिससे प्रत्येक वर्ष के अन्त में अवरोध अपीलों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई लेकिन उसके परचाह से निस्तारण में तेजी आने के कारण अवरोध अपीलों की संख्या में गिरावट हुई है, परन्तु तन् 1984-85 में केवल 1079 अपीलों का निस्तारण किया गया जिसके फल-स्वरूप तन् 1984-85 के अन्त में अवरोध अपीलों की संख्या 1753 हो गयी।

दाखिला (दायर) व निस्तारण के आँकड़ों के अनुसार दाखिला गत दो वर्षों से बढ़ा है। इसका कारण तदायक आयुक्त (कर निर्धारण) के पदों में वृद्धि व उनके द्वारा पारित यादों का अधिक संख्या में अपीलों में जाना है।

^x तन् 1984-85 में 228 अपीलों तदायक आयुक्त (न्याय) की पत्रावली से हस्तान्तरित होकर प्राप्त हुयी।

निस्तारण कार्य में वृद्धि की दृष्टि से उपायुक्त। अपील। के पदों की संख्या तथा उनके द्वारा निस्तारित की जाने वाली कोटों की संख्या में वृद्धि करना उल्लेखनीय रहा है। तालिका नं० 6.2 सम्बन्धित स्थिति को स्पष्ट करता है :-

तालिका नं० 6.2

निस्तारित अपीलों का वर्षवार प्रति अधिकारी प्रति/कार्य दिवस औसत निस्तारण

वर्ष	वर्ष में निस्तारित अपील	कार्यशील दिवस	प्रति कार्यशील दिवस औसत निस्तारण	कार्यरत अधिकारियों की संख्या। 31 मार्च।
1976-77	56	-	-	1
1977-78	188	195	0.96	1
1978-79	340	255	1.33	1
1979-80	328	218	1.50	1
1980-81	384	228	1.68	3
1981-82	1320	671	1.96	3
1982-83	1189	654	1.81	6
1983-84	1975	1243	1.58	4
1984-85	1079	648	1.66	3

स्रोत : आयुक्त झिन्डी कर (उत्तर प्रदेश) : त्रैमासिक अनुभाग, झिन्डीकर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85, तलक, पृ० 39.

टिप्पणी : 111 दिसम्बर 1980 तक एक तथा जनवरी 1981 से दो और उपायुक्त। अपील। गैरठ तथा जलाहाबाद ने कार्य प्रारम्भ किया।

121 वर्ष 1977-78 तथा उसके पहले एक अपील प्रतिदिन का निस्तारण कोटा था।

131 1.7.78 से 31.1.1979 तक तीन अपील प्रतिदिन निस्तारण का कोटा था।

141 1.2.79 से वर्तमान में 1.5 अपील प्रतिदिन निस्तारण का कोटा है।

तालिका नं० 6.2 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 31 जनवरी 1979 तक औसत निस्तारण निर्धारित निस्तारण कोटा से कम था लेकिन इसके पश्चात् से औसत निस्तारण तदैव निर्धारित निस्तारण कोटा से अधिक रहा है। यद्यपि सन् 1983-84 में उपायुक्त (अपील) के 6 पद थे लेकिन केवल 4 कार्यरत रहे। इसी प्रकार 1984-85 में भी 6 पद थे, परन्तु केवल 3 उपायुक्त (अपील) कार्यरत रहे।

उपायुक्त अपील द्वारा निस्तारित बिछीकर अपीलों की कर राशि में किये गये संशोधनों का विवरण तालिका नं० 6.3 में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 6.3

निस्तारित बिछीकर की अपीलों के वर्षवार परिणाम तथा घटाई गई/बढ़ाई गई/विवादित कर की धराशि के आँकड़े

वर्ष	अपीलों के परिणाम				कुल निस्तारित अपीलें	राशि/लाभ/हानि में		
	कार्यरत अपीलें	संशोधित अपीलें	स्वी-कृत अपीलें	प्रति-प्रति अपीलें		घटाया गया कर	बढ़ाया गया कर	विवादित कर
1976-77	22 1392.41	12 121.41	11 1195.61	11 119.61	56	4.88	-	72.50
1977-78	43 122.91	62 133.01	42 122.31	41 121.81	188	14.32	-	375.85
1978-80	75 122.11	140 141.21	63 118.51	62 118.21	340	47.86	0.07	405.77
1979-80	78 123.81	109 133.21	72 ⁷² 121.91	46 ⁶⁹ 121.11	328	47.35	-	302.73
1980-81	118 130.71	149 138.81	71 118.51	46 112.01	384	105.16	-	552.65
1981-82	426 132.31	504 138.21	239 118.11	151 111.41	1320	521.06	0.01	3497.52
1982-83	280 123.51	474 139.91	283 123.81	152 112.81	1189	754.55	-	1305.46
1983-84	630 131.91	539 127.31	469 123.71	337 117.11	1975	873.91	0.44	7557.16
1984-85	312 ²³⁹ 128.91	274 125.41	242 122.41	251 123.31	1079	202.36	0.06	3257.34

स्रोत : पूर्वोक्त, पृष्ठ 44.

नोट : कोष्ठक में प्रतिशत के आँकड़े दर्शाये गये हैं।

तालिका नं० 6.3 से स्पष्ट है कि सामान्यतः करों की राशि में कमी ही की गई है, लेकिन अवशेष अपीलों की संख्या एवं विवादग्रस्त कर राशि 1982-83 को छोड़कर निरन्तर बढ़ती रही है। तन् 1984-85 में भी विवादग्रस्त कर राशि 32.57 करोड़ रुपये हैं।

11। उपायुक्त। विशेष अनुसन्धान शाखा।

करापूर्वक की रोकथाम के उद्देश्य से प्रदेश को तीन क्षेत्र-पूर्वी, मध्य और पश्चिमी में विभक्त किया गया है, जिनके मुख्यालय क्रमशः वाराणसी, कानपुर और मेरठ में हैं। प्रत्येक क्षेत्र से एक और राज्य में कुल मिलाकर तीन उपायुक्त।वि० अनु०शा०। कार्यरत हैं। वाराणसी क्षेत्र के अन्तर्गत वाराणसी।प्रथम।, वाराणसी।द्वितीय।, गोरखपुर, लखनऊ, सीतापुर, झांझाबाद तथा कानपुर क्षेत्र में कानपुर।प्रथम।, कानपुर।द्वितीय।, आगरा।प्रथम।, आगरा।द्वितीय।, अलीगढ़, हांसी और मेरठ क्षेत्र में मेरठ, गाजियाबाद।प्रथम।, गाजियाबाद।द्वितीय।, सहारनपुर बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद आते हैं। उपायुक्तों।विशेष अनुसन्धान शाखा। के प्रशासनिक नियन्त्रण में विशेष अनुसन्धान शाखा की 19 इकाइयाँ कार्यरत हैं। ये इकाइयाँ विहीकर अधिनियम अधिकारी।प्रभारी। की देखरेख में कामती हैं। वाराणसी क्षेत्र।पूर्वी क्षेत्र। में 6 इकाइयाँ, कानपुर क्षेत्र।मध्य क्षेत्र। में 6 इकाइयाँ, मेरठ क्षेत्र।पश्चिमी क्षेत्र। में 7 इकाइयाँ आती हैं। इस शाखा की कार्य प्रगति के सन्दर्भ में तमकों की तालिका संख्या 6.4 में दिखाया गया है।

तालिका नं० 6.4 से स्पष्ट है कि विशेष अनुसन्धान शाखा अपने कार्य क्षेत्र में निरन्तर सक्रिय रही है। इस शाखा द्वारा तन् 1979-80, 1983-84 और 1984-85 को छोड़कर प्रतिवर्ष 4000 से ऊपर सवैक्षण किये गये और इस शाखा के कार्य के कारण तन् 1976-77 में 3.18 करोड़ रुपये का अतिरिक्त विही कर एकत्रित किया गया। यह राशि तन् 1977-78 में बढ़कर 9.94 करोड़ रुपये हो गयी। बाद के वर्षों में यह राशि इस प्रकार रही है। 1978-79 14.06 करोड़।, 1979-80 43.73 करोड़।, 1980-81 33.97 करोड़।, 1981-82 35.76 करोड़।,

तालिका नं० 6.4

उत्पादन की रोजगार

विभिन्न अनुभागों का की प्रगति

सं०	सं०	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1.	सामान्य संकेत	556	1383	836	746	766	753	711	449	1259
2.	प्रतिष्ठान संकेत	2342	2263	2176	1729	2025	2460	2099	1632	1767
3.	संकेत जिसमें खाते अभिज्ञान विधे की	1429	1279	1503	1168	1317	1561	1528	1188	913
	कुल संकेत	4327	4925	4515	3643	4108	4774	4338	3269	3941
4.	विचारित विधे का अनुपात	3.18	9.94	4.06	3.73	3.97	5.76	5.47	8.06	7.62

स्रोत : अनुसूची सं० 130 प्र० 1 : त्रिस्तरीय अनुभाग, विद्युत् विभाग का सामान्य वार्षिक प्रगति 1984-85.

सं० 46.

1982-83 35.47 करोड़, 1983-84 48.06 करोड़, 1984-85 47.62 करोड़ थी ।

1द। उपायुक्त (चाँच)

कराचयन की रोकथाम के लिए चाँच चौकी एवं तका टन स्कीम की देख-रेख के लिए उपायुक्त (चेक पोस्ट एवं तका टन) का एक पद है । उपायुक्त (चेक पोस्ट एवं तका टन) का यह पद मुख्यालय तकाऊ में है । इनका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है । इनकी तहायता के लिए क्षेत्र में 4 तहायक आयुक्त (चाँच चौकी एवं तका टन) के पद हैं ।

1य। उपायुक्त (तंगुह)

कर तंगुह योजना के लिए उपायुक्त (तंगुह) का एक पद है । उपायुक्त (तंगुह) का यह पद मुख्यालय तकाऊ में है । इनका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य है । इनकी तहायता के लिए क्षेत्र में 15 डिप्टी क्लेक्टर (तंगुह) के पद हैं ।

1र। उपायुक्त (प्रशासन)

उपायुक्त (प्रशासन) से आशय उन व्यक्ति से है जो राज्य सरकार द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) के अधिकारों को प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया हो । दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक उपायुक्त (प्रशासन) का पद होता है । यह पद मुख्यालय तकाऊ में है । उपायुक्त (प्रशासन) एक प्रान्तीय सिविल सप्लिय का अधिकारी होता है ।

4. तहायक आयुक्त

तहायक आयुक्त भी आयुक्त के सामान्य नियन्त्रण में काम करते हैं । अधिनियम, नियमों एवं आयुक्त द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं । इन कार्यक्षेत्र एक क्षेत्र होता है । तहायक आयुक्त स्तरीय पदों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है - तहायक आयुक्त (आतकीय), तहायक आयुक्त

।न्याय।, तहायक आयुक्त ।जयि चौकी एवं तयल ल।, तहायक आयुक्त ।कर-
निर्धारण।, तहायक आयुक्त ।पुशासन। तथा तहायक आयुक्त ।वाद-मुकदमा। ।

।3। तहायक आयुक्त ।शातकीय।

प्रदेश में बिजुी कर पुशासन की दृष्टि से कुल 22 क्षेत्र हैं । प्रत्येक क्षेत्र में एक तहायक आयुक्त ।शा0। के आधार पर कुल 22 तहायक आयुक्त ।शा0। हैं । तहायक आयुक्त ।शा0। का पद एक निरीक्षक अधिकारी के नाते बहुत ही महत्वपूर्ण पद है । तहायक आयुक्त ।शा0। के मुख्य अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व अधीनस्थ मंडल/उपमंडल/खंड के बिजुीकर अधिकारी तथा बिजुी कर अधिकारी ग्रेनी-2 के प्रतिदिन के कार्यों को देख-रेख करना तथा उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देशों का पालन करना है। क्षेत्र के तहायक आयुक्त ।शा0। अपने कार्य के लिए परिक्षेत्र के उपायुक्त ।शा0। के माध्यम से आयुक्त के प्रति उत्तरदायी है । इनके प्रमुख अधिकार एवं कर्तव्य² : अधीनस्थ कार्यालयों का प्रभावशाली निरीक्षण करना; प्रत्येक विशेष अनुसन्धान शाखा की इकाई का वर्ष में दो बार निरीक्षण करना, कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत कामों को ठीक से भरेवाना एवं कम्प्यूटर इकाई को समय से उपलब्ध कराना ; क्षेत्र के मुख्यालय पर व्यापारियों तथा बार स्तोतियेन आदि की समस्याओं को सुनना तथा उनका समाधान करना ; क्षेत्र का संग्रह पूरा कराना, 5000 रुपये तक के वादों में द्वितीय अपील करने या न करने का निर्णय लेना; 2500 रुपये तक वस्तु न होने वाली राशि को बट्टे आते में डालना, आडिट आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही पर नियन्त्रण रखना ; तृतीय ग्रेनी कर्मचारियों की नियुक्ति करना, व्यापारियों एवं कार्यालय प्रयोग से सम्बन्धित कामों को उपलब्ध कराना, । लाख रुपये वार्षिक से अधिक कर देने वाले व्यापारियों की मानीटरिंग करना, । लाख से 5 लाख तक की कमाया राशि के सम्बन्ध में कार्यवाही करना, क्षेत्र के बड़े-बड़े व्यापारियों पर विशेष दृष्टि रखना, अधीनस्थ अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों में संशोधनों तथा उत्पन्न एवं तर्कों न्यायालय

2. मैनुअल-5/1984, पत्र संख्या-मैनु0-कार्य विभाजन-5/30-5/84-85-23/मुख्यालय-सकल : जुलाई 10, 1984 पर आधारित ।

के निर्णयों से अवगत कराना, क्षेत्र के बैंक पोस्टों का निरीक्षण करना, व्यापारियों और मोटर-वाहनों के मालिकों के उत्पीड़न के मामलों पर उचित कार्यवाही करना, बैंकों के भुगतान की व्यवस्था देना, अपने कार्यालय का वर्ष में दो बार निरीक्षण करना, 5000 रुपये से अधिक मूल्य का माल आयात करने हेतु फार्म-32 वितरित करना, नये व्यापारियों को पंजीयन देने का अनुमोदन करना, क्षेत्र के एक कर-निर्धारण से दूसरे कर-निर्धारण अधिकारी को वादों का हस्तान्तरण करना, तरेण्डर किये गये प्रपत्रों को जलाकर नष्ट करना और इसका प्रमाण रजिस्टर में अंकित करना, छाप्पाधिकारी को कर-निर्धारण आदेश पारित करने में परामर्श देना, शासन और आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशानुसार बिज्जी कर अधिकारी ग्रेजी-2 के अधिकारों का नियमानुसार प्रयोग करना है। इनके अतिरिक्त क्षेत्र के सभी कार्यों का सुचारु संचालन कराने तथा उच्च अधिकारियों के निर्देशों का तमय से पालन कराने, अधिनियम के प्रावधानों का सही उपयोग कराने, राजस्व के संग्रह की वृद्धि हेतु तथा विभाग को छवि को उज्ज्वल बनाये रखने हेतु यह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन करते हुए निर्देश दे सकते हैं।

।ब। सहायक आयुक्त (न्याय)।

सहायक आयुक्त (न्याय) बिज्जीकर, बिज्जीकर अधिकारी तथा बिज्जीकर अधिकारी ग्रेजी-2 के कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलों की सुनवाई करते हैं। वर्तमान में प्रदेश 24 न्यायिक क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है जिनमें 54 सहायक आयुक्त (न्याय) के पद हैं लेकिन तन् 1984-85 में 45 सहायक आयुक्त (न्याय) ही कार्यरत थे।

सहायक आयुक्त (न्याय) कर निर्धारण के आदेश अथवा अर्थेण्ड के आदेश को तत्सुद्ध, कम, वृद्धि अथवा रद्द कर सकता है या आदेश को रद्द करके कर-निर्धारण अधिकारी को विशिष्ट बाँच पड़ताल करके पुनः आदेश देने का निर्देश दे सकता है या आदेश में निर्दिष्ट बातों की बाँच पड़ताल करके निर्धारित तमय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कह सकता है। सहायक आयुक्त (न्याय) रिपोर्ट प्राप्त होने पर और

निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर प्रावधानों के अनुसार निर्णय दे सकता है।

सहायक आयुक्त (न्याय) द्वारा किये गये कार्य-निष्पत्तियों का तालिका नं० 6.5 में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 6.5

उत्तर प्रदेश में सहायक आयुक्त (न्याय) बिछी कर ले सम्बन्धित अपीलों की विभिन्न वर्षों की स्थिति

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में अवरोध अपीलों की संख्या (अप्रैल 1 को)	वर्ष में दायर अपीलों की संख्या	नित्सारण्य अपीलों की संख्या	वर्ष में नित्सारित अपीलों की संख्या	वर्ष के अन्त में अवरोध अपीलों की संख्या (31 मार्च को)
1970-71	80,141	54,405	1,34,546	55,085	79,461
1971-72	79,461	54,928	1,34,389	73,606	60,783
1972-73	60,783	60,341	1,21,124	69,486	51,638
1973-74	51,638	67,521	1,19,159	60,105	59,054
1974-75	59,054	74,656	1,33,710	66,084	67,662
1975-76	67,662	81,066	1,48,728	69,009	79,719
1976-77	79,719	84,247	1,63,966	64,039	99,927
1977-78	99,927	82,076	1,82,003	62,619	1,19,384
1978-79	1,19,384	70,489	1,89,873	79,234	1,10,639
1979-80	1,10,639	71,488	1,82,127	79,928	99,831
1980-81	99,831	71,762	1,71,593	2,368	99,795
1981-82	99,795	59,151	1,58,946	63,306	95,436
1982-83	95,436	59,667	1,55,103	204	91,830
1983-84	91,830	53,500	1,45,330	63,004	73,421
1984-85	73,421	38,110	1,11,531	269	41,704
				103	
				185	
				228	

स्रोत : पूर्वोद्धृत, पृष्ठ 38.

तालिका नं० 6.5 के विश्लेषण से स्पष्ट है तन् 1976-77 तक सहायक आयुक्त (न्याय) के तत्समक दायर की गई अपीलों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई है, परन्तु इसके पश्चात् दायर की गई अपीलों की संख्या कम होती गई है। जिसके कारण है,

11। अधिकारियों द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों में गुणात्मक स्तर का सुधार होना ;

12। सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) की संख्या में वृद्धि होना तथा

13। तर्कों का बन्द होना ।

तन् 1970-71 में जहाँ 54,405 अपीलों दायर की गई थी, जिनकी संख्या तन् 1976-77 में सर्वाधिक 84,247 थी, लेकिन तन् 1984-85 में घटकर केवल 38,110 ही रह गयी। तन् 1972-73 तक दायर की गई अपीलों की संख्या की तुलना में निस्तारित अपीलों की संख्या अधिक रही जिससे अवशेष अपीलों की संख्या कम होती गई, परन्तु तन् 1973-74 से तन् 1977-78 तक अवशेष अपीलों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई, लेकिन इसके पश्चात् दायर अपीलों से निस्तारित अपीलों की संख्या अधिक होने से अवशेष अपीलों की संख्या निरन्तर कम होती गई। तन् 1984-85 में मात्र 41,704 अपीलों अवशेष थी।

सहायक आयुक्त (न्याय) द्वारा निस्तारित बिड्डीकर की अपीलों की कर राशि में किये गये संशोधनों का विवरण तालिका नं० 6.6 में दर्शाया गया है। इस तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि निस्तारित अपीलों की कुल संख्या के 30 प्रतिशत से अधिक अपीलों पुतिमर्थ तन् 1973-74 को छोड़कर। खारिज कर दी जाती है। सामान्यतः करों की राशि में कमी ही की गई है लेकिन विवादग्रस्त कर राशि सामान्य रूप से बढ़ती रही है। तन् 1983-84 में सर्वाधिक विवादग्रस्त कर राशि 38.23 करोड़ रुपये थी जो तन् 1984-85 में 35.20 करोड़ रुपये रह गयी।

निस्सारित बिजुली की अपीलों के वर्धमान परिणाम तथा घटाई गई/बढ़ाई गई/विवादित कर राशि

वर्ष	आरिय की गई अपील की संख्या	सर्वाधिक अपील की संख्या	स्वीकृत की गई अपील की संख्या	प्रति के लिए अपील की संख्या	निस्सारित अपील की संख्या	घटाया गया कर लाख रु० में।	बढ़ाया गया कर लाख रु० में।	विवादित कर लाख रु० में।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1970-71	18,279 135.21	19,841 135.81	9,085 116.51	7,980 114.51	55,085	182.86	अनुपप्य	अनुपप्य
1971-72	22,693 130.81	26,883 136.51	13,141 117.91	10,889 114.81	73,606	247.79	अनुपप्य	अनुपप्य
1972-73	21,077 130.31	25,453 136.61	12,050 117.41	10,906 115.71	69,486	262.93	अनुपप्य	अनुपप्य
1973-74	17,737 129.51	21,664 136.01	10,517 117.51	10,187 117.01	60,105	265.50	01.58	1170.58
1974-75	20,171 130.51	23,621 135.71	13,015 119.71	9,241 114.11	66,048	390.90	0.59	1441.06
1975-76	23,297 133.71	26,141 137.91	13,833 120.11	5,738 108.31	69,009	427.38	0.37	1618.04
1976-77	22,427 135.01	25,036 139.11	13,292 120.81	3,284 105.11	64,039	654.36	1.06	2156.84
1977-78	19,802 131.61	25,792 141.21	14,281 122.81	2,744 104.41	62,619	817.54	0.57	2556.62
1978-79	26,750 133.81	30,294 138.21	19,635 124.81	2,555 103.21	79,234	801.54	1.10	2416.65

कुल: अगले पृष्ठ पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1979-80	30,624 138.31	28,603 135.81	18,178 122.81	2,523 103.11	79,928	725.83	2.21	2436.09
1980-81	27,343 138.11	24,594 134.31	17,105 123.81	2,756 103.81	71,798	805.91	0.66	2913.22
1981-82	22,602 135.71	22,938 136.21	14,411 122.81	3,355 105.31	63,306	932.29	1.39	3543.18
1982-83	21,215 133.71	21,752 134.51	15,958 125.31	4,079 106.51	63,004	940.74	0.75	3419.45
1983-84	25,020 134.81	22,315 131.11	20,041 127.91	4,430 106.21	71,806	1166.69	2.49	3822.59
1984-85	26,111 137.61	19,393 127.91	19,281 127.81	4,629 106.71	69,414	1090.60	3.30	3520.14

स्त्रोत - आयुक्त बिछी कर उत्तर प्रदेश : सांख्यिकीय अनुभाग, विद्युत् विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85,

मसुदा, पृष्ठ 43.

टिप्पणी : कोष्ठक में प्रस्तुत के अंकिते लगभगिये गये हैं ।

11। तहायक आयुक्त जाचि चौकी एवं तजल टल।

उत्तर प्रदेश बिजुी कर अधिनियम, 1948 की धारा 28 के अनुसार राज्य के बाहर से मंगाये गये मात की बिजुी पर देय कर अथवा अन्य राशि को चोरी को रोकने के लिए राज्य सरकार अधिमूज्जा जारी करके पैक पोस्ट या बैरियर की स्थापना का निर्देश दे सकती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य में तहायक आयुक्त जाचि चौकी एवं तजल टल। के 4 पद हैं जिनमें से तहायक आयुक्त जाचि चौकी। एवं तहायक आयुक्त तजल टल। प्रत्येक के दो-दो पद हैं। एक तहायक आयुक्त जाचि चौकी। तथा तजल टल। का क्षेत्र परिपक्वी क्षेत्र है। जिसका मुख्यालय गाजियाबाद में है तथा दूसरे तहायक आयुक्त जाचि चौकी। तथा तजल टल। का क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है जिसका मुख्यालय वाराणसी में है। तहायक आयुक्त जाचि चौकी। के अधीन 46 जाचि चौकियाँ तथा तहायक आयुक्त तजल टल। के अधीन 32 इकाइयाँ तजल टल। की कार्यरत हैं। ये जाचि-चौकियाँ एवं तजल टल। के बिजुी कर अधिकारी अपर। के नियन्त्रण में होती है। पैक पोस्ट या बैरियर अधिकारी को वाहन एवं मात के सम्बन्ध में विभिन्न प्रपत्रों को देखने, मात का निरीक्षण करने तथा मात जब्त करने का आदेश देने का अधिकार होता है। प्रदेश में 31 मार्च 1985 को कार्यरत जाचि चौकियों एवं तजल टल इकाइयों का वित्तृत विवरण परिशिष्ट 'द' में दर्शाया गया है।

प्रदेश में बिजुीकर जाचि-चौकियों द्वारा की गई कार्य प्रगति को निम्नलिखित तालिका नं० 6.7 में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 6.7 के विशलेषण से स्पष्ट है कि इन चौकियों पर वाहनों की चेकिंग व्यवस्था के कारण अनाधिकृत मात पर जमानत एवं अर्थदण्ड के रूप में वसूल होने वाली राशि में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। यह राशि तन् 1978-79 में मात्र 93.29 लाख रुपये थी जो तन् 1984-85 में बढ़कर 480.02 लाख रुपये हो गयी।

बिजुी कर में चोरी की रोकथाम की दृष्टि से तजल टलों की प्रगति भी

बिग्री कर जॉय बॉकियों की कार्य प्रगति

सू०	सद का नाम	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1.	जॉय बॉकियों की संख्या	28	28	30	38	39	42	46
2.	कुल बाहनों की संख्या जो जॉय बॉकियों से जुड़े	1487642	1712868	1811482	1890757	2431324	2541525	2227092
3.	बाहल जो कर योग्य साल के साथ जुड़े	941542	1219993	1314698	1372721	1773159	1870260	1614473
4.	बाहल जो कार्य के साथ जुड़े	874509	1158787	859252	917530	1090657	1304621	1417490
5.	अनाधिकृत साल माने वाले बाहनों की संख्या	67037	61206	52446	39661	59395	81465	105186
6.	बालू की गई बजानत/अवैतनिक की धराराशि लाख रुप में।	93.29	119.61	144.30	160.74	221.29	270.63	480.02

स्त्रोत : आयुक्त बिग्री कर उत्तर प्रदेश : सांख्यिकीय अनुभाग, बिग्री कर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85
लखनऊ, पृष्ठ 47.

तन्तोषजनक रही है और इनके द्वारा जमानत एवं अर्थदण्ड के रूप में वस्तु की गई धनराशि तन् 1978-79 में केवल 37.35 लाख रुपये से बढ़कर तन् 1984-85 में 237.73 लाख रुपये हो गयी। तब दोनों की कार्यप्रगति को विस्तार से तालिका नं० 6.8 में दर्शाया गया है।

16। सहायक आयुक्त कर-निर्धारण।

बड़ी-बड़ी कम्पनियों, फर्मों तथा बड़े-बड़े करदाताओं के कर निर्धारण का कार्य सहायक आयुक्त कर निर्धारण करते हैं। तन् 1975-76 में 6 सहायक आयुक्त कर निर्धारण के पद थे जो 1983-84 में बढ़कर 34 तथा तन् 1984-85 में बढ़कर 35 हो गये।

सहायक आयुक्त कर निर्धारण का कार्यक्षेत्र उनकी हस्तान्तरित व्यापारियों तक सीमित रहेगा। वह उन व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत स्व-पत्रों के परीक्षण, चेकों के तामयिक प्रस्तुतीकरण, विभिन्न प्रपत्र जारी करने, तामयिक एवं प्रभावी सर्वेक्षण, वापिसी के सभी मामलों, फार्म-31 की बैंक पोस्ट से प्राप्त प्रतियों की अभिलेखों में प्रविष्टि, डिलिक्वेन्सी रजिस्टर का रख-रखाव, बकाया वस्तु की मानी-टरिंग, धारा-15 ए, धारा-22, धारा-30, के वादों के निस्तारण, अधिवक्ताओं/करदाताओं की समस्याओं का समाधान, आडिट आपत्तियों के अनुपालन के विषय में उनी प्रकार उत्तरदायी होंगे/कार्यवाही करेंगे वित्त प्रकार छुड़ाधिकारी अपने छुड़ के अन्य व्यापारियों के सम्बन्ध में इन निर्देशों के अनुसार करेंगे/होंगे। इस प्रकार सहायक आयुक्त कर निर्धारण के समस्त कार्य एवं उत्तरदायित्व छुड़ अधिकारी की भाँति ही होंगे, केवल वे स्वतः कर-निर्धारण का कार्य नहीं करेंगे। सहायक आयुक्तों कर-निर्धारण द्वारा की गई कार्य प्रगति को तालिका नं० 6.9 में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 6.9 में। अप्रैल 1977 को सहायक आयुक्त कर-निर्धारण के यहाँ 980 अनिस्तारित कर निर्धारण वाद थे जो 31 मार्च 1985 को बढ़कर 7767 हो गये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वादों के निस्तारण में तीव्र वृद्धि होते हुए भी अनिस्तारित वादों की संख्या इतनी बढ़ गयी। तन् 1977-78 में 1619 कर-

बिछी कर सज टलों की पुनर्गति

सं०	सद का नाम	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1.	सज टल इकाइयों की संख्या	20	20	20	24	31	33	32
2.	कुल बाटनों की संख्या जिनकी जांच की गई	34172	21548	30460	50985	60597	70021	69413
3.	दोषी पाये गये बाटनों की संख्या	2293	2920	4521	6414	8072	6800	7085
4.	ड्रान्सपोर्ट कम्पनियों जिनकी जांच की गई	2363	1638	1344	1656	2146	2234	1066
5.	दोषी पाई गई ड्रान्सपोर्ट कम्पनियों की संख्या	430	547	754	1067	1309	1465	664
6.	रेलवे गोदाम/व्यक्तियों की संख्या जिनकी जांच की गई	8982	5796	3821	5448	4974	5999	4983
7.	दोषी पाये गये रेलवे गोदाम/व्यक्ति की संख्या	3999	2018	1527	2103	2100	2038	1632
8.	बसों की गई बयानत/अटेंडन्स की धमराशि लाख रु में	37.35	43.83	68.44	116.60	145.84	188.44	237.73

स्रोत : आयुक्त बिछी कर उत्तर प्रदेश : सांख्यिकीय अनुभाग, बिछीकर विभाग का त्रैमास्य वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85, सजक, पृष्ठ 47.

तालिका नं० 6.9

सहायक आयुक्त (कर-निर्धारण) बिछी कर, उत्तर प्रदेश द्वारा बिछीकर से सम्बन्धित कर निर्धारण वादों की स्थिति

सदर-निर्धारण की स्थिति	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1. प्रारम्भ में निस्तारणार्थ वाद	980	2372	3069	3149	3813	4061	5246	6330
2. वर्ष में निस्तारित हेतु वाद	3811	2618	4989	3692	6841	4263	6674	7472
3. इन वादों की संख्या	3011	2618	2473	3692	2994	8324	11920	13802
4. वर्ष में निस्तारित वाद	3991	4990	5542	6841	6807	3078	5590	6035
5. अन्त में अनिस्तारित वाद	1619	1921	2393	3028	2746	5246	6330	7767
6. कार्यरत सजाओ कर-निर्धारण की संख्या	2372	3069	3149	3813	4061	32	34	35
	16	20	20	20	20			

स्रोत : आयुक्त बिछी कर उत्तर प्रदेश : तांछिकीय अनुभाग, बिछीकर विभाग का त्रैमास्य वार्षिक प्रसिद्धन 1984-85, सख्त, पृष्ठ 33.

निधारण वादों का निपटारा किया गया जिनकी संख्या सन् 1984-85 में 6035 हो गई। अनित्सारित कर निधारण वादों की संख्या में वृद्धि होने का कारण यह है कि प्रत्येक वर्ष में जितने नये कर निधारण वाद बढ़ते हैं उतने वादों का निस्तारण नहीं हो पाता। यद्यपि तहायक आयुक्त (कर निधारण) के क्षेत्रों में बढ़ते हुए वादों को ध्यान में रखते हुए इनके पदों की संख्या सन् 1977-78 में 16 से बढ़कर सन् 1984-85 में 35 कर दी गई।

5. कर निधारण अधिकारी

कर निधारण अधिकारी से अभिप्राय उक्त अधिकारी से है जो विज्ञीकर अधिनियम के अन्तर्गत कर-निधारण की कोई भी कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार अथवा विज्ञी कर आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में कर निधारण अधिकारी के रूप में विभिन्न स्तरों पर निम्न-लिखित अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है : 1. तहायक आयुक्त (कर - निधारण), 2. विज्ञी कर अधिकारी (कंडाधिकारी), 3. अतिरिक्त विज्ञी कर अधिकारी (अपर विज्ञी कर अधिकारी), 4. विज्ञी कर अधिकारी ग्रेजी - 2 (तहायक विज्ञी कर अधिकारी)।

विज्ञी कर अधिकारी : विज्ञी कर अधिकारी से आगत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये विज्ञीकर अधिकारी से है। इसका कांक्षित एक मण्डल होता है, जो उक्त मण्डल में कर निधारण अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करता है। विज्ञीकर अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए कर-निधारण अधिकारी होता है। इस प्रकार यह व्यापारियों का कर निधारण करता है। विज्ञीकर अधिकारी में यह तहायक आयुक्त भी शामिल है ^{जिसे} ~~को~~ कर-निधारण अधिकारी का काम करने के लिए अधिकार दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विज्ञीकर अधिकारी ग्रेजी-2 भी शामिल है जिन्हें विज्ञीकर आयुक्त ने कर निधारण अधिकारी का काम करने के लिए नियुक्त किया है। सन् 1984-85 में 415 विज्ञीकर

अधिकारी और 62 बिजलीकर अधिकारी क्रेगी-2 प्रदेश में कर निर्धारण में कार्यरत थे ।

कंड के बिजलीकर अधिकारी को "कंडाधिकारी" कहा जाता है । ये अपने कंड से सम्बन्धित निम्न कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं :

कंडाधिकारी स्व-पत्र प्रस्तुत करने के बाद अस्थायी कर निर्धारण आदेश पारित की कार्यवाही करते हैं । स्व-पत्रों का परीक्षण करते समय कर की दर, कर भुक्ति के दावे, प्रदर्शित विक्रय धन आदि की जाँच करते हैं । करदाताओं से प्राप्त पैकों को दूसरे दिन बैंक में प्रस्तुत करना, बैंक रजिस्टर की मानीटरिंग करना, बैंक के भुगतान में क्लिम्ब होने पर स्टेट बैंक एवं सम्बन्धित बैंक अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करना, अनादरित पैकों के सम्बन्ध में कार्यवाही करना आदि के सम्बन्ध में कंडाधिकारी ही उत्तरदायी होता है । विक्रय योग्य फार्मों को सुरक्षित रखने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सम्बन्धित मण्डल/कंड के बिजलीकर अधिकारी का होता है । कंड के बिजलीकर अधिकारी ही करदाताओं को विभिन्न पत्र जारी करते हैं । करदाताओं का सामयिक तथा पुनर्जाँच करवाना, व्यापारियों को पंजीयन देना, पंजीयन के लिए संतुष्टि करना, बैंक पोस्ट से प्राप्त हुये फार्म-31 की प्रविष्टि विभागीय अभिलेखों में लिपिक से करवाना तथा फार्मों को पत्रावलियों में रखवाना, ककाया वसुली प्रमाण-पत्रों की जाँच करना, निर्माणाधीन कराना तथा समय-समय पर मानीटरिंग करना, निस्तारित वादों के मामलों की जानकारी के लिए कार्यालय का निरीक्षण करना, पुनरीक्षित स्वतः कर-निर्धारण योजना के सभी मामलों का निस्तारण करना, दत्त बाक स्वयं तथा उतते अधिक कर योग्य विक्रय धन वाले वादों में कर-निर्धारण करना, अधिवक्ताओं तथा करदाताओं की समस्याएँ सुनना एवं उनका समाधान करना, आडिट आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण करना और उनसे सम्बन्धित अनुपालन आदेश भिजवाना ।

कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत निर्धारित सभी फार्मों को ठीक से भरा-कर निर्धारित समय तारीखी से कम्प्यूटर इकाई को उपलब्ध कराना, कम्प्यूटर इकाई

ते प्राप्त रिपोर्टों पर तत्परता से कार्यवाही करना आदि के सम्बन्ध में कड़ाधिकारी का दायित्व होता है ।

1त। उपर विज्ञीकर अधिकारी : कूड के साथ सम्बन्ध उपर विज्ञीकर अधिकारी के निम्न कार्य, अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व होते हैं : दल नाक ल्यवे तक के कर योग्य विद्युत धन वाले समस्त सम्पत्ति वादों में कर निर्धारण तथा ल्य-पत्रों की जांच करना, पारित कर निर्धारण आदेशों की प्रविष्टि रजिस्टर में कराना, कर-निर्धारण आदेशों की सामीली समय से करना, निस्तारण मामलों से सम्बन्धित प्राप्ति पत्रों का नियमानुसार निस्तारण करना, हस्तान्तरित वादों के सम्बन्ध में प्राप्त अपीलीय आदेशों का परीक्षण करना, किसी वाद में द्वितीय अपील लिये जाने की दशा में निर्धारित प्रालम् में अपनी आठवा के साथ पत्रावली निर्धारित समय के अन्दर तहायक आयुक्त (सातकीय) को भेजना, सम्बन्धित कर निर्धारण वादों के सम्बन्ध में आडिट आपत्ति होने पर नियमानुसार निराकरण करके अनुपातम आठवा तहायक आयुक्त (सातकीय) और आडिट दल को भेजना, प्रतिमात 50 छूट वादों का कर निर्धारण करना इत्यादि ।

जिन कूड/उपकूड/कूड में विज्ञीकर अधिकारी लेगी-2 तैनात नहीं हैं, वहाँ पर तैनात अतिरिक्त विज्ञीकर अधिकारी अपने कार्यों के अतिरिक्त बातानों को प्रमाणित करने, पैकों को बैंक भेजने, सातपातकों के कार्यों का निरीक्षण, जिला स्तर की मीटिंग में प्रतिनिधित्व करने, द्वितीय अपील दायर करने के साथ-साथ दल नाक से ऊपर के वादों की अपीलों में तहायक आयुक्त (न्याय) के समक्ष विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

1द। विज्ञीकर अधिकारी लेगी-2 : कूड में तैनात विज्ञीकर अधिकारी लेगी-2 कड़ाधिकारियों के सभी कार्यों में उनकी सहायता करते हैं । वे कड़ाधिकारी द्वारा दिये गये विभिन्न निर्देशों का भी पालन करते हैं और विशेष ल्य से पैकों के सही समय पर बैंक भिजवाने, वापसी के मामलों में परीक्षण करके रिपोर्ट बनाने, क्यूरी प्रमाणपत्र को सही समय पर जारी करने, रौन्टर बनाकर कूडों के विभिन्न पद्यों

का नियमित निरीक्षण करने, दाखिल किये गये प्रतिभूति बाण्ड की जाँच करने तथा पंजीकरण के सम्बन्ध में तथानिक जाँच करना एवं अवरोध का तय्युह करना इत्यादि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार मुख्य कार्य बाजारों का तय्येक्षण करके सूचना प्राप्त करने तथा नये करदाताओं का पता लगाने की दृष्टि से किरीकर निरीक्षक भी नियुक्त किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर कर निर्धारण से सम्बन्धित कुल बाटों के विवरण की तालिका नं० 6.10 में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 6.10

उत्तर प्रदेश में किरीकर से सम्बन्धित समस्त कर निर्धारण के बाटों की प्रगति

वर्ष	बाटों की तय्येक्षा तालिका में						कर निर्धारण में कार्यरत अधिकारी		
	1. कुल की निर्धारण कर बाटों की तय्येक्षा	2. कुल की तय्येक्षा कर बाटों की तय्येक्षा	3. कुल की तय्येक्षा कर बाटों की तय्येक्षा	4. कुल की तय्येक्षा कर बाटों की तय्येक्षा	5. कुल की तय्येक्षा कर बाटों की तय्येक्षा	6. कुल की तय्येक्षा कर बाटों की तय्येक्षा	7. कुल की तय्येक्षा कर बाटों की तय्येक्षा	8. कुल की तय्येक्षा कर बाटों की तय्येक्षा	9. कुल की तय्येक्षा कर बाटों की तय्येक्षा
1970-71	1.57	2.01	3.58	1.57	2.01	87	111	-	
1971-72	2.01	2.21	4.22	1.61	2.61	118	115	-	
1972-73	2.61	2.34	4.95	1.92	3.03	119	172	-	
1973-74	3.03	2.38	5.41	2.17	3.24	119	260	-	
1974-75	3.24	2.62	5.86	2.30	3.56	185	204	-	
1975-76	3.56	3.07	6.63	2.43	4.20	202	198	6	
1976-77	4.20	2.86	7.06	2.81	4.25	221	241	20	
1977-78	4.25	3.45	7.70	3.12	4.58	233	226	16	
1978-79	4.58	3.48	8.06	3.68	4.38	275	195	20	
1979-80	4.38	2.95	7.33	3.67	3.66	418	221	20	
1980-81	3.66	3.07	6.73	3.17	3.56	401	231	20	

सूत्राः ऊपर सूत्र पर।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1981-82	^{3.56} 3.53	^{3.05} 3.07	6.61	2.90	3.71	396	212	20
1982-83	3.71	3.07	6.78	3.03	3.75	404	217	32
1983-84	3.75	2.98	6.73	2.56	4.17	377	187	34
1984-85	^{4.17} 4.17	2.87	7.04	1.75	5.29	415	62	35

स्रोत : पूर्वोद्धृत, पृष्ठ 31.

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1 अगस्त 1970 को अनिस्तारित कर निर्धारण वादों की संख्या 1.57 लाख थी जो 31 मार्च 1985 को बढ़कर 5.29 लाख हो गई। 1 अगस्त 1970 तक अनिस्तारित कर निर्धारण वादों की संख्या लगातार बढ़ती रही, लेकिन इसके बाद 31 मार्च, 1981 तक अनिस्तारित कर निर्धारण वादों की संख्या में निरन्तर कमी होती गई। इसके पश्चात् पुनः 1 अगस्त, 1981 के बाद से इनमें वृद्धि होने लगी। तन् 1978-79 के वर्ष में वादों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई। वहाँ तन् 1970-71 में वादों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि 2.01 लाख वादों की हुई वहीं तन् 1984-85 में 2.87 लाख वादों की वृद्धि हुई। जबकि 1978-79 में 3.48 लाख वादों की संख्या बढ़ी थी। वहाँ तन् 1970-71 में 3.58 लाख वादों का निस्तारण किया जाना था, वहीं तन् 1984-85 में 7.04 लाख वादों का निस्तारण होना था, लेकिन तन् 1970-71 में सिर्फ 1.57 लाख वादों का ही निस्तारण किया गया जबकि तन् 1984-85 में 1.75 लाख वादों का निस्तारण किया गया। तन् 1978-79 में सबसे अधिक 3.68 लाख वादों को निपटाया गया।

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि वहाँ तन् 1970-71 में 87 विज्ञापित अधिकारी स्लॉट 111 विज्ञापित अधिकारी स्लॉट-2 कार्यरत रहे, वहाँ तन् 1984-85 में 415 विज्ञापित अधिकारी स्लॉट 62 विज्ञापित अधिकारी स्लॉट-2 कार्यरत रहे। तन् 1975-76 में तत्कालीन आहुता (कर निर्धारण) नाम का नया पद सुविष्ट किया और इनके 6 पद थे। रायचंद में वृद्धि लाने की दृष्टि से सातम ने 1976-77 में 14 नये

पदों का तुलन किया, परन्तु 1977-78 में 16 तहायक आयुक्त (कर-निर्धारण) कार्यरत रहे। वर्ष 1978-79 से वर्ष 1981-82 तक 20, वर्ष 1982-83 में 32, वर्ष 1983-84 में 34 तथा वर्ष 1984-85 में 35 तहायक आयुक्त (कर-निर्धारण) कार्यरत रहे।

बिड्रीकर न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल)

यदि कोई व्यक्ति तहायक आयुक्त (न्याय) या उपायुक्त (अपील), पुनर्विचार करने वाले अधिकारी अथवा विवादोत्पन्न पुनः पर आयुक्त के आदेश से तन्मुष्ट नहीं होता तो वह ऐसे आदेश के विरुद्ध बिड्रीकर न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) से अपील कर सकता है। बिड्रीकर मामलों की अपील के लिए राज्य सरकार ने एक बिड्रीकर ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की है जिसका एक अध्यक्ष तथा आवश्यकतानुसार सदस्य होते हैं। उन व्यक्तियों में से सदस्यों की नियुक्ति की जाती है जो कि उच्च न्यायालय में जब की नियुक्ति की योग्यता रखते हैं अथवा उत्तर प्रदेश के बिड्रीकर विभाग में कम से कम उप-आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं या रह चुके हैं। ट्रिब्यूनल अपीलकर्ता को सुनवाई देकर अपील खारिज कर सकता है या आदेश को तन्मुष्ट (मुष्टी), रद्द या परिवर्तित कर सकता है या आदेश को रद्द करके यह आदेश दे सकता है कि अधिकारी मामले की पुनः जाँच करके नया आदेश दे या अधिक वस्तु की गयी राशि वापिस करें। 3 अक्टूबर वर्ष 1980 से बिड्रीकर ट्रिब्यूनल की स्थापना के फलस्वरूप अब द्वितीय अपीलों का निस्तारण बिड्रीकर ट्रिब्यूनल में किया जाने लगा है। प्रदेश में ट्रिब्यूनल की कुल 16 पीठें हैं और इन पीठों के 25 सदस्य हैं। अध्यक्ष न्यायाधिकरण की पीठों में हैं। बिड्रीकर न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों में सदस्यों की संख्या 25 है।

बिड्रीकर न्यायाधिकरण की कार्य प्रगति को तालिका नं० 6.11 में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 6.11 से स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण द्वारा निस्तारित अपीलों की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है, लेकिन दायर अपीलों का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक होने के कारण असीम रह जाने वाली अपीलों की संख्या वर्ष 1980-81 के अन्त में 31518 से बढ़कर वर्ष 1984-85 में 52595 हो गयी।

तालिका नं० 4.11

बिग्रीकर न्यायाधिकरण द्वारा द्वितीय अपीलों की पुनर्प्राप्ति

वर्ष	प्रथम अपीलों की संख्या	द्वितीय अपीलों की संख्या	तृतीय अपीलों की संख्या	चौथी अपीलों की संख्या	पांचवीं अपीलों की संख्या	छठी अपीलों की संख्या
1980-81 13.10.801 त	28157	12986	41143	9625	31518	14
1981-82	31518	19413	50931	16654	34277	15
1982-83	34277	23206	57483	16371	41112	11
1983-84	41112	19987	61099	15691	45408	16
1984-85	45408	21398	66806	14211	52595	15

स्रोत : पूर्वोद्धृत, पृष्ठ 45.

बिग्रीकर के सम्बन्ध में राज्य सरकार के अधिकार

बिग्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार को अनेक अधिकार दिये गये हैं जो कि निम्न प्रकार हैं :

1. नियम बनाने का अधिकार

राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्न विषयों के सम्बन्ध में नियम बना सकती है : 1.31 के तभी मामलों जिनके सम्बन्ध में अधिनियम में कहा गया है कि "वेता निर्धारित कर दिया जाय" ; 1.32 के वेता या विवेकाधीन के लिए लाइसेंस, लाइसेंस फीस तथा इससे सम्बन्धित शर्तों ; 1.33 अधिनियम के अन्तर्गत कर के निर्धारण हेतु वगैरह 1.34 के निर्धारण ; 1.35 विवरण दाखिल करने, किसी व्यक्ति को स्वयं उपस्थित होने के लिए बाध्य करना

तथा समय दिखाकर खान लेना ; 1य। अधिनियम के संघालन हेतु अधिकारियों की नियुक्ति, उनके अधिकार एवं कर्तव्य ; 1र। अधिनियम के अधीन की जाने वाली कार्यवाही की क्रिया विधि एवं अपनाये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में ; 1ल। धारा 29 1र। 111 के अधीन जमा करायी गयी रकम की वापसी, इसके लिए अधि एवं क्रिया विधि ; 1व। धारा 13 1र। 14 के अन्तर्गत तीन करने का टंन, तीन लगे माल, फ़ौकों व अन्य सम्पत्ति के रक्षण का टंन, तीन किये गये माल को हटाने का टंन तथा इसे हटाने वाला व्यक्ति ; 1द। धारा 13 1र। के अधीन जका किये गये माल का रक्षण ; 1य। वे मामले जो निर्धारित कर दिये जाएं ।

इस प्रकार क्वाये गये नियम इन्हें लागू करने की तिथि से कम से कम 4 सप्ताह पूर्व मजद में प्रकाशित किये जायेंगे । यदि राज्य सरकार विद्यमान परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह किसी नियम को बिना पूर्व प्रकाशन के तुरन्त लागू कर सकती है । इस प्रकार क्वाया गया प्रत्येक नियम क्वाने के बाद यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष सत्रकाल में रूज दिखाकर कम से कम 14 दिन के लिये रखा जायेगा । विधान सभा नियम में परिवर्तन कर सकती है । परिवर्तन किये जाने पर परिवर्तित नियम ही लागू होना ।⁴

2. अधिसूचना जारी करने का अधिकार

राज्य सरकार जनहित में ऐसा करना उचित समझे तो वह धारा 3 र, 3र, 3 डी, 4 अध्या 4 बी के अधीन अधिसूचना जारी कर सकता है ।⁵ यह अधिसूचना इसे जारी करने की तिथि से कम से कम 6 माह बाद लागू होगी । किसी व्यापारी का कर दायित्व बढ़ाने वाली अधिसूचना पिछली तिथि से लागू नहीं हो सकती है ।⁶

4. Added by Section 24 of U.P. Act 1 of 1973.

5. As per Section 25 of U.P. Sales Tax.

6. Ins. by U.P. Act 2 of 1980, 5.9 and deemed to have been inserted on 1.1.1979.

3. परिदेन, देन तथा मजदूर बनाने का अधिकार

राज्य सरकार मजदूर में अधिभूजा द्वारा 13। एक उपायुक्त 1। शासकीय। अध्या एक उपायुक्त 1। अपीत। के परिदेन को समाप्त कर सकती है या परिदेन बना सकती है तथा परिदेन में शामिल मजदूर और उपमजदूर को अधिभूजित कर सकती है। 14। एक सहायक आयुक्त 1। शासकीय। अध्या सहायक आयुक्त 1। न्यायिक। के देन को समाप्त कर सकती है या समाप्त कर सकती है तथा देन में शामिल मजदूर और उपमजदूर को अधिभूजित कर सकती है। 15। नया मजदूर या उपमजदूर बना सकती है अध्या समाप्त कर सकती है तथा इनकी सीमा का निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकती है।⁷

उत्तर प्रदेश में बिजुलीकरण प्रगति के वितरित ढाँचे का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जैसे विद्युत राज्य में बिजुलीकरण जैसे बलिष्ठ कर को लगाने, सक्रिय करने, करावसंधन को रोकने तथा करारोपण में न्यायिक व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से व्यापक व्यवस्था की गई है और समय के साथ बढ़ती हुई आवश्यकता तथा उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए नये पदों का सुझा दिया गया है और विद्यमान पदों पर अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई है, लेकिन विभिन्न पदों एवं त्तरों की दृष्टि से देनों को अनन-अन बाँटकर प्रशासनिक ढाँचे में बलिष्ठता तथा कुछ भ्रम उत्पन्न कर दिया गया है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश को सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार ही लक्ष्य, विचार और कमिशनरी त्तर पर बिजुलीकरण निर्धारण, संग्रहण तथा न्याय व्यवस्था को गठित किया जाए। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और लगभग समान भार के पदों की दृष्टि से देन समान ही रखे जाये। उदाहरण के लिए जब उपायुक्त 1। शासकीय। के 12 पद हैं तो उपायुक्त 1। अपीत। के भी 12 पद होने चाहिए। इसी प्रकार कुछ अन्य समानतायें भी बनायी जा सकती है। बिजुलीकरण के सम्बन्ध में जनता की आवश्यक जानकारी प्रदान करने,

7. Subs. by Notl. No. ST-11-255/X 900(17)-69. dt. 6.5.81
(w.e.f. 6.5.81)

जनता की समस्याओं एवं शंकाओं को हल करने तथा करदाताओं में कर भुगतान के प्रति ईमानदारी को विकसित करने के लिए बिज्जीकर प्रशासन में जनसम्पर्क की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कर प्रशासन को सुव्यवस्थित और प्रभावशाली बनाये रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि स्वीकृत पदों के अनुसार अधिकारियों की व्यवस्था हो। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1983-84 और 1984-85 में बिज्जीकर अधिकारी स्तर के 750 पद और बिज्जीकर अधिकारी ग्रेजी-2 स्तर के 642 पद स्वीकृत थे जबकि उन पर कार्यरत अधिकारियों की संख्या वर्ष 1983-84 में 674 तथा 428 और वर्ष 1984-85 में 672 तथा 409 थी। इसी प्रकार वर्ष 1984-85 में उपायुक्त बिज्जीकर के 26 पदों में से 22 पदों पर उपायुक्त नियुक्त थे। वर्ष 1983-84 में सहायक आयुक्त बिज्जीकर के 149 पदों में 120 पदों पर और वर्ष 1984-85 में 150 पदों में 116 पदों पर सहायक आयुक्त नियुक्त थे। पिछले दो वर्षों से आर्थिक सहायक, उपनिदेशक (संख्या 1), लेखा परीक्षा अधिकारी के पद खाली पड़े हुए हैं। प्रशासनिक कार्यक्षमता मात्र अधिकारियों पर ही नहीं बरन् निम्न स्तर के कर्मचारियों की पर्याप्तता व कुशलता पर निर्भर करती है। लेकिन चिन्ता का विषय है कि 31 मार्च 1984 को बिज्जीकर प्रशासन में तृतीय ग्रेजी व चतुर्थ ग्रेजी के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 6899 तथा 4292 थी लेकिन वास्तव में केवल 6325 तथा 3625 व्यक्ति ही इन पदों पर कार्यरत थे। यद्यपि वर्ष 1984-85 में इनके स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन 31 मार्च, 1985 को इनके स्वीकृत पदों की संख्या 6960 तथा 4337 में से केवल 5993 और 3486 व्यक्ति ही कार्यरत थे। इस प्रकार वर्ष 1984-85 में स्वीकृत पदों में वृद्धि होने के बावजूद भी वर्ष 1983-84 की तुलना में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में कमी हुई है।

बिज्जीकर निर्धारण में शीघ्रता तथा कुशलता लाने के लिए और विवादग्रस्त कर राशि का उचित समय में निवटारा करने की दृष्टि से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि सभी कर-निर्धारण पर अन्तिम निर्णय सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष में ही हो जाना चाहिये तथा अपील पर निर्णय कर-निर्धारण वर्ष से ठीक अगले वर्ष पूरा हो जाना चाहिए अर्थात् यह प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रशासन में कुशलता और सक्रियता लाकर अन्तिमस्तरीय वादों और अपीलों की संख्या को निरन्तर घटाने का प्रयास किया जाए।

सप्तम अध्याय

विशुद्ध आगम : ज्ञानात्मक विशेषता

अध्याय-7बिजली कर आगम : कृषि-आत्मक विवेचना

पुस्तक अध्याय में बिजली कर के आगम से सम्बन्धित तथ्यों का विवेचनात्मक अध्ययन किया गया है। प्रारम्भ में बिजली कर से सम्बन्धित मरदानुसार नियोजित अर्द्धे उपलब्ध न होने के कारण बिजली कर आगम का विवेचना करना कठिन कार्य था परन्तु जैसे-जैसे बिजली कर का महत्व स्वं आगम बढ़ता गया जैसे ही बिजली कर के कुल आगम को वर्ष 1967-68 में निम्न चार भागों में विभाजित किया गया।

1. बिजली कर ;
2. केन्द्रीय बिजली कर ;
3. मोटर ट्पुट पर बिजली कर ;
4. गन्ने पर कुय कर ।

बिजली कर से प्राप्त अर्द्धों से ऐसा अनुमान लगाया गया कि वर्ष 1938-39 में इससे प्राप्त आगम मात्र 1 लाख रुपये थी जो वर्ष 1939-40 में 600X से बढ़ गई। इस वर्ष बिजली कर से कुल आगम 6 लाख रुपये थी। अन्य राज्यों द्वारा बिजली कर के अपनाये जाने के कारण बिजली कर की राशि में निरन्तर वृद्धि होने लगी और तन् 1943-44 में बिजली कर से 8 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। स्वतन्त्रता के पश्चात् के बिजली कर आगम की प्रवृत्ति को निम्न तालिका नं० 7.1 में स्पष्ट किया गया है।

तालिका नं० 7.1विविध वर्षों में बिजली कर आगम

वर्ष	राशि लाख रुपयों में।					
	सामान्य बिजली कर	केन्द्रीय बिजली कर	मोटर ट्पुट पर बिजली कर	गन्ने पर कुय कर	कुल बिजली कर	वृद्धि प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
1947-48	-	-	-	-	1703	-
1948-49	-	-	-	-	3845	125.78

1	2	3	4	5	6	7
1949-50	-	-	-	-	5139	33.65
1950-51	-	-	-	-	5685	10.62
1951-52	5440	-	453	-	5893	3.65
1952-53	5121	-	599	-	5720	-2.93
1953-54	5833	-	735	-	6568	14.83
1954-55	6641	-	725	-	7366	12.15
1955-56	8010	-	150	-	8160	10.78
1956-57	9660	-	100	-	9760	19.61
1957-58	10737	-	975	-	11712	20.00
1958-59	11170	-	1219	-	12389	5.78
1958-60	12437	-	1246	-	13683	10.44
1960-61	14245	-	1633	-	15878	16.04
1961-62	16314	-	1830	-	18144	14.27
1962-63	18752	-	2135	-	20887	15.12
1963-64	24541	-	2290	-	26831	28.46
1964-65	27053	-	2700	-	29753	10.89
1965-66	33857	-	2922	-	36779	23.61
1966-67	40685	-	3584	-	44269	20.36
1967-68	37400	10136	3374	908	51819	17.05
1968-69	43709	10007	3529	1170 ⁹²¹	66796 ⁷⁵⁷⁵	12.07
1969-70	49079	12692	3855	1170	66796	15.01
1970-71	56155	14722	4634	1110	76621	14.78
1971-72	63617	14130	4893	1298	83938	9.55
1972-73	76566	13440	2797	1846	97649	16.35
1973-74	84448	21221	6770	1843	114282	17.03

1	2	3	4	5	6	7
1974-75	113064	30078	8866	3030	155038	35.66
1975-76	142815	37470	9487	4598	194370	25.37
1976-77	165005	46519	10915	4600	227039	16.80
1977-78	178019	47420	11401	4589	241429	6.39
1978-79	206246	54750	12178	4157	277331	14.87
1979-80	240729	61306	14131	4943	321109	15.78
1980-81	297014	72004	15447	4293	388758	21.07
1981-82	366912	97041	20274	5061	489288	25.86
1982-83	421050	101402	21221	5933	549606	12.33
1983-84	486507	104708	27358	7533	626106	13.92
1984-85	543565	128707	29030	5163	706465	12.83
1985-86	607173	142399	33879	5043	788494	11.61

। बजट।

स्रोत : रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया क्वार्टरलि 1951 से 1985.

टिप्पणी : 1. सन् 1947-48 से सन् 1950-51 के कुल बिजलीकर में सामान्य बिजलीकर एवं मोटर-स्प्रेड पर बिजलीकर की राशि शामिल है।

2. सन् 1957-58 से सन् 1966-67 की सामान्य बिजलीकर की राशि में केन्द्रीय बिजलीकर की राशि भी सम्मिलित है।

कुल बिजलीकर के आँकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 1947-48 में इस कर से मात्र 1703 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई थी, वह वर्ष 1983-84 में 626106 लाख रुपये हो गयी और वर्ष 1985-86 के बजट अनुमान के अनुसार 788494 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। प्रारम्भ में कुल बिजलीकर की राशि में वृद्धि की दर काफी धीमी थी लेकिन वर्ष 1973-74 के पश्चात् से इसमें तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1974-75 और

1975-76 में लगभग 40000 लाख रुपये वार्षिक की वृद्धि हुई जो वर्ष 1976-77 में लगभग 33000 लाख रुपये और वर्ष 1977-78 में 14400 लाख रुपये रह गयी, लेकिन इसके पश्चात् वर्ष 1978-79 में 36000 लाख रुपये और वर्ष 1979-80 में लगभग 44000 लाख रुपये की वृद्धि हुई। इसके बाद आगम में वृद्धि की गति और भी तीव्र हुई और वर्ष 1980-81 में लगभग 67000 लाख रुपये की वृद्धि हुई। वृद्धि की सर्वोच्च राशि वर्ष 1981-82 में हुई जब इस वर्ष बिजलीकर के कुल आगम में लगभग 100000 लाख रुपये की वृद्धि हुई। इसके पश्चात् वर्ष 1982-83 में लगभग 600000 लाख रुपये की वृद्धि हुई तथा इसके बाद तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष लगभग 80000 लाख रुपये की वृद्धि हुई।

सामान्य बिजलीकर की प्रवृत्ति और बिजलीकर की कुल आगम की प्रवृत्ति लगभग एक ही रही है, क्योंकि कुल बिजलीकर का एक बड़ा भाग सामान्य बिजली से ही प्राप्त होता है। वर्ष 1951-52 में सामान्य बिजलीकर से प्राप्त आगम 5440 लाख रुपये थी जो प्रथम योजना के अन्त में 1955-56 में 8010 लाख रुपये, द्वितीय योजना के अन्त में 1960-61 में 14245 लाख रुपये और तृतीय योजना के अन्त में 1965-66 में 33857 लाख रुपये हो गयी। इस तरह पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में सामान्य बिजलीकर से आगम 6 गुना हुआ लेकिन इसके बाद के बीच वर्षों में सामान्य बिजलीकर से आगम लगभग 18 गुना हो गया। कुछ संशोधन एवं रियायत किये जाने के कारण इस दर से आगम में वर्ष 1952-53 में मामूली गिरावट भी आयी। वर्ष 1957-58 से 1966-67 तक केन्द्रीय बिजलीकर की राशि भी सामान्य बिजलीकर में शामिल की जाती थी लेकिन वर्ष 1967-68 में सामान्य बिजलीकर की राशि कम होने का कारण केन्द्रीय बिजलीकर की राशि को अलग से दिखाया जाना था। इसी प्रकार 1972-73 में कुछ राज्यों (बिहार, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु) के सामान्य बिजलीकर के समक उपलब्ध न होने से सामान्य बिजलीकर की राशि कम दिखायी गयी थी। अन्यथा इस दर से आगम में निरन्तर वृद्धि ही हुई है। वर्ष 1980-81 से 60000 से 70000 लाख रुपये तक की वृद्धि का क्रम बना हुआ है। यद्यपि केन्द्रीय बिजलीकर का आरौपण वर्ष 1957-58 में ही हो गया था, लेकिन इसके पृथक् और वितरित समक वर्ष 1967-68 से ही उपलब्ध है। प्रारम्भ में केन्द्रीय बिजलीकर से आगम

में स्थिर और धीमी गति की वृद्धि की स्थिति रही लेकिन सामान्य बिजलीकर की भाँति ही वर्ष 1979-80 से वृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

मोटर स्पिड पर बिजलीकर और गन्ने पर क्रय कर से आगम में तुलनात्मक रूप से धीमी गति से वृद्धि हुई है। मोटर स्पिड पर बिजलीकर की राशि वर्ष 1951-52 में 453 लाख रुपये थी जो वर्ष 1956-66 में 2922 लाख रुपये हो गयी। इन 15 वर्षों में इस कर से आगम में लगभग $6\frac{1}{2}$ गुनी वृद्धि हुई। यद्यपि वर्ष 1955-56 और 1956-57 में काफी गिरावट आयी थी। वर्ष 1965-66 के पश्चात् इसमें धीमी गति से वृद्धि होती गयी जो वर्ष 1983-84 में बढ़कर 27358 लाख रुपये हो गयी जो वर्ष 1965-66 की तुलना में लगभग $9\frac{1}{2}$ गुनी थी। यद्यपि वर्ष 1967-68 में इसमें मामूली गिरावट भी आयी थी। गन्ने पर क्रय कर की राशि वर्ष 1975-76 से वर्ष 1981-82 तक बहुत कुछ स्थिर बनी रही और वर्ष 1982-83 और 1983-84 में उसमें सुधार हुआ, लेकिन 1984-85 और 1985-86 में आगम राशि पूर्व स्तर पर आ न गई।

कुल भिनाकर बिजलीकर से आगम में दीर्घकालीन प्रवृत्ति बढ़ती हुई दर से सृद्धि रही है। इसमें यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इसमें देश में निरन्तर बढ़ती हुई बिजली तथा समय-समय पर बिजलीकर की दरों में वृद्धि महत्वपूर्ण उत्तरदायी घटक रहे हैं। जब तक केन्द्रीय बिजलीकर नहीं था कुल बिजलीकर का लगभग 98 प्रतिशत भाग सामान्य बिजलीकर से प्राप्त होता था लेकिन केन्द्रीय बिजलीकर के पश्चात् बिजलीकर के कुल आगम में सामान्य बिजलीकर के भाग में कमी आयी है। वर्ष 1967-68 में कुल बिजलीकर में सामान्य बिजलीकर का भाग लगभग 72 प्रतिशत था जो वर्ष 1979-80 में 75, वर्ष 1983-84 में 78 और वर्ष 1985-86 में 77 प्रतिशत था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय देश ^{के} विभिन्न राज्य तीन वर्गों में विभाजित थे। "अ" वर्ग में 9 राज्य थे, जिनमें असम, बिहार, मध्यप्रदेश, बम्बई, उड़ीसा, पंजाब, मद्रास, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल शामिल थे। इनमें असम और उत्तर प्रदेश को छोड़कर यह कर अन्य राज्यों में पहले से ही आरोपित था। "ब" वर्ग के राज्यों में 7 राज्य - हैदराबाद, मध्यभारत, मैसूर, पेशवा, राजस्थान, तौराबद और

द्रावणकोर-कोचीन शामिल थे। "त" वर्ग के राज्यों में अजमेर, भोपाल, हुग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर आदि आते थे। वर्ष 1947-48 में ब और त वर्ग के अधिकांश राज्यों में बिड़कीकरण नहीं था। देश में स्वतन्त्रताप्राप्ति और नियोजन-प्रारम्भ के मध्य की अवधि 1947-48 से 1950-51 तक। में बिड़कीकरण आगम को तालिका नं० 7.2 में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 7.2

राज्यों की बिड़कीकरण-आगम 1947-48 से 1950-51

राज्य का नाम	लाख लव्यों में।			
	1947-48	1948-49	1949-50	1950-51
1	2	3	4	5
<u>"अ" वर्ग के राज्य</u>				
1. असम	-	24	49	56
2. बिहार	106	233	258	440
3. मध्य प्रदेश	62	143	199	235
4. बम्बई महाराष्ट्र	466	676	1323	1518
5. उड़ीसा	6	30	62	80
6. पंजाब	21	27	139	178
7. मद्रास तमिऴनाडु	831	1303	1524	1587
8. उत्तर प्रदेश	-	427	612	521
9. वंग बंगाल	211	432	464	520
<u>"अ" वर्ग का योग</u>	<u>1705</u>	<u>3295</u>	<u>4630</u>	<u>5135</u>
<u>"ब" वर्ग के राज्य</u>				
1. हैदराबाद	-	-	-	73
2. मध्य भारत	-	-	-	42

1	2	3	4	5
3. मैसूर	-	-	-	140
4. पेंडु	-	-	-	30
5. राजस्थान	-	-	-	-
6. तौराष्ट्र	-	-	-	6
7. दून कोर कोचीन	-	-	-	259
"ब" वर्ग का योग	-	550	509	550
"त" वर्ग के राज्य	-	-	-	-
कुल योग (अ + ब)	1703	3845	5139	5685

स्रोत : "रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया क्वोटिन", अप्रैल 1952.

टिप्पणी : कुल बिजलीकर में सामान्य बिजलीकर एवं मोटर त्रिप्ट पर बिजलीकर की राशि शामिल है ।

तालिका नं० 7.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल भिनाकर वर्ष 1947-48 में बिजलीकर से 1703 लाख रुपये की आमद हुई जिसमें से लगभग 49 प्रतिशत राशि अकेले मद्रास राज्य को प्राप्त हुई थी और 27 प्रतिशत राशि बम्बई राज्य को मिली थी । इस तरह देश में बिजलीकर आमद का 76 प्रतिशत भाग केवल दो राज्यों को ही अपनी व्यापारिक सम्यन्वता के कारण प्राप्त हो रहा था । वर्ष 1948-49 में बिजलीकर से कुल आमद 3845 लाख रुपये था जिसमें से 3295 लाख रुपये "अ" वर्ग के राज्यों और 550 लाख रुपये "ब" वर्ग के राज्यों को प्राप्त हुए । वर्ष 1949-50 में बिजलीकर आमद में पर्याप्त वृद्धि होकर आमद राशि 5139 लाख रुपये हो गयी जिसमें 4630 लाख रुपये अ वर्ग के राज्यों को और 509 लाख रुपये ब वर्ग के राज्यों को प्राप्त हुई।

वर्ष 1950-51 में बिजली कर आगम की कुल 5685 लाख रुपये की राशि में अ और ब वर्ग के राज्यों की राशि क्रमशः 5135 लाख रुपये और 550 लाख रुपये थी। स्पष्ट है कि नियोजन से पूर्व के चार वर्षों में बिजलीकर से आगम में निरन्तर वृद्धि हुई। इसमें ब वर्ग के राज्यों की बिजलीकर से आगम लगभग स्थिर रही लेकिन अ वर्ग के राज्यों की बिजलीकर आगम से निरन्तर बढ़ती हुई राशि प्राप्त हुई। इस राशि में वर्ष वार और राज्य वार दोनों ही दृष्टि से वृद्धि हुई। इन चारों ही वर्षों में देश में बिजलीकर आगम में प्रथम और द्वितीय स्थान लगातार क्रमशः मद्रास और बम्बई का बना रहा। यह उल्लेखनीय है कि बम्बई का प्रारम्भ से दूसरा स्थान रहा लेकिन तुलनात्मक रूप से इसकी राशि में सर्वाधिक वृद्धि हुई। वर्ष 1947-48 में देश में बिजलीकर आगम में मद्रास और बम्बई का भाग क्रमशः 49 और 27 प्रतिशत था जो वर्ष 1950-51 में क्रमशः 28 और 27 प्रतिशत हो गया। अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल को इस कर से प्रशसनीय आगम प्राप्त हुई।

बिजलीकर आगम नियोजन काल में

वर्ष 1957 में राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व तक देश के सभी राज्यों में यह कर लागू किया जा चुका था। इस अवधि में सामान्य बिजलीकर और मोटर स्प्रिंट पर बिजली कर की धुंध-धुंध राशियाँ उपलब्ध थी। वर्ष 1951-52 में सामान्य बिजलीकर से कुल कर आगम 5440 लाख रुपये था जो 1956-57 में 7069 लाख रुपये हो गया। इस अवधि में मोटर स्प्रिंट पर बिजलीकर से आगम 453 लाख रुपये से बढ़कर 870 लाख रुपये हो गया और इस प्रकार बिजलीकर से कुल आगम 5893 लाख रुपये से बढ़कर 7939 लाख रुपये हो गया। इन तथ्यों को विस्तृत रूप में तालिका नं० 7.3 में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 7.3 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्ष 1951-52 से 1956-57 की अवधि में केवल वर्ष 1952-53 में सामान्य बिजलीकर में अवसर कमी हुई लेकिन उसके परभाव निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति रही। यह उल्लेखनीय रहा कि वर्ष 1952-53 में अ वर्ग के विभिन्न राज्यों में यह कर लगा हुआ था उनमें केवल तीन राज्यों आसम,

ज्योतिष : सिध्द गणेश १९५६. पृष्ठ ५१२ एवं ५१५.

टिप्पणी : 'स' वर्ग के राज्यों के सामान्य बिजुगर में मोटर स्पुट पर बिजुगर भी सम्मिलित है ।

उड़ीसा और पंजाब को छोड़कर अन्य 6 राज्यों में सामान्य बिड़्डीकर से आगम में गिरावट आयी। वर्ष 1951-52 में बिड़्डीकर आगम में प्रथम स्थान मद्रास राज्य का था जिसकी बिड़्डीकर से कुल आगम 1688 लाख रुपये थी जो देश के कुल बिड़्डीकर आगम का 28.64 प्रतिशत थी। दूसरा स्थान बम्बई राज्य का था जिसकी आगम 1259 लाख रुपये 121.36 प्रतिशत थी। वर्ष 1954-55 में बम्बई राज्य का प्रथम स्थान हो गया और मद्रास राज्य द्वितीय स्थान पर आ गया। इसका मुख्य कारण वर्ष 1954-55 में मद्रास राज्य में से आन्ध्र प्रदेश का अलग हो जाना था। यही स्थिति वर्ष 1956-57 में रही। इतना ही नहीं बरन् इस अवधि में वहाँ बम्बई राज्य का आगम 1259 लाख रुपये से बढ़कर 2062 लाख रुपये हो गया। वहाँ मद्रास राज्य का आगम 1688 लाख रुपये से घटकर 1130 लाख रुपये हो रह गया। यह अवधि अधिकांश राज्यों में बिड़्डीकर आरोपण की प्रारम्भिक अवधि थी। अतः बम्बई राज्य को छोड़कर अधिकांश राज्यों में इस कर से आगम में वृद्धि की गति धीमी रही और बिहार राज्य में आगम की राशि वर्ष 1951-52 में 409 लाख रुपये से घटकर वर्ष 1956-57 में 350 लाख रुपये हो रह गयी।

इस अवधि में ब वर्ग के अनेक राज्यों में बिड़्डीकर पहली बार लगा और कुल मिलाकर इस वर्ग के राज्यों में बिड़्डीकर आगम में तेजी से वृद्धि हुई। वर्ष 1951-52 में ब वर्ग के 7 राज्यों में राजस्थान को छोड़कर अन्य 6 राज्यों में यह कर लगा हुआ था और उनमें आय की दृष्टि से प्रथम तीन स्थान क्रमातः द्रावन कोर कोचीन 1244 लाख रुपये, मैसूर 1142 लाख रुपये और हैदराबाद 1106 लाख रुपये के थे। वर्ष 1956-57 में प्रथम तीन राज्यों में क्रमातः हैदराबाद, द्रावन कोर कोचीन और राजस्थान शामिल थे। ब वर्ग के राज्यों में वर्ष 1951-52 में बिड़्डीकर आगम नगण्य था जो क्रमातः बढ़ता चला गया है और वर्ष 1956-57 में 203 लाख रुपये हो गया।

राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1947-58 से 1960-61 तक में बिड़्डीकर से आगम

वर्ष 1957 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् देश में 14 राज्य हो गये और वर्ष

1960 में गुजरात राज्य के गठन के पश्चात् राज्यों की संख्या बढ़कर 15 हो गयी । इस अवधि में यद्यपि केन्द्रीय बिजलीकर लग गया था लेकिन राज्यवार उसके कुछ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इसकी राशि को सामान्य बिजलीकर की राशि में जोड़कर ही तालिका नं० 7.4 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं० 7.4 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल मिलाकर राज्यवार और वर्षवार सामान्य प्रयुक्ति बिजलीकर आगम में वृद्धि की रही है । आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1958-59 में सामान्य बिजलीकर में गिरावट आयी लेकिन बाद के वर्षों में निरन्तर महत्वपूर्ण वृद्धि होती रही । अतः में वर्ष 1957-58 में बिजलीकर से कुल आगम 239 लाख रुपये थी जो वर्ष 1958-59 में बढ़कर 273 लाख रुपये हो गयी लेकिन वर्ष 1959-60 में सामान्य बिजलीकर से आगम में भारी गिरावट होने के कारण बिजलीकर से कुल आगम 227 लाख रुपये ही रह गया । लेकिन वर्ष 1960-61 में बढ़कर 282 लाख रुपये पहुँच गया । बिहार राज्य में इन चार वर्षों की अवधि में बिजलीकर से आगम लगभग दुगुना हो गया । मैसूर राज्य को प्राप्त बिजलीकर की राशि 497 लाख रुपये से बढ़कर 813 लाख रुपये, केरल राज्य की राशि 492 लाख रुपये से बढ़कर 920 लाख रुपये और मध्य प्रदेश की राशि 502 लाख रुपये से बढ़कर 720 लाख रुपये हो गई । बम्बई राज्य के पुनर्गठन के कारण इस राज्य की बिजलीकर आगम की राशि में कमी आई । यदि उतमें से विभक्त गुजरात राज्य की राशि को मिला दिया जाए तो स्पष्ट है कि वर्ष 1957-58 में प्राप्त आगम 3769 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 1960-61 में 4269 लाख रुपये हो गया । इन चार वर्षों की अवधि में उड़ीसा और पंजाब राज्यों में बिजलीकर से आगम लगभग डेढ़ गुना हो गया । राजस्थान में आगम की स्थिति में मामूली सुधार हुआ, लेकिन मद्रास राज्य का आगम 1382 लाख रुपये से बढ़कर 1912 लाख रुपये, उत्तर प्रदेश का आगम 1046 लाख रुपये से बढ़कर 1216 लाख रुपये हो गया । निरपेक्ष राशि के रूप में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिमी बंगाल में हुई जहाँ वर्ष 1957-58 में बिजलीकर का आगम 1253 लाख रुपये था जो बढ़कर वर्ष 1960-61 में 1973 लाख रुपये हो गया अर्थात् 720 लाख रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई । वर्ष 1958-

॥ रात्रि तारा स्थितौ ॥

रा.प्र. क्र. सं. सं.	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.
रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं.	रा.प्र. क्र. सं. सं

स्मृत : रिजर्व बैंक ग्राहक इण्डिया कुंटेडिन जून १९५९, मई १९६०, जून १९६१ तथा अक्टूबर १९६२.

टिप्पणी : 13। गजराज राज्य के द्वारा 1960-61 में रुब 1,960 के माप 1961 तक के आय 1960 का अनुमान 1960-61 के समान है।
14। महाराष्ट्र राज्य के माप 1960-61 के समान है।

59 और 1959-60 में उत्तर प्रदेश में बिज्जीकर आगम में गिरावट का कारण चीनी और वस्त्र पर बिज्जीकर के स्थान पर केन्द्रीय उत्पादन कर लगाना था ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-62 से 1965-66 तक। में बिज्जीकर से आगम

तृतीय पंचवर्षीय योजना में बिज्जीकर आगम में तेजी से वृद्धि हुई और इन पाँच वर्षों में बिज्जीकर से कुल आगम 18144 लाख रुपये से बढ़कर 36779 लाख रुपये अर्थात् दुगुने से भी अधिक हो गया । इस अवधि में कर आगम प्रवृत्ति को तालिका नं० 7.5 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं० 7.5 से स्पष्ट है कि इस अवधि में केवल जम्मू और कश्मीर के उत्पाद को छोड़कर शेष सभी राज्यों में प्रतिवर्ष बिज्जीकर आगम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस अवधि में जिन राज्यों में बिज्जीकर आगम दुगुने से भी अधिक हो गया, उनमें अतम, जम्मू व कश्मीर, मैसूर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल शामिल हैं । राजस्थान में इस अवधि में बिज्जीकर से आगम तीन गुने से भी अधिक हो गया । निरपेक्ष राशि के रूप में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिमी बंगाल में हुई जहाँ वर्ष 1961-62 में 2145 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 1965-66 में 4538 लाख रुपये हो गयी ।

तीन वार्षिक योजनाओं 1966-67 से 1968-69 की अवधि में बिज्जीकर से आगम

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्षों में योजना अवकाश रहा । इस अवधि में बिज्जीकर से आगम को तालिका नं० 7.6 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं० 7.6 के अफ़ोर्न से स्पष्ट है कि वर्ष 1966-67 की तुलना में वर्ष 1967-68 में कुल बिज्जीकर आगम में 7550 लाख रुपये की वृद्धि हुई और वर्ष 1968-69 में 6250 लाख रुपये से अधिक की वृद्धि हुई । इस अवधि में राज्यवार विश्लेषण की दृष्टि से दो नये राज्यों हरियाणा और नागालैण्ड का प्रवेश हुआ । विगत वर्षों की

तालिका नं० 7.5

एतीय पंचवर्षीय योजना में विद्युत् से आगम

राशि लाख स्वयों में

	1961-62	1962-63	1963-64	1965-66	1966-67										
राज्य का योग	1337	144	1481	1397	139	1536	1743	160	1903	1856	196	2052	2232	227	2459
अन्य प्रदेश	198	146	344	215	200	415	266	275	541	315	318	633	509	290	799
विहार	1024	110	1134	1132	113	1245	1549	126	1675	1611	140	1751	1990	153	2143
अवरात	1288	94	1382	1562	135	1697	1848	112	1960	2015	122	2127	2548	150	2698
पुन्य व काशीर	28		28	41		41	54	32	76	51	32	83	50	26	76
भूर कनाटका	944	02	946	1118	04	1122	1350	02	1352	1435	150	1585	1939	15	1954
केरल	939	117	1056	1080	121	1201	1427	25	1452	1527	135	1682	1804	26	1830
मध्य प्रदेश	726	81	807	876	82	958	1164	101	1265	1480	115	1595	1855	142	1997
महाराष्ट्र	3201	302	3503	3646	410	4056	5003	487	5490	5492	511	6003	6556	603	7059
उड़ीसा	356	46	402	497	53	550	679	65	744	722	65	787	930	63	993
पुषाव	799	92	891	897	100	997	1297	109	1406	1584	116	1700	1858	131	1989
राजस्थान	432	30	462	605	40	645	883	94	977	1075		1075	1417		1417
महाराष्ट्र	1849	277	2126	2190	290	2480	2494	208	2702	2836	300	3136	3710	385	4095
उत्तर प्रदेश	1302	135	1437	1463	171	1634	1868	202	2070	1953	210	2163	2485	247	2732
पश्चिम बंगाल	1891	254	2145	2163	305	2468	2926	292	3218	3101	300	3401	4074	464	4538
कुल योग	16314	1830	18144	18752	2135	20887	24541	2290	26831	27053	2700	29753	33857	2922	36779

स्त्रोत : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, बुलेटिन अगस्त 1963, मई 1964, मई 1965 तथा अगस्त 1967.

टिप्पणी : वर्ष 1964-65 तथा 1965-66 के राजस्थान के सामान्य विद्युत् से आगम में मोरारजी देसाई की राशि भी शामिल है। सामान्य विद्युत् की राशि में केन्द्रीय विद्युत् की राशि भी शामिल है।

तीन वार्षिक योजनाओं में बिजली के आगम

राशि लाख रुपये में।
1966-67 1967-68 1968-69

वर्ग	1966-67	1967-68	1968-69	कुल	अनुमानित	कुल	अनुमानित
आम्र प्रदेश	2823	186	3009	3476	3868	216	52
असम	444	395	839	1021	648	50	479
बिहार	2426	239	2665	3474	3303	51	3354
गुजरात	3295	219	3514	3922	3399	934	256
हरियाणा	323	23	346	954	1284	66	66
जम्मू व कश्मीर	66	43	109	131	119		
केरल	2478	165	2643	2825	2998	409	13
कोलकाता	2278		2278	2628	2641	246	
मध्य प्रदेश	2199	154	2353	2828	2134	809	177
महाराष्ट्र	8125	622	8747	9885	7334	2545	766
नागालैण्ड					02	03	
उड़ीसा	1012	85	1097	1256	876	450	1306
पंजाब	1872	119	1991	1806	1643	680	162
राजस्थान	1591		1591	1976	2004	247	
तमिलनाडु	4398	479	4877	5648	4522	1036	544
उत्तरप्रदेश	3013	332	3345	4759	3848	347	456
प० बंगाल	4342	523	4865	5230	3086	2055	548
योग	40685	3584	44269	51819	43709	10007	3529
				908	831		58076

स्त्रोत : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन मई 1968, जून 1969, तथा अगस्त 1970.

टिप्पणी : तन् 1967-68 तथा 1968-69 में हरियाणा के सामान्यबि००० में के०बि०कर एवं मो०लिट्ट पर बि०कर सम्मिलित है।
तन् 1968-69 में बिहार के सामान्य बिजली के केन्द्रीय बिजली एवं मोटरलिट्ट पर बिजली सम्मिलित है।

तामान्य प्रवृत्ति की भाँति ही महाराष्ट्र राज्य का स्थान बिजुलीकर आगम में प्रथम बना रहा और उसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 10 लाख रुपये से अधिक की वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप वर्ष 1966-67 में महाराष्ट्र की बिजुलीकर से प्राप्त 8747 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 1968-69 में 10974 लाख रुपये हो गयी। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु की आय इस अवधि में 4877 लाख रुपये से बढ़कर 6112 लाख रुपये हो गयी। यद्यपि पश्चिमी बंगाल का तृतीय स्थान बना रहा लेकिन आगम में वृद्धि लगभग 4000 लाख रुपये वार्षिक ही रही। उत्तर प्रदेश का बिजुलीकर आगम वर्ष 1966-67 में 3345 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 1968-69 में बढ़कर 5102 लाख रुपये हो गया। इस राशि में वृद्धि के तन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इस राज्य की गन्ने पर क्रय कर के रूप में पर्याप्त राशि को इन वर्षों के तमकों में बिजुलीकर आगम में शामिल किया गया है। इसी अवधि में हरियाणा की आगम 346 लाख रुपये से बढ़कर 1284 लाख रुपये हो गयी। इस अवधि में बिहार और पंजाब राज्यों में किसी वर्ष की गिरावट की प्रवृत्ति को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में बिजुलीकर आगम में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति रही।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल (वर्ष 1969-70 से 1973-74 तक) में बिजुलीकर से आगम

इस अवधि के वर्षों के तमकों में बिजुलीकर के चारों उपभागों अर्थात् तामान्य बिजुलीकर, केन्द्रीय बिजुलीकर, मोटर स्प्लिट पर बिजुलीकर और गन्ने पर क्रय कर को अलग-अलग तालिका नं० 7.7 में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 7.7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1969-70 में गन्ने पर क्रय कर की राशि 1170 लाख रुपये थी जो वर्ष 1970-71 में घटकर 1110 लाख रुपये रह गयी। लेकिन इसके बाद के दो वर्षों में यह बढ़ती हुई क्रमशः 1298 लाख रुपये और 1846 लाख रुपये हो गयी। वर्ष 1973-74 में यह राशि 1843 लाख रुपये रही। वर्ष 1969-70 में यह कर केवल तीन राज्यों बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में लागू था। वर्ष 1971-72 में इसे मध्य प्रदेश, वर्ष 1972-73 में आन्ध्र प्रदेश तथा वर्ष 1973-74 में हरियाणा में भी लागू कर दिया तथा पिछले महत्त्वपूर्ण भाग उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों को भी प्राप्त होता है।

राशि लाज समयों में।
1971-72

06-6261

1978-79

卷之七

11-10-61

169

क्र.सं.	विवरण	1972-73	1973-74	1972-73	1973-74	1972-73	1973-74	1972-73	1973-74
1.	अन्य प्रदेश	4978	491	191	5660	6429	957	-	-
2.	असम	794	128	-	1475	868	170	580	7386
3.	बिहार				4916	4465	674	06	1618
4.	गुजरात				8742	7005	1865	527	5240
5.	हरियाणा				5220	1686	1245	120	9397
6.	हिमाचल प्रदेश	237	08	29	274	266	14	10	3105
7.	जम्मू व कश्मीर	344	-	24	368	321	-	28	290
8.	कर्नाटक	4691	1110	-	5801	5537	1285	-	349
9.	केरल	4149	465	-	4614	4879	501	-	6822
10.	मध्य प्रदेश	3808	1398	58	5266	4284	1614	02	5380
11.	महाराष्ट्र	12990	4476	767	18233	15078	5591	1703	5903
12.	मणिपुर				39	50			23115
13.	मेघालय	31	05	19	55	50	03	25	50
14.	नागालैण्ड	39	-	06	45	51			78
15.	उड़ीसा	1237	714	170	2121	1660	832	172	51
16.	पंजाब	3388	871	350	4609	3911	1017	323	2664
17.	राजस्थान	3234	471	-	3705	3901	587	-	5251
18.	तमिलनाडु				11402	9808	2082	1335	4488
19.	उत्तर प्रदेश	6412	628	754	8680	7791	527	852	13225
20.	प.० बंगाल	5615	2675	834	9124	6403	2507	1259	10118
	योग	61947	13440	2797	97649	84448	21221	6770	1843
									114693

स्रोत : रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया क्वार्टरली अकॉउंट्स 1971, सितम्बर 1972, जून 1973, सितम्बर 1974 तथा सितम्बर 1975.

टिप्पणी : 1. हिमालय प्रदेश के तन् 1970-71 में 25 जनवरी 1971 से 31 मार्च 1971 तक के आंकड़े हैं।

2. तन् 1969-70 में बिहार राज्य के सामान्य विद्युत् में केन्द्रीय विद्युत् तथा मोटर स्पिड पर विद्युत् शामिल है।

3. नागालैण्ड और राजस्थान के सामान्य विद्युत् में मोटर स्पिड पर विद्युत् की राशि शामिल है।

चतुर्थ योजना काल के पाँच वर्षों में कुल बिजलीकर की राशि में 71.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इनमें सामान्य बिजलीकर में लगभग 72 प्रतिशत, केन्द्रीय बिजलीकर में लगभग 67 प्रतिशत, मोटर टिप्ट पर बिजलीकर में 76 प्रतिशत और गन्ने पर कुय कर में लगभग 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्यवार क्रम की दृष्टि से वर्ष 1969-70 में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात क्रमाः पहले पाँच स्थानों पर थे और यही क्रम वर्ष 1974-75 में बना रहा। महाराष्ट्र में इन पाँच वर्षों में वृद्धि की दर भी पर्याप्त ऊँची अर्थात् 78.3 प्रतिशत थी और देश की कुल बिजलीकर आगम में वर्ष 1973-74 में महाराष्ट्र का भाग लगभग 20 प्रतिशत था। इस योजनाकाल में राज्य ^{सूचियों} में प्रथम बार शामिल राज्यों में हिमाचल प्रदेश, मणि-पुर सरकारों को भी क्रमाः बढ़ती हुई राशि प्राप्त हुई। कुल मिलाकर इस अवधि में मामूली अपघातों को छोड़कर सभी राज्यों की बिजलीकर आगम में निरन्तर वृद्धि होती रही है और अनेक राज्यों में इन पाँच वर्षों में आगम की वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर 171.72 प्रतिशत से अधिक रही। इनमें उत्तर प्रदेश 173.2 प्रतिशत, तमिलनाडु 183.3 प्रतिशत तथा उड़ीसा 183.7 प्रतिशत के नाम उल्लेखनीय हैं।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना एवं उसके परचात छठवीं योजना से पूर्व अन्तराल की अवधि 1 जन. 1974-75 से 1979-80 तक में बिजलीकर से आगम

1 अप्रैल वर्ष 1974 को पाँचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई जो मूल रूप से 31 मार्च, 1979 को समाप्त होनी थी लेकिन केन्द्र में सरकार परिवर्तन के कारण इसे 31 मार्च, 1978 को ही समाप्त कर दिया गया और इसके परचात दो वर्ष तक योजना अंतराल रहा। इस तरह चौथी और छठी योजना के मध्य लगभग 6 वर्षों का अन्तराल रहा। इन 6 वर्षों में बिजलीकर से आगम को तालिका नं० 7.8 में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 7.8 के विवरण से स्पष्ट होता है कि इन 6 वर्षों की अवधि में बिजलीकर आगम में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1974-75 में बिजलीकर से कुल आगम 155098 लाख रुपये था जिसमें वर्ष 1975-76 में 25.32 %

तालिका नं० 7.9

पाखी पंचवर्षीय योजना एवं छवी योजना के पूर्व विहीकर ले आगम

लाक रुपया में

क्षेत्र	1974-75				1975-76				1976-77			
	अ. वि.	अ. वि.	अ. वि.	अ. वि.	अ. वि.	अ. वि.	अ. वि.	अ. वि.	अ. वि.	अ. वि.	अ. वि.	अ. वि.
आन्ध्र प्रदेश	9091	1936	372	11399	11328	2439	-	341	14108	12846	1990	-
असम	1029	437	610	2076	1348	699	671	-	2718	1525	637	428
बिहार	5920	1049	142	7119	7827	1420	23	221	9491	9829	1556	-
गुजरात	9749	2787	916	13452	11204	3353	1028	-	15585	14025	4567	15
हरियाणा	2125	1463	217	3899	2804	1822	2004	120	4950	3283	2721	272
हिमाचल प्रदेश	336	16	16	368	434	20	18	-	472	525	27	19
जम्मू व कश्मीर	399	-	23	422	616	-	41	-	857	557	-	93
कर्नाटक	7652	1712	-	9364	9482	2305	-	-	11787	10964	2766	-
केरल	5900	632	-	7532	8974	818	-	-	9792	9792	1042	-
मध्य प्रदेश	6254	2114	-	8374	8982	2743	-	13	11738	9528	3125	-
महाराष्ट्र	20748	7101	2207	30872	24307	8598	2224	1875	37004	28412	112152503	178043910
मणिपुर	79	04	21	51	80	07	34	-	96	99	08	23
मेघालय	51	01	10	104	76	01	06	-	121	77	01	05
नागालैण्ड	1964	686	81	2731	2929	791	84	-	3804	3069	1549	89
उड़ीसा	4021	1751	563	6335	5061	1700	555	-	7316	7147	1898	567
पंजाब	4944	810	-	5754	5672	1088	-	-	6760	7003	1426	-
राजस्थान	13	-	-	13	23	-	-	-	23	37	-	-
सिक्किम	14044	2887	1857	19075	15594	3327	1972	234	21127	16506	4242	2186
तमिलनाडु	9942	1055	1232	13542	16024	1658	1350	1794	20826	18457	2347	1615
त्रिपुरा	7765	3637	1105	12507	9554	4681	1277	-	15912	11252	5402	1593
उत्तर प्रदेश	113064	30078	9866	155098	142815	37470	9487	4598	194370	165005	46519	109154600
पश्चिम बंगाल	20748	7101	2207	30872	24307	8598	2224	1875	37004	28412	112152503	178043910
योग	113064	30078	9866	155098	142815	37470	9487	4598	194370	165005	46519	109154600

राज्य	1977-78			1978-79			1979-80		
	राज्य	राज्य	राज्य	राज्य	राज्य	राज्य	राज्य	राज्य	राज्य
जान्य प्रदेश	14255	1671	345	16271	16274	1870	18493	19610	2131
असम	1520	655	669	2844	3432	5571	3432	3009	251
अरुणाचल	14907	4997	1289	21193	16576	5571	23526	20652	6851
बिहार	9624	2340	201	12165	11150	1756	13063	15226	273
हरियाणा	3839	2723	350	6962	4423	3103	7968	4697	3682
हिमाचल प्रदेश	610	32	25	667	720	37	801	994	72
जम्मू-काश्मीर				886	1049		1049	1280	
कर्नाटक	12099	3010		15109	12474	3975	16449	16225	3753
केरल	10769	1105		11874	13285	1404	14689	14762	1502
मध्य प्रदेश	9862	2810	02	12672	10874	3533	14407	12234	3870
महाराष्ट्र	30193	11137	2749	46085	35576	13845	53727	40983	15836
मणिपुर	105			105	107		107		
मेघालय	102	14	28	144	09	112	159	143	14
नागालैण्ड	101	01	04	106			120	140	03
उड़ीसा	2778	1690	245	4713	3899	1618	5518	4642	1953
पंजाब	7434	2680	637	10751	9630	2458	11931	9275	2939
राजस्थान	8562	1463		10025	9662	1706	11368	11818	1768
सिक्किम	47			47	44		44	54	
तमिळनाडु	17680	4290	2216	24304	21736	4984	29418	23412	6245
त्रिपुरा	99			99	117		117	155	
उत्तर प्रदेश	19123	1935	1678	24603	20707	2301	27225	23495	2197
पश्चिम बंगाल	13424	4867	1511	19802	15382	6477	23720	17795	7966
योग	178019	47420	11401	241429	206246	54750	277331	240729	61306

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, कुएटिन लिटम्वर 1976, लिटम्वर 1978, लिटम्वर-अक्टूबर 1979, अक्टूबर 1980 तथा अगस्त दिव्यणी : सन् 1978-79 में असम के लामान्य बिहीकर एवं सुट्टरस्पिटपर बिहीकर की राशि शामिल है । 1981. सन् 1978-79 और 1979-80 में जम्मू-काश्मीर के लामान्य बिहीकर में सुट्टरस्पिटपर बिहीकर की राशि शामिल है । कुछ राज्यों की कुछ बिहीकर की राशि शामिल है लेकिन उनका असल विवरण उपलब्ध नहीं है ।

की वृद्धि हुई और यह 194370 लाख रुपये हो गया । इस कुल कर आगम में वर्ष 1976-77 में 16.80 प्रतिशत, वर्ष 1977-78 में 6.34 प्रतिशत, तन् 1978-79 में 14.9 प्रतिशत और वर्ष 1979-80 में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कुल मिलाकर इन 6 वर्षों की अवधि में बिजलीकर आगम दुगुने से अधिक हो गया । वर्ष 1977-78 में बिजलीकर आगम में धीमी प्रगति का कारण आयातकालीन स्थिति के पश्चात् केन्द्र में तत्ता परिवर्तन और विभिन्न राज्यों में आम चुनाव के कारण करारोपण और उसकी कसूलचावी में धीमी गति रही ।

इस अवधि में लगभग सभी महत्वपूर्ण राज्यों में बिजलीकर से आगम दुगुने से अधिक हो गया । इस तन्दर्भ में कुल बिजलीकर आगम की दृष्टि से महाराष्ट्र में 103 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 123 प्रतिशत, पश्चिमी बंगाल में 125 प्रतिशत, राजस्थान में 136 प्रतिशत और गुजरात में 115 प्रतिशत की वृद्धि हुई । देश के कुल बिजलीकर आगम में वर्ष 1974-75 में प्रथम पाँच स्थान क्रमशः महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिमी बंगाल के थे । वर्ष 1979-80 के अन्त में भी यही स्थिति बनी रही ।

छठीं पंचवर्षीय योजना । वर्ष 1980-81 से वर्ष 1984-85 तक। में बिजलीकर से आगम

इस योजना में राज्यवार बिजलीकर की प्रवृत्ति और सातवीं योजना के प्रथम वर्ष तन् 1985-86 के बजट अनुमानों की तालिका नं० 7.9 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका नं० 7.9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस योजनाकाल में भी पूर्ववर्ती प्रवृत्ति के अनुसार लगभग सभी राज्यों में बिजलीकर आगम में वृद्धि होती रही है । वर्ष 1980-81 में बिजलीकर से कुल आगम 388758 लाख रुपये था जो वर्ष 1984-85 में तर्जोहित अनुमानों के अनुसार 706465 लाख रुपये हो गया । इस अवधि में विभिन्न राज्यों की कुलनात्मक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है । वर्ष 1984-85 में यद्यपि प्रथम दो स्थानों पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु रहे लेकिन तीसरे स्थान पर गुजरात राज्य आ गया तथा चतुर्थ स्थान पर आन्ध्र प्रदेश की स्थिति बन गयी ।

छत्तीसगढ़ पंचवर्षीय योजना में बिजलीकरण के आगम

आगत व्ययों में
1982-83

क्र.सं.	विवरण	1980-81			1981-82			1982-83		
		आगत व्यय	आगत व्यय	आगत व्यय	आगत व्यय	आगत व्यय	आगत व्यय	आगत व्यय	आगत व्यय	आगत व्यय
ग्राम्य प्रदेश		24566	3313	347	28226	26549	7618	395	34562	33549
असम					3149				5326	3348
बिहार		16981	2192	203	19376	24008			24008	21014
गुजरात		23714	9240	2431	35385	31892	10519	3830	46241	34941
हरियाणा		10483		117	10600	7730	5546	561	13837	9143
हिमाचल प्रदेश		1230	79	47	1356	1575	117	53	1745	1662
जम्मू-काश्मीर		1788			1788	2289			2289	2367
कर्नाटक		19075	4661		23736	24020	7866		31886	27116
केरल		18251	2143		20394	22414	2135		24549	25609
मध्य प्रदेश		15575	4425		20000	19627	6869		26096	24981
महाराष्ट्र		49442	18937	4804	74959	60098	22486	7662	92411	68789
मणिपुर					135				192	167
मेघालय		165	35	31	231	220	22	29	271	281
नागालैण्ड					187	295			295	38
उड़ीसा		5637	2026		7663	6815	2614		9429	7870
पंजाब		11384	3414	795	15593	14032	4296	854	19182	
राजस्थान		13109	1622		14731	16514	2107		18621	19879
सिक्किम		50			50	71			71	
तमिलनाडु		34264	8559	2865	45963	44622	9547	190	54733	55218
त्रिपुरा		196			196	305			305	
उत्तरप्रदेश		27455	2819	3236	35088	33454	4448	5306	45335	35847
प० बंगाल		20178	8539	1238	29955	24864	11251	1789	37904	26508
योग		297014	72004	15447	388758	366912	97071	20274	5061	489288
										421050
										101402
										21221
										5933
										549606

पश्चिम और छठवाँ स्थान क्रमशः उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल का था । इस अवधि में अंशतः राज्य में शान्ति व्यवस्था स्थापित होने से उत्तरी निरपेक्ष राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । वर्ष 1980-81 में बिजुलीकरण से आगम अंशतः राज्य में 3149 लाख ल्यूमेन था जो वर्ष 1984-85 में तीन गुने से अधिक 9598 लाख ल्यूमेन हो गया ।

राज्यों की विविध वर्षों में बिजुलीकरण से आगम

देश में वर्ष 1957 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् बिजुलीकरण के कुल आगम और कुल आगम में राज्य बिजुली के प्रतिशत की राज्यवार और वर्षवार स्थिति को तालिका नं० 7.10 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं० 7.10 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1957-58 में बिजुलीकरण आगम में प्रथम स्थान तत्कालीन बम्बई राज्य का था जिसे देश के बिजुलीकरण आगम का 32.18 प्रतिशत प्राप्त होता था । यद्यपि इस प्रतिशत में कमी होती गयी है लेकिन आज भी प्रथम स्थान इसी राज्य का है । वर्ष 1983-84 में देश में बिजुलीकरण के कुल भाग का 19.11 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ था । निरपेक्ष राशि की दृष्टि से गुजरात के आगम होने के पश्चात् वर्ष 1960-61 में महाराष्ट्र राज्य को 3215 लाख ल्यूमेन प्राप्त हुआ था जो वर्ष 1983-84 में 119671 लाख ल्यूमेन हो गया और वर्ष 1985-86 में 133860 लाख ल्यूमेन हो जाने का क्वट अनुमान है । बम्बई के पश्चात् दूसरा स्थान तमिळनाडु का था जिसे वर्ष 1957-58 में 1382 लाख ल्यूमेन 111.80 प्रतिशत बिजुलीकरण से प्राप्त हुए । विभिन्न वर्षों में तमिळनाडु और पश्चिमी बंगाल में द्वितीय एवं तृतीय स्थान का पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होता रहा है लेकिन वर्ष 1983-84 में दूसरा स्थान तमिळनाडु का ही था जिसे 70152 लाख ल्यूमेन 111.20 प्रतिशत बिजुलीकरण से प्राप्त हुए । वर्ष 1957-58 में पश्चिमी बंगाल को 1253 लाख ल्यूमेन बिजुलीकरण से प्राप्त हुए जो देश के कुल बिजुलीकरण आगम का 10.70 प्रतिशत था तथा सापेक्ष रूप से यह भाग वर्ष 1958-59 में 13.44 प्रतिशत तक पहुँच गया था लेकिन उसके पश्चात् इस भाग में कमी होती रही और वर्ष 1982-83 में कुल बिजुलीकरण आगम में पश्चिमी बंगाल का भाग 7.09 प्रतिशत रह गया । वर्ष 1984-85 में पश्चिमी बंगाल को बिजुलीकरण

सांख्यिकी नं० 7.10

कुल विपरीत आगम की राज्यवार और वर्षवार स्थिति

आगत वर्षों में

राज्य का नाम	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65								
राशि प्रतिशत	राशि प्रतिशत	राशि प्रतिशत	राशि प्रतिशत	राशि प्रतिशत	राशि प्रतिशत	राशि प्रतिशत	राशि प्रतिशत	राशि प्रतिशत								
आन्ध्र प्रदेश	962	8.21	921	7.43	1166	8.52	1283	7.83	1481	8.16	1536	7.35	1903	7.09	2052	6.90
आसम	239	2.04	273	2.20	227	1.66	282	1.72	344	1.90	415	1.99	541	2.02	633	2.13
बिहार	546	4.66	849	6.85	925	6.76	1138	6.94	1134	6.25	1245	5.96	1675	6.24	1751	5.89
गुजरात							1053	6.43	1382	7.62	1697	8.13	1960	7.31	2127	7.15
हरियाणा																
हिमाचल प्रदेश																
जम्मू व कश्मीर																
कर्नाटक	497	4.24	706	5.70	719	5.26	813	4.98	946	5.21	1122	5.37	1352	5.04	1585	5.33
केरल	492	4.20	617	4.98	774	5.44	903	5.50	1056	5.82	1201	5.75	1452	5.41	1662	5.59
मध्य प्रदेश	502	4.29	437	3.53	605	4.42	720	4.39	807	4.45	958	4.59	1265	4.72	1595	5.36
महाराष्ट्र	13769	32.18	3486	28.14	3640	26.60	3215	19.62	3503	19.31	4056	19.42	5490	20.46	6003	20.18
मणिपुर																
मेघालय																
नागालैण्ड																
उड़ीसा	199	1.70	213	1.72	242	1.77	314	1.92	402	2.22	550	2.63	744	2.77	787	2.65
पंजाब	503	4.30	547	4.42	668	4.88	719	4.57	891	4.91	997	4.77	1406	5.24	1700	5.71
राजस्थान	322	2.75	297	2.40	309	2.26	370	2.26	462	2.55	645	3.09	977	3.64	1075	3.61
तमिलनाडु																
त्रिपुरा	1382	11.80	1503	12.13	1675	12.24	1912	11.67	2126	11.72	2480	11.87	2702	10.07	3136	10.54
उत्तर प्रदेश	1046	8.93	885	7.14	1039	7.59	1642	10.02	1437	7.92	1634	7.82	2070	7.72	2163	7.72
पुच्छान	1253	10.70	1665	13.44	1711	12.51	1973	12.04	2145	11.82	2468	11.82	3218	11.99	3401	11.43
योग	11712	100	12389	100	13683	100	16388	100	18144	100	20887	100	26831	100	29753	100

राज्य का नाम	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73								
राशि प्रतिशत राशि प्रतिशत राशि प्रतिशत राशि प्रतिशत राशि प्रतिशत राशि प्रतिशत																
आन्ध्र प्रदेश	2459	6.69	3009	6.80	3476	6.71	4136	7.12	4309	6.45	4990	6.51	5001	5.96	5660	5.80
असम	799	2.17	839	1.90	1021	1.97	1177	2.03	1224	1.83	1154	1.50	1416	1.69	1475	1.51
बिहार	2143	5.83	2665	6.02	3474	6.70	3354	5.78	3637	5.44	3814	4.97	4227	5.04	4916	5.03
गुजरात	2698	7.34	3514	7.94	3922	7.57	4589	7.90	5457	8.17	6383	8.32	7362	8.77	8742	8.95
हरियाणा			346	0.78	954	1.84	1284	2.21	1419	2.12	1741	2.27	2162	2.58	2520	2.58
हिमाचल प्रदेश											38	0.04	225	0.27	274	0.28
जम्मू व कश्मीर	76	0.21	109	0.25	131	0.25	125	0.32	222	0.33	249	0.32	260	0.31	368	0.38
कर्नाटक	1954	5.31	2643	5.97	2825	5.45	3420	5.89	4051	6.06	4887	6.37	5159	6.15	5801	5.94
केरल	1830	4.98	2278	5.15	2628	5.07	2887	4.97	3224	4.83	3742	4.88	4237	5.05	4614	4.73
मध्य प्रदेश	1997	5.43	2353	5.32	2828	5.46	3120	5.37	3765	5.64	4097	5.34	4421	5.27	5266	5.39
महाराष्ट्र	17059	19.19	8747	19.76	9885	19.08	10974	18.90	12959	19.40	16002	20.87	16216	19.32	18233	18.67
मणिपुर											26	0.03	27	0.03	39	0.04
मेघालय											64	0.08	05	0.01	55	0.06
नागालैण्ड											14	0.01	28	0.03	45	0.05
उड़ीसा	993	2.70	1097	2.48	1256	2.42	1306	2.25	1450	0.17	1754	2.29	1748	2.08	2121	0.17
पंजाब	1989	5.41	1991	4.50	1806	3.49	2485	4.28	3071	4.60	3728	4.86	3769	4.49	4609	4.72
राजस्थान	1417	3.85	1551	3.59	1976	3.81	2251	3.88	2613	3.91	2797	3.65	3310	3.94	3705	3.79
तमिलनाडु																
तेलंगाना	4095	11.13	4877	11.02	5648	10.90	6112	10.52	7215	10.80	8185	10.67	9897	11.79	1402	11.68
त्रिपुरा																
उत्तर प्रदेश	2732	7.43	3345	7.56	4759	9.18	5102	8.79	5842	8.75	6227	8.12	7050	8.40	8680	8.89
पश्चिम बंगाल	4538	12.33	4865	10.99	5230	10.09	5689	9.80	6331	9.48	6793	8.86	7418	8.84	9124	9.34
योग	36779	100	44269	100	51819	100	58076	100	66796	100	76685	100	83938	100	97649	100

राज्य का नाम	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80							
	राशि प्रतिलक्ष	राशि प्रतिलक्ष	राशि प्रतिलक्ष	राशि प्रतिलक्ष	राशि प्रतिलक्ष	राशि प्रतिलक्ष	राशि प्रतिलक्ष							
1. ग्राम्य प्रदेश	7386	6.44	11399	7.35	14108	7.26	15264	6.72	16271	6.74	18493	6.67	22022	6.86
2. ग्राम	1618	1.41	2076	1.34	2718	1.40	2854	1.26	2844	1.19	3432	1.24	5508	1.09
3. शहरी	5440	4.57	7119	4.59	9491	4.88	11649	5.13	12165	5.04	13063	4.71	15546	4.84
4. शहरी	3105	2.71	3899	2.51	4950	2.55	6395	2.82	6962	2.88	7968	2.87	9005	2.80
5. ग्राम	9397	8.19	13452	8.67	15585	8.02	19835	8.74	21193	8.78	23526	8.48	28937	9.01
6. विमान प्रदेश	290	0.25	368	0.24	412	0.84	571	0.25	667	0.28	801	0.29	1113	0.35
7. ग्राम व शहरी	349	0.30	422	0.27	657	0.34	650	0.29	886	0.37	1049	0.38	1280	0.40
8. शहरी	6822	5.95	9364	6.04	11787	6.06	13730	6.05	15109	6.26	16449	5.93	19978	6.22
9. शहरी	5380	4.69	7532	4.86	9792	5.04	10760	4.74	11874	4.92	14689	5.30	16264	5.06
10. ग्राम प्रदेश	5903	5.15	8374	5.40	11738	6.04	12658	5.58	12674	5.25	14407	5.19	16104	5.02
12. शहरी	23115	20.15	30872	19.90	37004	19.04	43910	19.34	46085	19.09	53727	19.37	62643	19.51
12. शहरी	50	0.04	51	0.03	96	0.05	104	0.05	105	0.04	107	0.04	128	0.04
13. शहरी	78	0.07	104	0.07	121	0.06	130	0.06	144	0.06	159	0.06	197	0.06
14. शहरी	51	0.04	62	0.04	83	0.04	83	0.04	106	0.04	120	0.04	150	0.05
15. शहरी	2664	2.32	2731	1.76	3804	1.96	4704	2.07	4713	1.95	5518	1.99	6595	2.05
16. शहरी	5251	4.58	6335	4.08	7316	3.76	9612	4.23	10751	4.45	11931	4.30	12979	4.04
17. शहरी	4488	3.91	5754	3.71	6760	3.48	8429	3.71	10025	4.15	11368	4.10	13586	4.23
18. शहरी	-	-	13	0.01	23	0.01	37	0.02	47	0.02	44	0.02	54	0.02
19. शहरी	13225	11.53	19075	12.30	21127	10.87	23055	10.15	24304	10.07	29418	10.61	32506	10.12
20. शहरी	-	-	47	0.03	-	-	42	0.02	99	0.04	117	0.04	155	0.04
21. शहरी	10118	8.82	13542	8.73	20826	10.71	24317	10.71	24603	10.19	27225	9.82	30252	10.04
22. शहरी	10169	8.87	12560	8.06	15912	8.19	18247	8.04	19802	8.20	23720	8.55	28107	8.75
योग	114699	100	155098	100	194370	100	227039	100	241429	100	277331	100	321109	100

राज्य का नाम	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
राशि प्रतिवर्ष	राशि प्रतिवर्ष	राशि प्रतिवर्ष	राशि प्रतिवर्ष	राशि प्रतिवर्ष	राशि प्रतिवर्ष	राशि प्रतिवर्ष
आन्ध्र प्रदेश	28226	34562	40635	50338	61574	74355
असम	4149	5326	7544	89389	9598	10110
बिहार	19376	24008	26375	29841	33660	36844
गुजरात	35385	46241	50401	55487	62000	66235
हरियाणा	10600	13837	16048	16746	18770	22638
हिमाचल प्रदेश	1356	1745	1861	2225	2805	3172
जम्मू व कश्मीर	1788	2289	2367	2650	2915	3256
कर्नाटक	23736	31886	34478	39930	49200	55100
केरल	20394	24549	27520	30661	35000	38500
कोय प्रदेश	20000	26096	30765	35278	38778	42648
झारखण्ड	74959	92411	102694	119671	123457	133860
मणिपुर	135	192	167	169	140	170
मेघालय	231	271	352	489	413	442
महाराष्ट्र	187	295	337	527	527	530
मिजोरम	7663	9429	10205	11400	12702	15396
उड़ीसा	15593	19182	21993	25533	25000	32132
पंजाब	14731	18621	22223	24998	27800	32550
राजस्थान	50	71	84	92	100	107
सिक्किम	45963	54733	65549	70152	86060	96301
तमिलनाडु	196	305	347	410	461	485
त्रिपुरा	35085	45335	48698	35114	60537	62663
उत्तर प्रदेश	29995	37904	38963	45006	55000	61000
पश्चिम बंगाल	388758	489288	549606	626106	706465	788494
योग	100	100	100	100	100	100

स्रोत : रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया क्वैटिन 1957-58 से 1985-86

टिप्पणी: प्रतिवर्ष की जमा सम्बन्धित वर्ष में विहीन राज्य के योग में विभिन्न राज्यों की राशियों के आधार पर की गयी है।

ते कुल 55000 लाख रुपये की आय प्राप्त होने का अनुमान ^{की} जो देश में बिजलीकर आगम का 7.79 प्रतिशत थी। यह उल्लेखनीय है कि पश्चिमी बंगाल की तुलना में उत्तर प्रदेश में बिजलीकर आगम में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1957-58 में उत्तर प्रदेश में बिजलीकर से कुल आगम 1046 लाख रुपये 18.93 प्रतिशत था जो वर्ष 1984-1985 में 60537 लाख रुपये 18.57 प्रतिशत हो गया।

महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश के पश्चात् वर्ष 1957-58 में बिजलीकर आगम में पाँचवाँ स्थान आन्ध्र प्रदेश का था जिसकी आगम 962 लाख रुपये 18.21 प्रतिशत थी। इस राज्य के तुलनात्मक भाग में बीच में कुछ कमी हुई लेकिन वर्ष 1984-85 में देश में बिजलीकर आगम में आन्ध्र प्रदेश का भाग 8.72 प्रतिशत 133वाँ स्थान था। तन् 1984-85 में पाँचवाँ स्थान गुजरात राज्य का था जिसकी आगम 62000 लाख रुपये 18.78 प्रतिशत थी।

बिजलीकर आगम में राज्यों की स्थिति

देश के विभिन्न राज्यों के अर्द्धे वर्ष 1974-75 से उपलब्ध हो सके हैं और इस सन्दर्भ में देश में बिजलीकर के कुल आगम में विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक स्थिति को तालिका नं० 7.11 में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 7.11

बिजलीकर आगम : विविध राज्यों की तुलनात्मक स्थिति

राज्य	देश के बिजलीकर आगम में राज्य का प्रतिशत	
	1974-75	1984-85
1	2	3
1. महाराष्ट्र	19.04	17.47
2. तमिलनाडु	10.87	12.18
3. उत्तर प्रदेश	10.71	8.57
4. पश्चिम बंगाल	8.19	7.79
5. गुजरात	8.02	8.78

1	2	3
6. आन्ध्र प्रदेश	7.26	8.72
7. कर्नाटक	6.06	6.96
8. मध्य प्रदेश	6.04	5.49
9. केरल	5.04	4.95
10. बिहार	4.88	4.76
11. पंजाब	3.76	3.54
12. राजस्थान	3.48	3.94
13. हरियाणा	2.55	2.66
14. उड़ीसा	1.96	1.80
15. असम	1.40	1.36
16. जम्मू व कश्मीर	0.34	0.41
17. हिमाचल प्रदेश	0.24	0.40
18. मेघालय	0.06	0.06
19. मणिपुर	0.05	0.02
20. नागालैण्ड	0.04	0.07
21. त्रिपुरा	0.00	0.06
22. तिलिक्म	0.01	0.01
योग	100.00	100.00

स्रोत : प्रामाणिक।

तालिका नं० 7.11 के अन्वयेन से स्पष्ट है कि देश के विद्युत् आगम में पहले दोनों स्थानों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन गुजरात, वर्ष 1974-75 में पाँचवें स्थान पर था वह वर्ष 1984-85 में तीसरे स्थान पर आ गया

और आन्ध्र प्रदेश छठवें स्थान से उठकर चौथे स्थान पर आ गया। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल जिनका वर्ष 1974-75 में तीसरा और चौथा स्थान था, वर्ष 1984-85 में पाँचवाँ और छठा स्थान हो गया। कुल विक्रीकर आगम में राज्यों के क्रम में 7 से लेकर 10 तक और 13 से लेकर 17 स्थान तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन वर्ष 1974-75 में पंजाब में विक्रीकर आगम राजस्थान से अधिक था जबकि 1984-85 में राजस्थान की कर आगम पंजाब से अधिक थी। इसका मुख्य कारण पंजाब में अशान्ति की स्थिति से वहाँ के उद्योगों और व्यापारों पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव था। 18 से 22 तक क्रम स्थिति में भी परिवर्तन हुआ लेकिन उन राज्यों में विक्रीकर आगम इतना कम है कि वह परिवर्तन विशेष महत्वपूर्ण नहीं है।

राज्यों की आगम में विक्रीकर की स्थिति

वर्ष 1948-49 से लेकर वर्ष 1985-86 तक विभिन्न वर्षों में विक्रीकर की राशि और आगम के विभिन्न पक्षों की दृष्टि से उनमें विक्रीकर के भाग को तालिका नं० 7.12 में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 7.12 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभिन्न वर्षों में विक्रीकर आगम की निरपेक्ष राशि में ही वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं रही है बल्कि उनकी तुलनात्मक स्थिति भी सुदृढ़ होती गयी है। वर्ष 1951-52 में राज्य सरकारों द्वारा स्वयं लगाये जाने वाले करों में विक्रीकर का भाग 25.88 प्रतिशत था जो अल्पकालीन उच्चावचनों के साथ निरन्तर बढ़ता हुआ वर्ष 1981-82 में अपने सर्वोच्च स्तर 59.42 प्रतिशत पर पहुँच गया। इसके परवाह इस स्थिति में मामूली निरावट हुई। वर्ष 1984-85 में संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्यों के कर आगम में विक्रीकर का भाग 57.72 प्रतिशत था और तन् 1985-86 में जितना 54.74 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। कुल मिलाकर प्रवृत्ति को निष्कर्ष रूप में इस प्रकार रखा जा सकता है कि नियोजन काल के प्रारम्भ में राज्यों के करों में विक्रीकर का भाग लगभग 25 प्रतिशत था जो पिछले 10 वर्षों में 54 से 60 प्रतिशत के मध्य उच्चावचित होता रहा है। इस प्रकार वह कर-आगम में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है।

तालिका नं० 7.12

राज्य की कर आय, कुल कर आय, कुल आय एवं कुल प्राप्ति में विभाजन का भाग

राशि लाख में

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		राज्य की कर आय	कुल कर आय	कुल आय	कुल प्राप्ति	राज्य की कर आय	कुल कर आय	कुल आय	कुल प्राप्ति	राज्य की कर आय	कुल कर आय	कुल आय	कुल प्राप्ति
1948-49	3845	370	370	370	25520	9639	35159	370	370	-	15.07	10.94	-
1949-50	5139	370	370	370	27998	10799	38797	370	370	-	18.35	13.25	-
1950-51	5685	370	370	370	29211	10853	40064	370	370	-	19.46	14.19	-
1951-52	5893	22770	22770	5335	28105	12435	40540	16360	56900	25.88	20.97	14.54	10.36
1952-53	5720	23169	23169	7323	30492	12757	43249	16630	59879	24.69	18.76	13.23	9.55
1953-54	6568	25736	25736	7294	33030	13864	46894	17370	64264	25.52	19.89	14.01	10.22
1954-55	7568	26561	26561	7161	33722	13804	47526	23490	71016	27.73	21.84	15.50	10.37
1955-56	7568	26561	26561	7161	33722	13804	47526	23490	71016	27.73	21.84	15.50	10.37
1956-57	7939	29380	29380	7293	36673	21025	57698	46970	104668	27.02	21.64	13.76	7.58
1957-58	11712	35601	35601	11597	47198	23973	71171	40000	111171	32.90	24.81	16.46	10.54
1958-59	12389	38584	38584	15120	53706	27553	81259	44150	125409	32.11	23.07	15.25	9.87
1959-60	13683	43093	43093	18237	57742	32957	90699	48200	138899	-	23.70	15.09	9.85
1960-61	16388	48400	48400	17900	66300	41100	107400	70000	177400	38.03	26.72	16.16	10.34
1961-62	18144	57000	57000	22400	79400	49000	128400	77800	206200	37.49	27.37	16.89	10.23
1962-63	20887	68100	68100	25800	93900	55100	149000	86500	235500	36.64	26.31	16.27	10.13
1963-64	26831	72200	72200	26200	98400	63100	161500	108700	270200	29.40	28.58	18.01	11.39
1964-65	29753	84200	84200	36800	111800	73200	185000	130900	315900	41.21	30.24	18.42	11.01
1965-66	36779	93800	93800	36800	130600	82900	213500	122400	335900	43.68	32.90	19.88	11.64
1966-67	44269	106552	106552	40724	147276	85192	232468	134800	367268	47.20	33.90	20.73	13.18
1967-68	51819									48.63	35.18	22.29	14.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1969-70	58076	120500	48720	169220	97780	267000	159300	426300	48.20	34.32	21.75	13.62
1970-71	66796	135600	62500	198100	107200	305300	183600	488900	49.26	33.72	21.88	13.66
1970-71	76685	152785	75565	228350	108699	337049	170000	507049	50.19	33.58	22.75	15.12
1971-72	83938	169528	94222	263750	140722	404472	182800	587272	49.51	31.82	20.75	14.29
1972-73	97649	192800	106100	298900	192300	491200	287500	787700	50.65	32.67	19.88	12.54
1974-75	114282	230500	116300	346800	208400	555200	248300	803500	49.58	32.95	20.58	14.22
1974-75	155038	288100	122800	410900	232300	643200	217100	860300	53.81	37.73	24.10	18.02
1975-76	194370	354600	159900	514500	279300	793800	259400	1053200	54.81	37.78	24.49	18.46
1976-77	227039	403300	168000	571300	332400	903700	288300	1192000	56.29	39.74	25.12	19.05
1977-78	241429	434900	180600	615500	377600	993100	319800	1312900	55.51	39.22	24.31	18.39
1978-79	277331	497000	195300	692300	472400	1164700	514100	1678800	55.80	40.06	23.81	16.52
1979-80	321109	566900	340800	907700	455200	1362900	427300	1790200	56.64	35.38	23.56	17.94
1980-81	388788	661600	378900	1040500	588800	1629300	558000	2187300	58.76	37.36	23.86	17.77
1982-83	489288	823400	426000	1249400	596100	1845500	609600	2455100	59.42	39.16	26.51	19.93
1982-83	549606	948600	463200	1411800	700700	2112500	715100	2827600	57.94	38.93	26.02	19.44
1983-84	626106	1075300	500800	1576100	825300	2401400	909300	3310700	58.23	39.73	26.07	18.91
1984-85	706465	1223900	573800	1797700	969700	1104600	3872000	3872000	57.72	39.30	25.53	18.25
संग्रहीत												
1985-86	788494	1440500	668600	2109100	1110800	3219900	1026400	4246300	54.74	37.39	24.49	18.57
कुल												

संग्रहीत : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, क्लेदिन, 1948-49 से 1985-86.

टिप्पणी : केन्द्रीय कर आगम में भाग का अर्थ है आयकर, सम्पत्तिकर और संघीय उत्पादन शुल्क में भाग ।

यदि राज्यों के कर आगम में केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये करों में राज्यों को मिलने वाले हिस्सों को भी शामिल कर लिया जाए तो स्पष्ट है कि राज्य सरकारों के कुल कर आगम में बिजलीकर का भाग 20.97 प्रतिशत था। मामूली उच्चावचनों के साथ क्रमशः बढ़ता हुआ वर्ष 1978-79 में अपने सर्वोच्च स्तर पर 40.06 प्रतिशत हो गया और उसके बाद विभिन्न वर्षों में 35 से 40 प्रतिशत के मध्य उच्चावचित होता रहा है।

यदि राज्यों के कर आगम में गैर कर आगम को जोड़कर बिजलीकर की स्थिति का अंशोक्तन किया जाए तो स्पष्ट होगा कि वर्ष 1951-52 में राज्यों के कुल आगम में बिजलीकर का भाग 14.54 प्रतिशत था जो क्रमशः बढ़ता हुआ वर्ष 1981-82 में 26.51 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1984-85 में यह भाग 25.53 प्रतिशत था। स्पष्ट है कि राज्य सरकारों के कुल आगम का 1/4 भाग बिजलीकर से ही प्राप्त होता है।

यदि राज्य सरकारों की आगम में पूँजीगत प्राप्तियों को भी जोड़ दिया जाए तो उस दृष्टि से भी बिजलीकर के भाग में पर्याप्त प्रगति हुई है। वर्ष 1951-52 में राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियों में बिजलीकर का भाग 10.36 प्रतिशत था जो वर्ष 1981-82 में 19.93 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1984-85 में यह 18.25 प्रतिशत था।

कुल मिलाकर स्पष्ट है कि राज्य सरकार के सभी पहलुओं की दृष्टि से बिजलीकर के प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बिजलीकर हटाने को माँग और राजनीतिक घायलों के कारण बिजलीकर के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति में स्थिरता आयी है, जो राज्य सरकारों के कर संरचना एवं आगम के विभिन्न स्रोतों के तन्मूलन की दृष्टि से एक अच्छा संकेत है।

राज्य सरकारों की कर आगम में बिजलीकर का भाग

वर्ष 1973-74 से लेकर वर्ष 1985-86 के खबट अनुमानों सहित विभिन्न राज्य सरकारों की निजी कर आगम में बिजलीकर के भाग को तालिका नं० 7.13 में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 7.13

राज्य सरकारों की कर आगम में विद्योकर का भाग

राशि लाख रुपये में।

राज्य का नाम	कर आगम	1973-74			1974-75			1975-76			1976-77			1977-78		
		कर आगम	विद्योकर	प्रतिशत	कर आगम	विद्योकर	प्रतिशत	कर आगम	विद्योकर	प्रतिशत	कर आगम	विद्योकर	प्रतिशत	कर आगम	विद्योकर	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1. अन्य प्रदेश	2013	7386	36.69	2518	11399	45.27	3255	14108	43.34	3428	15264	44.53	3682	16271	44.19	
2. असम	335	1618	48.30	444	2076	46.76	593	2718	45.84	632	2854	45.16	786	2844	36.18	
3. बिहार	1152	5240	45.49	1442	7119	49.37	1864	9491	50.92	2085	11649	55.87	2140	12165	56.85	
4. गुजरात	1512	9397	62.15	2012	13452	66.86	2360	15585	60.04	2982	19835	66.52	3293	21193	64.36	
5. हरियाणा	761	3105	40.80	991	3899	39.34	1170	4950	42.31	1381	6395	46.30	1477	6902	47.14	
6. हिमाचल प्रदेश	110	290	26.36	138	368	26.67	157	472	30.06	190	571	30.05	208	667	32.07	
7. कश्मीर व जम्मू	118	349	29.58	134	422	31.49	177	657	37.12	187	650	34.76	306	886	28.95	
8. कर्नाटक	1504	6822	45.36	1986	9364	47.15	2367	11787	49.80	2692	13730	51.00	2973	15109	50.82	
9. केरल	955	5380	56.34	1236	7532	60.94	1597	9792	61.32	1865	10760	57.69	2134	11874	55.64	
10. मध्य प्रदेश	1284	5903	45.97	1728	8374	48.46	2315	11738	50.70	2496	12658	50.71	2603	12674	48.69	
11. महाराष्ट्र	3823	23115	60.46	4979	30872	62.00	5860	37004	63.15	6800	43910	64.57	7128	46085	64.65	
12. मणिपुर	10	50	50.00	12	51	42.50	19	96	50.53	20	104	52.00	22	105	47.72	
13. मेघालय	15	78	52.00	19	104	54.74	22	121	55.00	25	130	52.00	28	144	51.43	
14. नागालैण्ड	16	51	31.88	15	62	41.83	22	83	37.73	20	83	41.50	23	106	46.08	
15. उड़ीसा	422	2664	63.13	504	2731	54.19	684	3804	55.45	808	4707	58.25	838	4713	56.25	
16. पंजाब	1231	5251	42.66	1516	6335	41.79	1728	7316	42.34	2020	9612	47.58	2351	10751	45.73	
17. राजस्थान	907	4488	49.48	1061	5754	54.23	1308	6760	51.68	1517	8429	55.56	1727	10025	58.05	
18. तमिलनाडु	330	330	-	330	113	-	11	23	20.91	14	37	26.43	19	47	24.74	
19. तमिळनाडु	2731	13225	48.43	3057	19075	62.40	3191	21127	66.21	3463	23055	66.57	3614	24304	67.25	
20. त्रिपुरा	8	4848	44.85	11	47	43.73	18	-	-	20	42	21.00	22	99	45.00	
21. उत्तर प्रदेश	2256	10118	44.85	2760	13542	49.07	3934	20826	52.94	4547	24317	53.48	4673	24603	52.65	
22. पश्चिमी बंगाल	1892	10169	53.75	2243	12507	55.76	2810	15912	56.63	3142	18297	58.23	3446	19802	57.46	
योग	23055	114282	49.57	28806	155038	53.82	35462	194370	54.81	40334	222039	56.29	43493	241429	55.50	

राज्य का नाम	1978-79		1979-80		1980-81		1981-82					
	कर आयम	विद्युत्तर प्रतिमाल	कर आयम	विद्युत्तर प्रतिमाल	कर आयम	विद्युत्तर प्रतिमाल	कर आयम	विद्युत्तर प्रतिमाल				
1. आन्ध्र प्रदेश	4209	18493	43.94	4927	22022	44.70	5821	28226	48.49	7029	34562	49.17
2. आन्ध्र	886	3432	38.73	720	3508	48.72	658	3149	47.86	903	5326	58.98
3. बिहार	2039	13063	64.06	2336	15546	66.55	2765	19376	70.08	3381	24008	71.01
4. गुजरात	3726	23526	63.14	4480	28937	64.59	5310	35385	66.64	6606	46241	70.00
5. हरियाणा	1706	7968	46.70	1973	9005	45.64	2339	10600	45.32	2906	13837	46.62
6. हिमाचल प्रदेश	240	801	33.37	287	1113	38.78	339	1356	40.00	415	1745	42.05
7. जम्मू व कश्मीर	346	1049	30.32	290	1280	44.14	378	1788	47.30	603	2289	37.96
8. कर्नाटक	3340	16449	49.25	4049	19978	49.34	4747	23736	50.00	6070	31886	52.53
9. केरल	2542	14689	57.78	2908	16264	55.93	3365	20394	60.61	3742	24549	65.60
10. कर्ग प्रदेश	2876	14407	50.09	3203	16104	50.28	3859	20000	51.83	4759	26096	54.84
11. झारखण्ड	8508	53727	63.15	9808	62643	63.87	11303	74959	66.32	13837	92411	66.78
12. गुजरात	105	4772	46.52	26	128	49.23	26	135	51.92	39	192	49.23
13. झारखण्ड	34	159	46.76	40	197	49.25	49	231	47.14	62	271	43.71
14. नागालैण्ड	27	120	44.40	34	150	44.12	43	187	43.49	55	295	53.64
15. उत्तराखण्ड	984	5518	56.07	1121	6595	58.83	1321	7663	58.01	1597	9429	59.04
16. पंजाब	2671	11931	44.67	3090	12979	42.00	3489	15593	44.69	4322	19182	44.38
17. राजस्थान	1975	11368	57.56	2168	13586	62.67	2302	14731	63.99	3120	18621	59.68
18. सिक्किम	21	44	20.95	25	54	21.60	26	50	19.23	31	71	22.90
19. तमिलनाडु	4474	29418	65.75	4864	32506	66.83	6391	45963	71.92	8424	54733	64.97
20. त्रिपुरा	26	117	45.00	32	155	48.44	38	196	51.58	53	305	57.55
21. उत्तर प्रदेश	5082	23720	59.79	5623	30252	53.80	6452	35085	54.38	8228	45335	55.10
22. वरिष्म बंगाल	8968	23720	59.79	4678	28107	60.08	5141	29955	58.27	6161	37904	61.52
योग	49703	277331	55.80	56691	321109	56.64	66162	388758	58.76	82343	489288	59.42

राज्य का नाम	1982-83		1983-84		1984-85 संशोधित		1985-86 संशोधित					
	कर आय	विद्युत् प्रसारित	कर आय	विद्युत् प्रसारित	कर आय	विद्युत् प्रसारित	कर आय	विद्युत् प्रसारित				
1. राज्य प्रदेश	8084	40635	50.27	9654	50338	52.14	11729	61574	52.50	15376	74355	48.36
2. अरुण प्रदेश	1083	7544	69.66	1357	9389	69.19	1425	9598	67.35	1505	10110	67.18
3. बिहार	3815	26375	69.13	4415	29841	67.59	4879	33660	68.99	5397	36844	68.27
4. गुजरात	7630	50401	46.06	8790	53487	63.13	9906	62000	62.59	11056	66235	59.91
5. हरियाणा	3367	16048	47.66	3659	16746	45.77	4119	18770	45.57	5666	22638	39.95
6. हिमाचल प्रदेश	479	1861	38.85	542	2225	41.05	641	2805	43.76	740	3172	42.86
7. जम्मू व कश्मीर	619	2367	38.24	714	2650	37.11	789	2915	36.95	901	3256	36.14
8. कर्नाटक	6741	34478	51.15	7595	39930	52.57	9414	49200	52.26	11214	55100	49.14
9. केरल	4383	27520	62.79	4868	30661	62.98	5732	35000	61.06	6608	38500	58.26
10. मध्य प्रदेश	5583	30765	55.10	6430	35278	54.86	7309	38778	53.06	8561	42648	49.82
11. महाराष्ट्र	16480	102694	62.31	18225	119671	65.66	19453	123457	63.46	22069	133860	60.66
12. गुजरात	41	167	40.76	49	169	34.49	49	140	28.57	55	170	30.91
13. झारखण्ड	74	352	47.57	95	489	51.47	85	413	48.59	222	442	19.91
14. नागालैण्ड	65	337	51.85	95	527	55.47	87	495	58.24	94	530	56.38
15. उत्तरांचल	1736	10205	58.78	2009	11400	56.74	2256	12702	56.30	3423	15396	44.98
16. पंजाब	4905	21993	44.84	5441	25533	46.93	5285	25000	47.30	6936	32132	46.33
17. राजस्थान	3895	22223	57.06	4412	24998	56.66	4902	27800	56.71	5878	32550	55.38
18. तमिलनाडु	33	84	25.45	38	92	24.21	41	100	24.39	43	107	24.88
19. त्रिपुरा	10115	65549	64.80	11452	70152	61.26	13506	86060	63.72	15175	96301	63.54
20. उत्तर प्रदेश	61	347	56.89	84	410	48.81	73	461	63.15	78	485	62.18
21. वाराणसी	9293	48698	52.40	9921	55114	55.55	11074	60537	54.67	12092	62663	51.82
22. पश्चिम बंगाल	6379	38963	61.08	7686	45006	58.56	9637	55000	57.07	10981	61008	55.55
योग	94861	549606	57.94	107531	626106	58.23	122391	706465	57.72	144052	788494	54.74

स्रोत : रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया क्रेडिट, नवम्बर 1985.

टिप्पणी : प्रसारित की गयी सम्बन्धित वर्ष में राज्य सरकारों की निजी कर आय में विद्युत् की राशियों के आधार पर की गयी है।

तालिका नं० 7.13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यद्यपि विभिन्न राज्यों की कर आगम में बिजुलीकर के भाग में व्यापक भिन्नताएँ हैं। सामान्यतया इसकी प्रवृत्ति यह रही है कि लगभग सभी राज्यों के बिजुलीकर के भाग में वृद्धि हुई है। यद्यपि इस वृद्धि की दर में भी व्यापक भिन्नता है। वर्ष 1973-74 में बिन राज्यों के कर आगम में बिजुलीकर का भाग 60 प्रतिशत से अधिक था उनमें गुजरात 162.15 प्रतिशत, महाराष्ट्र 160.46 प्रतिशत, और उड़ीसा 163.13 प्रतिशत राज्य शामिल थे। वर्ष 1984-85 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 7 राज्य ऐसे हैं जिनके निजी कर आगम में बिजुलीकर का भाग 60 प्रतिशत से अधिक है, इनमें असम, बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और त्रिपुरा शामिल है। बिहार में राज्य के कर आगम का लगभग 69 प्रतिशत बिजुलीकर से ही प्राप्त होता है। जबकि असम में यह प्रतिशत 67.35 था, शेष चार राज्यों में राज्य सरकारों के कर आगम में बिजुलीकर का भाग लगभग 63 प्रतिशत था।

वर्ष 1973-74 में राज्यों के कर आगम में बिजुलीकर का भाग 50 से 60 प्रतिशत के बीच के राज्यों में चार राज्य केरल, पश्चिमी बंगाल, मेघालय और मणिपुर राज्य थे। वर्ष 1984-85 में इस वर्ग के राज्यों की संख्या बढ़कर 8 हो गई जिनमें आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल शामिल थे। वर्ष 1973-74 में बिजुलीकर के न्यूनतम भाग की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश था जिसका अपने करों में बिजुलीकर भाग 26.36 प्रतिशत था।

अध्याय अष्टम

विभिन्न राज्यों में विहीन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन एवं उनकी समीक्षाएँ

अध्याय-8

विभिन्न राज्यों में बिजली-कर व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन स्वयं उनकी समस्यायें

भारत में बिजली कर से आगम स्वयं उनके तुलनात्मक विश्लेषणों से अब स्पष्ट हो चुका है कि राज्य सरकारों के कर आगमों में बिजलीकर का महत्वपूर्ण स्थान है। कर व्यवस्था के विविध पहलुओं की विवेचना के तन्द्भ में यह उपयुक्त होगा कि विभिन्न राज्यों में बिजलीकर व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय। अतः इस आशय से कुछ राज्यों का ज्यन करके उनकी स्थिति को स्पष्ट किया गया है।

1. कर योग्य विक्रय-अवधारणा

कर योग्य बिजली की राशि की गणना करने के लिये प्रायः सभी राज्यों में विक्रय की कुल राशि में निम्न ढटों को घटा दिया जाता है - सम्बन्धित राज्य के बिजली कर अधिनियम के अनुसार कर मुक्त वस्तुओं की बिजली, जिन वस्तुओं पर विक्रय के किसी पूर्व स्तर पर विक्रय कर दिया जा चुका है तथा अन्तराज्यीय अध्या नियमित बिजली। इनके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में कुछ विशिष्ट प्रावधान भी किये गये हैं। उदाहरणार्थ, राजस्थान में सेती बिजली की राशि को भी घटा दिया जाता है, जित पर अन्तिम बिन्दु पर कर देय हो माल को केता से निर्धारित छोछा-यन लेकर बेचा गया हो। हरियाणा में जनता को विद्युत शक्ति वितरित करने वाले तथा भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के अधीन लाइसेन्स प्राप्त अध्या स्वीकृति प्राप्त प्रतिष्ठानों को सेते माल की विक्रय राशि को बिजली के निमाणि अध्या प्रेक्षा अध्या वितरण में काम आता है तथा कर मुक्त घोषित सहकारी समितियों अध्या अन्य संस्थानों को किये गये विक्रय को भी घटा दिया जाता है।

केन्द्रीकृत प्रदेश दिल्ली में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल तथा दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय को वैज्ञानिक उपकरणों की बिजली एवं भारतीय पर्यटन विकास निगम को पालम हवाई अड्डे पर तीमा शुल्क फ्री दुकान से की गयी बिजली को भी घटा दिया जाता है। पंजाब में एक बिजली कम्पनी द्वारा भेजी गयी बिजली शक्ति की लागत या इसी प्रकार की कम्पनी द्वारा बेचे गये अन्य माल की बिजली भी घटा दी जाती है।

उत्तर प्रदेश में किसी ग्राहक की सुविधा के लिए यदि कोई व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से माल मंगाकर उसे उसके स्वयं के स्टॉक में नहीं है। बिना लाभ लिये तुरन्त उसे बेच देता है और अपने खातों में इस बिछी को उस समय ही लिख देता है और उस व्यापारी का नाम भी लिख लेता है जिसने माल खरीदा है तो यह विक्रय राशि घटा दी जाती है।

इसके अतिरिक्त प्रायः सभी अधिनियमों में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी अन्य बिछी को भी इस प्रकार की कटौती के लिये अधिसूचित कर सकती है।

2. बिछी कर पदाधिकारी

बिछीकर व्यवस्था को क्रियान्वित रख देने के लिये सभी राज्यों में बिछी कर पदाधिकारियों की विस्तृत शृंखला बनायी गयी है। राजस्थान राज्य में बिछी कर संग्रहण को दो भागों में विभक्त किया गया है - प्रशासनिक पदाधिकारी एवं न्यायिक पदाधिकारी। प्रशासनिक पदाधिकारियों में आयुक्त, उप-आयुक्त, प्रशासनिक, वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी और निरीक्षक प्रमुख पदाधिकारी है। न्यायिक पदाधिकारियों में उच्च-न्यायालय, राजस्व मंडल, आयुक्त, उप-आयुक्त (अपील), वाणिज्य कर अधिकारी और सहायक वाणिज्य कर अधिकारी और मुख्य पदाधिकारी है।¹

हरियाणा में बिछी कर प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी के रूप में आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसकी सहायता के लिए "सहायक" अथवा "संग्रहण आबकारी एवं करारोपण कमिशनर" कार्य करते हैं। निम्न स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी के रूप में आबकारी एवं करारोपण अधिकारी कार्य करता है। यह बिछी कर की दृष्टि से जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है और अपने जिले में कर निर्धारण करता है। इनमें "अतिरिक्त आबकारी एवं करारोपण अधिकारी" भी शामिल होते हैं। आबकारी

1. शाकता, मुक्त एवं नाहर : राजस्थान बिछी कर परिषद, पृष्ठ 183-186.

एवं करारोपण अधिकारी की सहायता के लिए सहायक आबकारी एवं करारोपण अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। बाजार का सर्वेक्षण करके नये करदाताओं का पता लगाने की दृष्टि से करारोपण निरीक्षक और उप-निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। बीत हजार रुपये तक बिजुी होने पर करारोपण निरीक्षक और पाँच लाख रुपये तक बिजुी होने पर सहायक आबकारी एवं करारोपण अधिकारी को कर निर्धारण का अधिकार होता है। बिजुी कर अधिनियम को न्यायपूर्ण ढंग से लागू करने के लिये न्याय सम्बन्धी उच्च तत्ता के रूप में "न्यायाधिकरण" का प्रावधान है। न्यायाधिकरण में एक सदस्य होता है। न्यायाधिकरण काज्य सरकार द्वारा एवं अधिनियम द्वारा पदतल अधिकारों का प्रयोग करके निर्दिष्ट कार्य करता है।² पंजाब में बिजुी कर संगठन एवं पदाधिकारियों की व्यवस्था हरियाणा की तरह है।³

तमिनाडु में बिजुीकर के प्रशासनिक ढाँचे में उपायुक्त वाणिज्यिक कर, सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। न्यायिक दृष्टि से अपील द्विकूल का गठन किया जाता है और उसके नीचे विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।⁴

मध्य प्रदेश में भी बिजुी कर संगठन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है- प्रशासनिक और न्यायिक। प्रशासनिक व्यवस्था में आयुक्त, अपर विजुय कर आयुक्त उपायुक्त या अपर आयुक्त, अपीलीय सहायक आयुक्त या अपर अपीलीय सहायक आयुक्त, सहायक आयुक्त या अपर सहायक आयुक्त, विजुय कर अधिकारी अथवा अपर विजुय कर अधिकारी, सहायक विजुय कर अधिकारी और विजुय कर निरीक्षक होते

2. गोकुल, वेपी० : हरियाणा बिजुीकर, पृ० 13-14.

3. गौड़, बीपी० एवं नारंग, डीपी० : पंजाब सामान्य बिजुीकर अधिनियम-1948, पृ० 16.

4. श्रीनिवासवारी, एम० : तमिनाडु जनरल टैक्स ऐक्ट 1948 अधिनियम। पृ० 3-4.

हैं। विक्रय कर आयुक्त तथा अपर विक्रय कर आयुक्त राज्य शासन द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और अन्य अधिकारी राज्य शासन या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, जितने वह निर्देश दें। न्यायिक व्यवस्था में न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। यह सर्वोच्च तत्ता मानी जाती है। इसके अतिरिक्त न्यायिक व्यवस्था में अन्य अधिकारी भी होते हैं।⁵

उत्तर-प्रदेश में बिज्जीकर संगठन की दृष्टि से बिज्जी कर आयुक्त सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसके अधीनस्थ अतिरिक्त अध्या संपुक्त आयुक्त, उप-आयुक्त एवं सहायक आयुक्त होते हैं। जिसे स्तर पर बिज्जी-कर अधिकारी, सहायक बिज्जी-कर अधिकारी एवं बिज्जी कर निरीक्षक भी होते हैं।⁵

कुल मिलाकर स्थिति यह है कि यद्यपि विभिन्न राज्यों में बिज्जीकर पदाधिकारियों के नाम में अन्तर अवश्य है लेकिन प्रायः अधिकांश राज्यों में बिज्जीकर पदाधिकारियों की व्यवस्था को प्रशासनिक एवं न्यायिक दो मुख्य भागों में विभक्त किया गया है।

2. बिज्जीकर का बिन्दु

बिज्जी कर आरोपण की दृष्टि से बिज्जीकर प्रावधानों में उल्लेखनीय विशेषता यह होती है कि बिज्जीकर जितने और किस बिन्दु पर लगाया जायेगा। इस तदर्थ में बिज्जी कर एक बिन्दु के आधार पर, दो बिन्दु के आधार पर तथा बहु बिन्दु के आधार पर लगाया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि एक बिन्दु कर में भी यह निर्दिष्ट करना होता है कि विक्रय व्यवहार के किस बिन्दु पर बिज्जी कर आरोपित किया जायेगा अर्थात् इसे विक्रय व्यवहार के प्रथम बिन्दु पर लगाया जायेगा या अन्तिम बिन्दु पर।

भारत में विभिन्न राज्यों में बिज्जीकर के बिन्दुओं में केवल विविधता ही नहीं है वरन् एक ही राज्य में विभिन्न बिन्दुओं पर कर आरोपण का प्रयोग पाया जाता

5. हींगरा, इकम्प्यूटरी: मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय-कर अधिनियम, 1958, पृष्ठ 23.

है अर्थात् ऐसे अनेक राज्य हैं जिनमें कुछ वस्तुओं पर एक बिन्दु कर और कुछ वस्तुओं पर बहुत बिन्दु कर लगाया जाता है जिन वस्तुओं पर एक बिन्दु कर लगाया जाता है उनमें से कुछ पर प्रथम बिन्दु पर और कुछ पर अन्तिम बिन्दु पर लगाया जाता है। विभिन्न प्रकार के बिन्दुओं पर करारोपण के तन्द्भ में सामान्य प्रवृत्ति यह है कि देश के अधिकांश राज्यों में अधिकांश वस्तुओं पर एक बिन्दु बिज्जीकर को अपनाया गया है। इन राज्यों में असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और दिल्ली प्रमुख हैं। यह उल्लेखनीय है कि इनमें से कुछ राज्यों में कुछ वस्तुओं पर एक से अधिक बिन्दुओं पर भी बिज्जी कर लगाया जाता है।⁶

वित्तुत विवेका की दृष्टि से राजस्थान बिज्जी कर अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य-तया मात के क्रय-विक्रय पर एक बिन्दु कर लगाने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत अधिकांश मातों पर प्रथम बिन्दु पर तथा कुछ मातों पर अन्तिम बिन्दु पर बिज्जी कर लगाया गया है। अपवाद-स्वरूप कुछ मातों पर बहुत-बिन्दु कर लगाने की भी व्यवस्था है। यद्यपि राजस्थान बिज्जी कर अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी मात पर बहुत बिन्दु बिज्जी कर लगा सकती है। लेकिन केन्द्रीय बिज्जी कर अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जोखित मातों पर राज्य सरकारों को बहुत बिन्दु कर लगाने का अधिकार नहीं है।⁷

उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ में बहुत बिन्दु बिज्जी-कर लगाया गया था लेकिन। दिसम्बर 1973 से इसे मुख्य रूप से एक बिन्दु बिज्जीकर में परिवर्तित कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत या तो राज्य के उत्पादक को या राज्य के बाहर से आये गये सामान पर

6. Ministry of Finance (Government of India) : Report on Indirect Taxation Enquiry Committee, 1978 (Vol. II) Page 61.

7. वाकना, मुष्ता रस नाहर : राजस्थान बिज्जी कर परिषद, पृष्ठ 241-244.

बिक्री कर देना होता है। राज्य में अधिकांश वस्तुओं पर बिक्री के प्रथम स्तर पर ही कर लगाने का प्रावधान है लेकिन कुछ वस्तुओं पर बिक्री के प्रथम स्तर पर ही कर लगाने का प्रावधान है लेकिन कुछ वस्तुओं पर जैसे पत्थर के सामान, बत्ताश, भांग, गाँजा, चरत, पके हुए भोज्य पदार्थ, जूते इत्यादि पर बिक्री के अन्तिम बिन्दु पर कर लगाया जाता है।⁸ मध्यप्रदेश में भी एक बिन्दु कर में अधिकांश वस्तुओं पर प्रथम बिन्दु पर बिक्री कर लगाया जाता है।

हरियाणा में राज्य सरकार बिक्रीकर अधिनियम की अनुसूची ती तथा डी में वर्णित वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिभूजा जारी करके अधिभूजा में वर्णित वस्तुओं पर निर्दिष्ट तिथि से उनकी प्रथम बिक्री पर बिक्री कर लगाने का निर्देश दे सकती है। वर्तमान में अनेक वस्तुओं के ऊपर बिक्री के प्रथम स्तर पर कर लगाया जाता है जैसे तीखेन्ट, ताईबिल, माफिन आदि। विक्रय के प्रथम स्तर पर कर योग्य वस्तु की बाट की बिक्रीकर से मुक्त होती है किन्तु यह बिक्रीकर से मुक्त तभी होती है जबकि बाट की बिक्री करने वाले व्यापारी द्वारा नियत दंग से इस आगम का प्रमाण पत्र कर निर्धारण अधिकारी के यहाँ दाखिल कर दिया जाए कि ऐसी वस्तुओं के प्रथम विक्रय पर कर चुका दिया गया है।⁹ दिल्ली में वस्तुओं की प्रथम स्तर की बिक्री पर ही कर लगाने की व्यवस्था है।¹⁰

महाराष्ट्र और गुजरात ने द्विबिन्दु बिक्रीकर अपनाया है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में औपचारिक रूप से बहु बिन्दु बिक्री कर अपनाया है लेकिन इन राज्यों में भी बिक्री कर आगम का अधिकांश भाग ऐसी वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन पर एक बिन्दु बिक्रीकर का प्रावधान है। तमिलनाडु में

8. गोयल, राधेयामः उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अधीन करयोग्य वस्तुओं की दरें, पृष्ठ 1.

9. गोयल, वैष्णवी : हरियाणा बिक्रीकर, पृष्ठ 22.

10. गोयल, वैष्णवी : दिल्ली बिक्रीकर, पृष्ठ 14-15.

4 मार्च, 1974 से अधिकांश वस्तुओं को एक बिन्दु बिछी कर के अन्तर्गत लिया गया है। जम्मू और काश्मीर तथा राजस्थान को छोड़कर प्रारम्भ में एक बिन्दु बिछी-कर लगाने वाले अधिकांश राज्यों ने बिछी के अन्तिम बिन्दु पर कर लगाने की व्यवस्था की थी लेकिन करव्यय को रोकने की दृष्टि से यह परिवर्तन किया गया कि अधिकांश राज्यों में अधिकांश वस्तुओं पर बिछी के प्रथम स्तर पर ही कर लगाया जाता है।¹¹

3. बिछीकर की दरें

विभिन्न राज्यों में बिछीकर की दरों में व्यापक विभिन्नताएँ हैं। जिन राज्यों में बहु बिन्दु बिछीकर है उनमें आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिऴनाडू। कर की दरें 4 प्रतिशत रही है। बिहार में यह दर कुछ नीची रही है। यदि यह मान लिया जाए कि एक वस्तु विषय व्यवहार में सामान्यतः दो या तीन स्तरों से गुजरती है तो यह दर व्यावहारिक रूप से 8 से 12 प्रतिशत तक प्रभावित होती है। इन राज्यों में जिन वस्तुओं पर एक बिन्दु बिछीकर अपनाया गया है उनमें खातिता की वस्तुएँ मुख्य हैं जिनमें बिछी के प्रथम स्तर पर 12 से 15 प्रतिशत तक बिछीकर लगाया गया है। खातिता की इन वस्तुओं में मोटरगाड़ी, अस्त्र, रेफीयरैटर, वातानुकूलित तंत्र, रेडियो, ग्रामोफोन, कैमरा और फिल्म, चढ़िया, मोटे की तिमोरी इत्यादि उल्लेखनीय रहे हैं। एक बिन्दु बिछीकर की अन्य वस्तुओं में सामान्य प्रयोग की वस्तुओं को रखा जाता रहा है जिन पर सामान्यतः 1 से 10 प्रतिशत तक कर लगाया जाता रहा है इन वस्तुओं में ताइकि और ताईकि के घुने, काप लेन और मिट्टी का लेन, चाय, काथान्न, औषधियाँ इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। कुछ राज्यों में इस वर्ग में सीमेन्ट और उर्वरक को भी शामिल किया गया है। एक बिन्दु बिछी कर वाले राज्यों में बिछीकर की दरें 4 से 7 प्रतिशत थी, लेकिन वर्तमान में यह दरें अनेक वस्तुओं पर 20 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है।¹²

11. Ministry of Finance (Government of India) : Report on Indirect Taxation Enquiry Committee, 1978 (Vol. II) Page 61.

12. Ibid. Page 61-62.

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विभिन्न वस्तुओं पर बिजुीकर की दरें 2 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक है । तमिलनाडु में वर्तमान में बिजुीकर की सामान्य दरें 2 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक हैं । 2 प्रतिशत की दर गेहूँ के उत्पादकों जैसे आटा, सुबी, कच्ची अन् इत्यादि पर लागू होती है । अधिकांश वस्तुओं पर कर की दर 4 से 10 प्रतिशत तक है, लेकिन टाइपराइटर, टेलीप्रिन्टर, घड़ी, मोटर-कार, फ्रिज, फौटो सामान इत्यादि वस्तुओं पर कर की दरें 15 प्रतिशत है । शराब पदार्थों पर बिजुी कर की दरें 50 प्रतिशत है ।¹³

मध्य प्रदेश में शराब पर 20 प्रतिशत, कोयला पर 2 प्रतिशत, लिफ्टन पर 3 प्रतिशत, प्लास्टिक के सामान पर 7 प्रतिशत, ऊनी तथा रेशमी सामान पर 8 प्रतिशत, मोटर गाड़ियों पर 11 प्रतिशत, रेफ्रिजरेटर पर 15 प्रतिशत, धातु फर्नीचर, फोटोग्राफ के सामान, टेलीफोन, ताउड स्पीकर, काले, कालीन, हाथी दाँत के सामान, स्टील की वस्तुओं इत्यादि पर 12 प्रतिशत है ।¹⁴ राजस्थान में भी विभिन्न वस्तुओं पर कर की विभिन्न दरें हैं । अधिनियम में घोषित वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर कर लगाने की सीमा के तत्त्वन्ध में 60 प्रतिशत का उल्लेख है । यद्यपि व्यवहार में अन्य राज्यों की तरह मादक पदार्थों को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर कर की दरें 4 से 20 प्रतिशत है ।¹⁵

हरियाणा में करों की दर की दृष्टि से मान को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है । कर मुक्त मान, विभाजितापूर्ण मान और साधारण मान । प्रतिशत सामान्यतः साधारण मान पर कर की दर 7 प्रतिशत और विभाजितापूर्ण मान पर कर की दर 10 प्रतिशत रखी गयी है ।¹⁶ दिल्ली में बिजुीकर अधिनियम के अन्तर्गत

13. श्रीनिवासाचारी एम० : सुप्रीम, पृ० 45-68.

14. हरिारा, इकन्यूमी० : मध्य प्रदेश सामान्य बिजुीकर अधिनियम, 1958, पृ० 152.

15. वाक्ता, मुप्ता एवं नाहर : राजस्थान बिजुी कर परिषद, पृ० 241.

16. गोक, वे०पी० : हरियाणा बिजुी कर, पृ० 21.

कर की दरों की दृष्टि से वस्तुओं को तीन अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। पहली अनुसूची में धातु तथा की वस्तुओं को रखा गया है जिन पर कर की अधिकतम दर 12 प्रतिशत रखी गयी है किन्तु व्यवहार में इन वस्तुओं पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया है। दूसरी अनुसूची में जन साधारण द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं को रखा गया है जिन पर कर की अधिकतम दर 4 प्रतिशत है तीसरी अनुसूची में कर मुक्त वस्तुओं को रखा गया है। इसके अतिरिक्त सभी वस्तुओं पर की अधिकतम दर 5 प्रतिशत है लेकिन किसी होटल या जलपानगृह में कैबरे या अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों। जलपानगृह में कच्चाली प्रोग्राम को छोड़कर। के साथ परोते जाने वाले भोज्य तथा पेय पदार्थों पर कर की दर 40 प्रतिशत है। कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर कर की रियायती दरें भी घोषित की गयी है और उन पर कर की सामान्य 7 प्रतिशत की दर लागू नहीं होती है।¹⁷

कुछ राज्यों में एक निश्चित सीमा से अधिक बिजुली होने पर "अतिरिक्त बिजुली कर" और बिजुली कर पर तराज का प्रावधान भी है।

4. बिजुलीकर से मुक्त वस्तुएं

प्रायः सभी राज्यों में कुछ वस्तुएं बिजुलीकर से मुक्त रखी गई हैं लेकिन इनमें समानता नहीं है। बिजुलीकर से मुक्त वस्तुओं में सामान्यतः नमक, फल, तखियाएँ और दस्तकारी के सामान की शामिल किया गया है। कुछ राज्यों में जिन वस्तुओं को बिजुलीकर से मुक्त रखा गया है उन्हीं पर अन्य कुछ राज्यों में अत्यन्त रियायती दर से कर लगाया गया है।

हरियाणा बिजुलीकर अधिनियम में वस्तुओं के 16 वर्ग बिजुलीकर से मुक्त है। इनमें तखियाएँ, बिना पैकिंग के माँस, मछली, अण्डे, दूध, नमक, ताजा फल, फूल, पेन, पेंटिल, पुस्तकें, हाथकरघा या शक्ति करघा पर कने सामान, विद्युत शक्ति,

मोटर त्रिप्ट, कुधियन्त्र, परखा, आद, मिट्टी के बर्तन, देशी शराब, भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी को बेचा गया मात, अदालती एवं गैर अदालती स्टाम्प, रेबड़ी, बत्ताशा, मजक, मिर्ची, सब्जियों के बीज, मुर्गियों का दाना इत्यादि उल्लेखनीय है ।¹⁸

दिल्ली बिज्रीकर अधिनियम में 36 प्रकार के वस्तु तौलों को बिज्रीकर से मुक्त रखा गया है । जिसमें अन्य सामान्य कर मुक्त वस्तुओं के अतिरिक्त तभी अनाज, दालें, आटा, मैदा, केसन तथा तूबी, चीनी, उर्परक, तम्बाकू, विद्युत्ताक्ति, पान के पत्ते, अचार और मुरब्बा, पौधरक्षण के लिए कीटनाशक दवाएं, पौधरक्षण यन्त्र, तृती गद्दियाँ, माय, मैस, मेह, ककरा, ककरी, घोड़ा, कुक्कुट आदि उल्लेखनीय हैं ।¹⁹

पंजाब बिज्रीकर अधिनियम में ताजी सब्जी, फल, दूध, मांस, मछली, अण्डा, नमक, फूल, चीनी, पेन, पेन्सिल, पुस्तकों, पत्रिकार, तम्बाकू, तिमरेट, बीड़ी, तिनार, मिठाई, कृषि उपकरणों को शामिल किया गया है ।²⁰

उत्तर प्रदेश बिज्रीकर अधिनियम में कर मुक्त वस्तुओं की सूची में 57 वस्तुओं शामिल की गई है ।²¹ इन वस्तुओं में पानी, दूध, नमक, तमाखार पत्र, मोटर त्रिप्ट तथा डीजल तेल, एल्कोहल, कृष्ण यन्त्र, घोट, घाव आदि पर बांधी जाने वाली पट्टियाँ, बारदाना तथा डिब्बे, पुस्तकें तथा मैगजीन, गन्ने के बीज, देशी शराब, पशु ^{सुरक्षा} सुलम्मा आदि उल्लेखनीय है ।²²

मध्य प्रदेश बिज्रीकर की धारा 10 के अन्तर्गत 23 वस्तुओं को बिज्रीकर से

18. गोकुल वेणी० : हरियाणा बिज्रीकर, पृ० 8-9.

19. गोकुल वेणी० : दिल्ली बिज्रीकर, पृ० 8-10.

20. नारैन गौड : पंजाब सामान्य बिज्रीकर अधिनियम, 1948, पृ० 7.

21. वस्तुओं का विवरण परिशिष्ट 'त' में उद्धृत है ।

22. मेहरोजा रचणी० एवं गोकुल तीक्ष्णः उत्तर प्रदेश बिज्रीकर अधिनियम, पृ० 43-45.

मुक्त रखा गया है, जो इस प्रकार है - कृषि उपकरण, पुस्तकें, पावरतूम व करघों पर तैयार किया गया कपड़ा, इकलरोटी, चूने, मिट्टी के बर्तन, ऊँडे, विद्युत्प्रतिष्ठ, अभ्यास पुस्तिकाएँ, पशु आहार, मछलियाँ, मासे, तख्तियाँ, ताजा दूध व दही, हाथ के बने कम्बल व कागज, कुनेन, शक्कर, तम्बाकू, तूप, खादी तिलक, परिवार नियोजन साधन, तूखे मैदे, बैलगाड़ी व बहिर आदि।²³

राजस्थान बिड़लीकर अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्त वस्तुओं को चार मुख्य भागों में विभक्त किया गया है। 1। ऐसे माल जो व्यापारी के पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लिखित होने पर ही कर मुक्त है। 2। ऐसे माल जिनके लिए व्यापारी के द्वारा 10 रुपये की निर्धारित फीस चुका कर कर मुक्ति का प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। 3। ऐसे माल जिनके लिए व्यापारी के द्वारा विक्रय राशि पर आधारित फीस चुका कर कर-मुक्ति का प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। 4। ऐसे माल जिनके लिए व्यापारी के द्वारा बिना कोई फीस चुका कर मुक्ति का प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। प्रथम वर्ग में 31 प्रकार की वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जिनमें कुछ कृषि यन्त्र, ताख की बुड़ियाँ, पत्थर व तंगमरमर की मूर्तियाँ, हस्तनिर्मित और उच्चारी कागज, कुँकुम, तिन्दूर तथा मेंढी, कुछ विशिष्ट प्रकार की ओढ़नियाँ एवं ताड़ियाँ शामिल हैं। द्वितीय वर्ग में कुछ ऐसी वस्तुएँ शामिल हैं जिन्हें विक्रेता स्वयं बनाकर विक्रय करता है और निर्माण कार्य में भाड़े के ब्रह्म या शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें जूते, मीनाकारी की वस्तुएँ, हाथ से बने चिम तथा ताड़ुन उल्लेखनीय हैं। तीसरे वर्ग में छप्पाइयों, डोलों, अल्पा-हार मूठों एवं चाय की दुकानों इत्यादियों को छूट दी गई है। यदि इनकी बिड़ली 30,000 रुपये तक हो तो इन्हें कर की मुक्ति के लिए कोई फीस नहीं देनी होती। लेकिन यदि बिड़ली 30,000 रुपये से अधिक हो तो उसके बाद प्रत्येक 5,000 रुपये पर 250 रुपये की फीस चुकानी होती है। चतुर्थ वर्ग में 34 प्रकार की वस्तुएँ शामिल की गई हैं। इनमें हाथी दाँत की बनी वस्तुएँ, अभ्यास पुस्तिकाएँ, पत्तन, हेन्डलूम की सूती दरियाँ, सभी प्रकार के बिड़ोने इत्यादि प्रमुख हैं।²⁴ प्रायः सभी राज्यों

23. दीपिका इकलपूजारी : मध्य प्रदेश सामान्य बिड़ली कर अधिनियम, 1958, पृ० 37.

24. वाचना, गुप्त एवं नाहर : राजस्थान बिड़लीकर परिचय, पृ० 218-226.

में परिवार नियोजन से सम्बन्धित साधनों और उपकरणों को विक्री कर से मुक्त रखा गया है ।

6. कर योग्य सीमा

कर योग्य सीमा से आशय उत राशि से है जिससे अधिक विक्री होने पर व्यापारी कर चुकाने के लिए दायी होता है । विभिन्न दशाओं में व्यापारी के लिये कर योग्य सीमा अलग-अलग निर्धारित की गई है । भारत में विभिन्न राज्यों में कर योग्य सीमाएँ भिन्न-भिन्न निर्धारित की गयी है ।

दिल्ली में व्यापारी के लिए विभिन्न दशाओं में कर योग्य सीमा निम्नलिखित निर्धारित की गई है : 13। ऐसे व्यापारी के लिए जो दिल्ली के बाहर से दिल्ली में माल बेचने के लिए माल आयात करता है कोई कर नहीं लगेगा । 14। केन्द्रीय विक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कर दायी या पंजीकृत व्यापारी पर कोई कर नहीं लगेगा । 15। ऐसे व्यापारी के लिए जो विक्रय के लिए माल का निर्यात करता है, चाहे निर्मित माल का मूल्य कितना ही हो, 50,000 रुपये से अधिक विक्री होने पर कर लगेगा । 16। अन्य व्यापारियों की दशा में 1,00,000 रुपये से अधिक विक्री होने पर कर लगेगा । अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रावधान भी है कि यदि विक्री कर प्रसारक यह समझता है कि उपर्युक्त 15। में वर्णित निर्माता व्यापारी को हितानुकूल-हितानुकूल रहने में कठिनाई होगी अथवा किसी अन्य वैध कारण से ऐसे व्यापारी की कर योग्य सीमा बढ़ा दी जाए तो वह अधिमुक्ता द्वारा इस कर योग्य सीमा की एक लाख रुपये तक बढ़ा सकता है ।²⁵

हरियाणा में धारा 7 के अधीन, विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के लिए निम्न कर योग्य सीमा है : 13। ऐसे व्यापारी पर, जो राज्य में विक्रय तथा निर्यात में प्रयोग के लिए किसी वस्तु का बाहर से आयात करता है, विक्री कर नहीं लगेगा । 14। ऐसे व्यापारी पर, जो किसी वस्तु का निर्यात करता है, विक्री कर

नहीं लेगा । 1त। ऐसे व्यापारी के लिए जो विक्रय के लिए स्वयं किसी वस्तु का निर्माण अथवा उत्पादन करता है, 10,000 रुपये से अधिक बिक्री होने पर बिक्री कर लगेगा । 1द। ऐसे व्यापारी के लिये जो तंदूर, दाबा, होल, जलपानगृह, हलवाई की दुकान, बेकरी या अन्य इसी प्रकार का प्रतिष्ठान खाते हैं, जिनमें भारतीय खाद्य पदार्थ एवं वाय मिलती है, 25,000 रुपये से अधिक बिक्री होने पर बिक्री कर लगेगा । 1य। किसी विशेष श्रेणी के व्यापारियों की दशा में जो उक्त 1अ। 1ब। 1त। एवं 1द। की श्रेणी में नहीं आते, ऐसी राशि जो निर्धारित कर दी जाए । 1र। अन्य किसी व्यापारी की दशा में 40,000 रुपये से अधिक बिक्री होने पर ।²⁶

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के लिए विक्रय राशि तथा कर योग्य बिक्री की सीमायें निम्न प्रकार हैं : 1अ। एक ऐसा व्यापारी जो माल का आयात करता है तथा जिसकी विक्रय राशि 10,000 रुपये या इससे अधिक होने पर 1ब। एक ऐसा व्यापारी जो किसी भी माल का निर्माण करता है ।इनमें पकाये हुए भोजन के निर्माणकर्त्ता व्यापारी शामिल नहीं है, किन्तु बेकरी उत्पादों के निर्माणकर्त्ता व्यापारी शामिल है। जिसकी विक्रय राशि 25,000 रुपये या इससे अधिक होने पर । 1त। एक ऐसी सहकारी समिति जो सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समिति है तथा जो स्वयं के द्वारा उत्पादित एवं निर्मित मालों का ही व्यापार करती है तथा जो उन मालों के उत्पादन या निर्माण कार्य में किसी भी स्तर पर भाड़े के प्रभ का उपयोग नहीं करती है जिसकी बिक्री 50,000 रुपये या इससे अधिक होने पर 1द। अन्य सभी प्रकार के व्यापारियों के लिए 75,000 रुपये या इससे अधिक बिक्री होने पर ।²⁷

उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यापारी, जो ऐसी वस्तुओं में व्यापार करता है, जिन पर उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री कर लगता है और जिसकी विक्रय राशि कर निर्धारण वर्ष के लिए कर योग्य सीमा से अधिक है, बिक्री कर देने

26. गौकन वैसी0 : हरियाणा बिक्री कर, पृ० 21.

27. पापला, मुक्त एवं नाहर : राजस्थान बिक्री कर परिषद, पृ० 210-211.

के लिए दायी है। यदि किसी व्यापारी का कर-निर्धारण वर्ष के लिए निम्न का योग उत्पादक की दशा में 50,000 रुपये तथा किसी अन्य व्यापारी की दशा में 1,00,000 रुपये या राज्य सरकार द्वारा इतने अधिक अधिभूयित राशि से ज्यादा है तो उस पर बिजुी कर लगेगा : 13। धारा 3 द के अन्तर्गत अधिभूयित माल का क्रय मूल्य 14। अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत कर योग्य खरीद दारियाँ 15। धारा 3 द के अन्तर्गत अधिभूयित माल की बिजुी काहीँ सेता माल राज्य में ही न खरीदा गया हो 16। धारा 3 द में अधिभूयित माल के अतिरिक्त अन्य सभी माल की बिजुी, चाहे सेता माल प्रत्यक्ष रूप से व्यापारी द्वारा अथवा उसके एजेंट, शाखा या डिपो द्वारा राज्य के अन्दर, अन्तराज्यीय व्यापार में अथवा राज्य के बाहर बेचा जाता है 128

पंजाब में न्यूनतम कर योग्य बिजुी की राशि के सम्बन्ध में वर्तमान में निम्न दशायें हैं 13। ऐसे प्रत्येक व्यापारी के लिए जो पंजाब में किसी माल के निर्यात में या बिजुी के लिए आयात करता है बिजुी कर नहीं लगेगा 14। ऐसे प्रत्येक व्यापारी के लिए जो स्वयं निर्यात या उत्पादन करके माल का विक्रय करता है अथवा ऐसे व्यापारी के लिए जो तन्दूर, टाबा, होटल, क्लबानगृह, हलवाई की दुकान, बेकरी या अन्य इसी प्रकार का प्रतिष्ठान जाते हैं जिनमें भारतीय खाद्य पदार्थ एवं गाय मिलाती है 40,000 रुपये से अधिक बिजुी होने पर बिजुी कर लगेगा 15। किसी विशेष श्रेणी के व्यापारियों की दशा में जो उक्त 13। और 14। की श्रेणी में नहीं आते ऐसी राशि जो निर्धारित कर दी जाए 16। अन्य किसी व्यापारी की दशा में 1,00,000 रुपये से अधिक बिजुी होने पर कर लगता है 129 स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों में बिजुीकर सुविधा की सीमायें अलग-अलग निर्धारित की गई हैं और समय-समय पर मूल्यवृद्धि तथा सरकारी नीतियों के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जाता रहा है।

28. गोखल जेम्पीठ : उत्तर प्रदेश बिजुीकर, पृष्ठ 10.

29. गोड्ड नारंग : पंजाब सामान्य बिजुीकर अधिनियम, 1948, पृष्ठ 13.

7. व्यापारियों का पंजीकरण

प्रत्येक व्यापारी माल बेचते समय ग्राहकों से बिछी कर वसूल नहीं कर सकता है अर्थात् केवल वे व्यापारी ही माल बेचते समय ब ग्राहकों से बिछी कर वसूल कर सकते हैं । जो बिछी कर व्यवस्था के अन्तर्गत पंजीकृत हों । इसके साथ ही पंजीकृत व्यापारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट वस्तुओं को बिछी कर चुकाये बिना खरीद सकता है यदि यह माल निर्माण कार्य या पुनः विक्रय के लिए खरीदा जाता है । यह उल्लेखनीय है कि एक ऐसा पंजीकृत व्यापारी जिसे बिछीकर के ध्यान पर एक मुक्त राशि का भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई है, ग्राहकों से बिछी कर वसूल नहीं कर सकता है ।

दिल्ली में व्यापारियों का पंजीकरण चार प्रकार का होता है । अनिवार्य, ऐच्छिक, अस्थायी एवं विशेष । अनिवार्य पंजीकरण केन्द्रीय बिछी कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर चुकाने के लिए दायी व्यापारी एवं निर्धारित कर योग्य सीमा से अधिक कुल पण्यावर्त होने की दशा में व्यापारी के लिए होता है । ऐच्छिक पंजीकरण 25,000 रुपये से अधिक लेकिन कर योग्य सीमा से कम बिछी वाले व्यापारियों के लिए होता है । अस्थायी पंजीकरण दिल्ली राज्य में एक वर्ष के अन्दर 30,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुएँ निर्मित करने के लिए व्यवसाय स्थापित करने वाले व्यापारियों के लिए होता है । विशेष पंजीकरण उक्त समय किया जाता है जब किसी व्यापारी की दृष्टि पर उतका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है और फिर उती वर्ष में या आगामी किसी वर्ष में किसी तिथि को उतकी कुल पण्यावर्त तथ्यप्रथम कर योग्य सीमा से अधिक हो जाता है ।³⁰

राजस्थान में व्यापारियों के लिए अनिवार्य, ऐच्छिक तथा अस्थायी पंजीयन की व्यवस्था है । ऐसे प्रत्येक व्यापारी के लिए जो अधिनियम के अन्तर्गत अपनी कर-योग्य बिछी पर कर चुकाने के लिए दायी है एवं जिसकी विक्रय राशि निर्दिष्ट

सीमाओं से अधिक है पंजीयन करवाना अनिवार्य है । यदि कोई व्यापारी बिजुी कर अधिनियम के अन्तर्गत कर के लिए दायी न हो किन्तु उसकी विद्युय राशि निर्दिष्ट सीमा से अधिक होने की सम्भावना हो तो वह अपना पंजीयन ऐच्छिक रूप से करवा सकता है । ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान में कोई उद्योग स्थापित करने का इरादा रखते हैं और उसके लिए मशीन व कच्चा माल खरीदते समय करों में रियायत का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं अथवा कोई व्यक्ति राजस्थान राज्य में कोई व्यवसाय स्थापित करना चाहे और उस व्यवसाय का उद्देश्य प्रतिवर्ष 10,000 रुपये से अधिक मूल्य का माल निर्माण करना हो तो वे अपना अस्थाई पंजीयन करवा सकते हैं ।³¹

हरियाणा सामान्य बिजुी कर अधिनियम के अधीन कर चुकाने के लिए दायी प्रत्येक व्यापारी को अनिवार्य रूप से अपने आपको पंजीकृत करना होता है । ऐसा व्यापारी जिसकी एक वर्ष के दौरान कुल बिक्रयार्थ 15,000 रुपये से अधिक है, कर चुकाने के लिए दायी न होने पर भी ऐच्छिक पंजीकरण के लिए आवेदनपत्र दे सकता है । यदि कोई व्यक्ति हरियाणा प्रान्त में विद्युय के लिए एक वर्ष में दस हजार रुपये मूल्य से अधिक की वस्तुएँ निर्मित करने के लिए व्यवसाय स्थापित करना चाहता है तो वह अस्थाई पंजीकरण के लिए कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकता है ।³²

उत्तर प्रदेश में पंजीयन दो प्रकार का होता है : अनिवार्य पंजीयन और अस्थाई पंजीयन । ऐसे प्रत्येक व्यापारी के लिए अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है । जो 1। राज्य के बाहर से माल का आयात करके बेचता है और बिजुी कर अधिनियम की धारा 3 अ।1। के अन्तर्गत कर दायी है । 1।2। इस अधिनियम के अन्य किसी प्रावधान के अधीन कर दायी है 1।3। भविष्य में कर दायी होगा यहाँ उत्पादक की दशा में वार्षिक या अनुमानित बिजुी 50,000 रुपये एवं अन्य किसी व्यापारी की दशा में 1,00,000 रुपये या उससे अधिक है जो धारा 3।2। के अधीन

31. नोक्स वेअरी0 : हरियाणा बिजुीकर, पृ0 23-29.

32. मेहरौना, नोक्स : उत्तर प्रदेश बिजुीकर अधिनियम, पृ0 52-59.

हैं तथा 12। ऐसा प्रत्येक व्यापारी जिसने कर-निधारण वर्ष के बीच में कभी अपना व्यापार प्रारम्भ किया हो और उसकी अनुमानित औसत मासिक बिक्री या किसी माह की वार्षाधिक बिक्री उत्पादक की दशा में 50,000 रुपये है के 1/12 भाग या अन्य व्यापारी की दशा में 1,00,000 रुपये के 1/12 भाग से कम नहीं है या उससे अधिक है वो धारा 312। के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए। कोई भी निर्माणकर्ता जो किसी भी वर्ष में बिक्री के लिए 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश में अपना व्यापार स्थापित करना चाहे तो वह अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र निर्धारित फार्म पर दे सकता है।³³

निष्कर्ष रूप में प्रायः सभी राज्यों में अनिवार्य, श्रेष्ठिक एवं अस्थायी पंजीयन की व्यवस्था है और पंजीयन के लिए निर्धारित शुल्क भी जमा करना होता है।

8. विक्रय राशि का अर्थ

राजस्थान बिक्रीकर अधिनियम के अनुसार विक्रय राशि का अर्थ किसी व्यापारी द्वारा गत वर्ष में की गई माल की बिक्री या पूर्ति के सम्बन्ध में प्राप्त मूल्यों के योग से है। चाहे वह राशि प्राप्त हो चुकी हो या न हुई हो अर्थात् उधार बिक्री को भी इसमें शामिल किया जाता है लेकिन नगद छूट को घटा दिया जाता है। यदि किसी ग्राहक विशेष की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से माल मँगाकर तुरन्त ही उस ग्राहक को बेच देता है तो उस माल का विक्रय मूल्य उस व्यापारी की विक्रय राशि में शामिल किया जाता है। जिसके यहाँ से माल मँगाया गया है। ठेके पर माल की पूर्ति के सम्बन्ध में विक्रय राशि का आशय उस राशि से होता है जो ठेके के लिए प्राप्त या प्राप्त्य राशि में से क्रम की लागत घटाने पर प्राप्त होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ शर्तें पूरा करने पर कुछ मूल्य में 10 प्रतिशत बढ़ाकर भी विक्रय राशि की गणना कर ली जाती है।

33. गोंया मेहरोत्रा : उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, पृष्ठ 52-59.

हरियाणा में विक्रय राशि से आशय एक व्यापारी द्वारा पुर्चन अथवा स्पेन्ट अथवा अन्य किसी हैतियत से निर्धारित समय के अन्दर की गयी किसी तथा खरीद की राशियों के योग में से व्यापारिक धन के अनुसार त्वीकृत कोड नगद बट्टा घटाकर शेष बची हुई राशि से है। यदि व्यापारी माल की तुपुर्दगी से पहले अथवा तुपुर्दगी के समय माल के सम्बन्ध में किये गये किसी कार्य के लिये कोड राशि प्राप्त करता है तो इसे भी विक्रय राशि में शामिल कर लिया जाता है। किसी व्यापारी की भावी अनुबन्धों के सम्बन्ध में विक्रय को कराधान के लिये विक्रय राशि में शामिल नहीं किया जायेगा, जिनके लिये अभी माल की वास्तविक तुपुर्दगी नहीं हुई है। ऐसे माल की विक्रय राशि को जिसे क्रय करने पर इस अधिनियम के अधीन कर देय है तथा ऐसे माल के क्रय मूल्य को जिसका विक्रय करने पर इस अधिनियम के अधीन कर देय है, विक्रय राशि (पण्यावर्त) में शामिल नहीं किया जायेगा लेकिन कर योग्य माल का क्रय मूल्य विक्रय राशि में शामिल किया जायेगा।

दिल्ली में विक्रय राशि से आशय किसी अवधि में विक्रय मूल्य के योग अथवा प्राप्त विक्रय मूल्यों के भागों के योग अथवा व्यापारी की इच्छा पर उस अवधि में वास्तव में प्राप्त रकम के योग से है। इस योग में से उस अवधि के अन्दर वास्तव लौटाये गये माल के सम्बन्ध में चुकायी राशि को घटा दिया जाता है शेष बची रकम ही पण्यावर्त कहलाती है। सामान्यतः उक्त अवधि तीन माह की होती है।

उत्तर प्रदेश में विक्रय राशि से आशय उस कुल राशि से है जितने में कि, एक व्यापारी द्वारा तीये अथवा अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से अपने हितार्थ में अथवा अन्य किसी व्यक्ति के हितार्थ में नगद अथवा स्थगित भुगतान अथवा अन्य मूल्यवान् वस्तुओं के लिए, माल बेचा जाता है। यहाँ कि किसी व्यक्ति द्वारा कृषि अथवा वानवानी उपज, जो उसने स्वयं बोयी हो अथवा किसी ऐसी भूमि पर बोयी हो जिसमें उसका हित स्वामी अथवा किरायेदार की हैतियत से हो, अथवा कुक्कुट पालन, अथवा डेरी का उत्पाद, जो उसकी रबी हुई भूमियों अथवा पशुओं से उदय हुआ हो, बेचने से जो विक्रय राशि प्राप्त हुई हो, वह विक्रय धन में शामिल नहीं होगी।

पंजाब में विक्रय राशि का अर्थ है किसी व्यापारी द्वारा निर्धारित समय के दौरान की गई विक्रय और क्रय अथवा विक्रय और क्रय राशि के भाग से है जिसमें सामान्य रूप से व्यापारिक रीति के अनुसार व्यापारिक स्वं नकद छूट को घटा दिया जाता है लेकिन इसमें ऐसी राशि शामिल की जाती है जो माल की सुपुर्दगी देते समय या माल की सुपुर्दगी से पहले प्राप्त कर ली जाती है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि विक्रय राशि का निर्धारण करने में सामान्यतः नकद और उधार दोनों विक्रियों को जोड़ लिया जाता है और उसमें से व्यापारिक खान के अनुसार दी जाने वाली छूट को घटा दिया जाता है।

9. कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रावधान

यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से बिजुली कर लगाने में उपभोक्ता वस्तुओं और कच्चे मालों में कोई अन्तर नहीं होता, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से कच्चे माल पर बिजुली कर लगाने पर उसका प्रभाव लगभग उत्पादन शुल्क जैसा हो जाता है और तैयार माल के मूल्य को प्रभावित करता है। इस कारण विभिन्न राज्यों में कच्ची ताम्बूरी और मध्यवर्ती वस्तुओं पर बिजुली कर के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की रियायतें दी गई हैं।

कुछ राज्यों में उत्पादकों को बेचे जाने वाले कच्चे माल पर बिजुलीकर से पूर्ण मुक्ति की व्यवस्था है, इनमें गुजरात, हरियाणा और पंजाब उल्लेखनीय हैं, लेकिन यह कर मुक्ति निर्धारित शर्तों के अधीन ही दी जाती है। गुजरात में यह कर मुक्ति केवल ऐसे कच्चे माल के विक्रयों पर दी जाती है जो कर योग्य निर्मित माल में प्रयोज्य होता है। पंजाब और हरियाणा में इस प्रकार की छूट उस परिस्थिति में मिलती है जबकि निर्मित माल राज्य में ही बेचा जाता है।³⁴

अधिकांश राज्यों में कच्चे माल पर पूर्ण कर मुक्ति के स्थान पर रियायती

34. अधुना कर बोर्ड आयोग प्रतिवेदन, जनवरी 1978, पृष्ठ 62.

कर पुनः प्राथमिकता दी गई है। राजस्थान बिजुलीकर अधिनियम के अनुसार यदि किसी पंजीकृत व्यापारी द्वारा कोई माल खरीदा जाये और जेता व्यापारी का उद्देश्य उस माल को कच्चे माल के रूप में लेकर राजस्थान के भीतर ही कर मुक्त माल के अतिरिक्त अन्य किसी माल का निर्माण करना हो तो इस प्रकार के कच्चे माल पर विक्रय कर की दर 2 प्रतिशत ही होती है। केरल में कच्चे माल और मशीनों के कल पुर्जे या हिस्से के विक्रय पर छूट के अलग प्रावधान हैं। कच्चे माल की बिजुली पर कर की छूट उन्नीसवीं सदी में मिलती है जबकि तैयार माल राज्य में विक्रय होने पर कर योग्य है। जबकि मशीनों के हिस्सों इत्यादि पर कर की रियायत उस समय भी मिलती है जबकि उनसे बना हुआ सामान कर योग्य न हो। उत्तर प्रदेश में कच्चे माल की कर सम्बन्धी रियायतों को इस प्रकार बनाया गया है, जितने नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रेरणा मिले। सन् 1974 के परचाहू में राज्य में नवीन औद्योगिक इकाइयों एक निर्धारित समयवधि तक 35 अधिसूचित वस्तुओं के निर्माण के सन्दर्भ में क्रय किये जाने वाले माल और ऋण्यवर्ती सामानों के क्रय पर पूरी छूट प्राप्त करते हैं। इन वस्तुओं में ताईरिंग, रेडियो, टेलीविजन, ट्रांसिस्टर तथा विद्युत सामान उल्लेखनीय है। कर छूट की निर्धारित अवधि विच्छेद जिलों में 5 वर्ष और अन्य जिलों में 3 वर्ष है। इस निर्धारित अवधि के पूरा होने के परचाहू कच्चे माल और ऋण्यवर्ती सामान के ऊपर बिजुलीकर की रियायती दर लागू होती है। 35 अधिसूचित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का निर्माण करने वाली नवीन इकाइयाँ उक्त निर्धारित अवधि तक रियायती बिजुलीकर की दरों पर कच्चे माल इत्यादि का क्रय कर सकती है, लेकिन इस अवधि के परचाहू पूरी दर से बिजुली कर देना होगा।

महाराष्ट्र में निर्याताओं को बेचे जाने वाले कच्चे पदार्थों पर रियायती बिजुली कर का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार कोई भी निर्याता, जो पंजीकृत व्यापारी है, कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं को 3 प्रतिशत की रियायती दर से भुगतान करके क्रय कर सकता है जो उत्पादन देश के बाहर निर्यात किया जाता है उसके लिये क्रय किये गये कच्चे माल पर चुकाया गया बिजुलीकर राज्य सरकार द्वारा नौटा दिया

जाता है। पश्चिमी बंगाल में रियायती बिजुीकर की दर कुछ विशिष्ट वस्तुओं के सम्बन्ध में। प्रतिशत और अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में 2 प्रतिशत है। लेकिन यह छूट तभी मिलती है जबकि विक्रेता और निर्यातकर्ता दोनों ही पंजीकृत व्यापारी हों। अन्ध प्रदेश में बिजुीकर की रियायती दर 3 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में या अन्त-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में या निर्यात में विक्रय हेतु अन्य माल के विनिर्माण हेतु कितनी कच्चे माल के, जो तैल पत्तों से भिन्न हों, विक्रय या क्रय दर, जो किसी पंजीकृत व्यापारी द्वारा किया गया हो, देकर ऐसे कच्चे माल की विक्रय कीमत या क्रय कीमत के तीन प्रतिशत की दर से लाना किया जाता है, परन्तु जब ऐसे कच्चे माल के क्रय या विक्रय पर देकर दो प्रतिशत से कम दर पर देय हो, तब देकर की गणना ऐसी कम दर से ही की जावेगी।

कुल मिलाकर स्थिति यह है कि यद्यपि अधिकांश राज्यों में कच्ची ताम्बूरी और ऋक्षवर्ती वस्तुओं पर बिजुीकर की छूट या बिजुीकर की रियायती दरों का प्रावधान है लेकिन यह छूट उनी परिस्थिति में मिलती है जबकि कच्चे माल का विक्रय राज्य में ही तैयार माल बनाने के उद्देश्य से किया गया हो। कुछ परिस्थितियों में यह शर्त अवश्य लगा दी गयी है कि तैयार माल बिजुीकर योग्य मालों में आता हो। कच्चे माल और ऋक्षवर्ती वस्तुओं पर कर छूट और रियायत का उद्देश्य राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करना, पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक स्थानीयकरण को प्रेरित करना तथा उपभोक्ता की दृष्टि से ऋक्षवर्ती मालों पर लगने वाले बिजुीकर के विपरीत प्रभावों को रोकना होता है।

10. वर्ध एवं कर निर्धारण के समय की सीमा

बिजुीकर का निर्धारण सामान्यतः वार्षिक आधार पर होता है। यद्यपि अधिकांश राज्यों में इसके लिए वित्तीय वर्ष 11 अप्रैल से 31 मार्च को आधार बनाया गया है, लेकिन कुछ राज्यों में इसमें विकल्प भी दिये गये हैं। उदाहरणार्थ, गुजरात और महाराष्ट्र में नियमित रूप से लेके रखने वाले करदाताओं को यह विकल्प दिया गया है कि अपने लेके वर्ष के आधार पर वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त, कोन्डर वर्ष, सम्यक् वर्ष, रामनवमी वर्ष इत्यादि को भी अपना सकते हैं।

यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि प्रारम्भ में अधिकांश राज्यों में इस तन्द्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी कि करदाता द्वारा रिटर्न जमा किये जाने के कितने समय के अन्दर कर निर्धारण हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ राज्यों में निकट के वर्षों में इस सम्बन्ध में प्रावधान किये गये हैं। गुजरात बिज्जी कर अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि सामान्यतः तीन वर्षों के अन्दर कर निर्धारण हो जाना चाहिए लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में और विशेष रूप से कम कर निर्धारण हो जाने पर पुनः कर निर्धारण की दशा में 4 वर्ष से 8 वर्ष तक हो सकती है।⁴²

दिल्ली केन्द्रशासित क्षेत्र में यह अवधि 4 वर्ष से 6 वर्ष तक है। राजस्थान बिज्जीकर अधिनियम में बिज्जी के नवी, साक्ष्य या सर्वोत्तम निधि के आधार पर कर निर्धारण सम्बन्धित वर्ष के पश्चात् 5 वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे मामलों में यह अवधि 8 वर्ष है जिनमें कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या व्यापारी ने अपना पंजीयन न कराया हो या अपना बिज्जी का विवरण दाखिल न किया हो।

11. कर निर्धारण की प्रक्रिया

कर निर्धारण की प्रक्रिया लगभग सभी राज्यों में एक ही है। इसके लिए सामान्य रूप से पंजीकृत व्यापारी को अपना बिज्जी का विवरण बिज्जी कर कार्यालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए विभिन्न राज्यों में अन्तर अवश्य है।

दिल्ली में प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी को तिमाही की समाप्ति के बाद 45 दिन के अन्दर अपना बिज्जी विवरण दाखिल करना होता है। कर निर्धारण अधिकारी कारणों का निहित रूप में उल्लेख करके किसी व्यापारी को प्रतिमाह बिज्जी विवरण दाखिल करने का आदेश दे सकता है। मासिक बिज्जी विवरण आगामी महीने की 15 तारीख तक दाखिल कर दिया जाना चाहिये।

हरियाणा में प्रत्येक पंजीकृत एवं नैर पंजीकृत व्यापारी को अपने क्षेत्र के कर निर्धारण अधिकारी के यहाँ प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर 30 दिन के भीतर अपना बिज्जी विवरण दाखिल करना होता है।

राजस्थान में भी बिजुली विवरण को, जिस तिखाही से वह सम्बन्धित है, उसकी अन्तिम तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि किसी व्यापारी की किसी मत वर्ष में कर-योग्य बिजुली उसकी सकल-विक्रय राशि के 10 प्रतिशत से अधिक न हो तो वह कर निर्धारण अधिकारी की स्वीकृति लेकर तेजा वर्ष समाप्त होने से 60 दिन के भीतर बिजुली विवरण पेश कर सकता है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य प्रत्येक ऐसे व्यापारी को जिसकी किसी कर-निर्धारण वर्ष में बिजुली दो लाख रुपये से अधिक है, अपनी मासिक बिजुली का विवरण प्रत्येक माह का उससे अगले माह की समाप्ति से पूर्व बिजुली-कर अधिकारी के यहाँ दाखिल करना होता है, परन्तु माह फरवरी का विवरण 20 मार्च तक दाखिल करना होता है।

उपरोक्त मुख्य प्रावधानों के अतिरिक्त बिजुलीकर अधिनियमों में छाता पुस्तकों के रख-रखाव, छातों के निरीक्षण, कर की वापसी, भूतुधार, अपराध एवं अध्येष्ट, अपील तथा पुनर्विचार, बैंक पोस्ट की स्थापना इत्यादि के सम्बन्ध में भी प्रावधान होते हैं। इनमें मौलिक रूप से लगभग समानता की स्थिति है, लेकिन अध्येष्ट की राशि, अपील की समय अवधि इत्यादि में कुछ व्यावहारिक अन्तर अवश्य है।

देश के कुछ राज्यों में बिजुलीकर से सम्बन्धित मुख्य प्रावधानों की विवेचना के पर्याप्त निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि बिजुली कर के करारोपण के उद्देश्य एवं प्रक्रिया लगभग एक ही है लेकिन बिजुलीकर की प्रशासनिक व्यवस्था, कर की दरें, कर का विन्दु, कर मुक्ति की सीमा, कर से मुक्त वस्तुएँ इत्यादि में व्यापक विभिन्नताएँ हैं, जिनके तन्मूर्ध में उचित एकत्वता और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

बिजलीकर की प्रमुख समस्याएँ

यद्यपि बिजलीकर आगम तथा उनकी प्रयुक्तियों के विवेचना से स्पष्ट है कि यह राजकीय आय के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, फिर भी इसके प्रावधानों, प्रक्रियाओं और कार्यव्यवस्थाओं का सूक्ष्म अन्वेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस कर के प्रावधानों में विविधता, कार्य प्रवृत्ति में कठिनाता स्वयं इसके कार्यव्यवस्था में अनेक कमियाँ देखने को मिलती हैं। यही कारण है कि यह अप्रत्यक्ष कर का यह स्वयं विचारकों, उद्योगपतियों और व्यापारियों द्वारा आलोचना का विषय रहा है। इस अध्याय के अन्तर्गत बिजलीकर की विभिन्न समस्याओं और कठिनाइयों को लेकर उन पर प्रकाश डाला गया है तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बिजलीकर व्यवस्था की सामान्य समीक्षा करते हुये उत्तर प्रदेश के विशिष्ट तन्त्र में इस कर की समस्याओं और कठिनाइयों का विवेचना निम्नांकित सूचों में किया गया है :

1. विविध कर प्रावधान

जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि देश के विभिन्न राज्यों में बिजलीकर के प्रारम्भ में समसामयिकता का अन्तर ही नहीं है, वरन् बिजलीकर प्रावधानों में भी पर्याप्त रूप व्यापक भिन्नताएँ हैं। इनमें बिजलीकर के विन्दु, बिजलीकर से मुक्त वस्तुओं की सूची; बिजलीकर के प्रमातन; पंजीयन की आवश्यकता, प्रकार एवं विधि; विद्युत राशि और कर योग्य बिजली का अर्थ; कच्चे माल के सम्बन्ध में कर प्रावधान तथा कर निर्धारण समय की सीमा इत्यादि के सम्बन्ध में भिन्नताएँ उल्लेखनीय हैं। विभिन्न राज्यों के अधिनियमों में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकी शब्द और धारणाओं का न्यायिक निर्वचन भी भिन्न-भिन्न हुआ है। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में कर प्रावधानों का पालन करने हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले विभिन्न कामों में भी अन्तर रहा है। इन सभी तथ्यों से कर की प्रभावशीलता में कमी आती है तथा कर प्रावधानों में कम सुविधा वाले राज्यों में व्यापारिक क्रियाएँ अन्तरित होने लगती हैं जिन राज्यों में कर प्रावधानों में अधिक सुविधायें दी गई हैं। विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रावधान व्यापारियों को यह अवसर भी प्रदान करते हैं कि वे अन्य राज्यों की तुलना के आधार पर अपने राज्य के कर प्रावधानों की बलिता,

अधिकता और रियायतों की जाँच करना कर तर्कों । यह ठीक है कि विभिन्न राज्यों में विकास की स्थिति, व्यापारिक क्रियाओं का स्तर, विभिन्न वस्तुओं के महत्व इत्यादि में अन्तर के कारण कर प्रावधानों में कुछ अन्तर रहना स्वाभाविक है, लेकिन बिड़्डीकर अधिनियम में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों, धारणाओं, प्रपत्रों, वस्तुओं के वर्गीकरण, कर की अधिकांश दरों, पंजीयन, कर-निर्धारण, अर्धदण्ड इत्यादि की व्यवस्थाओं में पर्याप्त एकस्यता बनाई जा सकती है । इसके लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक "आदर्श बिड़्डी कर अधिनियम" का प्राल्प तैयार किया जाए और उते क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुस्य तंशोधित एवं तमायोजित करके विभिन्न राज्य सरकारें अपना लें ।

2. बिड़्डीकर की दरों में अन्तर

विभिन्न राज्यों में बिड़्डीकर के प्रावधानों व व्यवस्थाओं में ही अन्तर नहीं है, वरन् बिड़्डीकर की दरों में भी व्यापक अन्तर देखने को मिलता है, जैसे धड़ियों पर तमिनाडू में बिड़्डी के प्रथम बिन्दु पर 15 प्रतिशत बिड़्डीकर लगता है जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में 10 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश में 12 प्रतिशत बिड़्डीकर लगता है । लोहा एवं इत्यादि पर तमिनाडू में 15 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 3 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में 4 प्रतिशत कर लगता है । किराने व पर मध्य प्रदेश तथा हरियाणा में 4 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 8 प्रतिशत तथा दिल्ली में 3 प्रतिशत कर है । इसी प्रकार कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जो कुछ राज्यों में कर से पूर्णतः मुक्त हैं जबकि अन्य कुछ राज्यों में कर योग्य हैं । उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में डबल रोटी पर 15 प्रतिशत कर लगाया जाता है जबकि दिल्ली और हरियाणा में यह कर-मुक्त है । दिल्ली में सभी अनाज तथा दानों पर मुक्त हैं जबकि हरियाणा में 4 प्रतिशत कर लगाया जाता है । इस प्रकार बिड़्डी कर की दरों में भिन्नताएँ जहाँ स्वर्य में इस कर व्यवस्था के अधिवैकपूर्ण होने का आधार बनती हैं, वहाँ दूसरी ओर इससे सरकार की उत नीति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके अन्तर्गत सरकार आवश्यक, आधारभूत एवं जनोपयोगी वस्तुओं के तन्दर्भ में तमान मुक्त बनाये रहना चाहती है । उदाहरण के लिए कनस्यति घी, औषधियाँ, उर्वरक इत्यादि के

तन्दर्भ में सरकार की यह नीति रही है कि देश भर में तमान मूल्य हों, लेकिन बिज्जी कर की दरों में भिन्नता के कारण ऐसी वस्तुओं के निर्धारित मूल्य तथा अंकित मूल्यों में बिज्जीकर अतिरिक्त शब्द जुड़ा रहता है। इसके कारण वहाँ एक ओर सरकार द्वारा तमान मूल्य बनाये रखने का औचित्य नष्ट हो जाता है, वहाँ दूसरी ओर उत्पादक या विक्रेता बिज्जीकर अतिरिक्त के नाम पर उपभोक्ता से मनमानी मूल्य प्राप्त करने का अवसर पा लेता है।

अतः यह कहना उपयुक्त होगा कि ऐसी वस्तुओं के तन्दर्भ में राज्यों में कर की दर तमान रखनी चाहिए, जिनके तन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय स्तर पर तमान मूल्य स्तर बनाये रखने का प्रयास करती है। मेरे विचार में राष्ट्रीय स्तर पर कर की दर में एकत्वता बनाये रखने के लिए देश को कुछ क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाए तथा सम्बद्ध और निकटवर्ती राज्यों में एक ही दर रखी जाए। इस तन्दर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि अक्टूबर, 1985 में नई दिल्ली में राज्य सरकारों एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों के वरिष्ठ आधिकारी एवं बिज्जीकर अधिकारियों की बैठक में बिज्जी कर से सम्बन्धित विभिन्न वस्तुओं पर विचार किया गया था और उसमें केन्द्र सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि बिज्जीकर दरों में एकत्वता बनाये रखने का प्रयास करना चाहिए।³⁵

बिज्जीकर की दरों के तन्दर्भ में केवल यही समस्या नहीं है कि विभिन्न राज्यों में बिज्जीकर की दर भिन्न है, वरन् एक व्यावहारिक समस्या यह भी है कि एक ही राज्य में बिज्जीकर की दरों के अनेक स्तर विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 2 प्रतिशत की दर से लेकर अधिकतम 15 प्रतिशत की दर तक के मध्य 9 दरें विद्यमान हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु में 2 प्रतिशत की दर से लेकर अधिकतम 20 प्रतिशत की दर के मध्य 12 दरें हैं। कर दरों की इतनी विविधताओं से कर निर्धारण जटिल होता है तथा करापव्यय के लिए वस्तुओं के नाम बदलकर बीचक

35. हिन्दुस्तान टाइम्स, 4 अक्टूबर, 1985.

बनाये जाते हैं। अतः यह उचित होगा कि वस्तुओं को चार या पाँच मुख्य वर्गों में विभाजित कर दिया जाए और इस तरह कर की दरों की भी चार या पाँच वर्गों तक ही सीमित रखा जाए। इस सन्दर्भ में दिल्ली का उल्लेख किया जा सकता है, जहाँ कुल वस्तुओं को कर की दर की दृष्टि से पाँच वर्गों (कर से मुक्त माल, जन साधारण द्वारा प्रयुक्त वस्तुएँ, फिलाती वस्तुएँ, छटी हुई दर वाली वस्तुएँ तथा होटल या क्लबान गृह में खाने-पीने वाले पदार्थ) में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार हरियाणा में भी वस्तुओं को चार वर्गों (कर मुक्त माल, साधारण कर योग्य माल, फिलातीत वस्तुएँ तथा घौषित माल) में विभाजित किया गया है।

3. कर मुक्ति की सीमा का निर्धारण

राज्यों में एक निश्चित वार्षिक बिजुी से अधिक की बिजुी पर ही यह कर लगाया जाता है अर्थात् एक निश्चित सीमा तक की बिजुी कर से मुक्त होती है। यद्यपि कर मुक्ति की सीमा को समय-समय पर बढ़ाया गया है लेकिन इस सीमा में वृद्धि देश में मुख्य स्तर में वृद्धि के अनुस्यू नहीं रहती है और राज्यों में इस कर की मुक्ति सीमाओं में भी पर्याप्त भिन्नताएँ हैं। अतः एकत्वता की दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि विभिन्न राज्यों में कर-मुक्ति की सीमा यथा सम्भव समान रखी जाए और इस सीमा को परिवर्तित करते समय मुख्य वृद्धि के निर्देशक को ध्यान में रखा जाए।

4. राज्य सीमाओं पर माल के निरीक्षण की समस्या

अन्तराज्यीय व्यवहारों में सीमा पर स्थित चेक-पोस्टों पर माल का निरीक्षण किया जाता है। यदि माल के विवरण और वार्षिक माल में अन्तर हो तो माल को रोका जा सकता है और अर्पण लगाया जा सकता है। तैदा-न्तिक रूप से यह व्यवस्था औचित्यपूर्ण है लेकिन भारत में जहाँ लगभग सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था "दुविधा मुक्त" अभित करने की अभ्यस्त हो चुकी हो और दूसरी ओर प्रभावशाली व्यापारी वर्ग दुविधा मुक्त के बड़े दुविधा उठाने का आदी हो चुका

हो, वहाँ इन फेक पोस्टों पर होने वाली अनियमितताओं और छोटे-छोटे तथा ईमानदार व्यापारियों को होने वाली कठिनाइयों का अनुमान तब ही लगाया जा सकता है ।

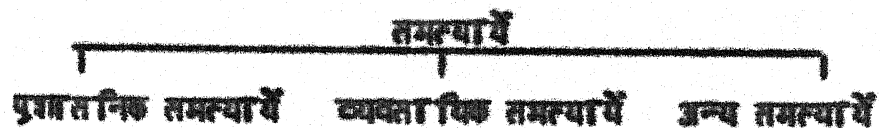
5. कच्चे माल पर कर निर्धारण की समस्या

राज्यों में निर्मित मालों में प्रयोज होने वाले कच्चे पदार्थों और आगंतों के प्रयोग के सम्बन्ध में बिज्जीकर की छूट अथवा बिज्जीकर में रियायत के प्रावधान है फिर भी यह पदार्थ पूरी तरह कर मुक्त नहीं है । यह व्यवस्था देश में लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के विपरीत है क्योंकि उत्पादक कच्चे पदार्थ और आगंतों पर बिज्जीकर बचाने के लिए संयोजन बनाना प्रारम्भ कर देते हैं या अपने आकार को बढ़ाकर उच्च मूल्य का स्वयं उत्पादन करना प्रारम्भ कर देते हैं । अतः इस सन्दर्भ में भी बिज्जीकर व्यवस्था को तन्तुलित बनाने की आवश्यकता है ।

सामान्यतः जब उत्पादन शुरू और बिज्जीकर की छूट की जाती है तो यह समझा जाता है कि उत्पादन कर, उत्पादन के बिन्दु पर लगाया जाता है जबकि बिज्जीकर उपभोग से पहले बिज्जी के स्तर पर लगाया जाता है । दूसरे शब्दों में, बिज्जीकर मुख्य रूप से उपभोग स्तर का कर है, लेकिन व्यवहार में अनेक प्रावधान इसके विपरीत हैं । जिन राज्यों में बहु बिन्दु कर या द्विबिन्दु कर लगता है, उनमें उत्पादन से लेकर उपभोग तक एक से अधिक बिन्दुओं पर बिज्जी कर लग जाता है । इसी प्रकार अन्तरराष्ट्रीय व्यवहारों में निर्यातक और आयातक दोनों ही राज्य बिज्जीकर लगाने का प्रयास करते हैं अर्थात् उत्पादक राज्य और उपभोक्ता राज्य दोनों ही बिज्जीकर लगाते हैं जबकि बिज्जीकर की भावना और धारणा के अनुसार उपभोक्ता राज्य को ही कर लगाना चाहिए । इसी प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि उत्पादक राज्य को भी बिज्जीकर में कुछ हित्ता मिलना चाहिए और इस आधार पर प्रारम्भ में केन्द्रीय बिज्जीकर की दर मात्र एक प्रतिशत रखी गई थी, लेकिन धीरे-धीरे इस भावना को भुला दिया गया । केन्द्रीय बिज्जीकर को आगम का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानकर इस दर की दर क्रमिक रूप से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी गई और इस प्रकार इस व्यवस्था से उपभोक्ता पर अनावश्यक कर भार की स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

उत्तर प्रदेश के तन्दर्भ में बिहरीकर की समस्यायें

उत्तर प्रदेश के तन्दर्भ में बिहरीकर की समस्यायों को प्रायः तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है : 1. प्रशासनिक समस्यायें 2. व्यवसायिक समस्यायें 3. अन्य समस्यायें ।



प्रशासनिक समस्यायें

इसके अन्तर्गत उन समस्याओं को रखा गया है जिनके सम्बन्ध में सरकार या बिहरीकर विभाग के उच्चाधिकारी यह अनुभव करते हैं कि बिहरीकर विभाग व्यापारियों की कार्यक्षमता के कारण यह समस्यायें उत्पन्न होती हैं और बिहरीकर विभाग की शिथिलता को कम करके तथा प्रशासन को सुदृढ़ करके इन समस्याओं का हल हो सकता है । इस प्रकार की समस्याओं के निम्न कई स्वल्प देखने को मिलते हैं ।

1. करावर्षक

राज्य स्तरीय करों में बिहरीकर में ^{करावर्षक} करावर्षक की समस्या सर्वाधिक है । उत्तर प्रदेश में बिहरीकर प्रथम श्रेणी पर लगाया जाता है । इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माता है तो उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का विक्रय करने पर बिहरीकर देय होता है । इस तरह उत्पादन क्रिया में लगी हुई समस्त कैपिटल बिहरीकर की देनदार है । इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बाहर से कोई माल लाया जाता है और पहली बार उसको प्रदेश के अन्दर बेचा जाता है तो उस पर भी बिहरीकर लगता है । तीसरे में निमाताओं और आयातकर्ताओं पर बिहरीकर लगता है, लेकिन दोनों ही बिन्दुओं पर करावर्षक होता है । प्रदेश में सबसे अधिक करावर्षक अन्य राज्यों से आयातित माल पर हो रहा है । राज्यों में

आयात मुख्य रूप से तड़क अधसा इसे रेल परिवहन के माध्यम से होता है । अनेक व्यापारियों द्वारा अपने द्वारा आयातित माल की सूचना को छिपाने का प्रयास किया जाता है और इसके लिए व्यापारी द्वारा हुन्डीकेट बही आते रहे जाते हैं । यद्यपि इसके लिए बिजुकर विभाग ने प्रान्त की सीमाओं पर जांच चौकियों की स्थापना की है लेकिन फिर भी करापर्यय होता रहा है क्योंकि आयातकर्ता सीमा पर माल कागजात दिखाकर किसी अन्य व्यापारी के नाम पर आयात को दिखाने की चेष्टाएं करता रहा है । इस समस्या के समाधान के लिये बिजुकर विभाग ने फार्म-31 की व्यवस्था की तथा उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए फार्म 31 की जांच-कित कामज पर जारी करने की व्यवस्था की है । ये फार्म केवल पंजीकृत व्यक्तियों को दिये जाते हैं । इस सन्दर्भ में कहीं नामों से पंजीयन कराने की प्रवृत्ति विकसित होने लगी जिसके लिए सरकार ने पंजीयन व्यवस्था को कठोर बनाने के लिए कदम उठाये हैं । तड़क परिवहन के माध्यम से आयातित माल पर करापर्यय की एक अन्य विधि भी प्रचलित है, कौ-कोई ट्रक दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा पर जाता है और यह घोषणा करता है कि माल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि बिहार या किसी अन्य प्रदेश के लिए ले जाया जा रहा है और उन्हें उत्तर-प्रदेश के अन्दर ले गुजरने की अनुमति दी जाए, उस पर बिजुकर विभाग का कोई अधिकार नहीं बनता और उत्तर-प्रदेश से निकलने हेतु उन्हें "ट्रान्जिट पास" (फार्म-34) दिया जाता है, लेकिन अनेक ट्रान्जिटपोटर इस ट्रान्जिट पास का दुरुपयोग करके माल को उत्तर प्रदेश के अन्दर ही उतार देते हैं और इस प्रकार समस्त माल बिजुकर विभाग के अभिज्ञों से छुट जाता है ।

वर्तमान में आयातित माल पर अत्यधिक कर-अपर्यय रेल के माध्यम से आयातित माल के द्वारा होता है । यद्यपि रेलवे से माल आयात करने वाले आयातकर्ता का यह दावित्व है कि वह बिजुकर कार्यालय में जाकर उसकी सूचना दे । मगर अधिकांश व्यापारी अपने नाम से माल न मंगाकर अस्तित्वहीन व्यक्ति के नाम से माल मंगाते हैं और उस पर बिजुकर का भुगतान नहीं करते तथा उसे छातों में भी नहीं निकालते । यह भी उल्लेखनीय है कि बिजुकर अधिकारी सूचना मिलने पर भी रेलवे स्टेशन पर ऐसे अनाधिकृत माल को अभिज्ञहीन नहीं कर सकते । परिणामस्वरूप विभाग

के अधिकारी को रेलवे स्टेशन के बाहर इन्तज़ार करना पड़ता है। इतने बचने के लिए व्यापारी या तो माल को रात्रि में निकालते हैं या रेले रास्ते से ले जाते हैं जहाँ विभाग के अधिकारी नहीं होते हैं। यदि ज्यादा ज़रूरी दिखाने देता है तो माल छुड़वाने के लिए उसे अन्य स्टेशन के लिए "रि-बुक" कर दिया जाता है। कुछ आयातकर्ता कर ले बचने के लिए बड़े रेलवे स्टेशनों के स्थान पर छोटे स्टेशनों पर माल मंगाते हैं। रेलवे द्वारा किज़ीकर-बॉक्स की एक विधि यह भी है कि कुछ लोग सामान की बुकिंग न कराके अपने साथ ले जाते हैं, जिसका रेलवे में अभिलेख नहीं होता। कुछ लोगों ने तो इस तरह सामान लाना ही अपना धंधा बना लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार रेल द्वारा माल मंगाने से 100 करोड़ रुपये वार्षिक का करापवर्ष हो रहा है।³⁶

जहाँ तक राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से माल के आयात का प्रश्न है, निगम ने अपनी यात्री बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के सामान की बुकिंग प्रारम्भ कर दी है और इसके पूरक काउन्टर भी खोलें गये हैं, लेकिन फिर भी कुछ कन्डक्टरों द्वारा यात्रीरहित व्यापारिक माल त्वर्य बसों में लाद लिया जाता है। यद्यपि निगम द्वारा यात्रीरहित सामान को न ले जाने के बड़े निर्देश दिये हैं और इन निर्देशों का उल्लंघन न हो, इसके लिए गहन जाँच भी निगम द्वारा कराई जा रही है, किन्तु फिर भी यह अनुभव किया गया है कि कन्डक्टरों की उक्त विधि-प्रतिकूल कार्य पूर्ण रूप से बन्द नहीं हुआ है, जिससे किज़ीकर राजस्व की हानि हो रही है।

आयातित माल के अतिरिक्त उत्पादन प्रक्रिया में भी ब्याप्त कर-बॉक्स किया जाता है। इसके लिए उत्पादन क्रिया में सम्मिलित व्यापारी क्रय और विक्रय के सभी व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाते हैं और अधिकांश दस्तावेजों में छिछोरा-छिछोरा के सम्बन्ध में हुम्मीकेट लाते रहे जाते हैं। जिन वस्तुओं पर राज्य स्तरीय कर की दरें अन्तराज्यीय किज़ीकर की दरों से अधिक है, वहाँ कभी अन्तराज्यीय किज़ी द्वारा करापवर्ष का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिये

36. प्रीयासत्य, वेदप्रतः : दैनिक राजपत्र, 21 मई, 1986.

तरतों, लाहा एवं दूजा के तेल निमाता यदि उत्तर प्रदेश में तेल बेचते हैं तो उन पर 4 प्रतिशत कर लगता है और अन्तराज्यीय व्यापार के दौरान विक्रय पर एक प्रतिशत कर लगता है। अतः कुछ व्यापारी वास्तव में उत्तर प्रदेश के अन्दर बिजुी करके अन्तराज्यीय क्रीं बिजुी दिखाते हैं जिससे करापर्वण होता है। इसी प्रकार गन्ना क्रेतर्त द्वारा बड़ी मात्रा में शुद्ध एवं कांड प्राप्त के आदतियों के माध्यम से अन्तराज्यीय व्यापार के दौरान बेची जाती है, किन्तु ऐसे मात को क्रेतर व्यापारी प्रान्त बाहर आदत पर बिजुी दिखाकर कर मुक्ति से लेते हैं। अनेक तस्थानों द्वारा अपने कार-जाने में बने हुए मात को दिल्ली व अन्य स्थानों पर अपने डिपो को चालान करना दिखाया जाता है और उती मात को अन्य नगरों में बिजुी के लिए भेजकर करापर्वण किया जाता है। बहुत से व्यापारी मात का विक्रय करते समय जितने का मात बेचते हैं, उतने कम मूल्य का बीचक या बिल बनाकर भी करापर्वण करते हैं। प्रान्त में उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये तर्कों से यह भी स्पष्ट होता है कि अनेक शीत भंडारण गृहों में क्रीं नामों में मात रखे जाने के कारण भी करापर्वण होता है।

अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि बिजुीकर में करापर्वण की महत्वपूर्ण और गम्भीर समस्या है। यद्यपि राज्य सरकार ने अपनी औपचारिक ध्येयों और प्रयातों के रूप में करापर्वण रोकने के लिए अनेक कदम उठाये हैं, लेकिन उनका प्रभाव काफी नगण्य रहा है। यद्यपि करापर्वण के विरोध से यह दिखाई देता है कि इस तथे के लिए व्यापारी दोषी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिजुीकर प्रशासन में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार भी इसके लिए कम उत्तरदायी नहीं है। करापर्वण कितना भी कम क्यों न हो। यदि कर प्रशासक ईमानदार, निष्ठावान, सुयोग्य और सुदृढ़ हों तो करापर्वण को एक बड़ी सीमा तक नियन्त्रित किया जा सकता है। करापर्वण को नियन्त्रित करने के लिए व्यापक जनसम्यर्क और जन चेतना कार्यक्रमों से व्यापारी वर्ग में ईमानदारी की भावना को विकसित करने का प्रयात करना चाहिए वहाँ दूसरी ओर कर प्रावधानों को सरल और एक रूप बनाने के साथ ही कर प्रशासन को सुपुशिक्षित और प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। करापर्वण के मायों में

दोषी व्यापारी पर ही दण्ड का प्रावधान नहीं होना चाहिए, वरन् किसी विभाग के उन अधिकारियों के विरुद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही की व्यवस्था होनी चाहिए जिनकी गिथिता, उदासीनता, अयोग्यता तथा भ्रष्टाचार के कारण करा-पर्वजन होता है। अन्ततोगत्वा करापर्वजन की समस्या राष्ट्रीय स्तर परारिक्त समस्या से सम्बन्धित है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक वातावरण और व्यवस्था के लिए प्रयास करना होगा। प्रान्तीय स्तर पर करापर्वजन की उन विधियों को सरलता से रोक जा सकता है, जो कर प्रावधानों की अपर्याप्तता, जटिलता अथवा व्यावसायिक भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं।

2. प्रपत्र 31 का दुरुपयोग :

विगत कुछ वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यवहार के लिए प्रयुक्त प्रपत्र 31 तथा सी-फार्मों के लोने तथा नष्ट होने की संख्या में वृद्धि अवृत्तावृत्ति रूप से वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश किसी कर आयुक्त द्वारा जून, 1985 में जारी किये गये परिपत्र में भी इस सम्बन्ध में विन्यास व्यवस्था की गई है, क्योंकि लोने हुए अथवा नष्ट हुए दिखाये जाने वाले प्रपत्रों के दुरुपयोग से राजस्व की भारी हानि की सम्भावना करी रहती है। व्यवहारिक दृष्टि से यह माना जा सकता है कि फार्मों का लोने या नष्ट होना अतम्भ नहीं है लेकिन ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिससे द्वारा जानबूझकर लोने अथवा नष्ट हुए प्रपत्रों को प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सके। इस तन्द्भ में ऐसे करदाताओं के गत 5 वर्षों में लोने अथवा नष्ट हुए प्रपत्र-31 तथा सी-फार्म का विवरण तैयार किया जाना चाहिए और जिन व्यापारियों के फार्मों के लोने की पुनरावृत्ति हुई हो या पुनरावृत्ति न हुई हो लेकिन एक बार में ही भारी संख्या में प्रपत्र लोने या नष्ट प्रदर्शित किये गये हों। उनसे भविष्य में ऐसे प्रपत्रों के जारी करने के लिए प्रतिभूति के रूप में समुचित धनराशि की बैंक गारन्टी प्राप्त की जा कर ताकि भविष्य में इन प्रपत्रों के दुरुपयोग का पता लगने पर राजस्व की हानि को रोक जा सके।

प्रपत्र 31 के प्रयोग के सम्बन्ध में एक समस्या यह भी रही है कि कदापि आयुक्त किसी करदाता द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि कम

कर योग्य जाती वस्तुओं के आयात के लिए फार्म पर अलग से उक्त वस्तु के नाम की मोहर लगायी जायेगी। इन वस्तुओं में बालू, कोयला, मिट्टी, पथर इत्यादि को शामिल किया गया है, लेकिन सम्बन्धित अधिकारियों की कार्य शिथिलता के कारण यह पाया गया है कि या तो फार्म पर इस तरह की मोहर लगायी नहीं जाती या इन सभी वस्तुओं की एक सामान्य मोहर लगा दी जाती है। इससे व्यापारी इन पुपत्रों के आधार पर अन्य वस्तुओं को आयात करके राजस्व को हानि पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं अतः विभागीय स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि पुपत्र 31 पर वस्तुओं के नाम की मोहर उचित प्रकार से लगाई जाए।

3. पुपत्र "ती" का दुरुपयोग

यह पाया गया है कि उत्तर-प्रदेश के विभिन्न करदाताओं द्वारा पुपत्र-ती के विरुद्ध भारी धनराशियों का "अन्तर्देशीय विक्रय" अन्य राज्यों को प्रदर्शित करके केन्द्रीय बिजुलीकर अधिनियम, 1956 की धारा 8(1)(क) के अन्तर्गत बिजुलीकर की रियायती दर का दावा किया जाता है। किसी विपरीत तथ्य के अभाव में विभाग द्वारा सामान्यतः उपर्युक्त दावा स्वीकार भी कर लिया जाता है, इससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि होती है। वास्तविकता यह है कि अभी तक पुपत्र ती के तत्थापन की कोई व्यवस्था नहीं है और इस कारण पुपत्र ती के आवरण में करारपूर्वक की सम्भावना रहती है। अतः पुपत्र-ती के आवरण में करारपूर्वक की सम्भावना के प्रकाश में इन पुपत्रों के आधार पर व्यवहारों के तत्थापन कराने को उचित व्यवस्था प्रारम्भ की जानी चाहिए। यह उल्लेखनीय है इस दृष्टि से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने "अन्तर्देशीय सूचना तत्थापन प्रकोष्ठ" बनाया है।

4. त्रुटि कार्य में शिथिलता

बिजुलीकर विभाग में करदाताओं की पत्रावलिओं के त्रुटि करने का प्रावधान है, लेकिन उच्चाधिकारियों³⁷ का यह अनुभव है कि सामान्यतः इस कार्य में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आवश्यक रुचि नहीं ली जाती और अधिकांश कार्य

37. आयुक्त बिजुलीकर उत्तर प्रदेश : महत्वपूर्ण आदेश एवं परिपत्रों की हेन्डबुक, 1985 वित्तीय मैगज़ीन अप्रैल-जून, पृष्ठ 4.

में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आवश्यक स्थिति नहीं की जाती और अधिकतर कार्य लिपिकों पर ही पूरी तरह छोड़ दिया जाता है। यह भी पाया गया है कि स्कूटनी में जो कमी निकलती है, अनेक परिस्थितियों में उनके उचित समाधान करने पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रभाव यह होता है कि एक ओर स्कूटनी के नाम पर कर्मचारी व अधिकारी अपना काफी समय लगा हुआ दिखाते हैं, लेकिन दूसरी ओर स्कूटनी का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न स्तरों पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों में स्कूटनी कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जाये और स्वयं निरीक्षण एवं भ्रमण करके यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाये कि स्कूटनी कार्य उचित रूप में और उचित समय में पूरा किया जाता है तथा स्कूटनी में पाये जाने वाली कमियों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।

5. वहीं जातों को निर्धारित अवधि के बाट भी रोके रक्ता

उत्तर प्रदेश विद्युत् अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि विद्युत् अधिकारियों द्वारा अभिमुहीत वही जातों की जाच के पश्चात् उन्हें 90 दिन के अन्दर व्यापारी को वापिस कर दिया जाये, लेकिन उच्च प्रशासन का यह अनुभव है³⁸ कि अधिकारियों द्वारा अभिमुहीत मामलों में 90 दिन से अधिक समय बढ़वाना एक सामान्य प्रक्रिया बन गयी है। ऐसा करने से व्यापारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने में क्लिम्ब होने के साथ-साथ व्यापारी को कभी स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य जुटाने का भी समय मिल जाता है। कर-निर्धारण कार्यवाही और अप्रैण्ड कार्यवाही में क्लिम्ब होने पर कभी-कभी व्यापारी व्यापार बन्द कर नायता भी हो जाते हैं। अतः कर जल्दी भी सम्पन्न नहीं रह जाती है, जिससे राजस्व की हानि होती है।

इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि हिताव-किताव अभिमुहीत

38. पूर्वोद्धृत, 1985, तृतीय मैग्रात 1 जुलाई-सितम्बर, पृष्ठ 35.

होने पर 90 दिन के अन्दर जचि कार्यवाही पूर्ण कर हिताब-किताब लौटाये जाने के हर सम्भव प्रयास होने चाहिए। यदि अपरिहार्य कारणों से हिताब-किताब 90 दिन के बाद लौटना आवश्यक समझा जाये, तो उपायुक्त किछीकर से कारणों का उल्लेख करते हुए समय बढ़ाये जाने का अनुरोध किया जाये। उपायुक्त शा० तथा उपायुक्त वि० अनु० शा० को भी यह चाहिए कि केवल आवश्यक मामलों में ही समय बढ़ाने सम्बन्धी आदेश जारी करें। तद्व्यतिरिक्त उपायुक्त शा० भी अपने निरीक्षणों के समय इस मामले को अवगत जचि करें।

6. जिलास्तरीय अधिकारियों की मासिक बैठकों में अनुपस्थित होना

आर्थिक अपराधों एवं करारपर्वक को रोकने हेतु जनपदों में अपर जिलाधिकारी वि० एवं शा० की अध्यक्षता में वन, मोरचनकर, आपूर्ति, किछीकर, आगकारी, उद्योग एवं परिवहन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की मासिक बैठकों का आयोजन की व्यवस्था है। उपायुक्त किछीकर द्वारा प्रकाशित टैन्डबुक³⁹ के अन्वये से स्पष्ट है कि किछी कर विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी जिला जिला सूचना के बैठक में अनुपस्थित रहते हैं और अपने विभाग से सम्बन्धित सूचार्य भी उपलब्ध नहीं कराते हैं। इस तथ्य में सम्बन्धित अधिकारियों को यह सुनिश्चित आदेश दिये जाने चाहिये कि वे अगला उनके प्रतिनिधि आवश्यक तथ्यों एवं सूचनाओं सहित मीटिंग में भाग लें।

7. काये किछीकर राशि में निरन्तर वृद्धि

प्रगतनिक दृष्टिकोण से यह चिन्ता का विषय है कि किछीकर धनराशि के अवशेषों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 1 अप्रैल, 1976 को किछीकर अवशेष की धनराशि 67.12 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 31 मार्च, 1981 को 194.07 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 1985 को 358.44 करोड़ रुपये हो गयी। यह उल्लेखनीय है कि किछीकर अवशेष की राशि में निरपेक्ष रूप से ही वृद्धि नहीं हो रही वरन् प्रगत्या-त्मक किछीकर संग्रह में हर अवशेष के प्रतिष्ठान में भी वृद्धि हुई है। यह प्रतिष्ठान तन्

39. पूर्वोक्त, 1985 द्वितीय त्रैमासिक अग्रिम-वृत्ति, पृष्ठ 108.

1976-77 में 6.6 प्रतिशत था तथा जो तब 1984-85 में 9.2 प्रतिशत हो गया।⁴⁰

अतः यह आवश्यक है कि बिजलीकर अवसंधों को तत्परता से वसूल किया जाये। बकाया वसूली तथा तंतुगत जांच के मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाये, जिसमें तंतुगत जांच के पुराने व बड़े मामलों को शीघ्रता के साथ निपटाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। सम्बन्धित अधिकारियों को तंतुगत जांच के मामलों की समीक्षा करके यह देखा चाहिए कि सभी मामलों में अपेक्षित कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक सम्पादित हो रही है। प्रदेश के जो बड़े बकायेदार हैं उनसे वसूली के प्रभावी प्रयास किये जाने चाहिए।

व्यवसायिक समस्याएँ

व्यवहारिक दृष्टि से बिजलीकर प्रशासन की कमियाँ और भ्रष्ट रीतियों से व्यापारी वर्ग को अनेकानेक कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हीं के कारण बिजलीकर उन्मूलन जैसे विषय को व्यापक स्तर से प्रचलित होने का अवसर मिलता है। व्यापारी वर्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में बिजलीकर की प्रमुख समस्याओं को निम्न प्रकार रखा जा सकता है :

1. निराधार सर्वेक्षणों से व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न

व्यक्तिगत द्वेष अथवा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण बिजली कर विभाग में प्रतिस्पर्धी या विरोधी व्यापारी के प्रति करासर्पक की शिकायतें प्रेषित की जाती हैं। अतः निराधार सर्वेक्षण करने पर यदि कोई विचरित तथ्य न पाया जाये तो व्यापारी का उत्पीड़न तो होता ही है, साथ ही बिजलीकर विभाग की छवि भी धूमिल होती है। अतः इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी व्यापारी के विरुद्ध करासर्पक की शिकायत प्राप्त होने पर विशेष अनुसन्धान शाखा के अधिकारियों को व्यापार रत्न का सर्वेक्षण न करके पहले अन्य तरीकों से प्राप्त

40. आयुक्त बिजलीकर उत्तर प्रदेश। त्रैमासिकीय अनुभाग। : बिजलीकर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85, लखनऊ, पृष्ठ 37.

शिकायत अध्या सूचना की सत्यता की जाँच करनी चाहिए तथा ऐसी जाँच के परिणामस्वरूप यदि वे शिकायत अध्या सूचना को पृथक् दृष्टि से तही पाते हैं तथा अगुतर जाँच हेतु सर्वेक्षण आवश्यक समझे, तभी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यदि किसी सर्वेक्षण में व्यापारी के विरुद्ध कोई तथ्य नहीं पाया जाता है तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की व्यवस्था होनी चाहिए।

2. जाँच चौकी के शिष्ट अधिकारियों की पाटों के निस्तारण की प्रक्रिया में भिन्नता

जिम्मीकर की चोरी को रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की तही सूचार्य सञ्चालित करने के लिये विभिन्न स्थानों पर जाँच चौकियों की स्थापना की गई है। यदि जाँच करते समय कुछ दुर्घटना पायी जाती हैं तो मान को विस्तृत पड़ताल के लिये रोक लिया जाता है। इस सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि किसी एक शिष्ट द्वारा अभिगृहीत किये गये मान से सम्बन्धित पाटों के निस्तारण की अलग-अलग प्रक्रिया जाँच-चौकी अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही है। किन्हीं जाँच चौकियों (के पोस्टों) पर ऐसा हो रहा है कि प्रत्येक शिष्ट अधिकारी द्वारा अपनी शिष्ट के दौरान अभिगृहीत मामलों से सम्बन्धित पत्रावलिओं एवं फंजी - 5 त्वर्य अपने पास रखते हुए उसका निस्तारण त्वर्य अपनी ही शिष्ट के कार्यालय के दौरान किया जाता है तथा किन्हीं के पोस्टों पर सभी शिष्ट अधिकारियों द्वारा अभिगृहीत मान से सम्बन्धित केवल एक फंजी-5 ही रखी गई है जिसके आधार पर मामलों का निस्तारण किसी भी शिष्ट में कार्यरत अधिकारियों द्वारा कर दिया जाता है। जहाँ शिष्ट अधिकारियों द्वारा त्वर्य अपनी इच्छा में ही मामलों का निस्तारण किया जाता है, वहाँ ऐसी समस्या हो जाती है कि शिष्ट अधिकारी के उपस्थित न होने पर अध्या शिष्ट के रैल्ट पर जाने के दो-तीन दिन तक रोके गये/अभिगृहीत मामलों पर कोई कार्यवाही अन्य शिष्ट के अधिकारी द्वारा किया जाना सम्भव नहीं हो पाता जिससे सम्बन्धित द्रान्तपोटी/व्यापारियों को कठिनाई होती है। यह भी देखा गया है कि शिष्ट अधिकारियों द्वारा रोके गये/अभिगृहीत मामलों से सम्बन्धित कागजात/जानकारी दूसरे शिष्ट के अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किये जाते, जिससे मान का निस्तारण उचित ढंग से किया जाना सम्भव नहीं हो पाता जिसके फलस्वरूप राजस्व की हानि होने की सम्भावना बनी रहती है।

सकलता बनाये रखने के उद्देश्य से तभी सिस्ट्र अधिकारियों द्वारा डिटेन्शन/अधिग्रहण से सम्बन्धित मामलों की प्रविष्टि एक पोस्ट पर रखी जाने वाली एक ही पंजी-5 में की जानी चाहिए तथा सिस्ट्र वार अन-अन पंजी-5 नहीं रखी जानी चाहिए। प्रत्येक सिस्ट्र की समाप्ति पर पंजी-5 अनुवर्ती सिस्ट्र अधिकारी को हस्तान्तरित करते हुये, इसका उल्लेख अपनी सिस्ट्र के दौरान रोके गये/अभिगृहीत मामलों से सम्बन्धित अभिलेख व विवरण रजिस्टर के अनुसार अपनी सिस्ट्र के अधिकारी को हस्तान्तरित किया जाना चाहिए। पंजी-5 में अंकित ऐसे मामलों में जिनका निस्तारण अपनी सिस्ट्र के दौरान कर दिया गया है, उनके सम्बन्ध में पंजी-5 में प्रविष्टि कराना, सिस्ट्र समाप्ति पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए जितने जितनी सिस्ट्र के दौरान अनिस्तारित मामलों की तदी जानकारी उपलब्ध हो सके। जितनी भी दिशा में एक ही सिस्ट्र के अधिकारी द्वारा यह करने का अवसर नहीं मिला चाहिए कि उनके पूर्व के जितनी सिस्ट्र द्वारा ऐसे मामलों के निस्तारण का कोई उल्लेख पंजी-5 में नहीं किया गया है या उसके सम्बन्धित पत्रावली उनके पास किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं हैं। यह उत्तरदायित्व कार्यरत सिस्ट्र अधिकारी का ही होना चाहिए कि उनके पूर्व में कार्यरत अधिकारी द्वारा पंजी-5 की प्रविष्टि का ^{उपलब्ध} ~~हस्ताक्षर~~ कर लिया गया है अथवा अनिस्तारित मामलों की पत्रावली प्राप्त करा दी गई है।

3. अभिगृहीत मान के विरुद्ध अपील की कार्यवाही निर्धारित अवधि में नहीं

व्यापारियों की ओर से एक शिकायत यह भी रही है कि जांच चौकियों और तत्काल इन इकाइयों द्वारा पंजीकृत व्यापारियों के मामलों में जहाँ विभिन्न कारणों से मान अभिगृहीत करते हुए जमानत वसूल की जाती है, उनके विरुद्ध अपील की कार्यवाही सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं की जाती है। अपील की कार्यवाही उचित समय में न किये जाने के कारण जहाँ एक ओर ईमानदार व्यापारियों से वसूल की गई जमानत का समायोजन उनके द्वारा देयकर में नहीं किया जाता है, वहीं कुरासवक व्यापारियों के विरुद्ध अपील आरोपित न किये जाने के कारण ऐसी जमानत की धराशायी व विवरण पत्रों में देयकर

कर दिये जाने पर भी उन्हें मंजूर किया जाता है कि वह जमानती धराराशि जमा कर दें तथा अगले माह में देयकर में समायोजित कर दें। यहाँ यह समझना होगा कि अनावश्यक अथवा अव्याप्त कारणों से माल रोकना तथा जमानत वसूलना राजस्व हित में नहीं रहता और साथ ही व्यापारी का उत्पादन भी होता है तथा बिजुली विभाग की छवि धूमिल होती है। अतः यदि यह सिद्ध हो जाये कि किसी बिजुली कर अधिकारी द्वारा बिना कारण माल रोक जाता है, व्यापारी की शिकायत पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की व्यवस्था होनी चाहिए।

6. कर समायोजन में कठिनाई :

व्यापारियों द्वारा यह शिकायत की जाती है कि उत्तर प्रदेश बिजुली अधिनियम की धारा 29-बी के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि यदि केन्द्रीय बिजुली अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत उल्लिखित वस्तुओं पर प्रान्तीय कर लग गया है और उसी वस्तु की अन्तःप्रान्तीय बिजुली की जाती है तो जो प्रान्तीय कर लगाया है, उसके बराबर धराराशि अन्तःप्रान्तीय बिजुली करने वाले को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जायेगी, लेकिन अनेक दशाओं में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह कार्यवाही नहीं की जा रही है।

7. अतिरिक्त बिजुली कर का अनुचित एवं अनावश्यक भार

व्यापारियों द्वारा यह समस्या भी रखी गयी है कि उत्तर प्रदेश में बिजुली कर की दरें ही काफी ऊँची हैं और उस पर भी अतिरिक्त बिजुली कर का प्रावधान करके व्यापारियों एवं सामान्य जनता पर बिजुली कर का अनुचित एवं अनावश्यक भार डाला जा रहा है। अतिरिक्त बिजुली कर की व्यवस्थाओं और दरों में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। वर्तमान में दत्त नाथ स्वयं वार्षिक से अधिक टर्नओवर पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त बिजुली कर का प्रावधान है। इससे कर की बटवटा बढ़ती है और व्यापारी अपना टर्नओवर घटाकर दिखाने के लिये प्रेरित होते हैं। जब केन्द्रीय सरकार ने आयकर पर तराबार्ज समाप्त कर दिया है तो राज्य सरकार को बिजुली कर पर अतिरिक्त बिजुली कर की व्यवस्था को भी समाप्त कर देना चाहिये।

8. स्वतः कर निर्धारण योजना का तही प्रयोग नहीं

छोटे व्यापारियों की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए 1 जनवरी, 1978 से स्वतः कर निर्धारण योजना लागू की गयी है। इसके अन्तर्गत छोटे करदाताओं को विक्रीकर कार्यालय नहीं बुलाये जाने की व्यवस्था है, लेकिन छोटे व्यापारियों की यह आम शिकायत है कि इस योजना का पूर्णतः पालन न करने के कारण उनको निरर्थक कठिनाई उठानी पड़ती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि तन् 1984-85 में 36230 व्यापारी स्वतः कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत अभिलेख पर रहे। 43026 वाट निस्तारणार्थ थे जिनमें से 10913 वाटों का निस्तारण किया गया और अन्त में 32113 वाट शेष रहे।⁴¹ इस प्रकार तन् 1984-85 में स्वतः कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत योग्य मामलों में से केवल एक चौथाई मामलों को ही निस्तारित किया जा सका। इस प्रकार योजना की प्रभावशीलता एवं व्यापारियों की दृष्टि से सरलता एवं लाभ-दायकता में कमी आती है। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि स्वतः कर निर्धारण योजना में निस्तारणार्थ सभी मामलों को यथा-सम्भव उती वर्ध निष्ठा दिया जाये।

9. विक्रीकर अधिकरण की स्थापना का विशेष लाभ न होना

विक्रीकर अधिकरण की स्थापना का ध्येय यह था कि यह स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा, लेकिन वास्तव में इससे जो आशाएँ की गईं थी, वह सब निरर्थक सिद्ध हुई है। सामान्यतः विक्रीकर अधिकरण के सदस्य के रूप में विक्रीकर उपायुक्तों को नियुक्त किया जाता रहा है, जो सदस्य अधिकरण बनने के पश्चात् भी अपने को आयुक्त विक्रीकर के अधीन समझते हैं और कार्य में स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता नहीं रह पाती। यह भी उल्लेखनीय है कि पूरे उत्तर प्रदेश में विक्रीकर अधिकरण के सदस्य के अनेक स्थान खाली पड़े हैं।

41. आयुक्त विक्री कर उत्तर प्रदेश (सांख्यिकीय अनुभाग) : विक्रीकर विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन, 1984-85, सऊअ, पृष्ठ 6.

10. पंजीकरण सम्बन्धी समस्याएँ

व्यापारियों का यह आरोप है कि उत्तर-प्रदेश के बिज़ीकर विभाग में पंजी-
कन कराने एवं फर्म के बदलने की प्रक्रिया भी काफी जटिल है, जैसे यदि एक फर्म पंजीकन
चाहती हैं तो अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार आवेदन के 90 दिन के अन्दर पंजी-
कन मिल जाना चाहिए, किन्तु व्यवहार में इससे अधिक समय लग जाता है। पंजीकृत
फर्म यदि अपना ताइटेदार बदलना चाहती है या नया ताइटेदार बनाना चाहती है, तो
उन्हें नये तिरे से सभी क्रियाएँ दुबारा करनी पड़ती है, जबकि अन्य राज्यों में यही
कार्य मात्र एक पत्र से हो जाता है।

11. बिज़ी कर की ऊँची दरें

व्यापारियों की ओर से इस दृष्टि से भी नज़्मीर चिन्ता प्रकट की जाती
रही है कि प्रदेश में बिज़ीकर की दरें निकटवर्ती केन्द्रशासित क्षेत्र दिल्ली और अन्य
राज्यों से ऊँची हैं जितने राज्य के व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण
के लिए उत्तर प्रदेश में डकरोटी पर 15 प्रतिशत बिज़ीकर है, लेकिन दिल्ली और
हरियाणा में इस पर कोई कर नहीं है। इसके कारण राज्य में की डकरोटी अन्य
राज्यों के लिए ख़ूबी तिह होती है जबकि अन्य क्षेत्रों में से डकरोटी के चोरी-छिपे
आयात को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में मालों पर बिज़ीकर
की दर 8 प्रतिशत है, जबकि मध्यप्रदेश में 4 प्रतिशत और दिल्ली में 3 प्रतिशत है।
इसी तरह की परिस्थिति अनेक वस्तुओं के सम्बन्ध में है और इसे निकटवर्ती क्षेत्रों के
साथ समान दर ही बनाकर हल किया जा सकता है। यह भी ध्यान रहे कि कर
की अधिक दरों से केवल व्यापार और उद्योग पर ही विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता,
वरन् कराव्यय की भी अनावश्यक प्रोत्साहन मिलता है।

12. अतिरिक्त कर प्रावधानों एवं दरों की घोषणा

व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं की ओर से बिज़ी कर व्यवस्था के तन्दर्भ में
यह आलोचना भी की जाती रही है कि सरकार समय-समय पर आकस्मिक रूप से
बिज़ी कर प्रावधानों एवं दरों में घोषणा करती रहती है जितने एक ओर तभी संबंधित

वर्गों को उचित जानकारी नहीं मिल पाती वहाँ दूतरी और कर निर्धारण में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। उदाहरणार्थ यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में कर की दरों में परिवर्तन कर दिया जाए तो व्यापारी और बिजलीकर अधिकारी दोनों के लिये यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कर परिवर्तन से पहले और बाद की बिजली की जलग-जलग गणना की जाये। इसी प्रकार यदि व्यापारियों के पंजीयन नम्बर परिवर्तित कर दिये जायें तो व्यापारी की सभी मुद्रित स्टेगरी बेकार हो जाती है। यह ठीक है कि परिवर्तन और संशोधन स्वाभाविक व्यवस्थाएँ हैं लेकिन यदि यह ध्यान रखा जाए कि जो भी परिवर्तन किये जायें वे समुचित रूप से राज्य सरकार के वार्षिक बजट में रखे जायें और उनके सम्बन्ध में प्रान्तीय स्तर के समाचार पत्रों में विस्तृत विज्ञापितियाँ प्रकाशित कराके अधिकारियों, अधिकताओं और व्यापारियों को विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए।

अन्य समस्याएँ

इस वर्ष में उन समस्याओं को रखा गया है जो या तो बिजलीकर प्रशासन या व्यापारी दोनों वर्गों की समस्याएँ हों अथवा आर्थिक विचारकों की दृष्टि से कर प्रावधान और क्रियान्वयन की सामान्य समस्याएँ हों। इनमें से कुछ समस्याएँ इस प्रकार हैं :

1. तांत्रिकीय अड़ियों में व्यापक भिन्नताएँ

यह आश्चर्य का विषय है कि बिजलीकर आगम जैसे महत्वपूर्ण और वित्तीय तथ्य के बारे में अड़ियों में व्यापक भिन्नताएँ मिलती हैं, जिससे तथ्यों के उचित विश्लेषण में कठिनाई आती है। केन्द्रीय स्तर पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया क्वांटिन तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित तथ्यों में ही अन्तर नहीं मिलता, वरन् एक ही राज्य में विभिन्न जिलों द्वारा प्रकाशित तथ्यों में भी अन्तर मिलता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में बिजली कर विभाग के अतिरिक्त महालेखाकार के कार्यालय में भी बिजली कर तथ्य एकत्र किये जाते हैं, लेकिन इनमें काफी अन्तर रहता है। इसकी पुष्टि मई, 1985 में उत्तर प्रदेश के अपर आयुक्त बिजलीकर द्वारा बिजली

कर अधिकारियों को भेजे गये परिपत्र में की गई है। इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि अधिकारियों की भिन्नताओं के कारणों का पता लगाकर उन्हें हल किया जाए और एक स्व-अच्छे सक्रित और प्रकाशित हों।

2. जांच चौकियों पर उचित व्यवस्था का अभाव

यद्यपि उत्तर प्रदेश में सन् 1986 के प्रारम्भ में बिजौर के क्षेत्र में 86 जांच चौकियाँ स्थापित थी, लेकिन अधिकांश जांच चौकियों पर समुचित व्यवस्था का अभाव, अभिगृहीत माल को रखने के लिए उपयुक्त गेह या गोदाम की अनुपलब्धता, वाहनों के भौतिक स्थापन के लिए माल को उतारने एवं चढ़ाने के लिए प्लेटफार्म का न होना, रात्रि के समय प्रकाश की समुचित व्यवस्था न होना, अभिलेखों को सुरक्षित रखने की पूर्ण व्यवस्था न होना तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पृथक विभ्राम रक्षा का न होना इत्यादि उल्लेखनीय है। साथ ही कहीं-कहीं बिजौर बैरियर ऐसे स्थानों पर स्थापित हैं, जहाँ पर घनी जंगल आबादी है, जिसके परिणामस्वरूप सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और दुर्घटनाएँ होती रहती हैं तथा नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन व्यवस्थाओं एवं अभावों से जांच-चौकियों की कार्य प्रभावशीलता में कमी आती है। अतः इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

3. अधिकारियों का निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुँचना

अधिवक्ता तर्जों की ओर से यह शिकायत निरन्तर की रही है कि बिजौर कार्यालयों में अधिकांश अधिकारी निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुँचते और समय से पहले कार्यालय छोड़ देते हैं। इससे व्यापारियों को असुविधा होती है एवं उनका समय अनावश्यक रूप से नष्ट होता है। साथ ही विभाग के कार्य में भी बाधा होती है। इस सम्बन्ध में उपायुक्तों को अपने अधिकारियों पर पर्याप्त नियन्त्रण रखना चाहिए और समय-समय पर बिना पूर्व सूचना के आकस्मिक निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिये कि अधिकारी समय पर कार्यालय पर उपस्थित रहें।

4. द्रांतपोर्टरों को कर निर्धारण के समय पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं

उत्तर प्रदेश बिजलीकरण अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत द्रांतपोर्टरों के विरुद्ध काफी अधिक संख्या में कर निर्धारण कार्यवाही की जाती है। इनमें से अधिकांश केस एक पक्षीय स्तर में पारित कर दिये जाते हैं। सामान्यतः समय कम रहने और अन्य कई कारणों से द्रांतपोर्टरों को अपने पक्ष में तथ्य प्रस्तुत करने और विभागीय अभिलेखों पर उपलब्ध सूचना का सत्यापन अपने अभिलेखों से करके उत्तर देने का समुचित अवसर ही नहीं मिलता। अतः एकपक्षीय स्तर से पारित किये जाने वाले केसों में द्रांतपोर्टरों को एक और अवसर देना चाहिए तथा अधिकारियों को एकपक्षीय आदेशों को पुनः जाँचकर द्रांतपोर्टरों को समुचित अवसर देने के बाद कार्यवाही करनी चाहिए।

5. ड्रांविट पास की समस्या

उत्तर प्रदेश बिजलीकरण अधिनियम की धारा 28 बी के अन्तर्गत एक प्रान्त के दूसरे प्रान्त को ले जाये जा रहे माल के सम्बन्ध में प्रवेश जाँच-चौकी से ड्रांविट पास प्राप्त करना आवश्यक है। यह फार्म बिजलीकरण विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है लेकिन आयातक अथवा द्रांतपोर्टर इसे मुद्रित कराकर घ भरकर प्रवेश जाँच चौकी के अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह फार्म बहुत ही पतले व छोटे कागज पर मुद्रित होते हैं और असाधारण फार्म-34 से सम्बन्धित कर-निर्धारण घाटों का निस्तारण होने तक इनके नष्ट और क्षतिग्रस्त हो जाने की सम्भावना रहती है। साथ ही बिजलीकरण कार्यालय की टिप्पणी आदि के लिये इसमें कोई स्थान नहीं रहता। इसके लिये उचित किस्म तथा उचित आकार के कागज पर मुद्रित फार्म-34 पर ही ड्रांविट पास जारी किया जाना चाहिए और एक तिहाई भाग में फार्म-34 का प्रारूप मुद्रित होना चाहिए और एक तिहाई भाग कार्यालय के प्रयोग के लिये जारी छोड़ा जाना चाहिए।

6. पृथक स्तरीय अपीलों में कमी

यदि सन् 1976-77 से उत्तर प्रदेश में दायर पृथक अपीलों की संख्या।
तालिका संख्या 5.81 का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि इनकी

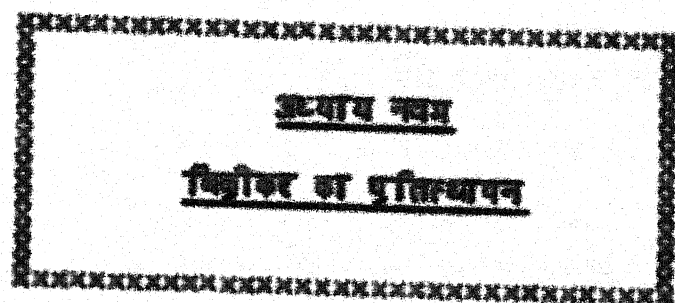
तंबा में निरन्तर कमी हो रही है और इस प्रकार पृथ्वी स्तर की अपीलों में प्रशासनिक भार कम हुआ है। यद्यपि इससे यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि बिजुीकर अधिकारियों द्वारा बिजुीकर का निर्धारण उचित प्रकार से किया जा रहा है, लेकिन यदि व्यापारियों के साथ गोपनीय रूप से किये गये साक्षात्कारों को देखा जाए तो यह स्पष्ट होगा कि यह अपीलें इसलिये कम हो रही हैं कि बिजुीकर का निर्धारण अधिकारिण परिस्थितियों में बिजुीकर अधिकारी और व्यापारी के मध्य तौटा तय करके किया जाता है और इस प्रकार व्यापारी में करापवर्जन की प्रवृत्ति और बिजुीकर अधिकारियों में सुविधा शुल्क के आधार पर कर-निर्धारण की प्रवृत्ति पनपी है। इससे राजस्व को उल्लेखनीय हानि हो रही है, जिसका समाधान बहुत कुछ कर-प्रशासन की सुदृढ़ता, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी पर निर्भर है।

7. बिजुीकर विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार

यद्यपि भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी भारत में सरकारी कार्यालयों तथा प्रतिष्ठानों की कार्यक्षेत्री का सामान्य अंग बन गये हैं, लेकिन व्यक्तियों का अन्दाज है कि बिजुीकर विभागों में पैसा भ्रष्टाचार परम सीमा पर है। बिजुीकर प्रशासन में भ्रष्टाचार के लिये कोई एक पक्ष नहीं चलू चारों पक्ष-बिजुीकर अधिकारी, व्यापारी, कर्मचारी एवं अधिष्ठाता किसी न किसी सीमा तक उत्तरदायी हैं। बिजुीकर विभाग की तुलना एक मन्दिर। मन्दिर। से की जा सकती है। अधिकारी उस मन्दिर का पुजारी है जो तिलक लगाये बैठा है, द्वितीय व्यापारी श्वाशु भक्त है एवं अधिष्ठाता उस मन्दिर के बाहर बैठा हुआ फूल बेचने वाला अथवा "पण्डा" है तथा कर्मचारी मन्दिर से बाहर निकलने पर बाइन में बैठे "फकीर" की स्थिति में है। तात्पर्य यह है कि चारों ही अपनी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, परन्तु सभी एक दूसरे पर दोषारोपण करते पाये जाते हैं। इस सम्प्रदाय की दृष्टि से यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ इस विभाग पर कड़ी निगरानी रखें और इस तथाकथित दुधाल माय के भ्रष्ट ग्वालियों। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्वेच्छाचारिता एवं भ्रष्टाचार पर समुचित अंकुश लगाये। इसके लिये इस विभाग के कार्य क्लार्कों पर मुस्तवर विभाग द्वारा ध्यान रखना चाहिये तथा बिजुी

कर अधिकारियों के वेतन तथा उनकी सम्पत्ति के मध्य सम्बन्धों की जाँच की व्यवस्था होनी चाहिये। जहाँ एक ओर सरकार ने बिज्जीकर घोररी को रोकने के लिए अनाधिकृत माल रेल से लाने की सूचना देने पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह अच्छा होगा कि उन व्यक्तियों को भी पुरस्कृत किया जाये जो बिज्जीकर के भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़वाने में शासन का सहयोग करें।

इस प्रकार बिज्जीकर की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि इस कर व्यवस्था में राष्ट्रीय नीति और राज्य स्तरीय प्रयास दोनों दृष्टिकोणों से अनेक समस्याएँ विद्यमान हैं। यद्यपि इस कर के प्रतिस्थापन पर विचार चल रहा है लेकिन राज्य सरकारों के दृष्टिकोणों के तन्द्भ में यह निकट भविष्य में सम्भव दिखाई नहीं देता, अतः मूल आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श बिज्जीकर अधिनियम निर्मित किया जाए और विभिन्न राज्य सरकारें उसे आधार मानकर राज्य की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार उनमें आवश्यक समायोजन कर लें और ऐसी स्थायी व्यवस्था विकसित की जाये जिससे इस कर में वांछनीय एकत्वता और समन्वय की दृष्टि से सभी राज्यों में और केन्द्रशासित क्षेत्रों के मध्य निरन्तर सहयोग और सम्पर्क बना रहें। राज्य स्तर पर प्रशासन की दृष्टि से जो कमियाँ समझी जा रही हैं, व्यापारियों द्वारा जो कठिनाइयाँ अनुभव की जा रही हैं और सामान्य दृष्टि से जो अभाव पाये जा रहे हैं, उन सभी दृष्टिकोणों में राज्य सरकार की विस्तृत तंगीधन और सुधार यथाशीघ्र करने होंगे, जिससे जन सामान्य और व्यापारियों को अनावश्यक कठिनाइयाँ और हतोत्साहनों के बिना कर से वांछनीय आगम प्राप्त होता रहे।



अध्याय-9

बिड़ीकर का प्रतिस्थापन

भारत में बिड़ीकर की विवेचना से स्पष्ट है कि यद्यपि वर्तमान क्रम में इसको प्रारम्भ हुए 50 वर्षों से हैं और इसे विस्तृत रूप से स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ही अपनाया गया है लेकिन पिछले दो दशकों में यह कर राज्य सरकारों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। जहाँ एक ओर राज्य सरकारें इस कर को अपनी वित्त व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयोग करके कर की उत्पादकता और लोचकता का पूर्ण लाभ उठा रही है, वहाँ दूसरी ओर व्यापारी वर्ग इस कर के प्रभाव और क्रियान्वयन के प्रति तत्काल आलोचक के रूप में उभरता रहा है और समय-समय पर इसके सरलीकरण, प्रतिस्थापन अथवा उन्मूलन की माँग होती रही है। यह उल्लेखनीय है कि यह माँग केवल व्यापारी वर्ग द्वारा ही नहीं की जाती रही बल्कि विभिन्न राजवित्त विशेषज्ञों द्वारा भी व्यापारियों की माँग का समर्थन किया जाता रहा है। अनेक राजनैतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्रों में इसका समर्थन करते रहे हैं और सरकार ने भी इस परियोजना में विचार करने और निर्णय लेने के लिए समय-समय पर विभिन्न समितियाँ गठित की हैं तथा राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया है।

भारत में बिड़ीकर के प्रतिस्थापन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक बैठक सन् 1956 में आयोजित की गई। बैठक में विशेषज्ञों ने यह निर्णय लिया कि तीन महत्वपूर्ण उत्पादों, तम्बाकू, वस्त्र और चीनी पर लगने वाले बिड़ीकर को समाप्त कर दिया जाए और इसके स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाकर राज्य सरकारों के आगम की हानि को पूरा किया जाए। इसे सन् 1957 से क्रियान्वित कर दिया गया। इसके पश्चात् केन्द्र और राज्य स्तर पर विभिन्न समितियों ने भी इस कर के विवेकीकरण और प्रतिस्थापन के विभिन्न पक्षों पर विचार करके अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किये। इनमें उत्तर प्रदेश कर जाँच आयोग 1974, बिड़ीकर जाँच समिति महाराष्ट्र 1975-76, केरल की वस्तु कर समिति 1976 तथा केन्द्र सरकार द्वारा श्री सलोकेश्वर की अध्यक्षता में गठित अग्रुपुष्प कर जाँच समिति के प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हैं। सन् 1977 में जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा

पत्र में यह आश्वासन दिया था कि वह बिजुलीकर को समाप्त करके उसके स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगायेगी, लेकिन वह अपने शासन काल में विभिन्न राज्य सरकारों को इसके लिए तैयार न कर सकी। इसके पश्चात् केन्द्र में कांग्रेस (आई) के सत्तारूढ़ होने पर पुनः यह प्रश्न उठा कि बिजुलीकर को किस तरह प्रतिस्थापित किया जाए और इस सन्दर्भ में सितम्बर सन् 1980 में तथा फरवरी सन् 1981 में केन्द्र ने राज्य के मुख्यमन्त्रियों के सम्मेलन आयोजित किये। फरवरी 1981 के सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर केन्द्र सरकार ने बिजुलीकर के प्रतिस्थापन के सन्दर्भ में एक विशेष समिति का गठन किया जैसे "त्रिपाठी समिति" के नाम से जाना जाता है और इस समिति ने जनवरी 1983 में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की। 6 जनवरी सन् 1984 को नई दिल्ली में भारतीय व्यापार एवं उद्योग महासंघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने भी यह संकेत दिया था कि सरकार लगभग 40 वस्तुओं पर बिजुलीकर हटाकर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को लगाने के विचार का विमर्श एवं मूल्यांकन कर रही है। स्पष्ट है कि बिजुलीकर के प्रतिस्थापन का प्रश्न एक महत्वपूर्ण राज्यकोषीय और राज-नैतिक प्रश्न के रूप में विचारित होता रहा है।

बिजुलीकर के उन्मूलन या प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष निकालने से पूर्व विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकारीय दृष्टिकोणों को भी ध्यान में रखा होगा इस सम्बन्ध में इकनामिक टाइम्स द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें राज्य सरकारों के दृष्टिकोण निम्न प्रकार थे :-

बिहार

बिहार राज्य में बिजुलीकर से आगम सन् 1951-52 में मात्र 4.09 करोड़ रुपये था जो सन् 1960-61 में 10.54 करोड़ रुपये, सन् 1970-71 में 38.14 करोड़ रुपये, सन् 1980-81 में 193.76 करोड़ रुपये और सन् 1984-85 में 336.60 करोड़ रुपये हो गया। स्पष्ट है कि राज्य सरकार को प्राप्त बिजुलीकर में तेजी से वृद्धि हुई है। अतः राज्य सरकार अपनी आय के इतने महत्वपूर्ण स्रोत को खोना नहीं चाहती।

राज्य सरकार का यह दृष्टिकोण भी रहा है कि यदि बिजुकर को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से ही प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इससे उत्पादन लागत में कोई कमी नहीं आयेगी और क्योंकि यह कर अखिल भारतीय आधार होगा। अतः उसमें राज्य के आय और उपभोग के दावे को विशेष रूप से ध्यान में न रखा जा सकेगा।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में से एक है जो बिजुकर से अपने कुल कर आय का एक महत्वपूर्ण भाग 160 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करता है। महाराष्ट्र सरकार के वित्त मन्त्रालय का स्पष्ट दृष्टिकोण यह रहा है कि जब तक केन्द्रीय सरकार कोई ऐसा विकल्प न निकाल ले जिससे राज्य सरकारों को बिजुकर से प्राप्त होने वाली राशि की क्षतिपूर्ति हो सके। राज्य सरकार बिजुकर समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकती।

पश्चिमी बंगाल

पश्चिमी बंगाल सरकार का दृष्टिकोण भी यह रहा है कि वह केन्द्र सरकार के हाथों में वित्तीय तांताधनों का अधिक केन्द्रीयकरण नहीं चाहती। अतः वह भी बिजुकर समाप्ति के विरोध में रही है। पश्चिमी बंगाल में तन् 1951-52 में बिजुकर से 6.70 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी जो तन् 1984-85 में 550 करोड़ रुपये हो गयी।

तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार बिजुकर को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से प्रतिस्थापित करने की पूर्ण विरोधी रही है। सरकार का मुख्य आधार यह रहा है कि ऐसा करने से राज्य सरकारों को उपलब्ध सीमित वित्तीय तांताधनों में क्षीणता आ जायेगी। सरकार का यह तर्क भी रहा है कि बिजुकर को प्रतिस्थापित करने से राज्य सरकार की राजकोषीय नीति की लोचता कम हो जायेगी। वास्तव में बिजुकर से पर्याप्त राजस्व ही प्राप्त नहीं होता वरन् यह कर व्यापार और उद्योगों को नियमित और नियन्त्रित करने के लिए महत्वपूर्ण राजकोषीय उपकरण के रूप में कार्य करता है।

तमिलनाडू सरकार का यह कहना भी रहा है कि कर दायें को विवेकपूर्ण आधार पर बनाने के लिए भी बिज्जीकर को समाप्त करने या प्रतिस्थापित करने पर भी विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य सरकार लगभग 150 वस्तुओं पर एक बिन्दु बिज्जीकर²²³ कर राज्य में बिज्जीकर को काफी विवेकपूर्ण बना चुकी है और व्यापारियों को होने वाले कटौतों को दूर करने के लिए कर निर्धारण और कर क्यूली की प्रक्रिया को काफी सरल कर चुकी है ।

गुजरात

गुजरात सरकार बिज्जीकर को पूरी तरह समाप्त करने के पक्ष में तो नहीं रही है लेकिन सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि यदि जनकल्याण की दृष्टि से कुछ जनोपयोगी एवं आवश्यक वस्तुओं पर बिज्जीकर समाप्त करने का प्रश्न हो तो विचार किया जा सकता है ।

जम्मू एवं काश्मीर

यद्यपि जम्मू-काश्मीर सरकार के कर आगम में बिज्जीकर का योगदान तुलनात्मक रूप से कम रहा है, लेकिन सरकार बिज्जीकर को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है।

उड़ीसा

उड़ीसा सरकार के क्वार्टों में लगभग हानि की स्थिति बनी रही है । अतः यह सरकार बिज्जीकर के स्रोत को खोना नहीं चाहती ।

राजस्थान

राजस्थान सरकार को सन् 1954-55 में मात्र 9 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी जो सन् 1984-85 में 278 करोड़ रुपये हो गयी । अतः इस सरकार का भी यह दृष्टिकोण रहा है कि जब तक इतने महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत के विकल्प के रूप में कोई अन्य व्यवहारिक साधन या स्रोत उपलब्ध नहीं होता । सरकार इस कर को छोड़ने के बारे में सोच नहीं सकती ।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार भी बिड़्डी कर समाप्ति के पक्ष में नहीं है क्योंकि इस कर से राज्य के कुल कर आगम का 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होता है। राज्य सरकार का यह तर्क भी है कि बिड़्डीकर में राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुकूल आवश्यक संशोधन और परिवर्तन किये जा सकते हैं जो वैकल्पिक उत्पादन शुल्क के लागू होने पर राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं होंगे।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार का यह स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि वह बिड़्डीकर की समाप्ति के लिये तैयार नहीं होगी। वह व्यापारियों को होने वाली कठिनाइयों को कम करते हुए तथा झूटागार की समस्या को हल करते हुए इस कर से राजस्व बढ़ाने का प्रयास करेगी।

बिड़्डीकर को प्रतिस्थापित करने के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है जब सितम्बर 1980 में केन्द्रीय वित्तमन्त्री ने राज्य के मुख्यमन्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था उसमें परिचामी अंशतः, केरल तथा जम्मू काश्मीर के मुख्यमन्त्रियों ने स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया था। यद्यपि कुछ व्यक्तियों का यह कहना है कि नैर काग्रेसी सरकारों ने इसका विरोध किया था, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। आठवें वित्त आयोग के तमाम प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्रीपति मिश्र ने कहा था, कि "चीनी, तूती वस्त्र और तम्बाकू पर बिड़्डीकर के प्रतिस्थापन से राज्य सरकारों को काफी हानि सहन करनी पड़ी है।" इसी आयोग के तमाम प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश सरकार ने यह उल्लेख किया था कि "तैदान्तिक रूप से बिड़्डीकर को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क द्वारा प्रतिस्थापित करके अनेक अच्छे तर्क हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें व्यवहारिक दृष्टि से अनेक समस्याएँ हैं।" अभी हाल में ही उत्तर क्षेत्रीय बिड़्डीकर एवं आबकारी कर परिषद का उद्घाटन करते हुए राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने कहा है कि "अधिकांश राज्यों में बिड़्डी कर राजस्व आय का एक प्रमुख एवं बड़ा स्रोत है। अतः इसकी समाप्ति सम्भव नहीं

लगती । राजस्थान जैसे प्रदेश में बिड़ोकर समाप्त करना कतई सम्भव नहीं है क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है । राज्यों के वित्तीय स्त्रोत सीमित है जबकि प्रगतनिक कर्षों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना जरूरी है । बिड़ोकर राजस्व की आय के बिना विकास कार्यों को तेजी देने में कठिनाई आती है । राज्य अपने स्तर पर आय के नये स्त्रोत ढूँढने के प्रयास करते हैं, परन्तु अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते । कुछ वस्तुओं पर बिड़ोकर को ब्याप उत्पादन शुल्क लगाने की प्रणाली के भी तुल्य अनुभव नहीं रहे हैं क्योंकि इससे राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व से वंचित रहना पड़ा है ।

प्रतिस्थापन का औचित्य

बिड़ोकर के प्रतिस्थापन के औचित्य के तन्द्भ में निम्न तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं :

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाये गये बिड़ोकर की कार्यप्रणाली एवं दरों में काफी विषमताएँ हैं । इससे विभिन्न क्षेत्रों में कर भार एवं अन्तराज्यीय व्यापार पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ते हैं जिनका समाधान करने के लिए किसी "सकल कर" से बिड़ोकर के प्रतिस्थापन की माँग की जाती है ।

विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्तरों पर बिड़ोकर लगने से ऐसे उत्पादकों के बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जो विभिन्न राज्यों से अपने लिए कच्चे माल एवं आवश्यक उपकरणों का क्रय करते हैं और विभिन्न राज्यों में अपने तैयार माल का विक्रय करते हैं । भिन्न-भिन्न राज्यों में बिड़ोकर की प्रक्रिया, नियम और प्रयोग किये जाने वाले कर्म विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनकी कठिनाई एवं जटिलता से बचने के लिए बिड़ोकर प्रतिस्थापन का प्रश्न उठाया जाता है ।

यदि बिड़ोकर को प्रतिस्थापित करके केन्द्रीय स्तर पर कर उत्पादन शुल्क लगाया जाए तो उसमें एक साथ उपभोक्ता, उत्पादक और विनिर्माताओं पर पड़ने वाले कर प्रभावों को ध्यान में रखा जा सकेगा और कर वसूली की लागत आदि भी कम हो जायेगी ।

व्यापारियों द्वारा और सामान्य जनता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि इस कर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है जो अप्रत्यक्ष रूप से काले धन को प्रोत्साहित करता है। यदि यह कर हटा दिया जाए तो व्यापारी वर्ग अपने लेखों को अधिक सही ढंग से रखने को प्रेरित होगा, जिससे जहाँ एक ओर काले धन को नियन्त्रित किया जा सकेगा, वहाँ दूसरी ओर प्रगतन में व्याप्त भ्रष्टाचार को पर्याप्त सीमा तक नियन्त्रित किया जा सकेगा।

बिड़्डीकर के कारण मध्य स्तरीय और कम पढ़े लिखे व्यापारियों को काफी कठिनाइयों और हतोत्साहनों का सामना करना पड़ता है जिसे एक मुक्त बिड़्डीकर या किसी अन्य विकल्प के द्वारा हल किया जा सकता है।

बिड़्डीकर के कारण क्रेता या उपभोक्ता पर अतिरिक्त भार पड़ता है जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है क्योंकि प्रायः बिड़्डीकर को बिल में जोड़कर दिखाया जाता है। इसके कारण वह अनेक बार पिछेता से बिना बिल के माल देने के आधार पर व्यवहार करता है, लेकिन यदि यही कर उत्पादन शुल्क या एक मुक्त कर के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो यह समस्या भी हल हो जायेगी क्योंकि इस परिस्थिति में बिड़्डी-बिल में अलग से कर जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा।

एक ही राज्य में विभिन्न व्यवसायों की वस्तुओं पर ही नहीं वरन् एक ही व्यवसाय की विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न दरों से बिड़्डीकर लगाया जाता है। इससे व्यापारियों को अपने विक्रय-विवरण और माल का स्टॉक रखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस दृष्टि से सरल या एक रूप व्यवस्था के द्वारा बिड़्डीकर के प्रतिस्थापन के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बिड़्डीकर की विभिन्नताओं, जटिलताओं, व्यवहारिक कठिनाइयों और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों के आधार पर बिड़्डीकर में तत्काल संशोधन, मितव्ययीकरण, सरलीकरण और प्रतिस्थापन की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है।

यदि देश में पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक वातावरण का अकालोक्त किया जाये, तो स्पष्ट होगा कि व्यापारी वर्ग, अनेक राजनीतिक दलों एवं आर्थिक विचारकों का यह दृष्टिकोण रहा है कि बिड़्डी कर काफी जटिल और अतुल्यविधायक कर है। इससे समाज में भ्रष्टाचार तेजी से फैल रहा है, कानूनी धन के सृजन को प्रोत्साहन मिला है और कर बोरी की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। अतः इस कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर इस दृष्टि से "अखिल भारतीय बिड़्डी कर उन्मूलन समिति" का गठन भी हुआ है। जिसने 12 नवम्बर, 1979 को देश के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री सन० संजीव रेड्डी को प्रस्तुत किये गये प्रत्येदन में यह कहा था, "अब बिना किसी तन्देह के यह अनुभव किया जाने लगा है कि बिड़्डीकर एक बहुत बड़ा सतरा है। यह कर अकेला ही बहुत बड़ा उत्तरदायी घटक है जो कानूनी धन के सृजन को प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति बिड़्डीकर से बचना चाहता है। वास्तव में बिड़्डीकर का प्रशासन इतना जटिल, विविधतापूर्ण, विस्तृत और परिवर्तनशील है कि उससे सम्बन्धित प्रत्येक वर्ग इसमें कठिनाइयाँ अनुभव करता है। कर के सरलीकरण के सभी प्रयासों के सभी प्रयासों से दर की जटिलता और बढ़ी है और एक ही विकल्प है कि बिड़्डीकर का उन्मूलन कर दिया जाए।"

प्रतिस्थापन का स्वल्प

बिड़्डीकर के स्थान पर किस प्रकार के कर का बदलाव किया जाय, यह एक विवादास्पद विषय रहा है। जब से बिड़्डीकर उन्मूलन का प्रश्न उठा है, इस पक्ष पर भी लगातार ध्यान दिया गया है कि यदि बिड़्डीकर जैसे महत्वपूर्ण एवं लोचपूर्ण कर को समाप्त किया जाए तो इसका विकल्प क्या होना। अर्थात् ऐसा कौन सा कर या व्यवस्था इसका प्रतिस्थापन कर सकती है जो इसकी कमियाँ एवं कठिनाइयों का समाधान कर सके, तथा राज्य सरकारों के लिए तत्तत् राजस्व का प्रोत्साहन कर सके। विकल्पों के सन्दर्भों में विभिन्न विचारकों और समितियों द्वारा जो दृष्टिकोण रखे गये हैं उनका समावेश करते हुए एक निष्कर्षात्मक प्रतिस्थापित स्वल्प रखने का प्रयास किया गया है।

111. अतिरिक्त उत्पादन शुल्क द्वारा प्रतिस्थापन

बिड़्डीकर के प्रतिस्थापन के रूप में सर्वाधिक समर्थित विकल्प अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की व्यवस्था है अर्थात् केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा लगाये जाने वाले सामान्य उत्पादन कर के अलावा अतिरिक्त उत्पादन शुल्क और लगाये, जो बिड़्डीकर के प्रतिस्थापन का कार्य करें। इसके समर्थन में दिये जाने वाले तर्क अधोलिखित हैं :-

1. यदि एक ही उत्पादन पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग कर लगाये जायें तो कर ढाँचा पूर्णतः विवेकपूर्ण नहीं बन सकता, लेकिन जब बिड़्डी कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क केन्द्रीय सरकार द्वारा ही लगाया जायेगा, जो कि उन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क भी लगाती है, तो उपभोग, उत्पादन और विनियोग इत्यादि सभी पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभावों को पूरी तरह ध्यान में रखा जा सकेगा।
2. ऐसा करने से कर संग्रहण की लागत में पर्याप्त कमी आयेगी।
3. विभिन्न राज्यों में बिड़्डीकर की विभिन्न दरों से व्यापारिक क्रियाओं का जो अनाधिक विषमता होता है, उसमें कमी आयेगी।
4. विभिन्न राज्यों से कच्चा माल प्राप्त करने और विभिन्न राज्यों में अपने उत्पादित माल को बेचने वाले उत्पादकों को विभिन्न राज्यों के पृथक-पृथक नियमों, प्रक्रियाओं और कार्यों में भिन्नताओं के कारण जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनका समाधान हो जायेगा।

दूसरी ओर राज्य सरकारों का यह कहना है कि कैंती भी योजना क्यों न तैयार कर ली जाये, बिड़्डीकर को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से प्रतिस्थापित करने पर उनके राजस्व में निश्चित रूप से कमी आयेगी और अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय में लगभग स्थिरता की स्थिति आ जायेगी जैसे कि सूती वस्त्र, तम्बाकू तथा चीनी पर लगे अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के आबंटन में आ गयी थी। ऐसा होने से राज्य सरकारों की आर्थिक स्वायत्तता में कमी आयेगी और केन्द्र पर निर्भरता बढ़ जायेगी। जब राज्य सरकार अपने प्रयासों से कर एकत्रित करती है तो व्ययों में

अधिक वित्तीय अनुशासन रहता है, लेकिन जब केन्द्र से आगम प्राप्त करना हो तो सामान्यतः राज्यों के व्यय में वित्तीय अनुशासन कम हो जाता है। बिजलीकर को पूर्णतः समाप्त कर उत्पादन शुल्क से प्रतिस्थापित करने में एक महत्वपूर्ण समस्या यह होगी कि अनेक वस्तुएँ बिना किसी औचित्य के करारोपण से बच जायेगी। उत्पादन शुल्क उत्पादन पर लगाया जाता है, लेकिन भारत में यह कर अधिकांशतः औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में लगाया जा रहा है। बिजलीकर की समाप्ति के पश्चात् कृषि क्षेत्र में भी उत्पादन शुल्क लगाने का प्रश्न उठेगा और कृषि उत्पादों से उत्पादन शुल्क एकत्रित करना अनार्थक और असम्भव हो जायेगा। इस सन्दर्भ में छोटे कृषकों को छूट देने की बात कही जा सकती है, लेकिन ऐसा होने पर बिजलीकर की राशि के अनुकूल उत्पादन शुल्क एकत्रित करने में कठिनाई आयेगी। इसके अतिरिक्त लघु और अंतर्गठित क्षेत्र में अनेक उत्पादन ऐसे हो रहे हैं जिन पर बिजली कर लग रहा है, लेकिन उत्पादन शुल्क व्यवस्था में प्रशासनिक कारणों से उन्हें छोड़ना पड़ेगा। यह सर्वविदित तथ्य है कि विद्यमान बिजलीकर व्यवस्था में राज्य सरकारों को अपने यहाँ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कर की दरों में समायोजन करने की दृष्टि से पर्याप्त लोच एवं स्वतन्त्रता उपलब्ध है, लेकिन उत्पादन शुल्क के प्रतिस्थापन से यह विशिष्ट लाभ समाप्त हो जायेगा और इसी आधार पर "त्रिपाठी समिति" के एक सदस्य प्रधान एच० प्रसाद ने बिजलीकर के प्रतिस्थापन के सन्दर्भ में अपनी अहमति प्रकट की थी।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जहाँ एक ओर राज्य सरकारों द्वारा बिजलीकर के प्रतिस्थापन का विरोध किया जाता रहा है, वहाँ दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पादन शुल्क द्वारा प्रतिस्थापन पर जोर देती रही है। जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में यही प्रस्ताव रखा था कि, "बिजलीकर के स्थान पर अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया जाए और उससे होने वाली प्राप्तियों में से राज्य सरकारों को यथोचित हिस्सा दे दिया जाए।" अखिल भारतीय बिजलीकर उन्मूलन समिति ने भी 12 नवम्बर, 1979 को राष्ट्रपति को दिये गये अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट माँग की थी कि बिजलीकर को समाप्त करके अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाए। कांग्रेस (आई) की सरकार पुनः स्थापित होने के बाद सितम्बर, 1980

में केन्द्रीय सरकार ने मुख्यमन्त्रियों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें बिड़लीकर समाप्ति के पुराने पर विचार किया गया। यद्यपि अधिकांश मुख्यमन्त्रियों ने इसका विरोध किया, लेकिन अन्त में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि कुछ राज्यों के मुख्यमन्त्रियों की एक समिति बनाई जाए जो अन्य बातों के अतिरिक्त उन वस्तुओं की सूची तैयार करे जिन पर बिड़लीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जा सके। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सन् 1957 में तीन वस्तुओं—सूती कपड़ा, तम्बाकू और चीनी पर बिड़लीकर समाप्त करके अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जा चुका था। अतः इस तथ्य पर भी जोर दिया जाता रहा है कि जब तीन वस्तुओं के सन्दर्भ में यह हो सकता है तो अन्य वस्तुओं के सन्दर्भ में भी यह व्यवस्था अपनाई जा सकती है। इसी परिपेक्ष्य में करवरी सन् 1981 में मुख्यमन्त्रियों की बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर एक विशेष समिति गठित की गई। इस समिति को यह अध्ययन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वनस्पति, औद्योगिक, तीमेन्ट, कागज व कागज गत्ता तथा पेट्रोलियम उत्पादन पर बिड़लीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की सम्भावना का अध्ययन किया जाए। यह भी देखा जाए कि इसके क्या वित्तीय परिणाम होंगे और राज्यों के वित्तीय हितों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1983 में भारत सरकार को प्रस्तुत की और सरकार ने 29 अप्रैल, 1983 को संसद के पटल पर रखा।¹ समिति की सिफारिशों का निष्कर्ष यह था कि वनस्पति, औद्योगिक, तीमेन्ट, कागज व कागज गत्ता तथा पेट्रोलियम उत्पादन इन पाँच वस्तुओं पर बिड़लीकर समाप्त कर दिया जाए और उनके स्थान पर सन् 1984-85 से अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाए। समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकारों के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के हितों की रक्षा की जाए। आगे समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सन् 1981-82 को आधार वर्ष मानकर इन पाँच वस्तुओं के सम्बन्ध में बिड़लीकर से प्राप्त राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही एक सेरा फार्मूला तैयार किया

1. The Economic Times, New Delhi, 30.4.83

जाना चाहिए। इसके साथ ही एक श्रेष्ठ परामर्श लेकर जिस राज्य को चाहिए, जो यथासंभव उन सभी तत्वों को ध्यान में रखे जो इन वस्तुओं के बिड़्डीकर राजस्व की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, जिससे अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के पश्चात् राज्यों की प्राप्तियों में उचित वृद्धि होती रहे। समिति ने यह सुझाव भी दिया कि एक ऐसी योजना विकसित की जाए, जिससे केन्द्र और राज्य सरकारें प्रस्तावित योजना के तत्त्व निरीक्षण और समीक्षा में सहभागी बनें रहे। समिति ने पाँच वस्तुओं को दो भागों में विभाजित किया। एक भाग में कागज व कागज गत्ता, वनस्पति और औषधियों को रखा गया, जिन पर अधिकांशतः स्वतन्त्र बाजार दशाएँ लागू होती हैं। दूसरे वर्ग में पेट्रोलियम उत्पादन तथा सीमेन्ट को रखा गया, जिनके बारे में अधिकांशतः स्वतन्त्र बाजार की स्थिति लागू नहीं होती। स्वतन्त्र बाजार की दशा वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में समिति ने यह तफ़्सील दी कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के रूप में वसूल की जाने वाली राशि की वार्षिक वृद्धि दर को सभी राज्यों के बिड़्डी कर राजस्व में भविष्य में होने वाली वार्षिक वृद्धि दर से सम्बन्धित किया जाए। पेट्रोलियम उत्पादन और सीमेन्ट के सम्बन्ध में समिति का यह विचार था कि इनके उपभोग मूल्य तथा संगृहित किये जाने वाले अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के मध्य अनुपातिक सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए अर्थात् वर्तमान में इन वस्तुओं से बिड़्डीकर राजस्व और इनके उपभोग मूल्य के मध्य प्रतिज्ञात सम्बन्धों की गणना की जाए और फिर यह व्यवस्था बनाई जाये कि भविष्य में इन वस्तुओं के उपभोग मूल्य और अतिरिक्त शुल्क की राशि के मध्य यह प्रतिज्ञात सम्बन्ध बना रहे।

समिति ने इन पाँच वस्तुओं से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की राशि के बँटवारे के बारे में अपना विचार रखा और कहा कि वित्त आयोग की तफ़्सीलों के आधार पर राज्यों को बाँटी जाने वाली राशि की वर्तमान पुणाली को जारी रखा जाये। प्रारम्भ के पाँच वर्षों में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से प्राप्त शुद्ध आय में से केन्द्र शासित क्षेत्रों का हिस्सा कम कर देने के पश्चात् राज्यों में इन-राशि का वितरण सन् 1979-80 से 1981-82 के तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य के बिड़्डी कर राजस्व के औसत अनुपात में किया जाना चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि

डा० प्रधान एवं पुताद ने इस सम्बन्ध में अपनी अतृप्तता प्रकट करते हुये लिखा है कि बिड़ोकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से मूल्यों में वृद्धि होगी और राज्य सरकारों को पिछले संग्रह के आधार पर बंटवारे में जो हिस्सा मिलेगा इससे असंगति हो सकती है क्योंकि भविष्य में विभिन्न राज्यों में इन वस्तुओं से सम्बन्धित विकास कार्यों को किस प्रकार ध्यान में रखा जायेगा ।

समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 2 नवम्बर तन् 1983 को मुख्यमन्त्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें कुछ मुख्यमन्त्रियों ने इस योजना को स्वीकार करने में अपनी अतृप्तता प्रकट की और कुछ मुख्यमन्त्रियों ने तैद्वान्तिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन कुल मिलाकर यह निर्णय लिया गया कि राज्य केन्द्र सम्बन्धों का पुनरीक्षण "सरकारिया आयोग" कर रहा है । अतः उत्तरी रिपोर्ट आने तक इस विकल्प के सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया न अपनाई जाए ।

इस प्रकार पाँच वस्तुओं के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की संतुष्टि पर वर्तमान में कोई निर्णय अवश्य स्थगित हो गया है, लेकिन सामान्य रूप से बिड़ोकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के प्रश्न पर सरकार निरन्तर विचार कर रही है । 6 जनवरी, 1984 को भारतीय व्यापार एवं उद्योग महासंघ द्वारा आयोजित "अखिल भारतीय व्यापारी संघ" का उद्घाटन करते हुए प्रधानमन्त्री श्री राजीव गान्धी ने कहा था कि केन्द्र सभी राज्यों को इस विकल्प के लिए तैयार कर रहा है कि बिड़ोकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाए और इस सम्बन्ध में मुख्यमन्त्रियों द्वारा दी गई 40 वस्तुओं की सूची पर विचार किया जा रहा है ।

करारोपण और संग्रह में समानता, मितव्ययिता और उत्पादकता के आधार पर अधिकांश पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि बिड़ोकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क एक अच्छा विकल्प है लेकिन राज्य सरकारों की आय में लोच और स्वायत्तता के तन्द्भ में राज्य सरकारों द्वारा इसका तीव्र विरोध किया जाता है ।

124 वार्षिक कर द्वारा प्रतिस्थापन

बिड़्डीकर व्यवस्था की विविध कठिनाइयों, को हल करने तथा राज्य सरकारों की वित्तीय स्वायत्तता पर अनुकूल प्रभाव पड़े इत तत्त्वबन्ध में विकल्प के रूप में यह सुझाव भी दिया जाता है कि बिड़्डीकर का प्रतिस्थापन एक सुमत वार्षिक कर से कर दिया जाये। इत दृष्टि से एक सुमत वार्षिक कर के अन्तर्गत व्यापारी को विस्तृत हिताव-किताब से मुक्ति मिलेगी। बिड़्डीकर की विभिन्न औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को पूरा करने से राहत होगी तथा व्यापारियों को अधिकारियों की ताना-शाही का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही इत प्रकार का कर माल बेचते समय बिल या बीजक में जोड़कर नहीं दिखाया जायेगा। इतसे उपभोक्ता को भी कर भार के प्रभाव की भावना से मुक्ति मिलेगी। यद्यपि अप्रत्याशित रूप से यह कर उपभोक्ता पर ही पड़ेगा। एक सुमत वार्षिक करके तन्द्भ में यह प्रश्न भी उठता है कि क्या सभी व्यापारियों से समान वार्षिक कर लिया जाए या इतमें भिन्नता रखी जाए। यदि समान वार्षिक कर लिया जाता है तो बड़े व्यापारियों को लाभ होगा तथा छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को कष्ट अनुभव होगा और यह करों में समता एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा। अतः बिड़्डीकर को एक सुमत समान वार्षिक कर से प्रतिस्थापित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

यदि व्यवहारिक दृष्टि से बिड़्डीकर को एक सुमत वार्षिक कर से प्रतिस्थापित करने पर कभी निर्णय लिया भी जाए तो इसके लिए बिड़्डी की विभिन्न श्रेणियाँ बनानी होगी और इन विभिन्न श्रेणियों के लिए एक सुमत वार्षिक कर की अलग-अलग राशियाँ निर्धारित करनी होगी। किसी श्रेणी में किसी भी व्यापारी को रखने की दृष्टि से कोई एक आधार वर्ष मानना होगा और एक आधार वर्ष से ठीक पिछले तीन या पाँच वर्षों की बिड़्डी के औसत के आधार पर यह निर्णय किया जा सकता है कि व्यापारी को किस बिड़्डी श्रेणी में रखा जाए। यद्यपि इत प्रतिस्थापन से ऐसे व्यापारियों के सामने समस्या उत्पन्न हो सकती है जिनके व्यापार या बिड़्डी में गिरावट की स्थिति उत्पन्न हो जाये। अन्यथा इत व्यवस्था से अधिकांश व्यापारियों को सुविधा एवं सरलता मिलेगी तथा सरकार का कर प्रशासन व्यय भी कम हो सकेगा। एक सुमत

वार्षिक कर के तन्द्भ में कर आधार के औचित्य की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि यह एक तरह का लाइसेन्स-सुल्क जैसा लगेगा और इसका जालू उत्पादन या बिक्री से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहेगा और सरकार भी मनमानी तरीके से एक मुक्त कर की राशि में चाहे जितना परिवर्तन कर सकती है। वस्तु विशेष के उत्पादन तथा उपभोग को प्रभावित करने की दृष्टि से भी एक मुक्त कर व्यवस्था में कोई प्रभावशीलता नहीं रह जाती। एक मुक्त वार्षिक कर के तर्जोहित रूप में अखिल भारतीय व्यापार संघ के उपाध्यक्ष श्री विशम्बर दयाल अग्रवाल ने यह सुझाव रखा है कि एक आधार वर्ष में या निश्चित आधार वर्षों में औसत रूप से जो बिक्री कर दिया हो उसमें प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से वृद्धि करते हुए बिक्रीकर से लिया जाए। बिक्रीकर की तरलता की दृष्टि से यह सुझाव औचित्यपूर्ण लग सकता है और इसमें इस बात की सुरक्षा भी है कि सरकार का राजस्व भी निरन्तर बढ़ता रहेगा, लेकिन मूल प्रश्न यह रह जाता है कि आधार वर्ष या वर्षों का निर्धारण ही गलत हो या भ्रष्ट रीतियों के आधार पर बहुत कम कर लिये गये हों, तो सरकार कब तक उस आधार पर होने वाली हानि को सहन करेगी। इसके साथ ही ऐसे व्यापारियों के लिए क्या समाधान होगा, जिनके व्यापार में गिरावट आ रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि बिक्रीकर वस्तु के मूल्य पर लगता है और वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर उच्चावचन होते रहते हैं। उनके प्रभावों को कैसे दूर किया जा सकेगा। वास्तव में बिक्रीकर के स्थान पर एक मुक्त वार्षिक कर का सुझाव तरलता के नाम पर ऐसा सुझाव है कि व्यक्ति से कपड़ों के पहनने की तरलता के नाम पर यह कहा जाए कि वह कोट, पैन्ट, टाई के स्थान पर एक गाऊन पहन ले। हमें बिक्रीकर का प्रतिस्थापन बिक्रीकर के उद्देश्यों, प्रभावों और औचित्यों के तन्द्भ में दूँदना होगा। केवल तरलता या सुविधा के नाम पर प्रतिस्थापन के किसी सुझाव को औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

13। मूल्य वृद्धि कर से प्रतिस्थापन

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में परम्परागत आवर्तन कर या बिक्री कर को प्रतिस्थापित करके मूल्य वृद्धि कर को अपनाया गया है। प्रारम्भ में तन् 1954

ते ही यह फ़्रान्स में बिड़ोकर के विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया था ।² इसकी विशेषताओं से प्रभावित होकर इस कर की ओर विशेष ध्यान दिया गया । तन् 1962 में "न्यूमार्क समिति" ने यह सुझाव दिया था कि यूरोपियन ताज़ा बाजार के सभी देशों में इस कर को अपना लिया जाना चाहिए³ और बाद में यूरोपीय आर्थिक समुदाय परिषद ने इस कर को सामान्य बिड़ोकर के विकल्प के रूप में स्वीकार करने के लिए सभी सम्बन्धित राज्यों को निर्देश दिये थे । जिसके आधार पर अधिकतर यूरोपीय राज्यों में तन् 1967 में इसे लागू किया गया । इसके परिणामस्वरूप इस प्रकार की कर व्यवस्था में सम्पूर्ण विश्व की दिलचस्पी पैदा हो गयी । यह व्यवस्था तन् 1968 में उराग्वे में तथा तन् 1970 में इस्वेडोर में लागू की गई । यह कर पुंजाली तन् 1972 में ब्रिटेन में भी शुरू हो गयी और विरोध के बावजूद तन् 1973 में अमेरिका में पुने हुए स्थानों पर इसे शुरू किया गया । भारत में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्गठन समिति (1968) ने फ़्रान्सीसी नमूने पर आधारित "वैट" के विस्तृत अध्ययन की सिफारिश की ताकि "अनूकूल" परिस्थितियों में उत्पादन शुल्क के ढाँचे को नया रूप देने के प्रश्न पर विचार किया जा सके ।⁴ श्री स्लोको डा की अध्यक्षता में गठित अप्रत्यक्ष कर जाँच समिति, 1976 ने भी विभिन्न देशों में मुख्य वृद्धि कर का विस्तृत अध्ययन करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की । इस आधार पर कुछ देशों में इसी इस कर द्वारा प्रतिस्थापित की गई कर व्यवस्था को दर्शाया गया है ।

2. Bhatia, H.L. , Public Finance 1983, p. 144.

3. अप्रत्यक्ष कर जाँच समिति प्रतिवेदन, 1978, भाग - II, पृष्ठ 282.

4. वन्त वे०सी०, राजस्व, पृष्ठ 593.

तालिका नं० 9-1

कुछ देशों द्वारा प्रतिस्थापित मूल्य वृद्धि कर⁵

देश का नाम	विविध वर्षों में	मूल्य वृद्धि कर द्वारा प्रतिस्थापितकर
अजेन्टाइना	1 जनवरी, 1975	बिड्डीकर
ऑस्ट्रिया	1 जनवरी, 1973	आवर्तन कर
बेल्जियम	1 जनवरी, 1971	क्रय कर
आयरलैण्ड	1 नवम्बर, 1972	आवर्तन कर
इटली	1 जनवरी, 1973	सामान्य विनियम कर
लक्समबर्ग	1 जनवरी, 1970	बहुस्तरीय आवर्तन कर
नीदरलैण्ड	1 जनवरी, 1969	बहुस्तरीय आवर्तन कर
पश्चिमी जर्मनी	1 जनवरी, 1968	बहुस्तरीय सकल आवर्तन कर

तालिका नं० 9.1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकांश देशों में विद्युय या आवर्तन कर को मूल्य वृद्धि कर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। भारतीय तन्द्भ में बिड्डीकर को मूल्य वृद्धि कर द्वारा स्थापित करने की सम्भाविकता का अध्ययन करने के लिए हम निम्न प्रश्नों का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे :

1. मूल्य वृद्धि कर क्या है ?
2. मूल्य वृद्धि कर से क्या लाभ और हानियाँ हैं ? तथा
3. इसके द्वारा बिड्डीकर को प्रतिस्थापित करने के कौन से पक्ष विचारणीय हैं ?

5. अप्रत्यक्ष कर बोध समिति प्रेसलेटन, जनवरी 1978 भाग 2।

पृष्ठ 709-710.

मूल्य वृद्धि कर क्या है ?

सामान्य भाषा में इसका अर्थ ऐसे कर से है जो किसी वस्तु या सेवा के व्यवहार में विभिन्न स्तरों पर होने वाली मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर जाँच समिति के अनुसार, "अपने विस्तृत रूप में मूल्य वृद्धि कर एक ऐसे कर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विभिन्न स्तर से मुक्त पदों या संस्थाओं को छोड़ कर वस्तुओं और सेवाओं के सभी विक्रेताओं द्वारा उनकी कर्म के मध्यम से वस्तु के मूल्य में की गई वृद्धि का चुकाया जाता है।⁶ इस आधार पर इसकी मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं :

1. यह एक बहुस्तरीय कर है जो उत्पादन और वितरण के सभी स्तरों पर लगाया जाता है ;
2. यह ^{पुनिर्वास} पुनीदा न होकर विस्तृत कर होता है।
3. इस कर की राशि ठीक ^{उत्पन्न} उत्पन्न राशि के बराबर होगी, जो अन्तिम खुदरा बिक्री पर मूल्य वृद्धि कर की दर से गणना करने पर आती है तथा
4. यह कर प्रत्येक आगत पर केवल एक बार ही लगता है।

यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश देशों में इस कर की गणना को सरल बनाने के लिए किसी व्यापारी कर्म द्वारा देयकर का हितान इस प्रकार लगाया जाता है - पहले उनकी कुल बिक्री पर लागू दर से कर लगाया जाता है और कर्म द्वारा आवश्यकता सामान की छरीट पर जो कर दिया जाता है उसे कुल बिक्री पर गणना किये गये कर में से घटा देते हैं।

गुण एवं दोष

अन्य कर व्यवस्थाओं की तुलना में इसके अनेक लाभ हैं, यह कर उत्पादन और

6. अप्रत्यक्ष कर जाँच आयोग प्रतिवेदन, जनवरी 1978 भाग 2। पृष्ठ 282.

वाणिज्यीकरण के प्रारम्भ के प्रति लक्ष्य रहता है। विदेशीकरण में प्रायः सम्भवतः संयोजन को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे आगत और कच्चे मालों पर चुकाये जाने वाले विदेशी कर से बचा जा सके। उदाहरणार्थ - यदि कोई कार बनाने वाली फैक्टरी, कार के विभिन्न पुर्जों, टायरों इत्यादि को स्वयं बना रही है तो ऐसी फर्म की तुलना में कम कर देना होगा, जो अन्य फर्मों से इन सामानों का क्रय कर रही है, लेकिन इसके कारण इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार यह अवस्था में ऐसी प्रारम्भों को ही विकसित होने का अवसर प्रदान करती है जो आर्थिक ^{अवस्था} आधारों पर उचित हो।

मुख्य वृद्धि कर के पक्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि इसके द्वारा करापवर्धन काफी कम हो जाता है। इसके दो कारण हैं, इस पद्धति में कर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, जिसके कारण करापवर्धन की प्रेरणा अधिक नहीं रहती; इस व्यवस्था में प्रत्येक फर्म अपने द्वारा क्रय किये गये सामानों पर चुकाये गये कर का पूर्ण विवरण रखने का प्रयास करती है और इस कारण यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि अन्य फर्मों द्वारा दिखाया गया विषय विवरण उचित या नहीं।

मुख्य वृद्धि कर पक्ष में यह भी कहा जाता है कि इसके अन्तर्गत प्रत्येक फर्म उत्पादन व्यवस्था में अधिकाधिक कुशलता लाकर उत्पादित लागत को कम करने का प्रयास करती है, क्योंकि लागत जितनी अधिक बढ़ जायेगी, मुख्य वृद्धि का अन्तर उतना ही अधिक हो जाने से कर भार अधिक हो जायेगा।

मुख्य वृद्धि कर किसी भी अन्तिम उत्पाद में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न आगतों पर केवल एक बार ही लगाया जाता है। अतः अन्तिम उत्पाद में पड़ने वाले कर भार को नियन्त्रित किया जा सकता है और इस कारण उस कर से आगतों पर चिन्तित कराधान के दोषों के बिना सामान्य कर के लाभ मिल जाते हैं।

मुख्य वृद्धि कर के अन्तर्गत किसी विशिष्ट उत्पाद के अन्तिम मुख्य पर कर का अनुपात समान रहता है और इस तथ्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उत्पादन के चरण कम हैं या अधिक और इस कारण उत्पादन में आवश्यक विवेकपूर्ण चरणों को बनाये रखे जा सकता है।

मूल्य वृद्धि कर द्वारा विट्टी कर में कर के संयोजी प्रभावों को नियन्त्रित किया जा सकता है अर्थात् इसमें कर के दोहरापन की सम्भावना नहीं रहती, क्योंकि उत्पादन और वितरण के प्रत्येक स्तर पर केवल उतनी राशि में कर लगता है, जो उस स्तर में मूल्यों में वृद्धि के रूप में गणना की गई है।

इस कर व्यवस्था में निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि किसी भी उत्पाद का निर्यात होने पर उसमें प्रयुक्त किये गये आगतों पर लगे करों की वापसी हो जाती है तथा उत्पादक विश्व बाजार में अपने उत्पादन में मूल्य को प्रतिस्पर्धी बनाये रखने में समर्थ रह सकता है। अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक विशेषज्ञ ने इसके महत्त्व की चर्चा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ^{अतः} ~~इससे~~ व्यवसायी को यह स्वतन्त्रता होती है कि वह अपनी लागत पर कर भार को कम करने के आधार को छोड़कर कुशलता के आधार पर उत्पादन के स्वरूप, उत्पत्ति के साधनों का समन्वय और उत्पादन की प्रक्रियाओं को अपना सके।⁷

अतः मूल्य वृद्धि कर को अपनाने पर कर की दरों में परिवर्तन करके पूर्वी प्रधान उद्योगों की तुलना में ग्राम प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, किसी तीव्र आगत को नियन्त्रित करने के लिए "अतिरिक्त गैर वापसी योग्य शुल्क" लगाया जा सकता है और कुछ विशेष उत्पादकों एवं उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कर से आवश्यक छूट भी दी जा सकती है।

मूल्य वृद्धि कर के लाभों की समीक्षा के पश्चात् उन तीमाओं का उल्लेख किया जा रहा है जो विकासशील देशों में इस कर के क्रियान्वयन में आ सकती है। यह व्यवस्था अत्यन्त जटिल है और इसके लिए जित्त तरह की कुशल और विस्तृत सरकारी मशीनरी की आवश्यकता होती है, वह सामान्यतः विकासशील देशों में नहीं मिलती। यह भी ध्यान रहे कि एक बिन्दु विट्टीकर की तुलना में इसको उत्पादन और वितरण

के विभिन्न स्तर पर लगाये जाने से पुशासन तन्त्र पर तुलनात्मक रूप से अधिक भार पड़ता है। वास्तव में इस पद्धति को उचित रूप में उन्हीं देशों में अपनाया जा सकता है जो आर्थिक और वित्तीय संरचना में विकसित हो चुके हैं और जहाँ व्यवसायियों द्वारा पूर्ण, विस्तृत और कुशल लेखे रखे जाते हैं। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ व्यवसाय में अनेकों छोटे-छोटे उद्योग और फर्म संलग्न हैं, वहाँ इसकी दृष्टि में आवश्यक लेखों का रखना कठिन और अवीला है। इसके समर्थन में यह बात कही जाती है कि ये अपने प्रभावों में काफी तटस्थ रहता है, लेकिन कोई भी सरकार हो, वह अपनी कर व्यवस्था से देश के उत्पादन, उपभोग और वितरण पर अनेक वांछनीय प्रभाव डालना चाहती है और यदि उस दृष्टि से इन समायोजनाओं को इसमें जोड़ा जाता है तो यह कर पद्धति जटिल और अनाकर्षक हो सकती है। भारत जैसी ^{जटिल वास्तविकता} अभावशील अव्यवस्था में इससे लाभ की भी आशा नहीं रह जाती है कि इससे उत्पादन लागत को कम करने का अवसर मिलता है। भारत में अधिकांश आवश्यक वस्तुओं में विक्रेता बाजार की स्थिति है जिसमें बढ़ते हुए मूल्यों पर भी मान आतानी से देया जा सकता है। संघीय देशों में इस कर की महत्वपूर्ण सीमा है क्योंकि यह अनुभव है कि इस कर को संघीय पुशासन की तुलना में एकात्मक शासन में आतानी से अपनाया जा सकता है। भारत जैसे देश में जहाँ केन्द्र और राज्य के मध्य करों का अधिकार विभक्त है। इसको पूर्ण रूप से अपनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि केन्द्रीय सरकार अप्रत्यक्ष कर की पूरी व्यवस्था को अपने हाथों में ले।

उक्त: विवेचना के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि तैदान्त्रिक रूप में यह अप्रत्यक्ष कराधान में यह एक महत्वपूर्ण सुधार है, लेकिन व्यवहारिक एवं पुशासनिक पक्षों से इसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं।

भारत में मूल्यवृद्धि कर द्वारा विक्रीकर के प्रतिस्थापन की सम्भाव्यता

मूल्यवृद्धि कर के उद्गम और विकास के इतिहास से स्पष्ट है कि अधिकांश देशों में इसे विक्रय कर के प्रतिस्थापन के रूप में अपनाया गया है, लेकिन भारतीय तन्त्र में अनेक समस्याएँ हैं - यहाँ के संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें संविधान के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों को कर के पृथक अधिकार मिले हुए हैं और यदि इसको पूर्ण रूप से अपनाया

गया तो राज्य सरकारों को बिड़ोकर के सम्बन्ध में जो स्वायत्तता प्राप्त है, वह समाप्त हो जायेगी, जिसके आधार पर इत कर ^{का} राजनैतिक विरोध होगा। इत कर व्यवस्था के लिए व्यापारियों द्वारा वित्तुत लेके रखने और अधिकारियों द्वारा उन्हें वित्तुत रूप में निरीक्षण करने की आवश्यकता होगी और उत तन्दर्भ में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। यहाँ यह भी समझना होगा कि यदि बिड़ोकर की भाँति राज्य सरकारों को मूल्य वृद्धि कर अपनाने की ^{स्वातन्त्रता} उपलब्ध कराई भी जाये तो उसमें एकलपता और सम्बन्ध की वही ^{समस्याएँ} आयेगी जो वर्तमान में बिड़ोकर में विद्यमान हैं।

इन्हीं सब परिवर्धनों में विचार करने के उपरान्त उपर्युक्त कर जाँच समिति ने यह सुझाव दिया था कि देश को प्रशासनिक और अन्य परिस्थितियों के तन्दर्भ में इत को अपनाने में आवश्यक सावधानी रखनी होगी और उत्पादन पूर्ण होने के उपरान्त की अवस्था में इत कर को अपनाना अभी व्यवहारिक नहीं हैं। समिति ने प्रयोगात्मक रूप में निर्माणी स्तर पर ^{समिति} रूप में इत कर को लगाने का सुझाव दिया था और इत तन्दर्भ में इत कर के लिए एक नया नाम "निर्माणी मूल्य वृद्धिकर" का सुझाव दिया था। स्पष्ट है कि समिति द्वारा किये गये वित्तुत विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष भविष्य में बिड़ोकर को इसके द्वारा या इसके किसी तंशोधित रूप से प्रतिस्थापित करने की सम्भावना नहीं है, लेकिन उत्पादन शुल्क ^{के} विवेकपूर्ण बनाने की दृष्टि से इतका प्रयोग किया जा सकता है और सन् 1986-87 के केन्द्रीय सरकार के बजट में इतको एक तंशोधित रूप में 'मोड वाट' के नाम से अपनाया गया है। यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों में बिड़ोकर प्रावधानों में कट्टे मात के प्रयोग के सम्बन्ध में कुछ छूटें दी गई हैं। इतकी धारणा के तन्दर्भ में इन छूटों को अधिक एक रूप और तर्कसंगत बनाने का प्रयास अवश्य किया जा सकता है।

बिड़ोकर के प्रतिस्थापन के तन्दर्भ में पिछले एक दशक से प्रबल माँग की जाती रही है और उत पर सरकार तथा राजस्व विशेषज्ञों द्वारा गम्भीर चिन्तन भी किया जाता रहा है लेकिन केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय स्वायत्तता

के पुनर्गठन को लेकर इस प्रतिस्थापन के तन्दर्भ में कोई तर्कमान्य निर्णय नहीं हो पाया है। वास्तविकता यह है कि बिड़ोकर के प्रतिस्थापन के पुनर्गठन पर विस्तृत रूप से विचार करने और निर्णय लेने से पहले देश में अप्रत्याशित रूप से दायि की सम्पूर्ण व्यवस्था की समीक्षा करना होगी और उसमें सुधार करने तथा बिड़ोकर के प्रतिस्थापन के साथ सम्बन्ध करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक विशेषज्ञ समझ इस बात पर सहमत हैं कि यदि बिड़ोकर को समाप्त करके उत्पादन शुल्क के साथ उसे मिला दिया जाये और उत्पादन शुल्क की व्यवस्था को सुधार कर केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मूल्य वृद्धि कर अपनाया जाए तो प्रारम्भिक कुछ तीमाजों और कठिनाइयों के बाद कराधान की एक आदर्श पद्धति सिद्ध हो सकती है, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा निरन्तर अपनी स्वायत्तता को बनाये रखने के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में निम्न भविष्य में यह सम्भव नहीं है कि इस तरह की व्यवस्था हो सके। यद्यपि "सरकारिया आयोग" का प्रतिवेदन केन्द्र और राज्यों के मध्य सम्बन्धों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यही दिखाई पड़ता है कि राज्य सरकारें बिड़ोकर के पूर्ण प्रतिस्थापन के लिए किसी भी परिस्थिति में तैयार नहीं होंगी। यद्यपि कुछ समीक्षकों के आधार पर कुछ आवश्यक और देश भर में समान मूल्य पर बिकने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में त्रिपाठी समिती के सुझावों के आधार पर बिड़ोकर को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से प्रतिस्थापित सरलता से किया जा सकता है।

जहाँ तक बिड़ोकर को एक मुक्त वार्षिक कर या इसी तरह की संशोधित पद्धति से प्रतिस्थापित करने का पुनर्गठन है। उसका सरलता के आधार पर व्यवसायी वर्ग भी ही समर्थन करें लेकिन कर व्यवस्था की किसी तर्कपूर्ण पद्धति के आधार पर इसे वांछनीय नहीं कहा जा सकता है। मूल्य वृद्धि कर के प्रतिस्थापन का पुनर्गठन एक तकनीकी विशेषज्ञ का पुनर्गठन है। केन्द्रीय सरकार अपनी उत्पादन शुल्क व्यवस्था में कुछ संशोधित अवस्था में सन् 1986-87 के बजट में इसे अपना चुकी है। उसके अनुभवों के आधार पर कुछ समय पर्याप्त इस पर अधिक विस्तृत और उपयोगी विचार सम्भव हो सकता है।

निष्कर्ष यह है कि वर्तमान परिस्थितियों के तन्द्भ में विक्रीकर के जितनी निष्कर्ष पूर्ण अध्ययन में इतकी प्रतिस्थापन का प्रश्न नहीं, परन्तु इतमें यथासम्भव तरलता, सक्रियता, प्रशासकीय कुशलता तथा प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के पहलुओं पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है ।

-----: : 0 : :-----

अध्याय दशम

सहाय सर्व निष्कर्ष

तुड़ाव एवं निष्कर्ष

बिछोड़ कर व्यवस्था से सम्बन्धित विविध पक्षों की समीक्षात्मक अध्ययन के उपरान्त इसे राज्य की मुख्य आगम के प्रोत्त के रूप में अधिक उपयोगी बनाने हेतु एवं राज्य में इसकी भूमिका को और प्रभावशाली बनाने के लिये निम्नलिखित तुड़ाव अनुकरणीय हैं। वर्तमान समय में बिछोड़ कर की जो भी समस्याएँ हैं वे मुख्यतः बिछोड़ कर प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं की भिन्नता के कारण हैं। अतः इस कर को राष्ट्रीय स्तर पर यथासम्भव एक रूप, सरल और विवेकपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिये। बिछोड़ कर की दरें, कर-मुक्त की सीमा तथा कच्चे माल और आगतों पर छूटों से सम्बन्धित प्रावधानों में एकत्वता अत्यन्त आवश्यक है। इस दृष्टि से सभी राज्यों में राज्य स्तर पर "विशिष्ट अध्ययन समितियाँ" गठित की जायें, जो अपने-अपने राज्यों में बिछोड़ कर व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा कर सकें और अन्य राज्यों के समक्ष बनाने की दृष्टि से आवश्यक तुड़ाव प्रस्तुत कर सकें। इसके पश्चात् राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्तरीय स्तर पर अध्ययन समिति गठित की जाये, जो राज्य स्तरीय समितियों के अध्ययन, विश्लेषण और तुड़ावों के तन्द्भ में बिछोड़ कर अधिनियम एवं नियमों का आदर्श प्रारूप तैयार कर सके और उसके आधार पर सभी राज्यों को यह निर्देश दिये जायें कि स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुस्य धोड़े - बहुत संशोधनों सहित अपने राज्य का नवीन बिछोड़ कर अधिनियम बनायें। यदि ऐसे निर्देश क देने के लिए केन्द्रीय स्तर पर संविधान में संशोधन के प्रावधान की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिये।

सोध कार्य में किये गये अध्ययन से अब स्पष्ट हो चुका है कि बिछोड़ कर का पूर्ण प्रतिस्थापन करने में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ होंगी अतः इस तन्द्भ में मुख्य धृष्टि कर विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इसे अपनाने में अब किम्ब नहीं करना ~~करना~~ चाहिये। दूसरी तरफ सम्पूर्ण राष्ट्र में समान मूल्य पर बिकने वाली आवश्यक उप-भोग्य वस्तुओं जैसे वनस्पति, औषधियाँ, तीमेन्ट, कागज व कागज गत्ता तथा पेट्रोलियम उत्पादन पर भिषाठी कमी के तुड़ावों के तन्द्भ में बिछोड़ कर को "अतिरिक्त

उत्पादन शुल्क से प्रतिस्थापित करना उचित रहेगा । इसके अतिरिक्त राज्यों की बिजुली कर व्यवस्थाओं को यथासम्भव समन्वय बनाये रखने की दृष्टि से यह उचित होगा कि एक स्थायी व्यवस्था के रूप में केन्द्रीय स्तर पर "बिजुली कर समन्वय परिषद्" का गठन किया जाये । जिसमें प्रत्येक राज्य के सर्वोच्च बिजुलीकर अधिकारियों को शामिल किया जाये और जिसकी वर्ष में एक या दो मीटिंग अनिवार्य हों, जिससे सभी राज्यों को बिजुलीकर से सम्बन्धित अनुभवों, पद्धतियों और समस्याओं का तामुहिक रूप से विश्लेषण करने और पारस्परिक विचार-विनिमय करने का अवसर प्राप्त हो सके ।

प्रायः सभी राज्यों में मोटर स्प्रिट पर बिजुलीकर, सामान्य बिजुलीकर के अतिरिक्त एक पृथक अधिनियम के अन्तर्गत लगाया जाता है । मोटर स्प्रिट के तन्दर्भ में पृथक बिजुलीकर अधिनियम होने का केवल ऐतिहासिक कारण है क्योंकि सर्वप्रथम इसी वस्तु पर मध्य प्रान्त और बरार में बिजुलीकर लगाया गया था । व्यवहारिकता की दृष्टि से पृथक रूप से केवल एक मद्द के लिए बिजुलीकर अधिनियम के होने का कोई औचित्य नहीं है । अतः मोटर स्प्रिट पर कर व्यवस्था को भी सामान्य बिजुलीकर व्यवस्था में ही मिला देना चाहिए ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की तरह ही राज्य सरकारों को भी दीर्घकालीन राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए और इस तन्दर्भ में आदर्श बिजुली कर अधिनियम की व्यवस्था लागू हो जाने के परचात कर की दर, कर मुक्ति की सीमा, करारोपित वस्तुओं की सूची इत्यादि में कम से कम पाँच वर्ष तक स्थायित्व रखना चाहिए और प्रत्येक पाँच वर्ष के परचात बिजुलीकर मुक्ति की सीमा को देश के मुख्य निर्देशांकों के अनुषात में समायोजित करना चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाये कि बिजुलीकर प्रावधानों में जो भी परिवर्तन किये जायें, वह राज्य सरकार के वार्षिक बजट में ही होने चाहिए । जिससे कर प्रशासन में सरलता रहे और व्यापारियों, अधिवक्ताओं तथा अधिकारियों को इसकी उचित जानकारी मिल सके । यह भी उचित है रहेगा कि सामान्य व्यापारियों की जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण तंगीधनों को राज्य एवं स्थानीय स्तर के समाचारपत्रों में भी प्रकाशित किया जाये ।

पिछले कुछ वर्षों में प्रायः अधिकांश राज्यों में बिजलीकर को लक्ष्य प्रधान बना दिया गया है अर्थात् राज्य सरकार द्वारा यह निश्चित कर दिया जाता है कि बिजलीकर राजस्व में कितनी वृद्धि करनी है जिसके कारण कर अधिकारी भी कर निर्धारण करते समय वास्तविक विक्रयों को नजर अन्दाज करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस सन्दर्भ में यह उचित होगा कि लक्ष्य निर्धारित न करके बिजली कर अधिकारी को अपने क्षेत्र में गत वर्ष में सक्रिय किये गये कर आगमन से अधिक राशि एकत्र करने पर कुछ पुरस्कार और प्रेरणाओं की योजनायें होनी चाहिए, लेकिन बिजलीकर अधिकारी इन प्रेरणाओं से प्रेरित होकर अनुचित स्व से कर बढ़ाने के प्रयास न करें। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी द्वारा किये गये अपील परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिए और इस दृष्टि से यह भी ध्यान रखना होगा कि कर-निर्धारण के एक वर्ष के अन्दर ही अपीलों का भी निपटारा हो जाना चाहिए। इसी के साथ बिजलीकर अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्पक्ष और ईमानदार बनाने की दृष्टि से यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि नियुक्ति के समय वे अपनी सम्पत्ति की घोषणा करें और पाँच वर्ष के पर्याप्त उनके या उनके परिवार के सदस्यों के नाम सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसमें अनुचित और अनावश्यक वृद्धि हो तो उससे सम्बन्धित व्यक्तियों से आवश्यक स्पष्टीकरण माँगे जाने चाहिए। बिजलीकर विभाग में तका दस्तों, बैंक पोस्टों और विशेष अनुसन्धान शाखा इत्यादि की विद्यमान व्यवस्था के अतिरिक्त विशेष चौकसी दल का गठन किया जाना चाहिए। यह विभाग सीधे बिजलीकर आयुक्त उधवा राज्य के सर्वोच्च बिजलीकर अधिकारी के नियन्त्रण में हो। इसे प्रत्यक्ष स्व से बिजलीकर जाँच के कार्यों में भाग लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन बिजलीकर अधिकारियों और व्यापारियों दोनों के सन्दर्भ में गोपनीय रिपोर्ट तैयार करने का कार्य दिया जाना चाहिए, जिसके आधार पर उच्च बिजलीकर प्रशासन सम्बन्धित अधिकारियों और व्यापारियों के विस्तृत आवश्यक कार्यवाही कर सके।

बिजलीकर की चोरी सामान्यता दूकों द्वारा मात्र होने के कारण होती है, इस प्रवृत्ति को नियन्त्रित करने के लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि ट्रान्सफॉर्मरों

को बिजुीकर विभाग से भी रजिस्ट्रेशन नम्बर लेना होगा और यदि किसी ट्रक या ट्रकों में बिना उचित तैकों के माल लाया जाये तो आवश्यक पैनल्टी प्रावधान के अतिरिक्त यह व्यवस्था भी होनी चाहिए कि सम्बन्धित ट्रक या ट्रकों की कम्पनी या फर्म भविष्य में कम से कम 6 माह तक माल लाने वाले जाने का कार्य न कर सके, लेकिन यह ध्यान रखा जाये कि ट्रान्स्पॉर्टरों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए और साथ ही मामले का निपटारा यथासम्भव अल्प अवधि में हो जाना चाहिए । राजस्व की दृष्टि से बिजुीकर की महत्वपूर्ण समस्या करापवंचन की है । यद्यपि करापवंचन प्रत्येक कर में होता है लेकिन ऐसा अनुभव है कि राज्य स्तरीय करों में सर्वाधिक करापवंचन बिजुीकर में होता है । यद्यपि सामान्यतः इसके लिए व्यापारी को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि बिजुीकर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए बिजुीकर अधिकारी वर्ग भी कम उत्तरदायी नहीं है । इस तन्दर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री बीर बहादुर सिंह ने स्वयं अपने कार्यकाल में स्वीकार किया है कि, "बिजुी कर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों तथा व्यापारियों की मिलीभगत से प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजुीकर की चोरी होती है ।" वास्तविकता यह है कि करापवंचक कितना भी कुशल क्यों न हो । यदि कर प्रशासक ईमानदार, निष्ठावान, सुयोग्य और सुदृढ़ हो तो इसे बड़ी सीमा तक नियन्त्रित किया जा सकता है । यद्यपि देश की सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार के तन्दर्भ में इस समस्या का पूर्ण निदान सम्भव नहीं है, तथापि सरकार और उच्च बिजुी कर अधिकारियों को इसके लिए द्वितीय प्रयासों और उपायों पर ध्यान देना आवश्यक है । जहाँ एक ओर व्यापारियों द्वारा अपनाये जाने वाले कर-वंचन के तरीकों पर कठोर नियन्त्रण की आवश्यकता है, वहाँ दूसरी ओर कर प्रावधानों को सरल और रक्ष्य बनाने के साथ ही कर प्रशासन को सुशिक्षित और प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए । करापवंचन के मामले में दोषी व्यापारियों पर ही दण्ड का प्रावधान नहीं होना चाहिए, वरन् बिजुीकर विभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही होनी चाहिए जिनकी मिलीभगत, उदासीनता, अयोग्यता

और शिक्षिता के कारण करापवंचन होता है। यह सन्तोष का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ आवश्यक कदम उठाये हैं। तन् 1985 में राज्य में बिजुलीकर विभाग के कुछ अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया और भ्रष्टाचार के आरोप में एक अधिकारी की सेवा समाप्त कर दी गयी। कुछ बिजुलीकर अधिकारी की पद-अवनति की गई और एक सहायक आयुक्त को चेतावनी दी गई। करापवंचन को नियन्त्रित करने के लिये छापे डालना और जांच करना बिजुलीकर प्रशासन का पूर्ण अधिकार है, लेकिन यदि किसी छापे में व्यापारी पर करापवंचन सिद्ध नहीं होता है या स्वतः कर निर्धारण में बिजुलीकर अधिकारी द्वारा आपत्ति लगाने के बाद भी तैकों में कोई झुटि या करापवंचन सिद्ध नहीं कर पाते तो यह व्यवस्था होनी चाहिए कि व्यापारी अपने वार्षिक बिजुलीकर के भुगतान के आधार पर अपनी मानहानि की क्षति-पूर्ति बिजुलीकर प्रशासन से करा लें। इससे अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने की प्रवृत्ति में कमी आयेगी। अन्तराज्यीय व्यवहारों में करापवंचन को नियन्त्रित करने की दृष्टि से यह उचित होगा कि व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुओं को छोड़कर अन्य सामानों को मँगाने की अनुमति केवल पंजीकृत व्यापारियों को होनी चाहिए। रेल या ट्रक परिवहन की बिल्टियों पर माल मँगाने व माल लाने वाले के नाम एवं पते के साथ ही उनके बिजुलीकर रजिस्ट्रेशन नम्बर का उल्लेख अनिवार्य होना चाहिए। सभी बैंक-पोस्टों पर कम्प्यूटर व्यवस्था होनी चाहिए, जिनमें बैंक पोस्टों से निकलने वाले ट्रकों के सामानों के बारे में पूर्ण विवरण फीड किया जा सके। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख बैंक पोस्टों पर कम्प्यूटर व्यवस्था प्रारम्भ की जा चुकी है। बैंक पोस्टों पर कम्प्यूटर के प्रयोग से फार्म-3 तथा फार्म-ती के दुरुपयोग को भी नियन्त्रित किया जा सकता है। रेलवे द्वारा मँगाये जाने वाले मालों पर करापवंचन रोकने के लिए वैधानिक रूप से बिजुलीकर अधिकारियों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे रेलवे पर लुटिंग या छुड़ाये जाने वाले माल की जांच कर सकें। कुछ प्रमुख वस्तुओं के सम्बन्ध में रेलवे बिल्टी के साथ व्यापारी का विस्तृत क्लि तालमेल करना भी अनिवार्य किया जा सकता है, जिसमें माल के क्रेता और विक्रेता व्यापारी तथा कर की राशि के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना हो। करापवंचन को नियन्त्रित करने के लिए व्यापक जन समर्थ और जन जागरण कार्यक्रमों से व्यापारी

वर्ग में ईमानदारी की भावना को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। वहाँ बिड़ोकर अधिकारियों में भी कुशल, ईमानदार, व्यवहारकुशल और कर्म बनने की भावना को विकसित करना होगा। बिड़ोकर के अपवर्णन को रोकने, कर के सम्बन्ध में व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने और व्यापारियों को कर व्यवस्था और उसके तन्द्भ में उचित जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से बिड़ोकर प्रशासन में जन सम्पर्क व्यवस्था को विकसित और सुदृढ़ करना चाहिए। जिला स्तर पर प्रथम से जन सम्पर्क अधिकारी की व्यवस्था होनी चाहिए और उसे बिड़ोकर के बारे में उचित जनमानस तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

करापवर्णन को नियन्त्रित करने, सम्पन्न कर निर्धारण करने तथा कर प्रशासन की शिथिलताओं का समाधान करने के लिये यह आवश्यक है कि बिड़ोकर प्रशासन को सुदृढ़ किया जाये। इस दृष्टि से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तैर्लक्षण एवं कर प्रावधानों के तन्द्भ में अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाये, सूचना पद्धति को सुधारा जाये, अनुसन्धान कार्य को प्रोत्साहित किया जाये, कर योग्य बिड़ो वाले व्यापारियों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा उच्च स्तरीय कर प्रशासन को सुगठित किया जाये।

बिड़ोकर विभाग के कार्यों के प्रति व्यापारियों में विश्वास की भावना और कर जमा करने में उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने के लिए यह भी आवश्यक है कि जहाँ बिड़ोकर की वसूलवासी कठोरता के साथ की जाये, वहाँ दूसरी ओर कर-निर्धारण या अपील के निर्णय के कारण व्यापारी को होने वाली राशि की वापसी व्यापारी द्वारा माँग किये बिना बिड़ोकर कार्यालय द्वारा व्यापारी को प्रेषित की जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के तन्द्भ में विभिन्न सुझाव

उत्तर प्रदेश में बिड़ोकर की दृष्टि से विभिन्न वर्गों को पाँच उपवर्गों में बाँटा गया है और इनमें से प्रथम एवं प्रथम वर्ग की वर्गों को कर के स्तर एवं कर

की दर की दृष्टि से क्रमाः 76 और 56 वर्गों में विभाजित किया गया है। तरलीकरण की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है कि वस्तुओं के वर्गों और कर की दर की विभिन्नताओं को यथासम्भव न्यूनतम किया जाये। इससे व्यवसायियों को लेबे रखने तथा अधिकारियों को कर की गणना करने में दोनों को ही सुविधा होगी तथा कर की जटिलता को न्यूनतम किया जा सकेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि चतुर्थ वर्ग की 76 वस्तुओं में भी 30 वस्तुओं पर 12 प्रतिशत या इससे अधिक की दर से कर है। व्यवहारिकता की दृष्टि से यह दर अधिक प्रतीत होती है। अतः इस वर्ग में कर की दर अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित रखनी चाहिए। पाँचवें वर्ग को केवल 3 वस्तुओं पर 8 प्रतिशत की दर से कर है, शेष पर 6 प्रतिशत या इससे कम की दर से कर है। अतः वर्गीकरण के औचित्य की दृष्टि से 8 प्रतिशत वाली तीन वस्तुओं पर भी कर की दर 6 प्रतिशत कर दी जानी चाहिए। यह भी उचित रहेगा कि सामान्य के उपभोग को कम मूल्य वाली वस्तुओं जैसे मायिस, डब्लरौटी, अभ्यास - पुस्तिका, फाउन्टेन पेन एवं पेंसिल, ज्ञाने की लकड़ी तथा बर्फ एवं बर्फ केन्डी इत्यादि को बिछी कर से मुक्त कर दिया जाये। उत्तर प्रदेश में बिछीकर की दरें अपेक्षकृत ऊँची हैं और उस पर अतिरिक्त बिछीकर का अनुचित और अनावश्यक भार है। उसे तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए। इस सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा जाकर पर तरवार की समाप्ति विचारणीय आदर्श माना जा सकता है।

इस समय यहाँ बिछीकर से छूट की सीमा उत्पादक विद्येता की दशा में 50,000 रुपये तथा अन्य व्यापारियों की दशा में 1,00,000 रुपये है। बिछीकर आगम के तथ्यों से स्पष्ट है कि तन् 1983-84 में राज्य में प्राप्त कुल बिछीकर आगम का केवल 6.5 प्रतिशत भाग 1,25,000 रुपये तक की बिछी जाने व्यापारियों से प्राप्त होता था और यह भाग तन् 1984-85 में घटकर 4.2 प्रतिशत ही रह गया। अतः सामान्य और छोटे व्यवसायियों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह व्यवहारिक होगा कि कर मुक्ति की विद्युत सीमा को बढ़ाकर उत्पादक विद्येता की दशा में एक लाख रुपये और अन्य व्यापारियों की दशा में दो लाख रुपये कर दिया जाये। ऐसा करने से बिछीकर आगम पर कोई विशेष विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन

व्यापारियों को भारी सुविधा होगी और बिजुलीकर प्रशासन के भार में महत्वपूर्ण कमी आयेगी। इस तन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि सन् 1984-85 में 1,25,000 रुपये बिजुली वाले व्यापारियों की संख्या कुल कर योग्य व्यापारियों के 58.5 प्रतिशत थी जबकि इनसे आगम मात्र 4.2 प्रतिशत था। यदि दो लाख रुपये बिजुली तक के व्यापारियों की दृष्टि से देखा जाए तो यह भाग क्रमशः 73.2 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत था। स्पष्ट है कि बिजुली कर से मुक्त बिजुली कर की सीमा में वृद्धि करने से कर प्रशासन पर आये से अधिक व्यापारियों का भार कम हो जायेगा और कर आगम में मामूली कमी होगी जिसे कर प्रशासन अपनी कुशलता द्वारा अन्य व्यापारियों से प्राप्त कर सकता है।

बिजुलीकर की दरों को कम करने, नगण्य राजस्व प्रदान करने वाली वस्तुओं पर से बिजुलीकर हटाने और कर मुक्ति की सीमा बढ़ाने से राज्य में बिजुलीकर राजस्व में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन करापर्वण को नियन्त्रित करके इसकी पर्याप्त क्षतिपूर्ति की जा सकती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के 59 निगम कार्य कर रहे हैं जिनमें लगभग 4460 करोड़ रुपये विनियोग है, फिर भी प्रतिवर्ष 1017 करोड़ रुपये का घाटा होता है।¹ अतः सरकार को राजस्व प्राप्त के तन्दर्भ में जनता से पर्याप्त मात्रा में ही कर राजस्व पर ही जोर नहीं देना चाहिये, वरन् अपने निगमों की कार्यकुशलता बढ़ाकर लाभ प्राप्त करना चाहिए और दूसरी ओर कर की जटिलताओं, विविधताओं और समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए। बिजुलीकर अवशेषों की धाराशि निरन्तर बढ़ी है। अतः इन अवशेषों की तत्परता से प्रसून करने की आवश्यकता है। बकाया वसूली तथा संयुक्त बांध के मामलों को निबटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए और सम्बन्धित अधिकारियों को मातृक या त्रैमासिक आधार पर यह समीक्षा करते रहना चाहिए कि अवशेष वसूली के प्रयासों में उचित कार्यवाही की जा रही है।

यदि बिजुलीकर से मुक्ति की सीमा बढ़ा दी जाये तो पाँच लाख रुपये तक की बिजुली पर पूर्णतः स्वतः कर-निर्धारण योजना अपनाई जानी चाहिए और जब तक बिजुलीकर विभाग के पास सम्बन्धित व्यापारी द्वारा बिजुलीकर बोरी का स्पष्ट प्रमाण

न हो, स्वतः कर निर्धारण मान लेना चाहिए। इस व्यवस्था में व्यापारी द्वारा तही तथ्यों को प्रेषित करने और प्रेरण देने की दृष्टि से स्वतः कर-निर्धारण योजना के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों के रिटर्नों की एक निश्चित प्रतिशत की प्रतिवर्ध अनिवार्य बैंकिंग होनी चाहिए और उसमें त्रुटि मिलने पर पर्याप्त अधिक दर से पेनल्टी का प्रावधान होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में बिजुलीकर प्रशासन में सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से अलग परि-क्षेत्र, क्षेत्र और मण्डलों का गठन किया गया है। यह उचित होगा कि बिजुलीकर प्रशासन का गठन भी प्रदेश की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरार ही तहसील, जिला और कमिश्नरी स्तर पर बिजुलीकर निर्धारण, संग्रहण और न्याय व्यवस्था को गठित किया जाये।

उत्तर प्रदेश में बिजुलीकर व्यवस्था में स्वीकृत पदों और कार्यरत व्यक्तियों में पर्याप्त अन्तर रहा है। तन् 1984-85 में उपायुक्त बिजुलीकर के 26, सहायक आयुक्त बिजुलीकर के 150, बिजुलीकर अधिकारी के 750, बिजुलीकर अधिकारी ग्रेजी-2 के 642, तृतीय ग्रेजी कर्मचारियों के 6960 और चतुर्थ ग्रेजी कर्मचारियों के 4337 पद स्वीकृत थे, जबकि इन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 22, 116, 672, 409, 5993 और 3486 थी। बिजुलीकर प्रशासन की कुशलता और प्रभावशीलता को बढ़ाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस अन्तर को न्यूनतम किया जाए और उसके पश्चात् यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाये कि विभाग के कार्यों में कोई पेन्डेन्सी न रहे। इससे व्यक्तियों के मन में अनिश्चितता कम होती है, करापरचयन को पकड़ने में सुविधा रहती है और विभाग का कार्य उचित रूप से संचालित होता है।

उत्तर प्रदेश में तन् 1983 में मंडी टैक्स प्रारम्भ किया गया, जो मुख्यतः खाद्यान्नों और किराने के कुछ कृषि उत्पादनों जैसे धनिया, ताँफ़, मेंथी इत्यादि पर लगता है। मंडी कर से प्राप्त राजस्व का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अविकसित मण्डियों को विकसित करने के लिए वित्त जुटाना था, लेकिन यह शहरी क्षेत्रों में भी लगता है और बहुत बिन्दु कर के रूप में लगता है। इससे व्यापारियों को अनावश्यक

कर भार की समस्या आती है। एक ओर बिजुलीकर को तरल और उदार बनाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर मंडी टैक्स को लगाना व्यापारियों के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न करना है और देश के अधिकांश राज्यों में मंडी टैक्स लगता भी नहीं है। अतः यह न्यायसंगत होगा कि मंडी टैक्स को पूर्ण समाप्त कर दिया जाए और बिजुलीकर की राशि में से ही एक निश्चित भाग अविकसित मंडियों के विकास के लिए सुरक्षित रखा जाए।

अतः स्पष्ट रूप में यह कहा जा सकता है कि अपने वर्तमान स्वत्व के अद्वितीय अवधि में बिजुलीकर, स्वतन्त्रता के उपरान्त कुछ ही वर्षों में राज्य के राष्ट्रीय स्तर पर राजस्व के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान समय में राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण आधार के रूप में राजस्व प्रदान कर रहा है। केन्द्र और राज्यों के मध्य वित्त व्यवस्था के आकंटन के वर्तमान परिपेक्ष्य में कुछ सीमित वस्तुओं की दशा में इसका प्रतिस्थापन भी ही हो जाये, लेकिन अप्रत्यक्षकर ढाँचे में राष्ट्रीय स्तर पर कितनी क्रान्तिकारी परिवर्तन के हुए बिना तक सामान्य रूप से यह कर देश में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाये रहेगा और इस सन्दर्भ में यदि उपरोक्त सुझावों को क्रियान्वित करके बिजुलीकर व्यवस्था को तरल, तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और एकस्य बनाया जा सका तो निश्चित रूप से करदाताओं में विशेष अतन्मुखित या विरोध के बिना एक अच्छे करारोपण के विभिन्न सिद्धान्तों की क्लांटी पर धरा उतार कर यह कर राज्य सरकारों के राजस्व में पर्याप्त योगदान प्रदान कर सकेगा।

-----: 0 :-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
परिशिष्ट ३ - ब
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

परिशिष्ट 14।

बिहीन विभाग के परिक्षे, क्षेत्र, मंडल एवं उपमंडल

क्र. सं.	उपायुक्त शा. 01 के परिक्षे का नाम	सहायक आयुक्त शा. 01 के क्षेत्र का नाम	सहायक आयुक्त के क्षेत्र में सम्मिलित मंडल	उपमंडल	समुच्चालीय मंडल का नाम	कुलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	वाराणसी	1. वाराणसी "ए"	1. वाराणसी	बलिया	वाराणसी	1-5
			2. बलिया		बलिया	2
			3. जौनपुर		जौनपुर	2
			4. गाजीपुर			
			5. मुलताबाद			
		2. वाराणसी "बी"	1. वाराणसी		वाराणसी	6-7
			2. गोपीगंज			
			3. मिर्जापुर		मिर्जापुर	2
			4. राबर्टगंज			
			5. भदोही			
2.	झाडाबाद	1. झाडाबाद	1. झाडाबाद		झाडाबाद	7
			2. पुतायगढ़			
			3. फतेहपुर			
		2. झांसी	1. झांसी		झांसी	2
			2. नमिस्तपुर			
			3. उरई		उरई	2
			4. बांदा		बांदा	2
			5. खीर			
			6. मधोबा			
3.	गोरखपुर	1. गोरखपुर	1. गोरखपुर		गोरखपुर	4
			2. आजमगढ़		आजमगढ़	2
			3. मऊना धर्मन			
			4. बलिया		बलिया	2

1	2	3	4	5	6	7
			5. तैतरी बाजार			
			6. देवरिया		देवरिया	2
			7. पहरौना			
	2. कैजाबाद	1. कैजाबाद			कैजाबाद	2
		2. अकबरपुर				
		3. गोण्डा			गोण्डा	2
		4. कलरामपुर				
		5. कुतानपुर				
		6. बहराइच			बहराइच	2
		7. नानपारा				
4. लखनऊ	1. लखनऊ	1. लखनऊ			लखनऊ	11
		2. रायबरेली				
		3. बाराबंकी				
	2. तीतापुर	1. तीतापुर		1. पणियाकना तीतापुर		2
		2. लखीमपुरखीरी		लखीमपुरखीरी		2
		3. हरदोई		हरदोई		2
		4. गालवहापुर		गालवहापुर		2
5. कानपुर	1. कानपुर "र"	1. कानपुर			कानपुर	1-10
		2. फुकरावा				
	2. कानपुर "बी"	1. कानपुर			कानपुर	11-19
		2. उन्नाव				
		3. इटावा				
6. अलीगढ़	1. अलीगढ़	1. अलीगढ़		1. कातगंज अलीगढ़		6
		2. हाथरस		2. गंजहंज बारा हाथरस		2
		3. रटा				
	2. मैनपुरी	1. मैनपुरी		1. जौरेया		
		2. बटावा		2. गिफोहाबाद		

1	2	3	4	5	6	7
			3. कोहगढ़ 4. कुम्हौज 5. मंझना		कोहगढ़	2
7. आगरा	1. आगरा "ए"	1. आगरा 2. फिरोजाबाद			आगरा फिरोजाबाद	1-7 3
	2. आगरा "बी"	1. आगरा 2. मथुरा 3. कोतीका			आगरा मथुरा	8-14 3
8. बरेली	1. बरेली	1. बरेली 2. बदायूं 3. पीलीभीत			बरेली बदायूं पीलीभीत	6 2 2
	2. हल्दानी	1. नैनीताल 2. काशीपुर 3. छटीमा 4. रघुपुर 5. रामनगर 6. अल्मोड़ा 7. पिथौरागढ़ 8. हल्दानी			हल्दानी	2
9. मुरादाबाद	1. मुरादाबाद	1. मुरादाबाद 2. चन्दाती 3. अमरौड़ा 4. हसनपुर 5. तम्भ 6. रामपुर			मुरादाबाद चन्दाती रामपुर	6 2 2
	2. कियनौर	1. कियनौर 2. कोटहार 3. धामपुर 4. नसीबाबाद	1. चान्दपुर 2. नैतडाउन 3. रघुपान		धामपुर	2

1	2	3	4	5	6
10. तहारनपुर	1. तहारनपुर	1. तहारनपुर 2. देवचन्द 3. देहरादून 4. शम्भोरा	तहारनपुर देहरादून	6 4	
	2. मुजफ्फरनगर	1. मुजफ्फरनगर 2. शास्त्री 3. छातीली 4. स्फुरी 5. हरिद्वार	मुजफ्फरनगर शास्त्री	4 2	
11. मेरठ	1. मेरठ	1. मेरठ 2. बढौत 3. सरय्या 4. मयाना 5. हापुड	मेरठ बढौत हापुड	7 2 3	
12. नाबियाबाद	1. नाबियाबाद	1. नाबियाबाद 2. मोदीनगर 3. कुन्दरहर 4. डिबाई 5. तिकुन्दराबाद 6. मुनापटी 7. कुर्वा 8. नोसडा	नाबियाबाद कुन्दरहर कुर्वा नोसडा	8 3 2 3	

स्रोत : आयुक्त दिल्ली उत्तर प्रदेश, सांख्यिकीय अनुभाग, दिल्ली विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतियोग, 1984-85 तकक पर आधारित, पृष्ठ संख्या 62-63

परिशिष्ट 1।

कर मुक्त वस्तुओं की सूची

उत्तर प्रदेश बिजलीकर अधिनियम की धारा 4।3। के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं के जूय-विक्रय पर बिजलीकर नहीं लगता । ये वस्तुएँ निम्न हैं :

- 13। पानी, परन्तु इसमें खनिज पानी, सोडा वाटर, टानिक का पानी, डिस्टिल्ड पानी तथा इत्र का पानी शामिल नहीं है ;
- 14। दूध, परन्तु इसमें Condensed दूध का पाउडर तथा Baby Milk शामिल नहीं है ;
- 15। नमक, इसमें काला नमक शामिल है ।;
- 16। तमाचार-पत्र ;
- 17। मोटर स्पिड तथा डीजल तेल ;
- 18। स्क्वोश ; तथा
- 19। अन्य कोई वस्तु जो राज्य सरकार द्वारा कर से मुक्त घोषित कर दी गयी हो । सरकार ने निम्न वस्तुओं को कर-मुक्त घोषित कर दिया है ;
 1. कृषक यन्त्र जो मानव अथवा पशुशक्ति से चलते हैं ।
 2. हथकरघा से निर्मित सब प्रकार का कपड़ा ।धोतियाँ, साड़ियाँ तथा पल्लन की चादर सहित।;
 3. पट्टियाँ जो चोट, घाव आदि पर बाँधी जाती हैं ;
 4. बारदाना तथा डिब्बे ।ऐसे व्यापारी द्वारा इसका विक्रय जो केवल कर मुक्त माल बेचता है और अपने मुख्य व्यापार के दौरान इसका भी विक्रय करता है।;

5. पुस्तकें तथा मैगजीन ;
6. जिल्दताजी में प्रयुक्त होने वाला कपड़ा, चमड़ा आदि ;
7. बैत का बना सामान । फर्नीचर को छोड़कर ;
8. गन्ने के बीज ;
9. कैनवास का कपड़ा ;
10. पशुओं का चारा । कुनी, भूरी, छिलके-चोकर, ग्वार आदि ;
11. चौकें छड़िया की ;
12. चरखा तथा उसके भाग ;
13. चिकन के काम का कपड़ा जो मिल में न बना हो ;
14. तिगार, तिगरेटें, बीड़ी तथा तम्बाकू का कोई रूप ;
15. देशी शराब ;
16. डीजल तेल ;
17. दरियाँ जो हथकरछे अथवा पिटलूम पर बनी हों ;
18. खाने का तेल जो घानी पर मानव अथवा पशुशक्ति से बना हो ;
19. अण्डे ;
20. तरकारी तत्ते गन्ने की दुकान पर तरकार की शतों के अधीन बेचा गया गन्ना ;
21. खाद, रासायनिक खाद छोड़कर ;
22. ताजी फल तथा हरी सब्जियाँ ;
23. चिकन का काम किये हुए तिले हुए चप्पल, चाहे मिल के कपड़े पर हो, चाहे हथकरछे के कपड़े पर ;
24. गैर गैल का प्लास्ट तथा उसके भाग । सेक्शन 31.3.81 तक ;
अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई, 1980।
25. स्थान ;
26. हाथ का बना गोटा यदि व्यापारी स्वयं निर्माता हो ;
27. हाथ का कता हुआ धागा ;
28. शब्द ;
29. तीर्थ के कंठे ;

30. होजरी का कपड़ा ;
31. क्लाबत्तू तथा जरी ;
32. खाड़ितारी शक्कर ;
33. जीर्ने, मुरमुरा लैया। तथा फिचड़ा ;
34. कोट्ट, रामदाना व तिंघाड़ा ;
35. पशु ;
36. कच्चा गोरत तथा मज्जी। कुली हुई व ताजी। ;
37. दूध (Condensed व डिब्बे का दूध छोड़कर) ;
38. मोटर त्रिप्ट ;
39. मुमम्मा ;
40. तमा चार-पत्र ;
41. हथकरधे पर बनी हुई निबाइ ;
42. गिलट के आभूषण ;
43. धान (Paddy)
44. तादा पान ;
45. धुने हुए धने ;
46. प्लास्टिक बैग का सामान। फनीयर को छोड़कर। ;
47. Water Proof पत्र ;
48. नमक ;
49. बीज। धैरों अथवा डिब्बों में।
50. ताछ बत्ती ;
51. तिंघाड़ा व तिंघाड़े का आटा ;
52. तलेटें व तलेट की बत्तियाँ ;
53. चीनी ;
54. पानी ;
55. वाटर मार्क कागज ;
56. फूल, फूलों के बीज, पौधे, कच्ची, खीरा, खरबूजा तथा खरबूजे के बीज ;
57. हवा से जाने वाली चक्की। विंडमिल,। जनवरी 1981 में।

परिशिष्ट 14।जांच चौकियाँ एवं तहल दल इकाईयाँ

<u>पिछीकर अधिकारी। पुरभारी। के नियंत्रण में जांच चौकियाँ</u>			
<u>क्र० जांच चौकियों</u> <u>त० के नाम</u>	<u>जनपद का नाम</u>	<u>क्र० जांच चौकियों</u> <u>त० के नाम</u>	<u>जनपद का नाम</u>
1. कुल्हाल	देहरादून	24. तहराय	इति
2. करगवाँ	तहारनपुर	25. रक्ता	तमितपुर
3. कैराना	मुजफ्फरनगर	26. म्हाँरा	तमितपुर
4. लोनी	मेरठ	27. ग्रीनगर	हमीरपुर
5. दूतिपौटनगर	गाजियाबाद	28. चौखटा	झाहाबाद
6. विजयनगर	गाजियाबाद	29. हुमनगंज। हुमनगंज।	मिनापुर
7. मोहननगर	गाजियाबाद	30. राबर्टगंज	मिनापुर
8. भीपुरा	गाजियाबाद	31. नौबतपुर	बाराणसी
9. ताहिबाबाद	गाजियाबाद	32. भोली	बलिया
10. डल्लपुरा	गाजियाबाद	33. मेहरौना	देवरिया
11. चिल्ना	गाजियाबाद	34. तमकुही राजपौराहा	देवरिया
12. महाराजपुर	गाजियाबाद	35. सुनौली	गोरखपुर
13. भीलापुर	गाजियाबाद	36. लुहंडिहा	बहराईव
14. इन्दपुरी	गाजियाबाद	37. कमनगर	खीरी
15. तूरपुर दादरी	गाजियाबाद	38. गौरकिन्टा	खीरी
16. कोटवन	मथुरा	39. कवाता	मैतीताल
17. हुगरी	मथुरा	40. तीछ	मथुरा
18. कडमेरा	आगरा	41. गोषधन	मथुरा
19. फोहपुर तीकरी	आगरा	42. नन्दगवि	मथुरा
20. नमराबाद	आगरा	43. देवरीमऊ रानीपुर	इति
21. तवाँ	आगरा	44. तीतापुर	बाँदा
22. गवरीन	इटावा	45. नरनीचौराहा	बाँदा
23. तवाँ	इटावा	46. बारा	गाजीपुर

बिड़ौकर अधिकारी (पुभारी) के नियन्त्रण में तका टल

1. सहारनपुर		17. हटावा	
2. मुजफ्फरनगर		18. कानपुर	पुथम
3. मेरठ		19. कानपुर	द्वितीय
4. गाजियाबाद	पुथम	20. कानपुर	तृतीय
5. गाजियाबाद	द्वितीय	21. पुष्कराया	
6. गाजियाबाद	तृतीय	22. हांसी	
7. कुनन्दाहर		23. हमीरपुर	
8. अलीगढ़		24. इलाहाबाद	
9. मथुरा		25. मिर्जापुर	
10. आगरा	पुथम	26. वाराणसी	पुथम
11. आगरा	द्वितीय	27. वाराणसी	द्वितीय
12. शटा		28. गोरखपुर	
13. बरेली		29. फैजाबाद	
14. मुरादाबाद	पुथम	30. बीरौ	
15. मुरादाबाद	द्वितीय	31. लखनऊ	
16. हाथुड़		32. मुख्यालय (इकाई)	

स्त्रोत : आयुक्त बिड़ौकर उत्तर प्रदेश, तारिखीय अनुभाग, बिड़ौकर विभाग का तामान्य वार्षिक प्रतिवेदन, 1984-85 लखनऊ पर आधारित, पृष्ठ 64.

परिशिष्ट 1य।

क्रय-विक्रय कर से मुक्त संस्थाएँ

उत्तर प्रदेश बिड्रीकर अधिनियम की धारा 41ब। के अन्तर्गत निम्न संस्थाओं द्वारा माल का क्रय-विक्रय कर-मुक्त है :

1अ। अखिल भारतीय कताई संघ ;

1ब। गांधी आश्रम, मेरठ तथा उसकी शाखाओं द्वारा माल का क्रय-विक्रय;
तथा

1स। अन्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग द्वारा किये गये क्रय-विक्रय पर जिनका नाम राज्य सरकार द्वारा कबट में इस सम्बन्ध में प्रकाशित कर दिया जाय ।

राज्य सरकार ने अग्रांकित व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के नाम इस सम्बन्ध में घोषित किये हैं :

1. कश्मीर सरकार के जार्ट एम्पौरियम की लकनऊ व देहरादून की शाखाएँ;
2. जवाहर लाल नेहरू स्मृति कोष, जलाहाबाद ;
3. उद्योग मन्त्रालय, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विकास योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र ;
4. रेलों में रेस्टोरेण्ट-कार द्वारा विक्रय ;
5. भारतीय रेल प्रदर्शनी, बम्बई द्वारा संचालित "परिषदों पर प्रदर्शनी" में भाग लेने वाले व्यापारियों द्वारा प्रदर्शनी में विक्रय ;
6. अखिल भारतीय छादी तथा ग्रामोफोन, बम्बई द्वारा उत्तर प्रदेश में मान्य संस्थाएँ ;
7. उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं में छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए काये गये भोज ;
8. तिब्बत महिला केन्द्र, देहरादून ; 13.1.3. 1984 तक।
9. तिब्बत नेहरू मेमोरियल फाउण्डेशन ;
10. नारी का मन्दिर, लकनऊ ;
11. उत्तर प्रदेश राजकीय कर्मचारी कल्याण निगम ;

12. मिलिट्री कैप्टीन व कैप्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट इण्डिया ;
13. भारतीय मिलिट्री अकादमी बेकरी, देहरादून ;
14. उत्तर प्रदेश में सरकार, स्थानीय सत्ता अथवा पुण्याई उद्देश्यों के लिए बनायी गयी संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पताल अथवा डिस्पेन्सरी ;
15. Indian Tourism Development Corporation Limited की बनारस हवाई अड्डे की शाखा द्वारा विदेशी यात्रियों को विदेशी मुद्रा के प्रतिफल स्वस्थ देया गया माल बगैरे Cash Memo/Bill पर निम्न सूझाई हों ;
 - ।अ। विदेशी यात्री का नाम ;
 - ।ब। पासपोर्ट नम्बर तथा पासपोर्ट जारी करने वाले देश का नाम ;
 - ।त। यात्री टिकट नम्बर ;
 - ।द। Flight नम्बर ;
 - ।य। हवाई कम्पनी का नाम ;
 - ।र। बिज्जी का विवरण ;
 - ।न। क्रेता के हस्ताक्षर ; एवं
 - ।व। विदेशी मुद्रा प्राप्ति की यात्रा (Notification dated 30th July, 1981).
16. व्यापारी द्वारा स्वनिर्मित मिला बिज्जी की शक्ति की सहायता के। तंगमरगर की मूर्तियों (Marble Idols) की बिज्जी (Notification dated 10th Sept., 1980).
17. आयुर्वेदिक सेवा समिति, बाबा काली कमी, उधिमरा द्वारा बिज्जीत आयुर्वेदिक औषधियाँ ; (Notification dated 16th May, 1981).

ग्रन्थ सूची

1. Aiyer, V.G.R., Public Finance, Rawat, Jaipur, 1978.
2. Andley, Sundram & Agarwal, Public Economics and Public Finance, Ratan Prakashan Mandir, Hospital Road, Agra, 1985.
3. Bhargava, P.K., Essay on Public Finance, Kishore Publishing House, Kanpur, 1978.
4. Bhargava, R.N., Public Finance, Chaitanya Publishing House, Allahabad, 1971.
5. Bhargava, R.N., and Bhargava P.K., Public Finance of the Central & State Government of India, Chugh Publication, Allahabad, 1978.
6. Bhatia, H.L., Public Finance, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 5 Ansari Road, New Delhi, 1982.
7. Bhatnager, Susha, Union State Financial Relations and Finance Commissions, Chugh Publication, Allahabad, 1979.
8. Bird, M., An Appraisal of the Columbian Sales Tax Baltimore, John Hopkins Press, 1967.
9. Chawla, O.P., Gupta, B.L. & Nahar, M.L., Introduction of Central & Rajasthan Sales Tax, Ramesh Book Depot, Jaipur, Rajasthan.
10. Chawla, O.P., Personal Taxation in India, Sonaya Publication, 1972.
11. Dalton, H., Principles of Public Finance, Printed in Great Britain by Butler & Tanner Ltd., Porre and London.
12. Dhingra, W.C., Madhya Pradesh Central Sales Tax Act, 1958.
13. Due, John F., The Retail Sales Tax in Honduras Reading on Taxation in Developing Countries, Bird and Oldman, John Hopkins Press, 1967.

14. Due, John P., Public Finance, John Hopkines Press, 1967.
15. Eckstein, O., Economic Policy in our Time Amsterdam, North Holland Publishing Company, 1968.
16. Gaur, V.P. & Narang D.B., Punjab General Sales Tax Act, 1948. Kalyani Publishers, New Delhi, 1981.
17. Gaves, Harold M., Financing Government Vth Edition.
18. Goyal, J.P., Sales Tax Uttar Pradesh & Central, 1985.
19. Goyal, J.P., Sales Tax Haryana, 1985.
20. Goyal, J.P., Sales Tax Delhi, 1985.
21. Goyal, Radhey Shyam, Rules and Interperations of Sales Tax Commodities under Uttar Pradesh Sales Tax Act 1948 & Central Sales Tax Act 1956.
22. Gurtoo, D.N., Public Finance College Book Depot, Jaipur, Printed by Bharat Printers Jaipur, 1972.
23. Haig And Shoup, The Sales Tax in American States.
24. Hajela, T.N., Public Finance, Shiv Lal Agarwal & Co., Agra-3, 1978.
25. Hicks, U.K., Public Finance-Oxford at the Clavendon Press, Printed at Great Britain.
26. Lokanathan, P.S., Sales Tax System in Andhra Pradesh, Published by National Council of Applied Economic Research, New Delhi, 1963.
27. Maheshwari, K.L., Rajaswa, Oriental Printing Press, Alighrh.
28. Mehrotra, H.C., & Goyal S.P., The Law Sales Tax in Uttar Pradesh & Sales Tax Sahitya Bhawan, Agra 3.
29. Mehta J.K., Public Finance, Kitab Mahal, Allahabad, 1973.

30. **Misra, B., Economics of Public Finance, Macmillan India Ltd., New Delhi, 1980.**
31. **Pant, J.C., Public Finance, 1984-85.**
32. **Pigou, A.C., A Study in Public Finance, Macmillan & Co., Ltd., New York, St. Martin's Press Printed at Great Britain, 1956.**
33. **Prest, A.R., Public Finance in Theory and Practice, English Language Book Society and Waidenfield and Nicolson, Printed at Great Britain, 1960.**
34. **Saligman, Studies of Public Finance.**
35. **Samana, R.C. and Mathur, P.C., Public Finance, Jai Prakash Nath & Co., Meerut, 1970.**
36. **Sharma, K.K., and Gaitan, R.K., Public Finance, Vikash Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, Printed at Rupak Printers, New Delhi.**
37. **Singh, S.K., Public Finance in Developed and Developing Countries, Published S.Chand & Company Ltd., Ram Nagar, New Delhi, 1986.**
38. **Srinivasachari, M., Tamil Nadu Sales Tax (Madras Act 1 of 1959).**
39. **Taylor, P.E., The Economics of Public Finance, Oxford & IBN Publishing Co., 36 Chowkinghee Road, Calcutta, 16, 1965.**
40. **Thathachary, V.G.K., Incidence of Taxation in Gujarat, Published, National Council of Applied Economic Research, Parisila Shewan, Indraprastha Estate, New Delhi.**
41. **Tyagi, B.P., Public Finance, Publisher, Jai Prakash Nath Publication, Meerut, 1983-84.**
42. **Venu, S., Public Finance & Fiscal Policy, Trimurti Publication Pvt. Ltd., H-152, Greater Kailash, New Delhi, 110048.**

B GOVERNMENT PUBLICATIONS & REPORTS

1. Central Sales Tax Act & U.P. Sales Tax Act.
2. U.P. Sales Tax Rule, 1948.
3. The Central Sales Tax Registration and Turnover Rules.
4. Report of Taxation Enquiry Commission, Vol. III, 1953-54.
5. Report of Indirect Taxation enquiry Committee (Jha Committee) 1977-78.
6. Reports of Finance Commissions.
7. Reports on Currency & Finance.

C आयुक्त, बिजलीकर, उत्तर प्रदेश के प्रकाशन

1. बिजलीकर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1978-79 से 1984-85।
2. महत्वपूर्ण आदेशों एवं परिषदों की बैठकें। त्रैमासिक कुमाई-सितम्बर 1984 से त्रैमासिक कुमाई-सितम्बर 1985।
3. बिजलीकर विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वार्षिक प्रतिवेदन, 1985-86.

D JOURNALS

1. Business Standard.
2. Commerce.
3. Eastern Economist.
4. Reserve Bank of India Bulletin.
5. The Economic Scene.

E NEWS PAPERS

1. Dainik Rajpath, New Delhi.
2. Financial Express, Bombay.
3. Hindustan Times, New Delhi.
4. Hindustan (Hindi), New Delhi.
5. Nav Bharat Times, New Delhi.
6. The Economic Times, New Delhi.